Fourth Series, Vol.II, No.8

Wenesday, November 26, 1969
Agrahayana 5, 1891 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Ninth Session)

(Vol. II contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

Price : Rs. 1 00

CONTENTS

No. 8—Wednesday, November 26, 1969/Agrahayana 5, 1891 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Question:	
*Starred Questions Nos. 211 to 213, 215 and 216	1--30
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 214 and 217 to 240	30--50
Unstarred Questions Nos. 1401 to 1412, 1414, 1415, 1417 to 1460, 1462 to 1533, 1535 to 1568, 1471, 1572, 1574, 1575, 1577 to 1592 and 1594 to 1600.	50--189
Reported Raids on certain villages in West Bengal ...	189
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance--Reported Violation of air corridor between West and East Pakistan by Pakistani air-craft ...	189--205
Papers laid on the Table ...	205--206
Committee on Private Members Bills and Resolutions--Fifty-fifth Report	206
Matter under Rule 377—	
Shri Nehru's decision on India's participation in religious conferences	206--211
Committee of Privileges--Nnth Report	211
Motor Vehicles (Amendment) Bill--	
motion to consider, as passed by Rajya Sabha	211--82
Shri Om Prakash Tyagi	211- 18,221
Shri R. S. Arumugam	221--223
Shri Krishna Kumar Chatterji	223--227
Shri Kiruttinan	227--229
Shri Randhir Singh	229--234
Shri S. Kundu	234--237
Shri Yashpal Singh	237--239
Shri Sarjoo Pandey	240--244

*The sign + marked above the Name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Shri Nathu Ram Ahirwar 244--248
Shri Shiva Chandra Jha 248--252
Shri Vikram Chandra Mahajan 252--256
Shri Tenneti Viswanatham 256--258
Shri Abdul Ghani Dar 258--263
Shri Beni Shanker Sharma 264--267
Shri Mohammad Ismail 267--270
Shri Iqbal Singh 270--279
Clause 2. ... 279--282
Re. Retrenchment in certain Defence Establishments. 219--221
Motion Re. encouragement to Subversive and Violent Activities in the country. ... 282--310
Shri Prakash Vir Shastri ... 283-85,288-95
Shri Prem Chand Verma ... 296--299
Shri Manubhai Patel .. 300--306
Shrimati Ila Palchoudhuri 306--310
Half-an-hour Discussion–
Income-Tax Arrears 310--328
Shri Om Prakash Tyagi 310--316
Shri P. C. Sethi 320--328

LOK SABHA

Wednesday, November 26, 1969/Agrahayana 5, 1891 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खादी तथा हाथकरघा उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले सूत पर उत्पादन शुल्क

*1211. **श्री क० मि० मधुकर:** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और हथकरघा उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले सूत पर भारी उत्पादन शुल्क लगा दिये जाने के परिणामस्वरूप देश में इस उद्योग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो हथकरघा उद्योग को राज्यवार कितनी मात्रा में सूत सप्लाई किया जाता है और उस पर कितना उत्पादन शुल्क लगाया गया है ; और

(ग) जब सरकार बड़े पैमाने के उद्योग को अनेक सुविधायें दे रही है तो उक्त छोटे पैमाने के उद्योग के मामले में उत्पादन शुल्क में कमी न करने और इस प्रकार इसे प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) हथकरघा उद्योग को राज्यवार सप्लाई किये गये धागे के परिमाण से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) हथकरघा उद्योग द्वारा सामान्यत: प्रयुक्त किये जाने वाले लच्छियों के रूप में धागे पर शुल्क-आपात, शक्तिचालित करघा उद्योग तथा मिलों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अन्य प्रकार के धागे पर लगने वाले शुल्क की तुलना में सदैव कम रखा जाता है।

श्री क० मि० मधुकर : मन्त्री महोदय जानते हैं कि इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि यह हैंडलूम चला कर अपनी रोजी कमाते हैं। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि हमारे यहां इस खादी तथा हथकरघा उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले सूत पर भारी उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है और उसके परिणामस्वरूप देश में इस उद्योग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में लाखों लोग बेकार हो गये हैं। अखबारों में भी खबरें निकली हैं जिनके अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में ऐसे 50 000 हथकरघे वाले लोग हैं जो कि आज बेकार पड़े हुए हैं और जिन्हें कठिनाइयों

का सामना करना पड़ रहा है ? क्या मन्त्री महोदय को इस की जानकारी है कि आज कितने लोग बेकार पड़े हुए हैं और यह कि इस उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है?

आप ने (ग) भाग में अपने उत्तर में कहा है कि हथकरघा उद्योग द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त किये जाने वाले धागे पर शुल्क अन्य प्रकार के धागे पर लगने वाले शुल्क की तुलना में सदैव कम रखा जाता है तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस पर शुल्क कितना बढ़ाया गया है और उसका असर क्या हो रहा है और आज जो हथकरघा उद्योग में लगे हुए बुनकर लोग भारी तादाद में बेकार पड़े हुए हैं उनको तत्काल राहत देने के लिए जिससे वह अपना धंधा कर सकें और रोजी कमा सकें मन्त्री महोदय क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत): जहां तक सूत के दाम का सवाल है खादी के सूत पर कोई कर है नहीं। किसी तरह के हैंडलूम उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले सूत पर उत्पादन शुल्क का यह सवाल था। पावरलूम का नया सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है। जहां तक कपास के सूत का सवाल है उस में कोई बहुत दाम बढ़ गये हों और कोई खास दिक्कत हो रही हो ऐसी तो बात नहीं है। आर्ट-सिल्क में जो पावरलूम के लिए है वह सवाल उस से अलग है। पावरलूम में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। यू पी में या भागलपुर में जो आर्टसिल्क का मसला है उस पर हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो दाम बढ़े हैं उनके लिए हम सोच रहे हैं कि उस दाम को घटायें जिससे कि जो बेकारी फैल रही है वह कम हो जाय। अगर बातचीत से यह हल नहीं होगा तो सोचेंगे कि हम और क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री क० मि० मधुकर : क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर वह मिल-मालिक लोग उनकी बात को नहीं मानते हैं तो वह ऐसी कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे खादी तथा हथकरघा उद्योग में लगे हुए बुनकरों के बीच में से यह बेकारी मिट सके और वह अपना धंधा चला सकें ? आज उन के बीच यह जो बेकारी की समस्या विद्यमान है यह हजारों तक ही नहीं बल्कि लाखों में फैली हुई है।

श्री ब० रा० भगत : एसेन्शियल सप्लाइज ऐक्ट में हमें अधिकार है कि प्राइस कन्ट्रोल करें और साथ ही डिस्ट्रिब्यूशन की भी उचित व्यवस्था करें और हम इन दोनों चीजों को करने की ओर सोचेंगे।

SHRI MANUBHAI PATEL : Last year the problem of the art silk industry, Surat, on which this heavy duty is there, was solved by importing some art silk and distributing it through the S.T.C. But the STC is keeping a very heavy margin so that it is very difficult for the art silk industry to work. Bulk of the produce of the Surat art silk industry is exported. Therefore I want to know whether Government will do some rethinking and reduce this levy on artificial silk supplied to powerlooms.

SHRI R. B. BHAGAT : It is a different question.

SHRI MANUBHAI PATEL : As you say, art silk is included in this; that is why I am asking it.

SHRI B R. BHAGAT : I am prepared to answer if the Chair allows me.

MR SPEAKER : You can give a separate notice. If the Minister is in a position to answer, I don't mind.

SHRI B R BHAGAT : I can answer. The S.T.C came into the picture when there was acute scarcity and the prices were high. Now the S.T.C. has built up stocks and the result is that the prices have come down and, fortunately, the production also of that particular commodity has gone up. So, at the moment, the position is easier. The S.T.C. is charging only the price which the Market can bear. There is no point in the S.T.C. selling at a very low price when the Market can offer more

श्री भाणभाई जे. पटेल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह गृह उद्योग और मशीन उद्योग इन दोनों को वह दरअसल किस सिध्दान्त पर चलाना चाहते हैं ? आज वर्तमान स्थिति यह हो रही है कि जो चीज हाथ से बनाई जाती है अर्थात गृह उद्योग पर भी उतना ही टैक्स लगाया हुआ है जितना कि मशीनी उद्योग पर लगा है। हालत यह है कि गृह उद्योग से जो तार बनाये जाते है उन पर 40 नम्बर से लेकर 150 और 200 नम्बर तक और मिल उद्योग में जो सूत निकलता है उसमें भी 40 नम्बर से लेकर 200 नम्बर तक का सूत निकलता है लेकिन जितना आप मशीन उद्योग के ग्रेड पर शुल्क लगाते हैं उतना ही करीब करीब गृह उद्योग से उत्पादित सूत पर भी शुल्क लगा देते हैं और जाहिर है कि गृह उद्योग उस कारण पनप नहीं पाता है और उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इन दोनों के बारे में सरकार की दरअसल क्या पालिसी है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारी पालिसी इस के बारे में निश्चित है। गृह उद्योग या हथकरघा उद्योग को हमने एक्साइज पालिसी में टैक्सेशन पालिसी में काफी रिआयत कर दी है। उदाहरण के लिए खादी के लिए कोई टैक्स नहीं है। हैंडलूम पर भी अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो पायेंगे कि हैंडलूम पर जो एक्साइज ड्यूटी है वह कोर्स और मीडियम काऊन्ट पर है। 40 के नीचे काऊन्ट पर जो ड्यूटी थी वह भी पिछले बजट के वक्त में उठा दी गई थी। बाकी जो ड्यूटी है पावरलूम और हैंडलूम में उसमें 66 परसेंट तक का वेरिएशन है।

श्री राम सेवक यादव : मन्त्री महोदय ने कहा है कि कर में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन क्या मन्त्री जी को इस की जानकारी है कि हथकरघा उद्योग बड़े संकट में पड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बुनकर लोग आज बिलकुल बेकार हैं। इन लोगों ने आप के उद्योग मन्त्री को एक मैमोरेंडम भेजा था और उसमें कुछ सुझाव दिये थे कि इस इस तरह के काम किये जायें तो उनकी सहायता हो सकती है। वह मैमोरेंडम मन्त्री महोदय को भेज दिया गया है मुझे उद्योग मन्त्री ने लिखा कि वह जो उनका मैमोरेन्डम आप ने भेजा है वह उन्होंने विदेश व्यापार मन्त्री को भेज दिया है। अब इस चीज को दृष्टि में रखते हुए कि यह हथकरघा उद्योग मिलों का मुकाबला कर नहीं पाता है इसलिए उससे बचाने के लिए क्या कोई उनको अनुदान या कुछ खास किस्म का कपड़ा बनाने के लिए विशेष रूप से हथकरघा उद्योग में लगे हुए लोगों को दिया जायेगा और इस तरह मिलों पर प्रतिवर्ष लगाया जायेगा ताकि इस गृह उद्योग को बचाया जा सके और उनको पर्याप्त सहायता मिल सके मैं इस बारे में बिलकुल साफ जानकारी चाहता हूं ?

श्री ब० रा० भगत : उन के उस मैमोरेन्डम पर विचार हो रहा है और उस में से कई बातों को स्वीकार भी किया है। यह भी कहा गया है जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया था कि हथकरघा उद्योग के लिए वह जैसे कलर्ड साड़ी की बात वह हथकरघा उद्योग में ही बनेगी और वह दूसरी जगह नहीं बनेगी। आर्टसिल्क का भी जहां तक सवाल है उसके लिए भी हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

SHRI UMANATH : The excise levy on yarn supplied to the handlooms in comparison to that supplied to the powerlooms and the mills was kept at a lower incidence, as the hon. Minister said, with a view to protect the handlooms so that they may get in a better position. Now, after doing that, despite the measure adopted by the Government, we find that the handlooms are still suffering and in a number of places they are closing down and the weavers are still suffering on account of the high prices of yarn. I would like to know, after the adoption of this method, what is the objection to the Government to completely do away with the excise duty on yarn supplied to the handlooms.

SHRI B R. BHAGAT : That can be considered. But the most important point

is reservation of certain types of production.

SHRI RANGA : That has been done without any effect.

SHRI B. R. BHAGAT : That is really the security, not the differential and that has been done.

SHRI UMANATH : My question has not been answered. I have not asked about any reservation for handloom sector. My question was : despite the lower incidence of excise levy for the handloom yarn, the handloom weavers are still suffering. The problem has not been solved. I would ask the Government as to what is the reason for the Government not accepting the position of doing away with the excise duty on yarn.

SHRI B. R. BHAGAT : I have answered that question. If the hon. Member is not satisfied, I cannot help it. I said that in the last Budget, all qualities upto 40 counts- that is the bulk of production-is exempt and it is only the finer varieties on which excise duty is levied.

SHRI UMANATH : You said on the handloom yarn.

SHRI B. R. BHAGAT : Only the higher group of finer varieties are taxed That is only the differential. The differential is 66% upto 60 counts. As I said, the real insurance to the handloom weaver is the reservation of production. That will help more and that is my answer to the question the hon. Member has put.

SHRI S. KANDAPPAN : The excise duty on yarn was first introduced in 1958-59. I think at that time the collection was about 13 lakhs of rupees. Now it is of the order of 52 crores of rupees. Will the Government consider whether there is a genuine case that at least in the case of handlooms, there should not be any excise duty on yarn at all ?

Secondly, I would like to know whether the Government will agree with the view that the international market for handloom fabrics is suffering because of the high incidence of excise duty on our fabrics and one of the contributing factors is the yarn price. Once you remove the duty on yarn, our handloom exports will pick up.

On these two counts I would like to know from the Government whether they are prepared to do away totally with the duty on yarn that is used for handloom fabrics.

SHRI B. R. BHAGAT : So far as export is concerned, it is not suffering because they get the drawbacks over such levies. Our handloom products and handicrafts are in great demand. We can export as much as we can produce. Organization of production is the only question Our exports are not suffering because of the drawbacks.

SHRI S. KANDAPPAN : That is not correct.

श्री नाथूराम अहिरवार : जो देहातों के अन्दर हथ-करघा उद्योग में काम करने वाले कारीगर हैं उन को जो सूत मिलता है वह बहुत मंहगा मिलता है । क्या एस. टी. सी. की तरफ से सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन के लिये कोई कोटा फिक्स किया जाय और उन को सूत सस्ता मिले ताकि उन का कपड़ा मिल के कपड़े के मुकाबले में सस्ता पड़े और लोग उस को आसानी से खरीद सकें ? उन को जो सूत मिलता है मिल वाले उस का ज्यादा दाम चार्ज करते हैं इस लिये उन का कपड़ा मंहगा होने के कारण उनका धन्धा ठप्प हो रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक दाम का सवाल है जो कपास का सूत है उस पर कोई दाम नहीं बढ़ा है क्योंकि वह काफी तादाद में मिलता है । आर्ट सिल्क का जहां तक सवाल है उस के दाम बढ़ गये हैं और हम कोशिश में हैं कि जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रिब्यूशन को भी अपने हाथ में ले कर उन की सहायता करें ।

SHRI RANGA : The hon. Minister may not be able to give a direct answer here and now in answer to the suggestions that have been made in view of the fact that the Finance Minister also is involved in this question of excise duty. But, in view of the fact that the reservation that has

been referred to by the Minister covers only upto 40 counts and certain varieties of cloth for which yarn upto certain counts.

SHRI S. KANDAPPAN : 100 counts are used.

SHRI RANGA : And also in view of the fact that it also gives protection to the power looms who are the worst possible competitors to the handlooms and in view of the recommendation made by the Government of India to the State Governments that they should give up sales tax on handlooms, would the Government be good enough to give some consideration from now on right upto the time of the next budget to the suggestion made by so many of us that the excise duty on yarn which is being used by handlooms should be removed so that the handloom weavers who number several lakhs and more than several lakhs are to-day unemployed, may be given some effective protection and relief ?

SHRI B. R. BHAGAT : That praticular question will be looked into, because it is our desire ...*(Interruption)*

SHRI RANGA : He need not give reply here and now, yes or no Let him consider it.

SHRI B. R. BHAGAT : I am saying that can be looked into. Even in the last budget, handloom production upto count 40 has been exempted altogether. It is only the higher variety counts...*(Interruption)*

SHRI UMANATH : Handlooms are produced in finer counts also.

SHRI B. R. BHAGAT : That is the only sector left now. The Asoka Mehta Committee which went into this question made a number of recommendations.

SHRI RANGA : You are not satisfied with it.

SHRI B. R. BHAGAT : The main recommendation was about reservation of production of certain categories for the handloom. That has also been implemented.

SHRI UMANATH : What about beyond 40 counts which are used by the handlooms ? That is the question. That question has not been answered. Let him say yes or no.

SHRI RANGA : Let him agree to give consideration to this particular suggestion.

SHRI B. R. BHAGAT : The hon. Member himself said I may not be able to give answer here and now. I said, that can be looked into. I have said that.

SHRI RANGA : Say, 'I will consider'. 'Looked into' is the language of a clerk. 'Consider' is the language of the Minister.

MR. SPEAKER : Next Question.

Export of Rail Wagons to U. S. S. R.

*212. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of the State Trading Corporation and the Soviet experts had discussions in Delhi to finalise deal for the export of wagons to the U. S. S. R. in October, 1969;

(b) whether it is also a fact that since the Indian wagon builders gave their first quotations, for such wagons the international price of steel has gone up by 30 per cent;

(c) whether this factor was taken into consideration while negotiating with the Soviet experts; and

(d) whether any final decision could be arrived at ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Yes, Sir.

(b) There has been considerable increase in the international price of steel since the Indian wagon builders gave their first quotations.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, I have point of order. Twice or thrice the same type

of Questions have been admited on the same subject and they have been discussed on the floor of the House. The same type of Questions, supply of wagons to U. S. S. R. have been taken up twice or thrice. We have tabled a number of important questions. Those have not been admitted. I don't know why such thingss hould happen. (*Interruptions*)

श्री शिव चन्द्र झा : कुछ लोगों के सवालों को ही रिपीट किया जाता है।

MR. SPEAKER : I quite admit this mistake which has happened thrice during this last week. I am going to take action about it. This has happend thrice.

SHRI D. N. PATODIA : Referring to the P. T. I. report from Moscow, on 23rd November, may I know from the hon. Minister whether it is a fact that the Soviet Delegation which visited India in October and November, 1969 was entrusted with the task of merely examining the cost structure of the wagons and negotiations of prices were outside its competence ? If so what was the reason and the justification for the Government to unnecessary leak out and reveal the cost structure of these things which is beyond our business ethics ?

SHRI B. R. BHAGAT : That may be the news report or may be, the understanding of the hon. Member. The Delegation came for the purpose of finalising the agreement, the technical agreement and the technical points may have been stated from Moscow. I do not know what is the authentic position about it. The technical point was cleared and the question of prices remained and that was negotiated. This is the position for which the Delegation came.

SHRI D. N. PATODIA : Are you satisfied with the answer, Sir ? I wanted to know whether the Delegation was competent to negotiate the prices or not ? My question is simple as that.

SHRI B. R. BHAGAT : They negotiated the price. Whether they were competent or not, they negotiated the price.

SHRI D N. PATODIA : Referring to the same report from Moscow, may I know whether it is true that as stated by the Soviet delegates, the Indian prices were considerably in excess of the ruling international prices, compared to those quoted by the Western countries, and if so, what the quotations given by the other Western countries were, and to what extent their prices were lower compared with the prices quoted by India ?

SHRI B. R. BHAGAT : For wagons of this specification, I repeat it, because the specifications were very special and they are not comparable with other categories, we maintain that it is internationally competitive.

SHRI D. N. PATODIA : My question has not been answered.....

MR. SPEAKER : The hon. Member has asked enough number of questions.

SHRI D. N. PATODIA : He has not replied to my questions.

SHRI SHEO NARAIN : The hon. Minister should come prepared. This is not a joke. It is a minority Government in power. So, the hon. Minister must come prepared.

SHRI D. N. PATODIA : May I point out that my question has not been answered ?

MR. SPEAKER : Ever since I have occupied this Chair, I have not known of a single occasion when the hon. Member was satisfied with any of the answers. Always he gets up and says that this question is wrongly answered or that question has not been answered. I cannot help it. Whatever the answer is, he has to take it. If he likes, he can ask a further supplementary question for further elucidation or clarification. But he should not get up all the time on every question and say that the question has been wrongly answered.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Let us have correct answers to the questions.

MR. SPEAKER : In a supplementary question he cannot take the position all the time that the answer has been wrongly given.

SHRI D. N. PATODIA : May I know whether in view of a report from Moscow

that certain Western countries had quoted for similar wagons as those for which India has quoted, and if that be so, to what extent the quotations given by the Western countries were lower compared to the Indian quotations ?

SHRI B. R. BHAGAT : So for as our information goes, there has been no quotation for similar wagons from any other country.

SHRI S. K. TAPURIAH : May I make a submission ?

MR. SPEAKER : The reply is very clear.

श्री जार्ज फरनेंडीज : रूसियों को रेल वैगन बेचने वाला मामला दो वर्षों से चला हुआ है और इस में बहस के सिवा और कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है । पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं इस सदन में आरोप करना चाहता हूं । रेलवे डैंगज लेने के नाम पर रूसियों के जो भी डैलीगेशन हिन्दुस्तान में आए, क्या यह सही नहीं है कि उन डैलीगेशंज ने हिन्दुस्तान के तमाम इंजीनियरिंग कारखानों में, हिन्दुस्तान के तमाम रेल के वैगन बनाने वाले कारखानों में, पूरी जासूसी और खफियागिरी की और जानकारी हासिल की ? हिन्दुस्तान में जो रेल वैगन बनाने वाले कारखानो के मालिक हैं इन लोगों से हिन्दुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में, हिन्दुस्तान की बन्दरगाहों के बारे में जानकारी उन्होंने मांगी और उनको कहा कि अगर वे जानकारी देंगे तभी उनको आर्डर्ज मिलेंगे, क्या यह सब सही नहीं है ? इस पृष्ठभूमि में क्या आप इस सदन की एक कमेटी तत्काल बिठायेंगे जो सारे रूसी वैगन डील के बारे में जांच करे ?

श्री ब० रा० भगत : यह सर्वथा निराधार है ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : यह सौ फीसदी सही है । दस्तावेजों के साथ मैं इस आरोप को साबित करूंगा ।

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : Are you going to appoint a parliamentary committee to look into this matter or not ?

श्री ब० रा० भगत : निराधार आरोपों के आधार पर कोई कमेटी नहीं बिठाई जा सकती है ।

श्री मधु लिमये : वह डाकुमैंटस देने के लिए तैयार हैं ।

श्री ब० रा० भगत : इस में मेन सप्लायर्ज पांच है और सब प्राइवेट सेक्टर के हैं । इतने बड़े आर्डर जो बायर है और सप्लायर है, चाहे वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया की टीम हो या जो पांच सप्लायर्ज हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वे हों, उन मे ऐसी कोई बात भी नही हुई है जो किसी भी दूसरी कंट्री से, दूसरे मुल्क के सप्लायर और बायर्ज में बात होती है, प्रोडक्शन दिखाने के लिए या फैक्ट्री दिखाने के लिए या टेक्नीकल डिसकशन के लिए जिस के आधार पर यह कहा जा सकता हो कि इस प्रकार के आरोप मे कोई तथ्य है ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : आप गलत कहते है । देश को आप बेचते हो । हम जानते हैं आप लोगों की पूरी चाल है ।

MR. SPEAKER : This question had come up last time, and a number of supplementary questions had been asked on that occasion. I think there is no need to ask any further supplementary questions now. Next question.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : It is a very important question. You will have to allow some supplementaries.

MR. SPEAKER : Next question.

T. V. Set Invested for Catching Signals from a satellite

*213. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian technicians has invented a television set entirely with the Indian know-how to catch signals directly from a satellite;

(b) whether this has been completed and tested;

(c) if so, how it compares in its performance and cost with similar foreign sets;

(d) whether its production will be undertaken on commercial basis; and

(e) the annual production thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) As far as the Ministry of Defence are aware, no such invention has been made by Indian technicians.

(b) to (e) . Do not arise.

MR. SPEAKER : Now, Shrimati Ila Palchoudhuri .

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : *r se—*

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : It was a very important question and you should have allowed some more supplemantary questions .....

MR. SPEAKER : This is the second time that this question has come up. This question had come up earlier also.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : No Member from our party has been allowed to put the question.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Apart from the question, here was a very serious allegation made by a very senior Member and the hon. Minister has denied it. How do we know who is right ? Both are equally hon. Members of the House.

श्री जार्ज फरनेंडीज : आप पार्लिमेंटरी कमेटी बिठाइये । तब पता चलेगा कि वह सही हैं या मैं सही हूं । इसका तब आपको सबूत मिलेगा । कमेटी के सामने श्री भगत भी जायें और मैं भी जाऊंगा । दूसरे लोग भी जायेंगे । हम जानते हैं कि रूसियों ने क्या क्या किया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर आरोप सरकार पर लगाये गये हैं ।

SHRI RANGA : May I suggest that it is within your rights ? You can remit this question to the Estimates Committee and let them inquire into it.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : We want a parliamentary inquiry into this matter.

श्री हुकम चन्द कछवाय : रूस के एजेंट यहां भी बैठे हुए हैं, रूस के दलाल यहां भी बैठे हुए हैं । आप जांच कमेटी बिठाइये । रूस के एजेंट उधर भी हैं और इधर भी है ।

MR. SPEAKER : Will the hon. Members please take their seats ? I cannot hear anything. (*Interruptions*) Will Shri George Fernandes take his seat now ? (*Interruptions*)

SHRI HEM BARUA : It pains me to say that Parliament has been reduced to a market-place. Any Member has a right to put a question. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Will Shri George Fernandes resume his seat or not ?

SHRI HEM BARUA : Any Member has a right to put a question and it is for you to give him protection. But you have not given him protection. How do the other Members come into the picture ?

MR. SPEAKER : I am very sorry that this has become a practice here. Sometimes a question may not be to the liking of another hon. Member.

A member has an inherent right to ask a question, whether the question or the answer is to the liking of another member or not. This is not a healthy practice that all the time some members interrupt

other members who are asking their questions and getting the answers. In this way how will you function ?

श्री रविराय : उन्होंने आप से सवाल पूछा था। (व्यवधान) यह कैसे पिक्चर में आये ? (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : इस सदन में कोई सदस्य किसी दूसरे को धमकी नहीं दे सकता है। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार के इनटरप्शन्ज़ को रोकते क्यों नहीं हैं ?

MR. SPEAKER : I have been warning Shri Ram Avtar Shastri since three or four days not to interrupt members during question hour.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : You have gone over to the next question. That is all right. But some grave allegations were made by an hon. member. The Minister requdiated them; would it be referred to a committee of inquiry since the hon. member has requested you and said that he has documentary proof ? Even in the reply the Minister has given, he has not clarified this position. The hon. member maintains that information from our defence establishments was collected by the Soviet delegation.....

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT) : That is not connected with this question.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : .. when they were here to finalise this deal. The Minister has onlysaid that this is baseless so far as this particular issue is concerned. But in regard to this allegation, we want to know if there is any truth in it.

SHRI B. R. BHAGAT : There is absolutely no truth in this. Any number of allegations can be sprung up like this without any facts or figures. Where are the facts ? Let the hon. Member come out with them.

SHRI MADHU LIMAYE : Let him agree to it going to a committee.

SHRI RABI RAY : Parliamentary Committee.

DR RAM SUBHAG SINGH : A serious allegation has been made. The hon. member making it says that he has various documents in his possession to prove it. I suggest that these documents be examined by you and if there is anything in them, the matter might be referred to a Parliamentary Committee.

SHRI D. N. TIWARY : There is no proof of these allegations. How could they be entertained ?

MR. SPEAKER : I have already called Shrimati Ila Palchoudhuri.

SHRI RANGA : We want to co-operate with you, but you do not want to co-operate with us. You do not give any chance to a member from this side to put a question while giving chance to others. We have made a helpful suggestion in this matter But you are not good enough to give any consideration to it. You simply say in reply that 'I have called the next question'. How do you expect us to co-operate in these circumstances ? You must give protection to us. This is not the way to conduct proceedings. Shrimati Sucheta Kripalani wanted to put a supplementary. In reply, you were good enough to say 'I am going to the next question'. But in between you allowed all these disturbances and you are sitting tight, completely helpless like ourselves. We have made a helpful suggestion but you are not willing to accept it. You do not want co-operation from members who are willing to co-operate. How can we co-operate if you are not willing to co-operate with us ? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : I must tell Shri Ranga not to try to cow me down.

SHRI RANGA : But we are not going to be brow-beaten either. Co-operation must be mutual. Is that trying to cow down.

MR. SPEAKER : He must sit down.

SHRI RANGA : I will not sit down. You must also co-operate with us. What is this ? (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER : On a point of order.

MR. SPEAKER : I told them in the beginning that this question had come up last week and a number of supplementaries were then asked. By mistake of the office, it has come up again on the question list today.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

MR. SPEAKER : Now, quite a few supplementaries were again allowed on that. Certain allegations are made. I wonder if on all repudiations and contradictions I should appoint committees. I do not know what the position of the Speaker is. I shall study if I can do that but that is not the way Prof. Ranga should talk to the Chair. I disapprove of it.

SHRI RANGA : Which other way ? We disapprove of your way also.

MR. SPEAKER : I do not like it.

SHRI RANGA : It does not matter. We are here to function.

MR. SPEAKER : If you are there, you must function properly. You must also show respect.

SHRI RANGA : We expect you to co-operate with us.

DR. RAM SUBHAG SINGH : This has been going on for a long time ..(*Interruptions*).

MR. SPEAKER : This is the second time I have allowed this question. I never wanted this question to be allowed. In spite of that, I called Mr. Patodia and allowed quite a few questions.

SHRI N SHIVAPPA : What happened to the other members here ?

MR. SPEAKER : Mr Patodia is your member.

DR. RAM SUBHAG SINGH : This is a matter of very great importance and it has been there for the last few years. and so it is bound to feature on the agenda of the House repeatedly, and there is nothing wrong if it is featured so often. As you say, perhaps it was discussed last week, I am not sure whether it came up or not, but here is a point that somebody is having some documentary proof and he is prepared to put that proof before you. So, it should be within your competence to pursue that and set up a parliamentary committee to enquire into it.

MR SPEAKER : I am not in a position to say offhand, just now, whether I will appoint a parliamentary committee or not. You cannot expect it. If you send that material to me, I will look into that. I am not in a position straightaway to say that I will do it.

SHRI RANGA : You can say you will consider.

MR. SPEAKER : You can come to me, show your papers and I will look into it, but I cannot say just now straightaway that I will appoint a committee.

SHRI RANGA : It is no good your threatening us.

MR. SPEAKER What were you doing ?

SHRI RANGA : I only said: you co-operate with us and expect us to co-operate with you. Is there anything wrong in that ? We have made that suggestion. Is there anything wrong in expecting you to say that you will consider the suggestion ? It is based on past practice.

MR. SPEAKER : You are a senior member, parliamentarian and my old friend, but when I am sitting here in the Chair, I just behave as the Speaker.

श्री तुलसीदास जाधव : अध्यक्ष महोदय, नियम 349 के अंडर मेरा पायंट आफ आर्डर है । आप मुझे दो मिनट दीजिए ।

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : There is no point of order in the Question Hour.

MR. SPEAKER : I have already gone over to the next question, and the Minister has read the answer. How can you raise a point of order ?

SHRI RANDHIR SINGH : Please do not allow any point of order during the Question Hour.

MR SPEAKER : How can I stop it ?

Shrimati Ila Palchoudhuri.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : May I know whether such T. V. sets with equipment, as was disclosed by the Information Minister on 4.11.69, exist with our defence units, and how many such sets would be required to equip our defence units ?

SHRI M R KRISHNA : The sets which the defence units are having are of different kinds and I do not think it is necessary for me to give the type of sets we have got and the capacity of these sets. Probably the hon. member is thinking of the entertainment T.V set

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : No

SHRI M. R. KRISHNA : I think that the sets which the Information Ministry was thinking of may not refer to the Defence Ministry sets.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Is the Defence Ministry aware that sets of this description have been distributed in the Tibetan side of our border in large numbers? Do we have any counterparts to counteract them ?

SHRI M. R. KRISHNA : We have got our counterparts. What type of equipment we are using in our area to find out what is going on in the other side, I am not supposed to reveal to the House at this moment.

Creation of Special Cell to supervise Implementation of Administrative Reforms Commission's Recommendations

+

*215. SHRI JAI SINGH :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI YAJNA DATT SHARMA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 370 on the 6th August, 1969 and state :

(a) whether the recommendations for the creation of a Special Cell in the Cabinet Secretariat to assist the Deputy Prime Minister in watching the implementation of the accepted recommendations, has since been accepted by Government;

(b) if not, the reasons therefor and what other arrangements in this regard are proposed to be made; and

(c) whether Government propose to entrust this work to a Parliamentary Committee at a later stage to assess the extent of implementation of the Administrative Reforms Commission's recommendations ?

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) to (c). The recommendations are among others contained in the ARC's Report on the "Machinery of the Government of India and its Procedures of Work". This particular report is rather a comprehensive one covering a varied range of important aspects relating to the position and functioning of the Machinery of Government. Many of the recommendations are inter-related. The House will, no doubt, agree that it is, therefore, desirable to take a view of the Report as a whole. The entire Report is under consideration.

Meanwhile, Government keep on reviewing, from time to time, at the highest levels, the process of consideration and follow-up of the various Reports submitted by the Commission.

श्री हरदयाल देवगुण : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफारिशों में दिल्ली के बारे में जो सिफारिश हुई है उसको दिल्ली के सब राजनैतिक दलों ने एक मत से अस्वीकार किया है और यह मांग की है कि दिल्ली में पूर्ण विधान सभा और उसके अनुसार यहां की सरकार बनाई जाय, तो क्या उसकी सिफारिशों पर अपना अन्तिम मत बनाने के पूर्व सरकार

दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों के इस मत को ध्यान में रखेगी और दिल्ली में विधान सभा स्थापित करने के बारे में शीघ्र कोई पग उठाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कहां से सवाल उठता है ? इस में से यह नहीं उठता ।

SHRI S. M. BANERJEE : One of the recommendations of the ARC was that there should be no right to strike for the Government employees. This has created a controversy and all the central trade union congresses and all the Central Government employees belonging to the trade union organisations have opposed this. Would the Prime Minister see to it that this recommendation is not accepted as this would go agninst the interest of the employees.

MR. SPEAKER : There is no question of any particular recommendation. The question speaks of a cell in the Cabinet Secretariat. Do not try to stretch it too far.

SHRI S.M. BANERJEE : This is a question arising out of the main question.

MR. SPEAKER : The question is, "whether the recommendations for the creation of a special cell in the Cabinet Secretariat to assist the Deputy Prime Minister..... " etc.

SHRI S. M. BANERJEE : The question is also about its implementation.

MR. SPEAKER : It is about the cell.

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly go through part (c) of the question.

MR. SPEAKER : I am very sorry I cannot allow it. It is not relevant; I am very sorry.

SHRI S. M. BANERJEE : Then what should be asked, Sir? This is relevant.

MR. SPEAKER : I can allow any questions about the cell, though there is no Deputy Prime Minister at present.

SHRI PILOO MODY : If there is no Deputy Prime Minister, it is because the Prime Minister has taken over all the portfolio.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : May I put a pertinent question ?

SHRI S. M. BANERJEE : The Deputy Prime Minister was not in office when this question was admitted. So, why was the question admitted at all ?

MR. SPEAKER : That is another thing. Next question.

चीनियों द्वारा पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षण

*216. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पाकिस्तान के बीजनात तथा रहीमसागरखां नगरों में जो भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर से उत्तर-पश्चिम में 30 मील दूर स्थित है, चीनी विशेषज्ञों द्वारा आजकल पाकिस्तानी सेना को छापामार युद्ध प्रणाली में व्यापक-प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को छापामार युद्ध के विशेषज्ञ चीनी दल के सैनिकों की, जो गिलगित के रास्ते छोटे हथियारों से लैस ऊंटों पर चढ़कर एक कारवां के रूप में पाकिस्तान आये हैं, संख्या और शक्ति की जानकारी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ऊंटों का यही कारवां जो गिलगित के रास्ते पाकिस्तान आया था जैसलमेर के रेतीले क्षेत्र तथा भारत पाकिस्तान सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊंट सवारों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा है ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Government are aware of the training being impa-

rted by Chinese instructors to Pakistani personnel in guerilla tactics, though, no reliable information relating to activities of Chinese instructors, across the Jaisalmer border has come to Government's notice. Recently, there have been some training exercises, across the Rajasthan border, involving Pakistani Army and para military personnel.

(b) A Chinese caravan consisting of some camels and horses came to Misgar, about 134 miles north of Gilgit in the last week of August, 1969 and thereafter returned to Sinkiang.

(c) Government have no such information.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है कि हमारी उत्तरी-पूर्वी और उत्तरी-पश्चिमी सीमा शत्रु सेनाओं से घिरी हुई है और देश की लगभग 25 हजार वर्ग मील धरती पर विदेशियों का कब्जा है तो क्या सरकार पुन: चीन से पिटने के बाद और पाकिस्तान से युद्ध और रबात से निकाले जाने के पश्चात् अभी इन्दिरा गांधी की कांग्रेस का जो सम्मेलन **हुआ उसमें सरकार ने कोई नई नीति निश्चित करने की कोई योजना बनाई है ?

श्री मणीभाई जे० पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द माननीय सदस्य इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । उनको मर्यादा के अनुसार शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हम लोग भी इस तरह बोल सकते हैं ... (**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : क्या मर्यादा बिगड़ गई जनाब ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये .. (**व्यवधान**) ...

MR. SPEAKER : Order, order. I am on my legs. Please sit down. I do not think Shri Bhadoria's question was in proper shape; he is a senior Member... . (*Interruption*)

श्री प्रेमचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस लब्ज पर मुझे आपत्ति है ।**....यह शब्द यहां प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

SHRI N. K. P. SALVE : It is for you to decide. It is your decision entirely. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : That expression is expunged.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*-

SHRI SWARAN SINGH : I cannot help if the hon. member and his party are rattled and upset by the upsurge and success of the last AICC meeting. But the House does expect that he should use better language and put the question in a proper form. He has not put any question which calls for a reply. He has expressed his own views which are old and outmoded and I am not going to controvert them.

DR. SUSHILA NAYAR : Is it for the minister to decide what is permissible and what is not permissible ? It is the prerogative of the Chair, not of the minister.

श्री क० ना० तिवारी : समाचार पत्रों में यह समाचार निकलता रहता है कि हिन्दुस्तान की सीमा के नजदीक पाकिस्तान के अन्दर चाईनीज लोग गुरीला वार-फेअर की ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं चाहे वह पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो । इसके अलावा पहले यह समाचार आता था कि नागा लोगों को दे रहें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक किन-किन तबकों के लोगों को गुरीला वार-फेअर की ट्रेनिंग इन कैम्पों में दी गई है, उनकी तादाद क्या है और उनको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

SHRI SWARAN SINGH : It is a fact that guerilla type of training has been imparted and our information is that it does continue to be imparted both in East Pakistan and in West Pakistan. We have information about the presence of Chinese guerilla experts who are giving training to

**Expunged as ordered by the Chair.

Pakistani guerilla units and formations. This is a fact which is within our knowledge and we have to take note of this development in formulating our defence arrangements.

श्री क० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था—पहले नागा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी अब दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि किस तबके के लोगों को इन दोनों सरहदों पर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका तादाद क्या है ? गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या मालूम है और इसको रोकने के लिये गवर्नमेंट क्या कार्यवाही कर रही है ?

SHRI SWARAN SINGH : Nagas were given training by taking the Nagas to the Chinese territory.....

श्री शिव नारायण : सरदार साहब, आप हिन्दुस्तानी में जवाब क्यों नहीं देते हैं ? आप अंग्रेज नहीं हैं। वह हिन्दुस्तानी में सवाल पूछते हैं तो आपको हिन्दुस्तानी में जवाब देना चाहिये।

SHRI SWARAN SINGH : I have not yet developed the habit of beating the table with my fists. That is not the way of replying and I think that is not the way of asking questions either. Naga hostiles went to China and were trained in various types of activities by the Chinese. Besides this, Chinese activities have been there in East Pakistan and West Pakistan. This is not confined to Nagas or Mizos in this region, but Pakistani nationals are involved and they are being given guerilla type of training in East Pakistan and also in West Pakistan. The second part is how we can check it. We cannot check the training given to Pakistanis by Chinese guerillas. What we have to do is to organise our defence in such a manner that this added potential is taken note of and have our own arrangements for our defence.

श्री क० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया....

अध्यक्ष महोदय : तिवारी साहब, आप चेयरमैन हैं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं।

SHRI HEM BARUA : The hon. Minister has said that the Chinese are imparting training in guerilla warfare to Pakistani nationals only. Is it not a fact that the Naga and Mizo hostiles are also being imparted training in guerilla warfare in Pakistani camps by the Chinese ? Have the Government tried to verify this or get information from our diplomatic channels in Pakistan on this point ? If not, have they not failed in their supreme duty of defending the country ?

SHRI SWARAN SINGH : The hon member is experienced enough to know that information of this type cannot be obtained through what he describes as diplomatic channels. But the information in our possession does show that Mizos and Nagas have been imparted some training by Chinese in Chinese territory and by Pakistanis in Pakistan territory. We have no information that Chinese instructors are training Mizos or Nagas in Pakistan.

SHRI HEM BARUA : I want to know whether the government have tried to find out whether the Chinese are being employed to give training to the Mizo and Naga hostiles in Pakistan territory.

SHRI SWARAN SINGH : I have given a very clear reply.

SHRI HEM BARUA : You have not.

SHRI SWARAN SINGH : According to our information; Chinese are not being employed for giving training in guerilla type or any other type of warfare to Mizos or Nagas in Pakistan territory.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्रीजी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उनको गुरीला वार की शिक्षा दी जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने नागा लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और कितने पाकिस्तानी लोगों को ट्रेनिंग दी है—क्या आप इसके आंकड़े बता सकते हैं ?

SHRI SWARAN SINGH : No, Sir; I cannot give that information.

SHRI SWELL : The Minister has admitted that Pakistan is giving guerilla training to the Mizos and Nagas in its own territory. I would like to know whether it it a fact that besides guerilla training Pakistan is giving training to Mizo and Naga young men to fly air force planes with a view to creating trouble in Naga and Mizo areas ?

SHRI SWARAN SINGH : Our information does not confirm this that Nagas and Mizos are being trained in the use of aircraft.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: The Minister has stated in his reply that Nagas and Mizos are getting training only outside India. Is it not a fact that some of those people who have received training from the Chinese outside India have come back and they are holding training camps inside India.

SHRI SWARAN SINGH : It is a fact that some of the Nagas who were trained by the Chinese by taking them to the Chinese territory have come back. I have made a detailed statement in the House about that. They may be giving some training even inside our territory in training camps but no sizable activity in that respect has come to our notice.

SHRI BASUMATARI : The Minister was kind enough to say that some Nagas and Mizos have been trained in guerilla warfare by Pakistan and China. Besides Nagas and Mizos I want to know whether any other anti-national elements among the Hindus are being given training outside India.

SHRI SWARAN SINGH : I could not really follow it. Pakistan is not interested in training our nationals. This question related to Pakistan training guerillas, Mizos, Nagas and their own nationals There is no doubt that we also impart some type of training to our forces (*Interruption*). We have no information of any such nature.

SHRI N. K. P SALVE : The unequivocal admission by the Defence Minister that the Chinese have shifted their insidious activities of training the guerillas on the western border is news which is extremely disconcerting. Guerillas are not trained to carry on a moral rearmament mission there; they are being trained to create trouble within our borders. Will he, therefore give an assurance to the House as to what active steps have been taken to ensure that no mischief is allowed to be done by these guerillas who are trained there and can he broadly indicate, if it is not in the public interest to disclose, the steps which are being taken to check this ?

SHRI SAWRAN SINGH : Whereas it is very difficult to say that they cannot create trouble, I can assure the House that if they create trouble, they will be adequately punished.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Entry of Tibetan Nationals into India

*214. SHRI J. AHMED :
SHRI BAIDHAR BEHERA :
SHRI MOHAN SWARUP :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fifteen Tibetan Nationals crossed over to India during the second week of September, 1969; and

(b) if so, whether they have been permitted to enter India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) No, Sir. However, a total of 31 Tibetan nationals entered India during the month of Sept. 1969.

(b) Yes, Sir.

Smuggling of Arms into West Bengal from Pakistan

*217. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently large number of rifles, small arms and ammunition have been smuggled into West Bengal from across East Pakistan.

(b) if so, the details of such arms smuggled;

(c) whether such arms smuggled is connected with underground activities of any political party; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (d). The Government of India have no information on the subject at present.

The Government of West Bengal have however been requested to furnish the required information which will be laid on the Table of the House on receipt.

Industrial Products for Exports

*218. SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI R. BARUA :
SHRI MAYAVAN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal to reserve a part of Industrial products for exports;

(b) whether it is also a fact that Government are considering an agreement under which any losses on exports can be shared equitably by various industrial units;

(c) whether it is further a fact that Government have also formulated some additional policy guidelines to achieve the target of 7 per cent annual growth rate in exports; and

(d) how far these proposals have been examined and put into practice ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Suggestions have been received in various forums to reserve a part of industrial products for exports. No concrete proposal has at present emerged.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Broad policy guide-lines for achieving a rate of growth of 7% per year in exports have already been indicated in the Fourth Five Year Plan Document. The policies for the export of individual products will naturally differ from one product to another and vary from time to time and cannot be indicated in advance. Government endeavours to keep the emerging problems of export under a constant watch and tries to evolve appropriate policies.

Rail Wagon Industry

*219. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the details of the orders for wagon exports from different countries secured this year;

(b) how far the present products including the orders from the Railways and internal consumers would be sufficient to utilise the installed wagon capacity in the country and how far the wagon capacity is still likely to lie idle during the current year; and

(c) the further efforts which are being made to secure orders sufficient to keep the industry working upto capacity ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

STATEMENT SHOWING EXPORT ORDERS ON HAND FOR RAILWAY WAGONS/ COACHES. (1969-70)

Country	Item	Value (Rs. crores)
1	2	3
Burma	14 Bogies and Petrol wagons	0.07
Ceylon	40 Bogies and Petrol wagons	0.32
East Africa	45 Cattle wagons	0.30
Poland	500 Covered Wagons	2.70
Taiwan	120 Covered Wagons	0.74
Thailand	45 Bogies	0.10

1	2	3
Hungary	1,000 wagons	5.85
Sudan	120 wagons and	0.75
	40 Under Frames	0 25
Taiwan	100 Bogies	0.21
Ghana	150 wagons	0.49

(b) As against the licensed capacity of 38,459 four wheelers, the orders available for execution during the year 1969-70 are 26. 554 numbers. Upto September, 1969, the combined out-turn from all wagon builders (in terms of four-wheelers) is 6,493,5.

(c) A regular programme of market surveys, publicity through publications and advertisements, participation in exhibitions and fairs, sponsoring of delegations and study teams, etc. is undertaken through the agency of Engineering Export Promotion Council for promotion of engineering goods as a whole including railway wagons/ coaches.

The Rolling Stock Export Association of which all the major wagon manufacturers are members is specifically concerned with the export of rolling stock. The State Trading Corporation, which is a founder-member of this Association, spearheads the export drive and co-ordinates the export of railway wagons.

Violation of Import Regulations by Reed, Camb and Allied Products (P) Ltd.

*220. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government/the Prime Minister has received any communication about the violation of import regulations by a Calcutta firm called "Reed, Camb and Allied Products (P) Ltd.";

(b) whether any investigation has been carried out into the complaint made by the Member of Parliament against these violations; and

(c) if so the results of these investigations and the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) . Yes, Sir. A communication has been received from the Collector of Customs. Calcutta. The matter has been referred to C.B.I. for investigation.

पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा की क्रियान्विति

*221. **श्री जगन्नाथ राव जोशी ।**
श्री शारदा नन्द :
श्री सूरज भान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने अब तक ताशकन्द घोषणा को कहां तक क्रियान्वित किया है और उसके अन्तर्गत अभी किये जाने वाले शेष कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ताशकन्द घोषणा के अनुकूल स्थिति उत्पन्न करने तथा उसके बाद उसे क्रियान्वित कराने में रूस का क्या योगदान है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने अब तक ताशकंद घोषणा को किस सीमा तक क्रियान्वित किया है । [ग्रन्थालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT.-2102/69]

(ख) सोवियत प्रधान मंत्री ने भारत और पाकिस्तान को परस्पर सुविधाजनक स्थान पर साथ लाने के लिए अपने सद्भावना से काम लेने की पेशकश की थी । इसी के परिणाम-स्वरूप जनवरी, 1966 में ताशकंद की बैठक हुई थी ।

जहां तक ताशकंद घोषणा के क्रियान्वयन का प्रश्न है यह एक ऐसा मामला है जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान की सरकारों से है।

इसराइल के प्रधान मंत्री की शवयात्रा में भारतीय प्रतिनिधि

*222. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर वियतनाम सरकार तथा इसराइली सरकार ने संवेदना प्रकट करने के लिये हमारे प्रधान मन्त्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की शव यात्रा पर अपने प्रतिनिधि भेजे थे अथवा भारत स्थित उनके दूतावासों से प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे, अथवा उन्होंने केवल संवेदना संदेश भेजे थे; और

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष इसराइल के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के निधन पर अपना प्रतिनिधि भेजा था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इन मौकों पर अपने देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन देशों के प्रतिनिधि नहीं आए। परन्तु, स्वर्गीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की अन्त्येष्टि में भाग लेने के उद्देश्य से बम्बई में इसराइली उप कौंसल 5 मई, 1969 को दिल्ली आए। नई दिल्ली में रहने वाले उत्तरी वियतनाम के कौंसल ने भी इसमें भाग लिया। इन तीनों अवसरों पर, इन दो सरकारों के नेताओं के शोक संदेश प्राप्त हुए।

(ख) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कमियां

*223. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 अगस्त, 1969 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपा यह समाचार कहां तक सही है कि भिलाई इस्पात कारखाने के महा प्रबन्धक ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अधिकांश कमियों के लिए योजना आयोग को दोषी ठहराया है; और

(ख) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) **इंडियन एक्सप्रेस** में जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वह श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा हाल में की गई कुछ आलोचनाओं के बारे में है। श्री इन्द्रजीत सिंह कुछ वर्षों पूर्व भिलाई इस्पात कारखाने में प्रमुख प्रबन्धक थे तथा मई, 1969 में सरकारी सेवा से निवृत हो गये हैं।

(ख) सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने में किसी प्रकार का सामान्यीकरण करना सम्भव नहीं। एक समूह के रूप में सभी सरकारी उद्यम विकास के समान चरण में नहीं हैं। जबकि कई निर्माण और विकास के चरण में हैं तो कई अन्यों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उनमें उत्पादन शुरू हो गया है और कई अन्य कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अब वे घाटे में नहीं चल रहे हैं। अन्य कई परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो अच्छा लाभ कमा रही हैं। सरकारी क्षेत्र के कतिपय उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति सरकार जागरूक है और उसने समुचित कार्रवाई शुरू कर दी है।

Trade Representation in East Berlin

*224. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether Government have opened Trade Representation in East Berlin from the 4th October, 1969;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the object of opening the Trade Representation there ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . There has been a substantial increase in India's trade with G.D.R. in recent years. The two-way trade reached the highest level in 1968 at Rs. 43.4 crores. In order to take full advantage of the possibilities of developing trade to still higher levels, the Trade Representation of India in G.D.R. has been opened.

Reduction in India's Army Strength

*225. SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there has been a reduction of 100,000 men in the strength of the Indian army; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि

*226. **श्री निहाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 200 रु० तक पेंन्शन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शन में 10 रु० की वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन रिजर्व सैनिकों को भी जो जनवरी, 1964 के बाद सेवा निवृत्त हुए और जिन्होंने चीन से संघर्ष के समय भी काम किया था, इस वृद्धि का लाभ दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 200 रु० प्रति मास पेन्शन पाने वाले सशस्त्र सेनाओं के पेन्शनरों को पहला सितम्बर 1969 से 10 रु० की तदर्थ वृद्धि दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

India's Exports during Fourth Plan

*227. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been drawn up under which export forecasts for Fifth Plan will be made in advance ;

(b) if so the details thereof and how the targets are being determined ;

(c) whether any export targets for the remaining years of the Fourth Plan have been fixed and if so, what are the targets, commodity-wise; and

(d) whether any changes in import and export policy are contemplated in the rest of the Fourth Plan or in the Fifth Plan?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) It is proposed to set up machinery in the Ministry of Foreign Trade for taking a view at the end of each financial year of the likely export outturn for the next five years.

(b) The details of the proposal are yet to be worked out.

(c) Tentative targets for the exports of major products/product groups have been formulated for the remaining years of the Fourth Plan and are in the process of finalisation.

(d) Since both the internal and external conditions governing exports and imports keep on changing continuously, it is Government's endeavour to bring about the required adjustments in policy expeditiously, in order to attain its import and export objectives for the plan in general and for the current year in particular.

Sending of U. S. Troops to Laos

*228. SHRI H. N. MUKERJEE :
SHRI C. JANARDHANAN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Neo Lao Hat Sat party of Laos has claimed that the United States has sent 12,000 troops to Laos to fight against the national liberation movement in that country;

(b) whether this same party has sent complaints to the Co-Chairman and members of the Geneva Conference to this effect ;

(c) whether the International Control Commission team in Laos has verified this claim; and

(d) if so, the findings thereof; and Governments' reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) The Government has seen such press reports on behalf of DRVN Government.

(b) Government is not aware of any such complaint sent to the Co-Chairman and members of the Geneva Conference to this effect.

(c) and (d). Do not arise

Memorandam for Muslim Home-Land in India

*229. SHRI SHRI CHAND GOYAL :
SHRI D. R. PARMAR :
SHRI P. N. SOLANKI :
SHRI ONKAR LAL BERWA :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI CHANDRIKA PRASAD :
SHRI DEVEN SEN :
SHRI P. M. MEHTA :
SHRI YASHPAL SINGH :
SHRI S KUNDU :
SHRI GUNANAND THAKUR :
SHRI KIKAR SINGH :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a memorandum has been submitted to the Indian High Commission in London demanding a separate homeland for the Muslims in India ;

(b) if so, the names of societies and other elements which are behind the above move; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

Export of Coir and Coir Goods

*230. SHRI YOGENDRA SHARMA:
SHRI VASUDEVAN NAIR :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that exports of coir and coir goods have shown a declining trend during the first half of the current year;

(b) if so, the reasons therefor:

(c) the actual decline registered in the export of coir and coir goods during the above period; and

(d) the steps being taken by Government to step up exports of coir and coir goods?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) The decline was due to the steep rise in prices of husks and also competition from synthetics.

(c) The decline was of the order of 6079 tonnes and in terms of value Rs. 114.37 lakhs, as compared to the first 6 months of the preceding year.

(d) The Kerala State Government are actively considering steps to bring down the price of retted husks; this should have a salutary effect on prices of coir yarn and goods. The Coir Board has undertaken measures for publicity and propaganda in foreign countries, sales teams, market studies etc. Research into new uses for coir is also being greatly encouraged. A study group on coir has also been set up by the Planning Commission to go into all problems relating to development and export of coir and coir products.

Agricultural Land Aquired in States for defence Purposes

*231. SHRI BHAGABAN DAS .
SHRI B K. MODAK :
SHRI K. HALDAR :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI JYOTIRMOY BASU:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the area of agricultural land aquired for defence purposes in each police station, under each district of each State during the last 3 years;

(b) the number of households in each police station affected;

(c) the total amount of compensation fixed for each police station;

(d) the total amount of compensation paid; and

(e) when the balance is going to be paid ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (e). The total area of land aquired i. e. the area which has vested absolutely in the Defence Ministry as a result of aquisition during the years 1966 to 1968 is approximately 80,374 acres. Most of the land is agricultural land.

The total amount of aquisition compensation disbursed during the three financial years 1966-67 to 1968-69 is Rs. 223 lakhs approximalely.

Information regarding the area acquired in each police station of each district, the number of households affected in the area of each police station, the acquisition compensation awarded for each police station, and the amount of acquisition compensation disbursed in the area of each police station is not available and the effort involved in the collecting the same will be out of proportion to the result likely to be achieved.

It is the responsibility of the Land acquisition Collector to determine the acquisition compensation and disburse the same through the local revenue authorities, effort Every is made to expedite the disbursement of the awarded compensation.

Closed Textile Mills

*232. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the total number of textile mills in the country and the total number of such mills closed in respective States;

(b) the total number of labourers turned unemployed and the amount of loss in textile production due to these closures;

(c) whether it is a fact that most of the mills are closed with a view to create artificial scarcity to reap high profits; and

(d) whether Government propose to take over the management of all such mills; if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT): (a) There are 653 Cotton Textile Mills including Waste Spinning Units in the country. As at the end of October, 1969, 85 cotton textile mills

were lying closed. The State-wise breakup is as follows :-

Name of State	*Number of mills*
Andhra Pradesh	1
Bihar	1
Gujarat	11
Kerala	3
Haryana	1
Maharashtra	3
Mysore	4
Panjab	1
Rajasthan	2
Tamilnadu	17
Uttar Pradesh	4
West Bengal	5
Delhi	1
Pondicherry	1
Total :	55

This is exclusive of mills considered fit to be scrapped.

(b) The total number of workers on rolls in these mills was about 68900. The loss in textile production due to closures of these mills is estimated at 9 million kgs. of yarn and 31 million metres of cloth per month.

(c) No, Sir. The reasons for closure are financial stringency obsolency of machinery and other working difficulties.

(d) No, Sir. The management of only such mills which, with injection of limited funds can be made economically viable within a reasonable time, is taken over by the Government under the industries (Development and Regulation) Act. The management of six closed mills has been taken over by Government under this Act and the cases of 3 such mills are under consideration. The affairs of 4 mills are being investigated under the said act. The question of taking over another 6 of these mills has been examined, but they have not been taken over as they have been considered to be uneconomic. The cases of 13 mills (out of which 8 have been investigated under the above mentioned Act) are pending in High Courts in regard to liquidation.

Import of Cotton

*233. SHRI N K. SOMANI :
SHRI D N. DEB :
SHRI MAHENDRA MAJHI :
SHRI J. MOHAMED IMAM :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
DR. P. MANDAL :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there have been any consultations between Government and the industry in regard to their decision to channelise the import of cotton from next year through Government agencies ;

(b) if so, the reaction of the industry thereto;

(c) whether there have been any prior consultations; and

(d) if so, whether Government have made any efforts to ascertain the views of the industry subsequent to this decision and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) and (c). Yes, Sir.

(b) and (d) . The representatives of industry were not in favour of canalisation of import of cotton. They expressed the view that in case a public sector agency was to be set up, it would be necessary that it should take advantage of the experience and expert knowledge of the traders.

Book Entitled "Minimum Deterrent India's Nuclear Answer to China"

*234. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the book "Minimum Deterrent India's Nuclear Answer to China" by Colonel R.D. Palsokar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) .

(a) Yes, Sir.

(b) Government's policy on the development of nuclear weapons has been explained to the House on several occasions. Attention is invited to the answers given to Unstarred Question Nos. 462 and 495 on 23rd July, 1969.

Self Sufficiency in Defence Production

*235. SHRI DHIRESWAR KALITA:
SHRI ESWARA REDDY :
SHRI INDRAJIT GUPTA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government have worked out any plan for attaining self- sufficiency in defence production;

(b) if so, the steps taken in this direction; and

(c) the role to be assigned to the private sector in increasing defence production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) :

(a) Yes, Sir.

(b) Capacity is being progressively established for the production of those Defence items for which the country is not fully self-sufficient.

(c) Manufacture of as many items as possible of the hitherto imported Defence items, is being progressively assigned to the Private sector, without affecting the public sector and the departmental factories.

Pak. attitude to Kabul meeting for Regional Co-operation

*236. DR. RANEN SEN :
SHRI ISHAQ SAMBHALI :
SHRI K.P. SINGH DEO :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there has been any change in Pakistan's attitude on the proposed Kabul Meeting to discuss regional co-operation between Iran, Afghanistan, Pakistan and India; and

(b) when the Kabul Meeting is likely to take place ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) :

(a) No, Sir.

(b) No decision has yet been taken in this respect.

नेपाल के साथ हुए 1965 के सैनिक करार को रद्द करना

*237. श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के बाद सरकार ने वर्ष 1965 में हस्ताक्षरित सैनिक करार को रद्द कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब नेपाल को अपनी इच्छानुसार किसी देश से शस्त्र प्राप्त करने का अधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसका भारत की सुरक्षा तथा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). भारत और नेपाल के बीच, 1965 के समझौते को रद्द नहीं किया गया है।

Book entitled "Defence of India" published by Press Institute of India

*238. SHRI MANGALATHUMADAM :
SHRI M. H. GOWDA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the Government have taken note of the recent book 'Defence of India' published by the Press Institute of India;

(b) whether it is a fact that the three Chiefs of the Defence Forces have written articles in this book;

(c) if so, whether any prior permission was obtained by these three Chiefs; and

(d) if not, the reasons for ignoring the lapse on the part of the three Chiefs for obtaining prior permission before writing in this book about the Indian Defence policies ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b). Government have seen the book "Defence of India" published by the Press Institute of India containing speeches delivered in March, 1966 by several persons including the three Service Chiefs at a seminar organised by the Institute. This book is mainly a collection of these speeches. Gen. Chaudhuri has, however, written a separate piece specifically for the book.

(c) and (d). Do not arise. No permission of Government was necessary in the case of General Chaudhuri, who had retired from the Army since 1966.

Exports by Engineering Industry

*239. SHRI RABI RAY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Engineering industry as a whole has orders worth about Rs. 120 crores out of which Rs. 110 are to be exported during the remaining period of this year;

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government to meet the situation; and

(c) the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) According to the information available from the Engineering Export Promotion Council, Calcutta, it is a fact that the orders worth about Rs 120 crores have been placed on the engineering industry for export. Out of this Rs. 110 crores are for shipment during the entire year 1969-70 and not for the remaining period of the year. During the seven months of the current year 1969-70, the exports of engineering goods amounted to Rs. 52 47 crores as against about Rs. 41 crores during the corresponding period last year.

(b) and (c). The present difficulties in the matter of engineering exports are mainly due to the shortage of steel and other raw materials required for the export production. These shortages have developed on account of the increased local demand alongwith reduced production during the last two years.

A statement outlining the steps to overcome the acute shortage of steel and to intensify export efforts is laid on the Table of the House.

Statement

Some of the steps to overcome the acute shortage of steel and to intensify exports efforts are summarised below :-

(a) A working arrangement has been arrived at with the Ministry of Steel and Heavy Engineering, the JPC and the main producers for supplying the steel requirements to export fabricators to the extent needed to fulfil the level of Rs.110 crores of exports during the current financial year. The requirements have been specified contractwise and the Ministry of Steel and Heavy Engineering has issued a direction to the JPC and the steel producers for meeting these requirements by giving 1.5 priority (next only to Defence Operational demands) both to works orders and rolling and despatch programmes.

(b) It has been decided to import roughly 60,000 tonnes of scarce categories of steel to enable the

manufacturers to fulfil their commitments by March 1970 and also be able to keep up their delivery schedules for 1970-71.

(c) Efforts are being made to make available steel from the reserve quota of the Iron and Steel Controller to meet the emergent orders.

(d) Several consortia to undertake large value contracts of prolonged deliveries and covering various products have been formed.

(e) The design engineering firms and consultants are being encouraged to undertake turn-key projects or to provide technical know-how.

(f) Efforts are also being made to encourage joint ventures in the developing countries and in fact success has already been achieved in various fields.

(g) New markets, such as Japan and Iran are being explored. Third country contracts are being entered into in collaboration with entrepreneurs from developed countries. Moreover, our associates in developed countries are being encourged to transfer to India orders received by them in the global market in certain lines which it would be uneconomical for them to produce such as medium-weighted trucks, some railway equipment, electric motors and other articles.

(h) Exports to associate companies located in developed countries are being increased and new manufacturing programmes to feed their specialised requirements are under consideration.

(i) Discussions are underway with industry to formulate plans for expansion of capacity or for creation of new units in order to generate export surplus.

Chinese Threat to India

*240. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese threat to India is increasing, of late as disclosed by him in New York; and

(b) if so, the basis on which this threat has been evaluated ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). In answer to questions put to him by reporters in New York, the Foreign Minister referred to the dangers posed by the increasing accumulation of nuclear weapons by China.

मंत्रियों के लिए आचरण संहिता

1401. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए आचरण संहिता तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा रखा जायगा तथा उसका समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मंत्रियों के लिए आचार संहिता पहले से ही बनी हुई है। यह संहिता सरकार ने 1964 में तैयार की थी और 18 नवम्बर, 1964 को लोकसभा-पटल पर रखी गई थी। इस में अन्य धाराओं के साथ, केन्द्रीय मंत्रियों के लिए अपनी आस्तियों तथा देनदारियों का

वार्षिक ब्यौरा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) यह पहले ही किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Import Licence to Pioneer Mission, Manipur

1402. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pioneer Mission operating in Manipur was granted a licence to import certain items fromU.S.A. in 1965; and

(b) if so, what are the items imported and the purpose of this import for which a special licence was given ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . Particulars of import licences are published in the Weekly Bulletin of "Industrial Licences, Import Licences and Export Licences" issued by the Chief Controller of Imports & Exports.

The information regarding the Pioneer Mission will be collected and placed on the Table of the House.

हथकरघा उद्योग

1403. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपड़े की कुल सप्लाई का कितना प्रतिशत कपड़ा हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित किया गया है;

(ख) इस लघु उद्योग में कितने मजदूर काम करते हैं तथा देश के कुल मजदूरों की कितनी प्रतिशतता इस उद्योग में है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फैले इस उद्योग के आर्थिक संसाधनों की ओर तथा इस तथ्य की ओर कि यह उद्योग अवनति को प्राप्त हो रहा है, कभी ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) हथकरघों द्वारा उत्पादित कपड़े के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तथा (घ) . सरकार ने सरकारी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं । ये योजनाएं, जिनमें ऋणों, अनुदानों तथा ऋण सह अनुदानों की व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं । इन उपायों के परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां तथा उनके द्वारा स्थापित करघे, जो कि वर्ष 1953 में क्रमश: 1716 तथा 4.3 लाख थे, बढ़कर वर्ष 1968 में क्रमश: 10,120 बुनकर समितियां तथा 14.15 लाख करघे हो गए हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Dehu Road Indrayani Colony

1404. SHRI BASWANT : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the work for the Dehu Road Indrayani Colony has been completed;

(b) if so, the amount spent so far;

(c) whether it is a fact that the contractor did not follow the terms and conditions and use sub-standard materials; and

(d) the decisions which have been taken for this purpose ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 151.20 lakhs.

(c) and (d) . The work has been carried out in accordance with the contract except that certain pieces of timber utilised were found to be inadequately seasoned and the weight of the high pressure water taps was less than prescribed. Recovery of Rs. 1,774 and Rs 6,666 respectively has been effected from the contractor in respect of these two items.

Indian Delegation to U. N. Assembly

1405. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total strength of the Indian delegation to the latest meeting of U.N. General Assembly and the names of the members;

(b) the criteria for selecting the members for this delegation: and

(c) whether any assessment of the performance of the different members of the delegation at the General Assembly meeting has been made and if so, the results thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The Indian Delegation to the XXIV Regular Session of the U. N. General Assembly consisted of the 14 persons shown in the list laid on the Table of the House [*Placed in Library. See No. L. T.-2103/69*] and also the Permanent Representative of India to the U. N. in New York and his officials.

(b) The Indian Delegation to the General Assembly represents the Government of India Apart from officials, non-official members of the Delegation are selected at the discretion of the Government of India and many factors are taken into account, including the considerations that the chosen delegates are in agreement with the Government's policies, their ability to project India's policies correctly and that they support fully in the General Assembly, etc.

(c) So far the performance has been up to the expected standards.

Economy in Indian High Commission, London

1406. SHRI N. K. P. SALVE : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken to effect economy in the expenditure incurred by the Indian High Commission in London; and

(b) if so, the extent of economy achieved in terms of rupees ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) . Several official teams have from time to time reviewed the working of the Indian High Commission in London since 1959, and continuous steps have been taken to effect economy in expenditure by means of rationalising staff and expenditure patterns on the basis of work studies and staff inspections. If it were not for the economies which are being effected continuously, the overall expenditure on the High Commission would have been larger than at present, considering the upward trend in the cost of living the world over and the rise in rentals, pay scales of local staff, etc.

A major item of rationalisation has been in the matter of staff. The total of 1340 posts which existed in 1959 has been gradually reduced to the present total of 749. The 'notional' savings which has resulted from this is approximately Rs. 37.53 lakhs per annum.

Tea Processing Unit at Palampur

1407. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kangra Tea Planters have submitted a representation to the Tea Board for setting up modren type of tea factory near about Palampur for the prossing of their tea leaves;

(b) whether they have given an undertaking that in that case they will close their old and outmoded machinery; and

(c) if so, the steps which Government propose to take to accede to their demand for producing better quality and improving the quality of green and black tea in Kangra valley ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) A representation has been made by the Kangra Tea Planters to the Himachal Pradesh Government with a copy to the Tea Board.

(b) Yes, Sir.

(c) A feasibility report is being prepared which the State Government and Tea Board would consider.

Offer of Rice from Burma

1408. SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI ESWARA REDDY :
SHRI YOGENDRA SHARMA :
DR. RANEN SEN :
SHRI RAMAVTAR SHASTRI :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Burma has offered India the option to purchase 1,00,000 tons of rice a year on a long-term contract in return of Indian goods of equivalent value; and

(b) if so, Government's decision thereon ?

THE DEPUTY MINITSER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH : (a) and (b) . The Government of the Union of Burma have made an offer to sell rice to the Government of India at a price to be negotiated in the light of the present market conditions and have indicatad their readiness to buy goods from India to the full value of the amount realised from such sale. Quantities and terms will be finalised through joint negotiations.

Crossing of Naga Hostiles into Burma

1409. SHRI MANGALATHUMADAM :
SHRI SRINIBAS MISRA :
SHRI P. VISWAMBHARAM :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several hundreds of Naga hostiles crossed into Burma through Indo-Burmese border in the first week of September; 1969; and

(b) if so, the arrangements which have been made at the border to prohibit these frequent crossing of the Naga hostiles into Burma ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b) . Government have no information about the crossing of Naga hostiles in the first week of September 1969. However, all possible steps are being taken by the security forces to prevent the crossing of Naga hostiles into Burma.

Dalai Lama

1410. SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI K. HALDER :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state whether Dalai Lama is an Indian citizen ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : No, Sir.

केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग

1411. **श्री गुलानन्द ठाकुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से अब तक कितने केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग नियुक्त किये गये हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन सिफारिशों को सरकार किस-किस सीमा तक क्रियान्वित करने में सफल हुई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . इस उल्लिखित अवधि में किसी भी केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध उसके आचार के सिलसिले में जांच आयोग कानून के आधीन कोई भी कमीशन नियुक्त नहीं किया गया । तथापि सदन को विदित होगा कि जीवन बीमा निगम के द्वारा खरीदे गये कुछ शेयरों की जांच करने और उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिए छागला आयोग नियुक्त किया गया था । इस आयोग की रिपोर्ट में एक भूतपूर्व वित्त मंत्री के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी । उस मंत्री ने आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के कुछ पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था । प्रधान मंत्री नेहरू ने इस विषय का ज़िकर 19 फरवरी, 1958 को इस सदन के समक्ष किया था । अन्य कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

सदन को यह भी स्मरण होगा कि 1963 में सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के बहीखातों में कुछ ऐसे इन्दराजों की जांच-पड़ताल के लिए जिनका सम्बन्ध एक भूतपूर्व खान तथा ईंधन मंत्री से बताया जाता था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम० के० दास को नियुक्त किया गया । इस विषय पर भी 17 अगस्त, 1963 को स्वर्गीय श्री नेहरू ने इस सदन के समक्ष एक बयान दिया था । इस जांच के परिणाम को जानने से पहले ही उस मंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया था । अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

Indian Troops killed in Encounters with Nagas

1412. SHRI N. K. P. SALVE : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the number of Indian troops and policemen killed during the period from January to September, 1969 in encounter with Nagas and in ambush ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING SHRI SWARAN SINGH) : Thirteen.

भारतीयों को विदेशी पुरस्कार

1414. **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री शंकर लाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 487 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में विदेशों से पुरस्कार आदि प्राप्त हुए;

(ख) पुरस्कारों आदि के नाम क्या हैं उनकी राशि कितनी-कितनी है और पुरस्कार देने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उन व्यक्तियों ने पुरस्कार का किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इन पुरस्कारों की राशि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यय न की जाये ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) . सूचना अभी इकट्ठी की जा रही है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में परिवर्तन

1415. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों में कोई परिवर्तन होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का और कितना परिवर्तन होने का पूर्व अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार यह बतायेगी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बढ़े हुए संसाधनों के वितरण के लिए चौथी योजना में प्राथमिकताएं किस आधार पर निर्धारित की जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) . यह विषय विचाराधीन है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना की संशोधित रूपरेखा

1417. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की संशोधित रूपरेखा क्या है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1969-70) में कृषि और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जनवरी, 1970 में उसे अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

(ख) 1969-70 की वार्षिक योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 332.16 करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है तथा सरकारी क्षेत्र मे ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए 38.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इन दोनों क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए परिव्यय का ब्यौरा अनुबन्ध I और 2 में दिया गया है । जो सभा पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2104/69] आगे और विस्तृत ब्यौरा सभा पटल पर 29 अगस्त, 1969 को प्रस्तुत वार्षिक योजना-1969-70 में देखा जा सकता है ।

लौंगों के आयात पर प्रतिबन्ध

1418. **श्री राम चरण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कितनी मात्रा में लौंगों का आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय लौंगों का बाजार मूल्य 130 रुपये से 150 रुपये प्रति किलोग्राम है; और

(ग) यदि हां, तो लौंगों के मूल्य में कमी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) आयातों के आंकड़े जुलाई, 1969 तक उपलब्ध है । मई से जुलाई, 1969 के तीन महीनों में 9518 किलोग्राम लौंग का आयात किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) संभरण बढ़ाने तथा मूल्यों को कम करने के लिये लौंग के आयात का प्रश्न विचाराधीन है ।

संयुक्त आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी आयोग का गठन

1419. **श्री देवेन सेन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अमरीका के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिये

भारतीय आर्थिक तथा व्याप र प्रतिनिधियों के बोर्ड ने संयुक्त आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी आयोग के गठन की सिफारिश की है तथा उन देशों के लिये एक आर्थिक कार्य महा-आयुक्त की नियुक्ति पर की जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

Purchase of Wool Tops by S. T. C.

1420. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that because of procedural delays by the State Trading Corporotion, huge stocks of wool tops were lying with wool combers;

(b) if so, whether Government are also aware that this pile up has resulted in artificial scarcity of yarn in the market;

(c) whether the All India Woollen Mills Federation has made cartain suggestions to meet the situation; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) There has been some accumulation of stocks with one of the combers owing to delay in lifting of wool tops by certain units.

(b) No, Sir. There has been no scarcity.

(c) and (d). Yes, Sir. It was guggested that actual users and registered exporters should be allowed to remit combing charges direct to combers. This has been allowed.

All-India Regional Disparity Board

1421. SHRI E. K. NAYANAR : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute an All India Regional Disparity Board to discuss and formulate the ways and means to eradicate the regional disparities; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b). No such proposal is under consideration. Suitable measures will however, be taken to lessen regional disparities. In this connection attention is invited to pages 17 to 19 of the "Fourth Five Year Plan 1969–74 -Draft" a copy of which was placed on the Table of the House in April, 1969.

परमाणु शक्ति केन्द्रों के निकट कृषि उद्योग समूह स्थापित करना

1422. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदानन्द :
श्री सूरजभान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री वृजभूषण लाल :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु शक्ति केन्द्रों के निकट कृषि उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में परमाणु शक्ति आयोग के कार्यकारी अधिकारियों के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ख) इस बारे में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस सम्बन्ध में भविष्य की योजनाएं क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कार्यकारी वर्ग का प्रतिवेदन तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलभ्य है ।

(ख) तथा (ग) . यह प्रतिवेदन एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन था । अब कार्यकारी वर्ग द्वारा आगे अध्ययन किया जा रहा है । किसी निष्कर्ष पर पहुँचने तथा प्रतिवेदन पर अमल करने का प्रश्न आजकल किए जा रहे अध्ययन की समाप्ति पर ही पैदा होगा ।

भूतपूर्व सैनिकों का जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और गुजरात में पुनर्वास

1423. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदानन्द :
श्री सूरजभान :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री का 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व सैनिकों को जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और गुजरात में किस किस स्थान पर बसाया गया, उनको क्या सुविधायें उपलब्ध की गई ;

(ख) उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इस बारे में भविष्य के लिए क्या योजना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . पूर्व प्रश्नों के उत्तर में जम्मू और काश्मीर तथा गुजरात सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में भूतपूर्व सैनिकों के 412 परिवार तथा गुजरात के कच्छ में भूतपूर्व सैनिकों के 6 परिवार सीमा पर बसाये गये हैं ।

उनके पुनर्वास के स्थान तथा उन्हें दी गई सुविधाओं और शर्तों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है । इस सूचना को संबंधित राज्य सरकारों से इकट्ठा किया जा रहा है । राजस्थान से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) इन तीन राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

Disciplinary Action taken Against Defaulting Officer in Tyre Case

1424. SHRI NARAIN SWARUP SHARMA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 468 on the 23rd July, 1969 regarding tyre deal scandal and state:

(a) whether any disciplinary action has since been taken against the Ministry officer concerned;

(b) if so, the charges levelled against him;

(c) whether the officer concerned was duly asked to give explanation in regard to the charges; and

(d) if the reply to part (c) above be in the nagative the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (d) There is no change in the position indicated in the reply to the question. The writ petition is still pending in the High Court and the mtater is sub-judice.

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में हिन्दी में कार्य

1425. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी भाषी राज्यों में और पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में तथा विदेशों में उनके मंत्रालय के कार्यालयों और उनके मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकायों की संख्या कितनी है और विदेशों में कार्यालय किन स्थानों पर हैं;

(ख) उनमें से कितने कार्यालयों में समूचा कार्य हिन्दी में किया जाता है और शेष कार्यालयों में, जिनमें विदेशों में स्थित कार्यालय भी शामिल है, सरकार का कब तक हिन्दी में कार्य आरम्भ करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के प्रत्येक कार्यालय में और मंत्रालय के अधीन प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय के कार्यालय में एक एक हिन्दी टाइपिस्ट और अनुवादक नियुक्त करने का है ताकि हिन्दी में कार्य आरम्भ किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा, यदि नहीं, तो हिन्दी के कार्य को किस प्रकार निबटाया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें वांछित सूचना दी गई है सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT-2105/69] अभी हमारे किसी भी कार्यालय में सारा काम हिन्दी में नहीं होता। हिन्दी टाइपिस्टों और अनुवादकों की नियुक्ति प्रत्येक कार्यालय की जरूरतों पर निर्भर करेगी और इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Number of Unemployed Ex-Servicemen in India

1426. SHRI NARAIN SWARUP SHARMA :
SHRI SHRI CHAND GOYAL :
SHRI RANJEET SINGH :
SHRI OM PRAKASH TYAGI :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state.

(a) the total number of ex-Servicemen registered as unemployed as on the 1st October, 1969;

(b) the total number of ex-Servicemen considered to be underemployed;

(c) the total number of ex-Servicemen who have been settled through the Resettlement Directorate of his Ministry; and

(d) the total number of ex-Servicemen who are members of ex-Servicemen's League ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) The total number of ex-service personnel on the Live Registers of Employment Exchanges as on 30th June, 1969 was 47,454. The corresponding figure as on 1st October, 1969 is not yet available.

(b) The information is neither available nor can it be usefully collected, as it is not possible to lay down any specific definition of the term "under-employed" and the situation in this regard is liable to change all the time.

(c) The main agency for the re-employment of individual ex-servicemen is the Employment Exchange Organisations. The total number of ex-servicemen who have been resettled through the Directorate General Resettlement, and through the Employment Exchanges, during the last three years is as under:

	Through Dte. Genl. Resettlement	*Through Employment Exchanges*
1967	128	12651
1968	1220	14311
1969	2213	7414
	(upto 31 Oct. 69)	upto 30 June 69)

(d) According to information available besides 400 individual members of the Indian Ex-servicemen's League, there are 85 Member. Associations all over India and 5 Branches of that League whose membership is not known.

Shortage of RCL and SLR Rifles

1427. SHRI NARAIN SWARUP SHARMA :
SHRI SHRI CHAND GOYAL :
SHRI RANJEET SINGH :
SHRI OM PRAKASH TYAGI :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is a shortage of weapors like RCL and SLR (Rifles) in the units; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARN SINGH): (a) No, Sir, the re-equipment plan is proceeding according to schedule.

(b) Does not arise.

Dacoits getting Ammunition from Pulgaon Depot

1428. SHRI S. K TAPURIAH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have seen the press reports in the Blitz of the 25th October, 1969 wherein it has been stated "Dacoits get Ammunition from Pulgaon Depot";

(b) whether the press reports that cartridges worth several thousand repees are suspected to have found their way from the Pulgaon Ammunition Depot to the Chambal Ravines are correct;

(c) whether it is also a fact that huge quantities of Cartidges (.303) are missing from that Depot;

(d) whether it is further a fact that some officers of the Depot are involved in this matter; and

(e) if so, whether Government propose to hold an inquiry into the matter and action taken or proposed to be taken against the officer concerned ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING SHRI SHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). 4,000 rounds of small arms ammunition were found missing from the Pulgaon Ammunition Depot on 28th February, 9969. A Court of Inquiry has been held and is awaiting finalisation Besides, the case is also under Police investigation. So far nothing has come to the notice of the Ministry of Defence to suggest that ammunition from the Pulgaon Ammunition Depot has found its way to the Chambal ravines.

Export of Jute Manufacturers

1429 SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI N. K. SOMANI :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the exports of Jute manufacture have fallen during the period from April to October this year;

(b) if so, the reasons for the decline in production and exports of Jute goods; and

(c) the steps being taken by Government to improve the situation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Production and exports of jute goods suffered a set back owing to the exceptionally poor crop last season and the high prices for jute goods. The position is now improving in view of the better crop position this season.

Manufacture of Helicopters by Hindustan Aeronautics Ltd. with Foreign Collaboration

1430. SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI N. K. SOMANI :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore have been licensed to manufacture helicopters;

(b) whether a collaboration agreement has been signed with a foreign party; if so, the terms thereof; and

(c) the number of helicopters to be produced annually and whether some quantity has been reserved for civilian and agricultural purposes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b). The manufacture of Alloutte III Helicopters has been undertaken at Hal (BD) under a licence agreement with M/s. Sud Aviation of France. Hal (BD) are also manufacturing the engines installed on the helicopters under a separate licence agreement entered into with M/s. Turbomeca of France. Disclosure of the terms of the Licence Agreements would be contrary to the normal commercial practice.

(c) Helicopters are being manufactured at present mainly to cater to the needs of the IAF and the Indian Navy. It would not be in the public interest to disclose the number of helicopters being produced annually.

Madam Svetlana's Book

1431. SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the book 'Only one Year' written by Madam Svetlana;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to ban entry of this book in India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The book contains the views of a private individual.

(c) Government do not propose to ban the entry of the book into India ?

दिल्ली सैनिक बोर्ड (दिल्ली सोलजर बोर्ड) के सचिव के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई शिकायतें

1432. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिक दिल्ली सैनिक बोर्ड के सचिव के पास सहायता के बारे में सलाह लेने के लिये गये तो उन्हें धमकी दी गई और बाहर निकाल दिया गया तथा उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत आठ महीनों में भूतपूर्व सैनिकों ने दिल्ली सैनिक बोर्ड के सचिव के विरुद्ध इस बारे में शिकायतें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कर्यावाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). दिल्ली सैनिक बोर्ड के सक्रेट्री के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष सुविधा तथा पुनर्वास निधि

1433. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 13 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश सरकार से भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष सुविधा तथा पुनर्वास निधि के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण): (क) से (ग). 13 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने हेतु एक विवरण सभा के पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य विभाग को प्रेषित किया जा चूका है। तथापि, उस विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 2106/69**]

पेंशन में वृद्धि

1434. श्री निहाल सिंह :
श्री शिवचरण लाल :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सितम्बर, 1969 से सशस्त्र सेनाओं की पेंशनों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि का अनुपात क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त वृद्धि उन रिजर्व सैनिकों और सेवानिवृत सैनिकों के लिये नहीं होगी जिन्हें सिविल सेवाओं पर पुनः रोजगार दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रति रक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) . सशस्त्र सेना के पेंशनरों के लिए जिन्हें 200 रु० प्रतिमाह पेंशन मिलती है, 10 रुपए प्रतिमाह की दर से पहली सितम्बर 1969 से तदर्थ वृद्धि कर दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) तदर्थ वृद्धि जीवन निर्वाह के बढ़े हुए खर्चों के अनुरुप मंजूर की गई है। चूंकि पुनर्नियुक्त पेंशनरों को या तो महगाई भता मिलता है, या मुफ्त राशन, वर्दी या उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि में बढ़े हुए जीवन निर्वाह के बढ़े हुए खर्चों के ध्यान में रखते हुए अन्य रियायतें दी जाती है या फिर उनकी पुनर्नियुक्ति पर महगाई भता उनके समेकित वेतन में शामिल कर दिया जाता है इसलिए उनकी पेंशन में कोई तदर्थ वृद्धि नहीं की जाती है।

देश में एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त बेरोजगार की संख्या

1435. श्री निहालसिंह :
श्री शिवचरण लाल :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जनार्दनन :
श्री जि०मो० बिस्वास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है जो बेरोजगार है और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें रोजगार दिलाया गया है; और

(ख) शेष बेरोजगार एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

प्रति रक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) स्थाई कमीशन प्राप्त करने या सेवा मुक्त होने वाले कुल 7947 एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों में से 3715 को या तो स्थायी कमीशन दे दिया गया है या इसके लिये उन्हें योग्य पाया गया है। शेष 4232 एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों में से जिनको सेवा मुक्त किया गया था, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2301 को पुनः नौकरी दी जा चुकी है। 493

के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है क्यों कि इनको या तो अनुशासनात्मक कारणों से या स्थायी कमीशन के लिये विकल्प न देने के कारण सेवा मुक्त किया गया था । अब शेष 1438 सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों में से सम्भव है कि कुछ अपने स्वयं के प्रयास से किसी व्यवसाय में लग जाएगें ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को सरकार द्वारा काम दिलाने के प्रयास

(1) अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये स्थायी तथा दीर्घ अवधि वाले अस्थायी रिक्त स्थानों में भरती होने के लिए निम्नलिखित रूप से स्थान सुरक्षित रखे गए हैं—

आई ए एस/आई एफ एस	20%
आई पी एस	30%
क्लास—1	25%
क्लास—ii	30%

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने इन खाली स्थानों को भरने के लिए एक विशेष प्रतियोगिता परीक्षा केवल एमरजेंसी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये आयोजित की थी । चयन/परीक्षा विशेष के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं, आयु सीमा, शारीरिक रूप से स्वस्थता के स्तर में सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों/शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अफसरों को रियायतें दी गई थी ।

(2) बहुत से राज्य सरकारों ने तथा कुछ सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने क्लास 1 और 2 स्थानों के एक (गैर तकनीकी) निश्चित प्रतिशत को सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये सुरक्षित रखा था । 1969 तथा 1970 के लिये आसाम राइफल्स के सहायक कमांडेंटों के 40% पद जिन पर अभी तक नियमित सेना के अफसर प्रतिनियुक्त किए जाते थे एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये सुरक्षित रखे गए हैं । आसाम सरकार सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को मिजो पहाड़ी के कठिन क्षेत्रों में रिक्त प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने में सहमत हो गई है ।

(3) सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को केन्द्रीय पुलिस फोर्स में लिया जा रहा है । सीमा सुरक्षा दल सेंट्रल रिजर्व पुलिस, इत्यादि और राष्ट्रीय कैडेट कोर में जहां तक सम्भव है उन्हें लिया जा रहा है । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है । सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स में लेने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(4) सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों के नामों की सूची उनके राज्यों के मुख्य सचिवों को उन्हें रोजगार दिलाने के लिए भेज दी गई है । रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक पुनः स्थापन ने बहुत से ऐसे नियोक्ताओं को एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों के नामों की सूची भेजी है जिन्होंने अपने संगठनों के

लिये उपयुक्त नामों के लिये इस सम्बन्ध में उस निदेशालय को लिखा था ।

(5) लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के चार विशेष कार्याधिकारी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली के मुख्यालयों, राज्य सरकारों,सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को उचित नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ।

(6) बहुत से नवीन पाठ्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिये व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिये और अधिक सुविधा प्राप्त हो सके ।

Track-link between Mor Khun and Khunjer AB on Kashmir-Sinkiang Border

1436. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURY : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to recent Press reports that:-

(i) The Chinese troops have established a vital track-link between Mor Khun in Pak-occupied Kashmir and Khunjer ab on the Kashmir-Sinkiang border;

(ii) the track under reference is expected to be made Jeepable by the middle of 1970;

(iii) the track would be ready to take 3-ton vehicles by the first-half of 1971;

(iv) about 12,000 PLA troops arrived in Pak-occupied Kashmir about 8 months ago to construct this crucial road link which would facilitate the transportation of heavy Chinese Armour from Sinkiang to Pak-occupied Kashmir; and

(v) the number of Chinese troops in the area, referred to is believed to have swelled to 5,000 during the last three or four months;

(b) if so, the reaction of Government thereto: and

(c) the steps taken to safeguard the Indian border and to prevent Chinese and/or Pakistani guerillas infiltrating into Indian territory ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) to (c) . Information relating to the construction of the road from Morkhun to Khunjerab Pass on the Kashmir Sinkiang border, and the reported induction of Chinese personnel of the People's Liberation Army into the area to help build the road, was given to the House in the statement by the Minister of External Affairs on 22nd July, 1969. Government have been recent Press reports regarding the progress in the construction of the road and further induction of Chinese personnel into the area. We have taken the note of these developments in making our defence arrangements.

Chinese Accusations against India on Dalai Lama

1437. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported accusations made by the Government of China through its Official News Agency-the New China News Agency-against the Government of India for using the Dalai Lama for hiding their expansionist designs;

(b) if so, Governments' reaction thereto; and

(c) the steps taken, if any, to counter this propaganda ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) There is little new in the item which is in line with the usual anti-Indian propaganda carried out by Chinese publicity media.

(c) Wild allegations of the New China News Agency against the Government of India carry no conviction with anyone. Where necessary steps are taken to present India's actions and policies in a correct perspective.

Trade Preferences for Developing Countries

1438. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to recent reports that the special meetings of the organisation for Economic Co operation and Development which was to have been held in Paris from the 27th to 29th October, 1969, to consider a scheme regarding generalised non-reciprocal and non-discriminatory trade preferences in favour of developing countries by the developed nations was indefinitely postponed at the instance of the Government of U.S.A.;

(b) if so, Government's reaction to the attitude of the Government of U. S. A. and consequential postponment of the meetings of the O.E.C.D.;

(c) the steps which Government have taken or proposed to take to convey their reaction in this regard; and

(d) whether any reply has been received from the authorities of the organisation for Economic Co-operation and Development ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (d). On receipt of reports that certain difficulties had arise in the formulation of the preferences at OECD meetings in Paris, the Chairman of the "Group of 77" developing countries of which India is a member made a statement in the U. N. Economic and Social Council (ECOSOC) in New York on 28th October, 1969 expressing the concern of the developing countries over the possible delay in the introduction of the scheme for Generalised scheme of preferences as a result of the postponment of the meetings of the Trade Committee of OECD scheduled for this purpose from 27th to 28th October, 1969.

2. Later, the United Nations passed a resolution on the 12th November, 1969, urging the early implementation of Generalised non-reciprocal and non-discriminatory references. It further welcomed the agreement of the developed market economy countries to submit substantive documentation to UNCTAD not later than 15th November, 1969. According to the information available to the Government, the industrially advanced countries members of the OECD have communicated their "offers" to the UNCTD Secretariate on the 15th November in accordance with the time scheduled earlier agreed upon.

Withdrawal of Quantitative Restriction on India's Export

1439. SHRIMATI ILA PAL CHOUDHURI :
SHRI K. P. SINGH DEO :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to efforts made by the State Minister for Foreign Trade during his talks with the European Community Market Officials when he visited European countries recently, the Council of the E.C.M. have decided to suspend Custom duties on imports of a number of items as well as to withdraw quantitative restrictions of certain items from India which will enable her to increase her exports to the E.C.M. countries;

(b) if so, the items which will get the benefit of these concessions;

(c) the period for which the concessions have been allowed; and

(d) the extent of benefit in terms of value and quantity approximately which will accrue to India as a result of the concessions allowed during the period the concessions will last ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) :(a)During his recent visit to Brussels, the Minister of Foreign Trade held discussions with the President of the Commission of the European Communities and urged upon him that the outstanding problems between India and the Community should be solved as quickly as possible. Requests were made for the consolidation of the total or partial suspension of tariffs on items of interest to India such as tea, East India Kips, Cashew-nuts, certain spices and handloom fabrics and handicrafts. Increased quotas for textiles and other products were also requested. The Minister asked for a meaningful contribution of the EEC within the framework of the Generalised scheme of preferences, which would be of real value for India.

A meeting of the Council of Ministers of the European Economic Community has not, however, been held so far to consider specifically India's case.

(b) to (d). Do not arise.

American Citizens in Israeli Army

1440. SHRI H. N. MUKERJEE :
SHRI C. JANARDHANAN :
SHRI ISHAQ SAMBHALI :
SHRI INDRAJIT GUPTA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the U. S. Government's statement that some American citizens are serving in Israeli Army;

(b) whether this revelation has led to wide-spread protests from the Arab countries; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Arab countries have strongly reacted against this.

(c) The Government of India is deeply concerned about the situation in West Asia, which has shown no sign of improvement. Anything which tends to aggravate the situation further is a matter of concern to us.

ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भारतीय लड़कियों को विदेशों में ले जाया जाना

1441. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईसाई धर्म प्रचारक 1 जनवरी, 1968 से ले कर अब तक धार्मिक शिक्षा के लिये कितनी लड़कियां विदेशों में ले गये;

(ख) उपर्युक्त अवधि में उन में से कितनी लड़कियां भारत वापिस आ गई हैं; और

(ग) उन को वापिस लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). पूछताछ की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Change in Non-Alignment Policy

1442. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian policy of non-alignment was formulated two decades ago when the U. S. S. R. and U. S. A. were at loggerhead and important powers were anxious to befriend India;

(b) whether it is also a fact that the position has now reversed and important powers of the world are more anxious to secure the friendship of Pakistan than of India and

(c) whether, in view of the above changed circumstances, whether Government propose to change the Indian Foreign Policy suitably ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c) . India's policy of non-alignment was fundamentally an independent foreign policy which enabled us to judge each issue on its mrits on India's national interests and in the interests of peace and progress in the world. Though conditions in the world have changed during the last two decades and our foreign policy must necessarily make adjustments to changing conditions, there is no need for a reversal or a change in our basic foreign policy which is rooted in India's national interests and in our desire for international peace, stability and progress.

In accordance with its foreign policy, India has sought friendship with all countries. All countries big and small, with two well-known exceptions have extended and continue to extend their friendship to India.

Nuclear Weapons with China and Pakistan

1443. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether defence personnel of China and Pakistan have been equipped with nuclear weapons;

(b) if so, whether it has adversely affected the morale of Indian defence personnel; and

(c) the steps, if any, being taken to equip them with nuclear weapons ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Information regarding Chinese nuclear weapons has been conveyed to the House on a number of occasions, the last being on 23rd July 1969 in answer to Unstarred Question No. 495. There is no information so far that China has developed tactical nuclear weapons for ground warfare, although it is not unlikely that she may have plans to develop them. According to Government's information, Pakistan does not possess nuclear weapons.

(b) The morale of our armed forces continues to be high.

(c) Government's policy on the development of nuclear weapons has been explained to the House, from time to time. Attention is invited to the answers given to Unstarred Question Nos. 462 and 495 on 23rd July 1969.

चीन द्वारा दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण

1444. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के समाचार पत्र "असाही" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि चीन ने 2,000 किलोमीटर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण किया है; और,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) . सरकार ने उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट देखी है। चीन की आणविक शक्ति सम्बन्धी सरकारी जायजे के सम्बन्ध में सदन को कितनी ही वार अवगत कराया जा चुका है। जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 4912 दिनांक 18 दिसम्बर 1968 के उत्तर में बताया गया था, चीन मझोले पराप्त वाले ऐसे प्रक्षेपास्त्रों का विकास कर रहा है जो कि लगभग 2000 मील तक मार कर सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक फैलाव कितना है इसके अभी ठीक संकेत नहीं मिले हैं।

पाकिस्तान द्वारा 200 रूसी टैंकों की मांग

1445. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री बंशनारायण सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पुनः रूस से 200 टैंकों की मांग की है, जो 120 मीलीमीटर तोपों से लैस हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के प्रेजीडेंट इस उद्देश्य से रूस गये थे अथवा निकट भविष्य में जाने वाले है;

(ग) क्या सरकार ने अपने साधनों से इस बात का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) . पाकिस्तान के राष्ट्रपति निकट भविष्य में सोवियत संघ जाने वाले हैं लेकिन उनकी यात्रा की ठीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Second Defence Plan

1446. SHRI YOGENDRA SHARMA :
SHRI C. JANARDHANAN :
SHRI SARJOO PANDEY :
SHRI INDRAJIT GUPTA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the progress so far made in regard to the Second Defence Plan launched in April last; and

(b) the expenditure so far incurred in this respect ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b) . "The Defence Plan 1969-74 is progressing according to schedule. It is not in the public interest to give further details.

Market Development Fund for Trade among Commonwealth Countries

1447. SHRI YOGENDRA SHARMA :
SHRI DHIRESHWAR KALITA :
SHRI ESWARA REDDY :
SHRI C. JANARDHANAN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up a market development fund to promote trade between the Commonwealth countries;

(b) if so, the scope and size of the proposed fund; and

(c) whether a three-man team representing the Commonwealth Secretariat had recently visited India and had discussions with Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) The scope and size of the proposed Marketing Development Fund are under examination by the Commonwealth Trade Promotion Study Team whose recommendations will be considered by the Commonwealth Governments.

(c) Yes, Sir.

Import of Cotton, Wool and Synthetic Fibres

1448. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI K. HALDER :

SHRI GANESH GHOSH :
SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the total quantity and value of (i) wool, (ii) synthetic fibres, and (iii) cotton imported from abroad during the period from 1966-67 to 1968-69, years-wise;

(b) the value of each commodity imported during the above period: and

(c) the total amount of royalty, if any, paid to the foreign business houses ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . A statement regarding the imports of wool and cotton is laid on the Table of the House. [*Placed in Liberary. See* LT-2107/69] Information regarding the import of synthetic fibres is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Indian Jute Industry Research Association

1449. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI K. HALDER :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the authority who controls the Indian Jute Industry Research Association;

(b) the total yearly expenditure for running this organisation and the total income and the share of Central Government therein;

(c) how Government check the activities of this organisation;

(d) whether Government have taken steps to see that no sabotage is done by foreigners; if so, the nature thereof; and

(e) the details of fundamental and applied research works conducted by this organisation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The Association is controlled by an autonomous Council of Management consisting of 12 elected members from the industry, three members nominated by Government of India, five nominated scientists and technologists and the Director of the Asssociation.

(b) In the year 1968-69, the expenditure was of the order of Rs. 29·98 lakhs of which Rs. 17.49 lakhs was contributed by the industry. The balance of Rs. 12·49 lakhs represented assistance by Government.

(c) The activities of the Association are checked through periodical audit of the accounts and by the Government nominees on the Council of Management.

(d) No special steps have been taken by Government.

(e) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-2108/69]

Persons sponsored by M. R. A. for Foreign Visit

1450. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI BADRUDDUJA :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Moral 'Reatmament' is an American :ponsored organisation operating through out the world including India;

(b) whether MRA (India) organises foreign tours for Indian citizens;

(c) if so, how many persons were sent by MRA (India) to foreign countries during the last three years; and

(d) the names and particulars of such persons ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (d) . Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वैदेशिक व्यापार में प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें

1451. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक व्यापार के बारे में तकनीकी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए उनके मन्त्रालय ने शिक्षा संस्थाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत और विदेशों में वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . विदेशी व्यापार मन्त्रालय ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन सोसाइटी के रूप में पंजीयित प्रयोजित किया है। अन्य कार्यकलापों के साथ यह संस्थान भारत में विदेशी व्यापार की तकनीक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलता है । इनमें नियमित तथा तदर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। नियमित पाठ्यक्रमों में से दस महीने तक चलने वाला एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। अन्य पाठ्यक्रम आई० ए० एस० (सं) अधिकारियों के विदेशी व्यापार में प्रशिक्षण हेतु है। इनके अतिरिक्त यह समय समय पर विदेशी व्यापार के विभिन्न पहलूओं पर तदर्थ कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। यह संस्थान उच्च अर्हता वाले प्रोफेसरों, गवेषणा तथा प्रशिक्षण अधिकारियों आदि के समूह द्वारा, जिन्हें संस्थान नियुक्त करता है, प्रशिक्षण देता है। अध्यापन कार्यक्रम में सहायता हेतु संस्थान से बाहर के विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया जाता है। एक विवरण जिसमें भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान में नियुक्त अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक अमले के संबंध में ब्यौरे दिये गये हैं सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०- 2109/69].**

आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलना

1452. **श्री मोलहू प्रसाद : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह कार्य मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8-1-69 एस्टेबिलशमेंट (एस० टी० सी०) दिनांक 28 जनवरी, 1969 के अनुसार आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलने के लिए गृह कार्य मन्त्रालय की अनुमति अत्यावश्यक होती है;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में इस नियम के अन्तर्गत गृह कार्य मन्त्रालय को उसकी अनुमति के लिए ऐसे कितने मामले भेजे गये और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) . अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था के प्रकाशन

1453. **श्री मोहलू प्रसाद : क्या प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा हिन्दी में अथवा दोनों भाषाओं में एक भी

सांख्यिकीय प्रकाशन न निकाले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस संगठन के उच्चाधिकारी हिन्दी के कट्टर विरोधी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों के स्थान पर अन्य हिन्दी समर्थक अधिकारियों को रखने का है ताकि इस संगठन से हिन्दी विरोधी भावनाओं को समाप्त किया जा सके ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अब तक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के दो नियमित प्रकाशन अर्थात् उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 1964 (खंड I) तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान द्विभाषी संस्करण के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य नियमित तथा तदर्थ प्रकाशन प्राविधिक (तकनीकी) होने के कारण तथा हिन्दी में योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कर्मचारी पर्याप्त संख्या में न होने के कारण केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये हैं। प्रकाशनों के हिन्दी / द्विभाषी संस्करण निकालने के काम में सुविधा लाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अब निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

(i) हिन्दी अधिकारी (श्रेणी II-राजपत्रित 350-900 रुपये)	एक
(ii) वरिष्ठ अन्वेषक (हिन्दी श्रेणी II अराजपत्रित) 325-575 रूपये)	दो
(iii) आशुलिपिक (पदक्रम III) (हिन्दी) (130-280 रुपये)	एक

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Article on 'Mahatma Gandhi' in *New York Times*

1454. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article "The Yogi and the Commissar" by Arthur Koestler on Mahatma Gandhi in the edition of the *New York Times* (Magazine) of the 5th October, 1969; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) This scurrilous article represents the views of an individual writer and the Government condemn this gross misrepresentation of a great man. Replies to this article by our M. Ps. and other delegates at U. N. were published in the *New York Times*.

Pak. Advocacy for Admission of Chaina to U. N. O.

1455. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the present U. N. General Assembly meeting, Pakistan advocated for the admission of Communist China to the U. N. O.;

(b) if so, the stand taken by India on this score ; and

(c) if not, the specific issues raised by the Indian Delegation to the recent U. N. O. meeting and with what success ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) India voted for the seating of the People's Republic of China in the United Nations.

(c) Does not arise.

Export of Cigarettes

1456. SHRI SHIVA CHANDRA JHA:
SHRI N.R. DEVGHARE :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India exports cigarettes and other tobacco goods abroad;

(b) if so, to which countries and the foreign exchange earned therefrom during the last three years, year-wise ; and

(c) if not, the steps taken by Government for stepping up the cigarette exports and with what success ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) Cigarettes and other tobaccoo manufactures are exported to the following countries:-

Bahrein Islands, Czechoslovakia, Nepal, Kuwait, Uganda, Tanzania, Afghanistan, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, Qatar, Aden/S. Yeman Republic and Kenya.

Freign exchange earned therefrom in the last three years (year-wise) is as under:--

	Value in Rs. '000'	
1966-67	1967-68	1968-69
9984	7417	5993

(c) Does not arise.

Naval Base in Lacadive Islands

1457. SHRI RAM AVTAR SHARMA :
SHRI MANIBHAI J. PATEL :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to have a Naval base in Laccadive Islands keeping in view the strategic position of those Islands ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Government have under consideration a proposal to set up limited base facilities in the Laccadive, Minicoy and Amindivi Group of Islands.

(b) Does not arise.

Black listing of firms

1458. SHRI RAM AVTAR SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to tighten the law regarding black listing of firms violating import and export regulations ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) when a decision in this regard will be taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) . There is no proposal under consideration at persent for tightening the penal provisions relating to the debarment and suspension of importers/exporters who violate the Import and Export Trade Control Rules and Regulations.

Exporting Units in Engineering Industry

1459. SHRI RABI RAY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have identified about forty units mostly in the engineering industry which should be allowed to expand so as to cater to the export market as well as to meet increasing domestic demand ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK): (a) to (b). There has recently been a significant revival of domestic demand, as a result of which a dimin ution of export capacity in certain lines is feared, threatening to curtail exportable is srpluses. The Ministry of Foreign Trade is at present engagedi n indentification of industrial units and product lines where expansion of capacity is needed to sususstain the momentum in the export of industrial products and to achive a compound growth rate of 7% per annum in our exports. Some applications for expansion of capacity have also been received and are under consideration. These applications after concrete proposal for expansion of capacity would be submitted to the Licensing Committee for advice. It is not possible at this statge of the exercise to list the units which may be concerned, as this exercise of identification is not yet complete. A list of the product lines so far identified in this connection is however laid on the Table of the House.

Statement

List of product–Lines so far Indentified

Sewing machines
Drop Forged Handtools
Small cutting tools
Dry batteries
Storage batteries
Stretch Reduction Mill for steel tubes
Bright bars and shaftings
Radio receivers and electornic components
Properzi rods
Refrigerators
Diesel engines
Fuel injection equipment
Bicycles & Parts.

Plan for Scientific Research and Development in Defence

1460. SHRI RABI RAY : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to spend twenty five crores rupees on scientific research any development in Defence, by the end of the current plan period, in view of the importance of the technological orientation of the Defence Department ;

(b) if so, the specific plans untder contemplation to reach the said target; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b) . A plan has been drawn up on the basis of current and anticipated requirements of weapons/equipment and materials for the Services, also far competence building in various fields of defence interest. It envisages a progressive bulid-up of expenditure rising from Rs. 16 crores in 1969-70 to Rs. 30 crores in 1973-74.

(c) It will not be in public interest to disclose the details on the floor of the House.

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए भारतीय प्रत्याशी

1462. **श्री रघुवीरसिंह शास्त्री** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में भारतीय प्रत्याशी पराजित हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पराजय के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां । दहोमे के उम्मीदवार के मुकाबले में भारत का उम्मीदवार हार गया; छह मतदानों के बाद महा सभा में दहोमे के हक में 69 मत पड़े और सुरक्षा परीषद में 9 जबकि भारतीय उम्मीदवार के हक में क्रमश: 62 और 6 मत पड़े ।

(ख) अफ्रीकी दल के 41 राज्यों ने एन मोके पर दहोमे के उम्मीदवार को वोट देने का निर्णय इस आधार पर किया कि इस न्यायालय

में अफ्रीका का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हैं; इसकी वजह से भारत के हक में अफ्रीका के वोट कट गए जबकि अफ्रीका देश के उम्मीदवार के खड़े होने से पहले ये वोट भारतीय उम्मीदवार को ही मिलने की उम्मीद थी। इसके अतिरिक्त थाईलैंड के विरोधी एशियाई उम्मीदवार की वजह से भी एशियाई देशों के भारत के पक्ष के प्रत्याशित वोट कम हो गए।

South Vietnam Provisional Government Office in India

1463. SHRI E. K. NAYANAR : Will the MINISTER EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to give diplomatic recognition to the Provisional Government in South Vietnam which was formed in the last June by the National Liberation Front leaders; and

(b) if not, whether Government propose to give permission to the South Vietnam Provisional Government to open an office in India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Government is not considering the question of diplomatic recognition to Provisional Revolutionary Government of South Vietnam.

(b) No such proposal is before the Government.

नई रेजिमेंट बनाना

1464. **श्री रामसेवक यादव** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समुदायों ने 1968 में इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि सेना में समुदायों के नाम पर नई रेजिमेंट बनाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की मांग इस आधार पर की जा रही है कि सेना में कुछ समुदायों और सम्प्रदायों के नाम पर पहिले से ही कुछ रेजिमेंट हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समुदायों और सम्प्रदायों के नाम पर रेजिमेंटों को समाप्त करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) . यद्यपि अभी तक कुछ रेजीमेंट समुदाय विशेष के नाम पर बने हुए हैं किन्तु सरकार की नीति सेना से धीरे धीरे वर्ग भेद को दूर करके उसका पुनर्गठन करना है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार समुदायों के नामों के आधार पर रेजीमेंटों को स्थापित करने के अन्य वेदनों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

Purchase of Cotton Fabrics by Government Departments

1465. SHRI VASUDEVAN NAIR :
SHRI ESWARA REDDY :
SHRI C. JANARDHANAN :
SHRI ISHAQ SAMBHALI :

Will the Minister of SUPPLY be pleased to state :

(a) the value of orders placed by various Government Departments with the cotton textile mills for the supply of cotton fabrics tc. in 1967-68;

(b) the estimated consumption of cotton fabrics and other products of cotton textile mills by Government Departments in 1969;

(c) the purchases from the de-centralised sector in respect of the above items; and

(d) the purchases from cotton textile mills taken over by Government or run under the Textile Corporation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (d) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Export Promotion Council for Oilseeds and Oilseeds Products

1466. SHRI CHENGALARAYA NAIDU :
SHRI R. BARUA :
SHRI MAYAVAN :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI V. NARASIMHA RAO :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the setting up of an independent Export Promotion Council for oilseeds and oilseed products has been suggested in a survey jointly made by the Bombay University, etc.;

(b) if so, whether this survey sponsored by the United States Agency for International Development was with the approval of his Ministry;

(c) if so, the main points made in the report; and

(d) how far they have been accepted by Government ?

THE DEPUTY MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) (i) Substantial frieght reduction should be obtained on exports of oilcakes and meal to U. K. and West Europe;

(ii) an independent Export Promotion Council should be set up for oilseeds and oilseed products;

(iii) the main impediments in the way of increased export of de-oiled rice bran, *e.g.* high freight rates, import levies imposed by importing countries etc should be improved; and

(iv) concrete efforts should be made both by the Government and Industry to overcome the various difficulties faced by the exporters of animal feeds.

(d) The survey is under examination of the Government.

Corporation for Import of Cotton

1467. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to set up a separate public sector corporation to handle cotton imports which are at present entirely in the hands of the private sector;

(b) if so, the probable date from which the Corporation will start functioning; and

(c) whether the proposed Corporation would also be entrusted with the task of cotton development within the country which is now the responsibility of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). Attention of the Hon'ble Member is invited to the statement made by the Minister of Foreign Trade and Supply in the Lok Sabha on 31. 8. 69. A suitable framework is being evolved to take over import of cotton from the cotton year 1970-71.

(c) No, Sir.

Production of Cotton

1468. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have made an estimate of the cotton crop this year;

(b) whether prices are likely to slump in view of the good harvest anticipated;

(c) whether Government propose to announce new, more remunerative support prices for cotton; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) It is too early to have a Government estimate made of the cotton crop for the cotton year 1969-70. However indications are that the crop this year is likely to be of a higher level than that of last year.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) The present support prices are considered to be adequate.

Director of National Test House, Calcutta

1469. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation, signed or otherwise, in regard to the Director, National Test House, Alipore, Calcutta about the efforts made by him to get extension, although he has reached the superannuation age of 58;

(b) whether the representation makes a complaint that he is harassing his subordinates and abusing his position for securing personal material advantage, etc.;

(c) if so, the nature of the complaint;

(d) whether Government have investigated/will investigate into these complaints; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c) . Yes, three representations were received. In two of the pseudonymous letters, it was alleged that the Director, National Test House, Calcutta, was trying to secure extension of service. It was also alleged that he was indulging in gross nepotism and favouritism in respect of certain transfers and promotions in the National Test House, Calcutta and Bombay.

In the third letter which was anonymous, it was alleged that the treatment of the Director towards the subordinate staff was intolerable and that he was making use of Government officials for his private work.

(d) and (e) . As the letters were found to be pseudonymous/anonymous, no action was taken on them. The Director, National Test House has since retired from service with effect from 31. 10. 1969.

Kashmir an Independent Entity in "National Geographic Globe, 1966"

1470. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a publication "National Geographic Globe, 1966" kept in the American Cultural Centre, Patna, in which Kashmir has been shown as an independent entity;

(b) if so, whether the American Cultural Centre has been asked to remove this book and other such publications, displaying wrong maps in American-run Centres, U.S.I.S. Libraries, etc, and

(c) if not, Government policy in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The matter was taken up with the U. S. Information Services in New Delhi. Government has been informed that the Globe of the world prepared by the National Geographic Society which is not an official Agency of the U. S Government, was removed in July, 1969.

Fall in prices of Jute Goods

1471. SHRI B. P. MANDAL :
SHRI BEDABRATA BARUA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been steep fall in the price of jute adversely affecting the growers and thus jeopardising the prospect of future produce; and

(b) whether Government contemplate to get themselves seized of the problem and save the growers from incurring heavy losses in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Reduction in Export Duty on Tea

1472. SHRI R. K. AMIN :
SHRI G. C. DESAI :
SHRI K. M. KOUSHIK :
SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH:

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the former Commerce Minister, Shri Manubhai Shah, recently urged Government to provide immediate relief in export duty to the tea industry to restore its competitive position *vis-a-vis* Ceylon and East Africa;

(b) whether there have also been demands from various quarters in support of the plea put forward by Shri Manubhai Shah sometime back;

(c) whether Government have assessed the total loss in revenue accruing from the Tea industry consequent upon imposition of export duty on tea in the wake of devaluation; and

(d) the steps which Government propose to take to restore the Tea industry to its original position in the world market ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) There have also been demands from the Tea Industry for giving relief in export and excise duties on Tea.

(c) There has been no loss of revenue due to imposition of export duty on tea, but there was reduction in revenue from this source because of reduction in the rate of export duty on tea made from time to time since the devaluation of the rupee.

(d) Substantial relief in export and excise duties has already been given in October 1968 and in March 1969. The position, however, is kept under constant review.

International measures to stabilise tea prices have been under discussion under the auspices of the FAO. In a meeting of the tea exporting countries held in Mauritius, it has been agreed that 90 million lbs. of tea will be withdrawn from the estimated exports in 1970. A consultative committee on tea has been formed consisting of producing and major importing countries to evolve regulatory measures to give effect to this decision and to study further measures necessary to stabilise prices.

Talks with Philippines Foreign Minister

1473. SHRI P. C. ADICHAN :
SHRI B. K. DASCHOWDHURY :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether, during the visit of Foreign Minister of Philippines to New Delhi, plans for Asian security and economic and political stability of the region were discussed;

(b) if so, the details of the proposals discussed and outcome thereof; and

(c) the steps being taken in pursuance of these decisions ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c). Matters of mutual interest to India and the Philippines were discussed during the visit of the Foreign Minister of Philippines to New Delhi. Both sides laid stress on steady economic growth and political stability. The Government of India assured the Philippines Foreign Minister of India's abiding interest in South East Asia and the need for peace and stability in this region.

'Dragon Rocket' launched from Thumba Rocket Launching Station

1474. SHRI P. C. ADICHAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether a two-stage 'Dragon Rocket' fired from the Thumba launching station on the 21st September, 1969, to study the atmospheric conditions in the range of 100-350 Kilometres failed to yield the required date;

(b) whether an inquiry has been made to find out the reasons for such failure; if so, the findings thereof; and

(c) the loss incrruel on this account ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b). Yes, Sir. The Dragon rocket was manufactured by Messrs Sud Aviation, France and supplied by the Centre National D'Etudes Spatiales, France. In conformity with normal practice, a standing Evaluation Committee consisting of Project Scientists, Scientific Coordinator, representative from Centre National D'Etudes Spatiales (CNES) France, Sud Aviation France, Range personnel and Director, Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) was convened by the Director TERLS, for investigating the failure of the experiment. It was the view of the Committee that though the lift off was normal, the rocket behaved abnormally 25 seconds thereafter causing disturbance to the rocket-borne instrumentation system.

(c) The loss to India was about Rs. 20,000.

Ban on Foreign Businessmen in Libya

1475. SHRI P. C. ADICHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Libyan Government have lately imposed a ban on foreign businessmen operating in Libya;

(b) if so, the percentage of these foreign businessmen who are Indians and their number; and

(c) the steps taken and being taken by Government to repatriate them along with their business assets ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

Export Duty on Leather

1476. SHRI P. C. ADICHAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the leather industry has against the background of declining leather exports demanded some concessions in export duty, etc;

(b) if so, the precise demands for concessions made; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). The leather industry has been pressing for the removal of export duties on East India tanned and Chrome tanned leathers. It has not been found possible to agree to their proposals in view of the significant increase in the exports of leathers which amounted to Rs. 71.99 crores during 1968-69 as against Rs. 53.22 crores in 1967-68 and Rs. 27.85 crores during April-July 1969 as against Rs. 25.03 crores during the corresponding period of 1968.

Study Group on Export Strategy for India

1477. SHRI NAVAL KISHORE SHARMA :
SHRI P. C. ADICHAN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have received the recommendations of the Study Group on Export Strategy for India;

(b) if so, whether Government have considered its recommendations; and

(c) the main features of the recommendations accepted and the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Yes, Sir. A number of Working Groups were constituted to consider the recommendations made by the Study Group. The Working Groups have completed their examination and Government is in the midst of formulating its view on the recommendations. It may, however, be pointed out that some of the recommendations made by the Study Group already form part of the General Policy being pursued at present.

Promotions in Defence Services

1478. SHRI S. K. SAMBANDHAN :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that promotions in the Defence Services, particularly in the Naval Services, are done on communal or regional basis; and

(b) if not, whether Government propose to lay a statement showing the promotions in the officers' ranks during the last three years on the Table ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Statistics giving the communal or regional particulars are not maintained.

Steps to Prevent Entry into India of Pak. trained Nagas

1479. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :
DR. SUSHILA NAYAR :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Nagas now getting training in Pakistan in guerilla warfare; and

(b) the steps taken to prevent their entry into India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The underground Nagas have been making sustained efforts since August, 1968 to send gangs to Pakistan but have not succeeded so far in their attempts. We have no definite information whether there are any Underground Nagas under training, at present, in Pakistan.

(b) The Security Forces are keeping unlawful movements either way.

Nanak Quincentenary Celebrations at Nankana Sahib

1480. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :
DR. SUSHILA NAYAR :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Pakistan has rejected the Indian request for sending an advance party to Nankana Sahib for making arrangements for Guru Nanak Quincentenary; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government deplores Pakistan Government's refusal to allow an advance party to visit Nankana Sahib on this occasion.

Increase in Pakistan's Defence Expenditure

1481. SHRI BANSH NARAIN SINGH :
SHRI RAM SINGH AYARWAL :
SHRI KANWAR LAL GUPTA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the news-item appeared in the Statesman of

the 30th October, 1969 regarding the steep rise in Pakistan's Defence expenditure;

(b) the contents of the report of the Institute for Strategic Studies, published in the Military Balance regarding the arms supplied to Pakistan by U.S.S.R. this year and Pakistan's strength of Army, Navy and Air Force:

(c) the estimate of Government regarding Pakistan's strength of Army, Navy and Air Force and the Arms supplied to Pakistan by foreign countries including the U.S S.R.; and

(d) the steps taken by Government to meet the situation ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes. Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2110/69]

(c) Pakistan's armed forces are more than half of India's. As regards, arms supplies to Pakistan from various sources, including the Soviet Union, attention is invited to the answers given to Starred Question No. 67 and Unstarred Question No. 503, 548 and 550 on 19th November, 1969.

(d) Government are alive to the situation created by the Pakistani military build-up. Necessary steps are taken to meet the threat.

Manufacture of MIG 21 Planes

1482. SHRI BANSH NARAIN SINGH :
SHRI RANJEET SINGH :
SHRI J. H. PATEL :
SHRI KANWAR LAL GUPTA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India will accept the Soviet proposal to manufacture an improved version of the Mig 21 planes;

(b) the response from Moscow to India's request for supersonic bombers;

(c) whether Government have made any alternative arrangements for the supply of supersonic bombers; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) At our request the Soviet Government have agreed to give collaboration for the manufacture of an improved version of Mig 21 plane in the existing factories.

(b) to (d). It will not be in the public interest to disclose information in this regard ?

Talks with the President of Rumania

1483. SHRI S. M. KRISHNA :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the President of Rumania paid a visit to this country during October this year;

(b) if so, the nature of discussions held between the Indian Leaders and the President of Rumania; and

(c) the decisions arrived at ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A copy of the joint communique is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2111/69]

Hardships to Indians in U.K.

1484. SHRI JAI SINGH :
SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 478 on the 23rd July, 1969 and state :

(a) whether Government have made any assessment of the hardships faced by Indians in U.K. as a result of curbs put on the immigrants by further tightening the immigration Rules;

(b) if so, the details of the assessment made in this regard;

(c) the number of representations received both in India and U.K. in this regard; and

(d) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (d). The implications of the recent rules and practices of the U.K. authorities in this field are under careful examination by Government.

Lifting of U.S. Arms Embargo

1485. SHRI JAI SINGH :
SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 418 on the 23rd July, 1969 and state :

(a) whether India's protest to the U.S. authorities against the lifting of arms embargo imposed on Pakistan during the Indo-Pak. conflict has since been decided by them;

(b) the developments about the supply of U.S. arms to Pakistan; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). The U.S. Government have informed us that no decision has yet been taken to lift the ban on arms supplies to India and Pakistan and that their policy in this respect is still under review.

(c) Our views on any move to lift the ban on arms supplies have been conveyed to the U.S. authorities.

Enquiry against Birla Group of Companies

1486. SHRI JAI SINGH :
SHRI YAJNA DATT SHARMA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 513 on the 13th August, 1969 and state the progress since made in the finalisation of cases which were filed in the various courts in respect of the Birla Group of companies ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : The present position of the charge sheets filed in court by the Central Bureau of Investigation against various concerns in the Birla Group is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT--2112/69]

Report of Chairman, State Trading Corporation on Quality of Goods Exported by India

1487. SHRI J. MOHAMED IMAM :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI GADILINGANA GOWD :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Chairman, State Trading Corporation has recently stated in his report that India is not regarded as manufacturer of quality goods abroad;

(b) if so, the reaction of Government in this regard;

(c) whether any steps are being taken or have been taken to come upto the expectation of the foreign buyers and consumers and thus increasing country's foreign exchange earnings ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) A statement to this effect is contained in the report of the State Trading Corporation Reviewing Committee, of which Chairman, S.T.C , was the Chairman.

(b) and (c). Necessary steps have already been taken by introducing compulsory quality control and pre-shipment inspection

schemes in respect of a large number of the commodities exported from India to ensure their quality. About 300 commodities have been covered under this scheme so far.

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी पूना में हिन्दी पढ़ाना

1488. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, पूना में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब हिन्दी अनिवार्य नहीं रही है जबकि अंग्रेजी पहले की तरह अनिवार्य है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर सीमा पर पाकिस्तान तथा चीन के आक्रमण की संभावना

1489. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर से प्रकाशित सम्पभोग पत्र में छपे समाचार के अनुसार आचार्य विनोबा भावे ने हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण की सम्भावना व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस इस बारे में तथ्यों का पता लगाने का भी प्रयत्न किया है;

(ग) क्या आचार्य विनोबा भावे ने बंगाल तथा आसाम में गुण्डागर्दी तथा हिंसा की घटनाओं को इसका पूर्व संकेत बताया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में सतर्क और सावधान है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). प्रेस रिपोर्ट के अनुसार वार्धा से प्रकाशित होने वाली "साम्ययोग" नामक साप्ताहिक पत्रिका के एक लेख में आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि उत्तर पूर्वी सीमा पर चीन और पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जाने की संभावना है और अगर बंगाल में कोई तोड़-फोड़ की वारदातें हुई तो आसाम शेष देश से अलग थलग पड़ जाएगा।

हमारी सीमाओं पर होने वाले खतरों के बारे में सरकार सजग है तथा वे खतरे क्या रूप ले सकते हैं यह भी सरकार जानती है।

रूस से शस्त्रास्त्र और टैंक प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में वृद्धि

1490. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री समर गुहा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लन्दन स्थित सामरिक अध्ययन केंद्र ने विश्व में शक्ति संतुलन के बारे में कुछ अनुमान, संभावनाएं आदि बताये हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा रूस टैंक बड़े और छोटे विमान और विमान भेदी तोपें प्राप्त किये जाने के कारण उसकी सैनिक शक्ति में भारी वृद्धि हो गई है; और

(ख) क्या सरकार ने शक्ति संतुलन में इससे होने वाली गड़बड़ी की ओर रूसी अधिकारियों का ध्यान दिलाया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) . सरकार ने उल्लिखित प्रकाशन को देखा है । इस संबंध में 19 नवम्बर, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 67 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता

1491. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 सितम्बर, 1969 को बेलग्रेड में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ उनकी वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में किन मुख्य बातों पर बातचीत हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने मार्शल टीटो को भारत के प्रधान मंत्री का एक पत्र दिया था;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा था; और

(ङ) उसके सम्बन्ध में मार्शल टीटो तथा यूगोस्लाविया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ये बातचीत गोपनीय थी और इस तरह की बातचीत का ब्यौरा बताने का कायदा नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). इस तरह के पत्र गोपनीय प्रकृति के होते हैं और उनमें निहित सामग्री का ब्यौरा बताने की प्रथा नहीं है ।

सैनिक सेवा कोर में पदोन्नतियां

1492. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में "सैनिक सेवा कोर" नामक एक कोर है जो सप्लाई का काम करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कोर व "स्टोर हैड टैक्निकल" नामक एक व्यवसाय (ट्रेड है);

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि इस व्यवसाय में काम करने वाले जवानों की पदोन्नति नायक से ऊंचे पदों पर नहीं की जाती;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्य दो या तीन कोरों में भी जवानों के लिए ऐसे व्यवसाय हैं जहां जवानों को पदोन्नति के और अवसर मिलते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार जवानों के लिए उपरोक्त व्यवसाय में भी पदोन्नति के और आगे अवसर प्रदान करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी हां, केवल उस स्थिति में जब कि वे क्लर्क (स्टोर) के रूप में काम करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से योग्य नहीं हो जाते ।

(घ) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Recall of Envoys from Morocco and Jordan

1493. SHRI R. BARUA :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :
DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI ABIDUL GHANI DAR :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Morocco and Jordan envoys have been recalled by the Indian Government;

(b) if so, whether India has asked their envoys also to be withdrawn; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The Government of India have recalled their Ambassador to Morocco and their Charge d' Affairs in Jordan.

(b) No, Sir.

(c) The Government of India did not consider it necessary to take the further step of demanding the recall of the two envoys from India.

Study Team on Development of Coir Industry

1494. SHRI P. VISHWAMBHARAN :
SHRI MANGALATHUMADAN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have appointed a Study Team to go into the schemes for the development of coir industry;

(b) if so, when the Study Team was appointed;

(c) whether there is a time limit within which the team is required to submit its report and if so, the time limit thereof; and

(d) how many meetings of the team have been held so far ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) On the 22nd July, 1969.

(c) Yes, Sir; within six months of its formation.

(d) Two.

Normalcy In Nagaland

1495. SHRI J. H. PATEL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the action taken during the last three years to solve the problem of hostile Nagas;

(b) the number of hostile Nagas who have returned from China and Pakistan and surrendred themselves and details of the arms surrendered;

(c) the scheme proposed to be implemented to bring normalcy in Naga'and ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Variousteps have been taken by the Government of Nagaland to restore normalcy in the State. These include the strengthening of the police posts, the intensification of patrolling on the international borders, the stepping-up of intelligence work, the extension of village guards scheme to bordering villages and the dissemination of information among the lawabiding people. Arrangements have been made to afford protection and rehabilitate Underground Nagas who have surrendered. There have been meetings between overground and underground leaders to discuss measures for maintaining peace.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The measures introduced by the Government of Nagaland to develop the area and achieve normalcy have gone a long way in raising the confidence of the people. By and large, what is needed is the continued implementation of the existing policies and schemes which have proved their worth rather then introduce many new schemes, though the situation is kept constantly under review and new measures are devised as and when necessary.

India's balance of trade

1496. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the country's adverse balance of trade has been brought down from

Rs. 921.80 crores in 1969-67 to a little over Rs. 500 crores in 1968-69;

(b) if so, the details of items in respect of which exports have been increased over the period indicating the extent of increase and the items in respect of which imports have been reduced and to what extent in each case; and

(c) when in view of the programmes under the Fourth Five Year Plan, the country is likely to have an even balance of trade and the efforts which would be made in that direction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is available in the Monthly Statistics of the Foreign Trade of India published by the Director General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta, for the months af March, 1967 and March, 1969 respectively, containing figures of the total exports and re-exports in Volume I and total imports in Volume II for the respective years.

(c) According to the long-term projections given in the Draft Fourth Five Year Plan 1969-74, the balance of trade is likely to be adverse at the end of the Fourth Five Year Plan but is expected to turn favourable to the tune of Rs. 100 crores by the end of the Fifth Five Year Plan in 1978-79. The specific efforts for the purpose would be to accelerate the processes of import substitution and export promotion which alone can help to achieve equilibrium in the trade balance.

Indian effort to resolve Vietnam Issue

1497. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Governments are aware that North Vietnam forces violated the temporary ceasefire following the death of President Ho Chi Minh; if so, what specific instances of violation of ceasefire cameinto Government's notice;

(b) whether Government's attention had also been drawn to the peaceful gesture made by the U. S. A. in withdrawing another 40,000 U.S troops from Viet Nam from November this year; and

(c) the Government's assessment about the latest situation in Viet Nam and other developments and the efforts made by Government during the last 3 months and proposed to be made for reviving permanent peace in Viet Nam ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Government has seen press reports regarding violations by each side against the other. Under the conditions existing in Vietnam it is very difficult to pinpoint who is responsible for a particular violation. Although it would be impossible to enumerate all the violations, fights broke out initially in the Provinces of Quang-Nam and Quang-Nagai in the north of the country and near Ny Tho in the Mekong Delta.

(b) Government have seen reports that the U. S. Government has offered to withdraw 40,000 troops by November, 1969.

(c) The progress towards a peaceful settlements has been disappointing though the scale of actual fighting seems to be less than before. The Government of India is in touch with all parties & other concerned through diplomatic channels and urged a peaceful settlement through negotiations.

India's Exports

1498. SHRI HIMATSINGKA :
SHRI D.N. PATDOIA :
SHRI B. K. DASCHOWDHURY :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while exports for the first six months of the current year went up, the rate of growth in this period fell short of the Planning Commission's traget ;

(b) if so, how far the exports increased over the exports during the corresponding

period last year and how far the rate of growth fell short of expectations and the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to ensure that the Planning Commission's target in respect of rate of growth during the current year as a whole is achieved ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) The increase in exports during April-September, 1969 amounted to about 3.1 per cent over the same period of 1968 as compared to the target rate of increase of 7 per cent per year. This compares with the extraordinarily high rate of growth of 13.6% achieved in 1968-69. It is not possible to indicate at this stage the extent of fall, if any, which may occur in the rate of growth of exports this year as compared to the preceding year.

(c) The main reasons for the deceleration in the rate of growth of exports during the current year are less buoyant world trading conditions than in 1968, growth of home demand, rise in the domestic price level, losses in production and exports on account of industrial unrest, shortages of certain raw material inputs, etc.

(d) Policies are being evolved to deal with the situation so as to arrest the trend towards undue deceleration in exports.

Nationalisation of Imports and Exports of Raw Materials

1499. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry have communicated their views on the proposed partial nationalisation of imports and Exports and Exports, especially the imports of raw materials;

(b) if so, their precise comments in this regard; and

(c) Government's reaction thereto and how far Government have modified the proposal in the light thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). Apprehensions were expressed by the Chairman of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry at the meeting of the Advisory Council on Trade held on the 27th and 28th September, 1969, that the S T. C. and M. M. T. C. may not be able to import the raw materials efficiently. It was pointed out that these Government agencies were importing, with increasing efficiency, a number of important raw materials from world market in competition with other buyers and have also been able to supply them at prices which are fair and equitable and it was, therefore, proposed to accelerate the process of canalising the import of raw materials through these agencies.

Russian Military Planes at Dum Dum Airport

1500. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state : (a) whether it is a fact that a number of Russian military planes landed at Dum Dum Airport on the 28th October, 1969;

(b) if so, the purpose of landing of such Russian military planes there;

(c) whether such Russian military planes are used for ferrying arms and ammunition and other military hard-wares to North Vietnam and whether Indian Airport facilities for ferrying military supply to North Vietnam or for the return journey of the Russian planes from North Vietnam for the purpose has been granted by Government;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) if not, why Russian military planes are found to use Dum Dum Airport on many occasions ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

Development of Calcutta

1501. SHRI SAMAR GUHA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during her last visit to Calcutta, the Prime Minister assured the people of West Bengal that the problems of Calcutta will be given special attention by the Central Government and whether she described the development problems of Calcutta as a national problem of the country; and

(b) if so, the steps taken or contemplated to be taken by Government to fulfill the assurances of the Prime Minister to the people of West Bengal ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b) . While there was no occasion for the Prime Minister to give any assurances as such, she expressed her concern about the special problems of Calcutta city, and her full appreciation of the importance to the country as a whole, of finding early and adequate solutions to these problems. She also mentioned the special assistance which the Central Government is already providing in the matter.

Proposals made by the State Government in this connection will be taken into account at the time of finalising the Fourth Plan in the light of re-appraisal of resources both of the Central and the State Government as a result of the Fifth Finance Commission's award.

Study of Defence Problems of South East Asia by General Chaudhuri

1502. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted General Chaudhuri, former Chief of Army Staff and currently Indian High Commissioner in Canada; to take an appointment in Megill University in Canada after the completion of his diplomatic tenure ;

(b) whether General Chaudhuri will undertake on behalf of the said University a study of Defence problems in South East Asia and Defence in a developing society; and

(c) whether Government propose to obtain General Chaudhuri's services for such studies which are of much more importance to this country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINCH) : (a) Yes, Sir. General Chaudhuri handed over charge as High Commissioner of India, Ottawa, on 2-8-1969 (AN).

(b) According to General Chaudhuri, his assignment in the McGill University would be as a Visiting Professor in the University's Centre for Developing Area Studies and part of this assignment would entail a study of the role of the military in Developing States starting with some selected States in Africa.

(c) No such proposal is under consideration.

Sale of Planes to Pakistan by Yugoslavia

1503. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Yugoslavia have decided to sell to Pakistan, Planes having military potential;

(b) whether it is also a fact that Government had requested the Government of Yugoslavia not to proceed with the deal;

(c) whether the Government of Yugoslavia have turned down the request to cancel the deal; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to guard our interest ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c) . So far as we know Yugoslavia has not sold any military planes to Pakistan.

(d) Does not arise.

पोलैंड के साथ व्यापार सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1504. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोलैंड के साथ व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिये वहां एक अध्ययन दल भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत में छोटे पैमाने के इंजीनियरी उद्योगों का माल उस देश में बहुत खप सकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पोलैंड के साथ देश का व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से इस दिशा में पोलैंड सरकार के सहयोग से तथा देश के अन्दर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). संभवतः माननीय सदस्य इण्डो-पोलिश चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित अध्ययन दल का उल्लेख कर रहे हैं, जिसने 12 जून से 4 जुलाई, 1969 तक पोलैंड का दौरा किया था। इस दल ने भारत से पोलैंड को मोटर-गाड़ी सहसाधन, ढली वस्तुएं तथा गढ़ी वस्तुएं, एवरेसिव्ज, छोटे तथा दस्ती औजार तथा सैनिट्री फिटिंग्स आदि जैसे माल के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया। दोनों देशों में विनिमय किये जाने वाले माल की सूची तैयार करते समय इन मदों को ध्यान में रखा गया है।

Rolling Five Year Plan for Defence

1505. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government have introduced a scheme known as "Rolling Five Year Plan" for the Defence of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the benefits to be achieved therefrom ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir, with effect from 1.4. 1969.

(b) The plan is based on the concept that instead of having a 5-year Plan as an individual operation, planning will now be a continuous process. A "Rolling plan" will be prepared every year deleting the completed year and adding one more year. The plan will be based on an assessment of 10 years requirements of the Services. At any given point of time, a firm 5-year Plan will be available to the Services with assured funds. Some details of the 1969-74 Plan have already been given in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 8189 on 30th April, 1969.

(c) The new concept will enable more effective effort towards indigenous design, development and production of weapon systems. It will also enable the Services to continually re-assess the threats and modify or amplify the Plan as necessary to get the maximum value from available resources. It will provide incentives to the Services for effecting economies in Defence expenditure which can be utilised for higher priority needs.

यूरेनियम ईंधन के बारे में आत्मनिर्भरता

1506. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत यूरेनियम ईंधन के बारे में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा तथा इसका आयात कब तक बन्द कर दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के लिए आवश्यक प्रारम्भिक ईंधन के अर्धभाग; जिसका आयात कनाडा से किया गया है, को छोड़ कर भारत के प्राकृतिक

यूरेनियम रिएक्टरों के लिए आवश्यक सारा ईंधन भारत में ही तैयार किया जायेगा तथा इसके लिये देश में निकाला गया यूरेनियम काम में लाया जायेगा।

तथापि, तारापुर परमाणु बिजलीघर में संघनीकृत यूरेनियम से बना ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इस बिजलीघर को चालू करने के लिए आवश्यक सारा ईंधन अमरीका से मंगाया गया था। पहली बार व्यय हुए ईंधन को बदलने के लिए आवश्यक ईंधन का भी आयात किया जायेगा। दूसरी बार और उसके बाद व्यय हुए ईंधन को बदलने के लिए आवश्यक ईंधन के लिए संघनीकृत यूरेनियम का तो आयात किया जायेगा लेकिन उस यूरेनियम का शोधन कर उससे ईंधन बनाने का काम भारत में ही किया जायेगा।

लद्दाख में सैनिक कर्मचारियों के लिये क्वाटर

1507. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख में तैनात जवानों तथा सैनिक अधिकारियों को क्वाटर देने की व्यवस्था की है ताकि वे अपने परिवारों को अपने साथ रख सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था कब तक करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं। लद्दाख संक्रियात्मक क्षेत्र है जहां कि सैनिकों को पारिवारिक आवास नहीं दिये जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा गिरफ्तार कुमारी शांति नायडू तथा भारत मूलक अन्य लोगों की रिहाई

1508. **श्री हा० ना० तिवारी** : क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** दिनांक 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमारी शांति नायडू जैसे भारत-मूलक लोग, जो कि दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे, इस बीच रिहा कर दिये गये हैं;

(ख) अब तक कितने लोग जेल से मुक्त किये गये हैं तथा कितने लोग अभी तक जेल में हैं तथा कितने लोगों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है; और

(ग) क्या जुलाई, 1969 के बाद कुछ और गिरफ्तारियां की गई हैं, और यदि हां, तो कितनी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जहां तक सरकार को मालूम है दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस वर्ष के शुरू में आतंकवादी अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था उनमें से किसी को रिहा नहीं किया है, जिनमें कुमारी शांति नायडू भी शामिल हैं। कैद व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या तो नहीं मालूम लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि आतंकवादी अधिनियम के अन्तर्गत कथित अपराधों के लिए करीब 12 से 15 व्यक्ति कैद की सजा भुगत रहे है। इसके अलावा इस वर्ष जनवरी और जुलाई के बीच कोई 40 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है जिसमें से अभी तक करीब 22 व्यक्तियों पर तो आरोप लगाए जा चुके हैं और बाकी पर अभी मुकद्दमा चलाया जाना है।

(ग) दुर्भाग्य से इस बारे में सूचना मुलभ नहीं है कि जुलाई 1969 के बाद भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने आतंकवादी अधिनियम के अंतर्गत कोई और गिरफ्तारियां की हैं या नहीं।

Indian efforts to solve Czechoslovakia Issue

1509. SHRI YAJNA DATT SHARMA :
SHRI JAI SINGH :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4148 on the 20th August, 1969 and also to his statement on the 8th April, 1969 and state :

(a) the efforts which have been made or whether India is in contact with U S S.R. and Czechoslovakia since the Prime Minister explained India's stand in the House on the 21st August, 1969 to extend sympathy and full support to Czechoslovakia in her struggle against Soviet intervention in her internal affairs, both being Sovereign States;

(b) whether this subject was discussed with the U.S.S R. Prime Minister's meetings and his meetings with him on several occasions during this year also with the subject of Kashmir;

(c) if so, with what results; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) In view of the very friendly relations that we have with the Governments of USSR and Czechoslavakia, the Govt. of India is always in contact with them on matters of mutual interest.

As Hon'ble Members may be aware, certain agreements for cooperation were arrived at last month between these two sovereign governments regulating their inter relations.

(b) to (d) . These discussions were of a confidential nature and it is not the practice to disclose the contents.

Targets achieved by STC

1510. SHRI LUTFAL HAQUE : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the weekly returns of the State Trading Corporation for the period between July and October, 1969 show declining achievements in the business compared to the targets set by the Corporation and its Chairman; and

(b) if so, the reasons behind the failure to improve the trading volume and exports of sophisticated goods ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) . The targets of exports and imports have been fixed by the State Trading Corporation on annual basis which take into account seasonal factors both in the matter of exports and imports. The weekly returns, therefore, do not indicate the overal achievements in the business of the Corporation. Every effort is being made by the Corporation to increase exports and imports to fulfil the targets for the current year.

Chinese Atomic Plant in Tibet

1511. SHRI V. NARASIMHA RAO :
SHRI J. K. CHOUDHURY :
SHRI D. N. PATODIA :
SHRI SHASHI BHUSHAN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether China is setting up its new headquarter of atomic plant in Tibet;

(b) if so, whether any protest has been made by Government in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The Government of India have no precise information on this.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Taking-over of Pakistan-occupied Kashmir Administration by Pak. Government

1512. SHRI V. NARASIMHA RAO :
SHRI C. K. BHATTACHARYYA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state ;

(a) whether Government have since examined the legal aspect of take-over of the Pakistan-occupied Kashmir administration directly by Rawalpindi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any formal protest has been sent to Pakistan in this connection ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c). Pakistan occupied Kashmir has throughout been under Pakistan's illegal military occupation and the situation continues. Recently a new puppet so-called President was installed and the old one removed. We do not take cognizance of such illegal measures.

प्रधान मन्त्री के अधीन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

1513. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके नियन्त्रण में कार्य कर रहे मन्त्रालयों/विभागों के अधीन कार्यालयों तथा हिन्दी भाषी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र के स्वायत्तशासी निकायों की कुल संख्या क्या है, और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) उनमें से कितने कार्यालयों में सारा काम हिन्दी में किया जाता है तथा शेष कार्यालयों में भी सरकार द्वारा सम्भवतः कब तक सारा कम हिन्दी में करना आरम्भ कर दिया जायेगा;

(ग) उनके अधीन कार्य कर रहे मंत्रालयों/विभागों का विचार कब तक इन कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार आरम्भ कर देने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके अधीन कार्य कर रहे कार्यालयों तथा उपरोक्त (क) भाग में वर्णित राज्यों के स्वायत्तशासी निकायों में से प्रत्येक में एक-एक हिन्दी टंकण-कर्ता (टाईपिस्ट) तथा अनुवादक नियुक्त करने का है ताकि कार्य हिन्दी में आरम्भ किया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं तो, हिन्दी में होने वाले कार्य के किस प्रकार किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

China-Trained Nagas Crossing over to India

1514. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 500 China-trained Naga hostiles crossed into India through Ukhrul Sub-Division of Manipur from Upper Burma during August-September, 1969; and

(b) if so, the estimated number of Nagas entered into India and the action taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Government are aware of groups of Naga underground personnel lurking near the India-Burma border trying to sneak into India, but no organised gangs have entered Indian territory during August-September, 1969.

(b) Does not arise.

Manufacture of Tanks by Ordnance Factories

1515. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that manufacture of heavy tanks by Ordnance Factories

in India is not up to the desired requirement and standard;

(b) whether there is any proposal to expand and modernise with sophisticated equipments any Ordnance Factory to the desired standard as per requirement of heavy tanks by our Armed Forces; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Indigenous manufacture has been undertaken in respect of medium tanks. These tanks are of the required standard and compare favourably with similar kind in the whole world. Production is increasing steadily and is expected to meet the desired requirement.

(b) At present there is no proposal to undertake indigenous manufacture of Heavy tanks.

(c) Does not arise.

'Al Fatah' Cells in India and Kashmir

1516. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the three members of the 'Al Fatah' visiting India and the reasons why these Arab revolutionaries were allowed to visit India;

(b) whether it is a fact that these 'Al Fatah' members propose to establish their cells in India and Kashmir to help Kashmiri Muslims in their fight against India;

(c) whether it is also a fact that Government have permitted to allow the 'Al Fatah' to open its "Information Office" in India; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The members of the Delegation were : Mr. Mohamed Abou Mizar, Mr. Mounir Assal and Miss Gihane El Helou, the Delegation visited India at the invitation of the Indian Association for Afro-Asian Solidarity, a non-official organisation.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Evacuation Notices served on Minorities in West Pakistan

1517. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 30 Hindu landlords of Mirpur Khas district of West Pakistan have been declared "illegal occupants" and served with notices to show cause why they should not be evacuated from Pakistan immediately;

(b) whether it is also a fact that similar notices have been served upon the Hindu residents of Hyderabad and Sukkur with a view to throw them out of Pakistan; and

(c) the total number of Hindus in West Pakistan who are under continuous pressure to leave West Pakistan and the steps taken by Government to help them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government has not received any such information.

(c) The Government is aware of the unhappy lot of Hindus in Pakistan and have repeatedly reminded that Government of their obligation towards the minorities. According to the 1961 census of Pakistan there were 621,805 Hindus in West Pakistan. The exact number of Hindus living there at present is not known.

Production of Cotton Textiles

1518. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the targets laid for production of cotton textiles, cloth and yarn, during the

Fourth Plan period to meet the internal demand and exports;

(b) the quantities fixed for the organised sector, powerlooms and handlooms; and

(c) the policy of Government for licensing new units in order to fulfil the targets ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The target for production of cotton textiles (including blends) by the end of the Fourth Plan period (1973-74) is estimated at 9350 million meters per annum. Out of this, 8550 million metres are for internal consumption and 800 million metres as the equivalent of exports in all forms. The target of production of yarn is estimated at 1150 million kgs.

(b) No quantities have so far beed fixed separately for the organised sector, powerlooms and handlooms. However, the question of fixing targets for the various sectors is being reviewed.

(c) The existing policy of the Government not to allow new units is being reviewed in the context of the need to fulfil the targets.

Closed Textile Mills in Small Towns

1519. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of closed textile mills in small towns with a population of one lakh to two and half lakhs;

(b) the number of direct employees that own out of jobs as a result thereof;

(c) the steps so far taken to reopen the mills; and

(d) the number of mills considered fit for scrapping in which case the steps taken to find alternate employment to the workers affected thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Five.

(b) 4131 workers were on roll in these mills.

(c) One mill has already been investigated under the Industries (Development and Regulation) Act and the report is under examination. The cases of remaining mills are being considered in consultation with the Governments concerned.

(d) Does not arise.

Items of Exports and Imports handled by S. T. C. and M. M. T. C.

1520. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the lists of items exclusively channelled so far through the State Trading Corporation and Minerals and Metals, Trading Corporation either for export or import during the last three years ;

(b) whether transactions are negotiated in all cases on most favourable terms without any other consideration ; and

(c) the percentage of profit earned by those concerns on each transaction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) A statement is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See No.* L. T. 2113/69]

(b) Yes, Sir.

(c) The total net profit earned by the S. T. C. and M. M. T. C. in the last three years, were as follows :

Year	S. T. C. (Rs. crores)	M. M. T. C. (Rs. crores)
1966-67	0.9	4.70
1967-68	2.3	1.26
1968-69	4.00	Not yet available.

It is not in the business interest of the Corporations to disclose profits transaction-wise.

Closer Relation with Vietcong

1521. SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to his interview with the press representatives at Dum Dum Air port as reported in the Statesment, Culcutta of the 9th September, 1969 that India would like to have close contacts with the Provisional Revolutionary Government set up by the N. L. F. in South Vietnam and state :

(a) whether policy of Government has been finalised ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) (a)and(b). The Provisional Revolutionary Government set up by the National Liberation Fornt in South Vietnam is a vital factor in the political situation of Vietnam. It will be useful for India, which has special responsiblities in Vietnam to keep in close touch with all the factors including Provisional Revolutionary Government.

Prime Minister's meeting with Rebel Naga Leader at Kohima

1522. SHRI C.K. BHATTACHARYYA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the rebel Naga underground leader met her at Kohima and submitted a memorandum ; and

(b) if so, the details of the talks and the memorandum ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). Shri Scato Swu, a leader of the anti-Phizo faction in the Underground Organisation, called on the Prime Minister at Kohima on the 25th September, 1969 and presented to her a memorandum in which he made an appeal for the resumption of political talks.

Government have made their position clear on the question of resumption of talks, on serveral occasions in the past. A solution of Naga problem was reached in 1960 and Government do not intend holding any further political talks with the Underground Nagas.

Nagas as Indian citizens may however, make suggestions for the betterment of Nagaland to the Governor and the Government of Nagaland.

Marriage of a Militry Officer with the Daughter of Shri Z. A. Phizo

1523. SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Captain Somprasad Anand has married Shrimati Tullu Raisinno daughter of Mr. Z. A. Phizo, the Naga underground leader ;

(b) whether the permission of Government was sought for the marriage ;

(c) why it was necessary to have this marriage celebrated secretly and in Punjab ; and

(d) whether such marriages between Indian Army Personnel and Naga girls are encouraged or allowed?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, but she is an Indian national.

(b) to (d). No permission or interference from Government is called for when Army personnel marry Indian nationals.

पूर्व जर्मनी में भारतीय वीजा जारी करने के अधिकार

1524. श्री शशी भूषण : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में पूर्व जर्मनी में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को वीजा जारी करने के अधिकार देने का है ;

(ख) इस समय पूर्व जर्मनी में कितने भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं ; और

(ग) सरकार का विचार पूर्व जर्मनी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को बीजा जारी करने के अधिकार कब तक देने का है ताकि जर्मनी के छात्र तथा अन्य लोग भारत आ सकें ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ग) . जर्मन लोक गणराज्य में आज कोई भारतीय कौंसलावास नहीं हैं । जर्मन लोक गणराज्य में जो भी बीजा का काम होता है वह प्राग स्थित भारतीय राजदूतावास के बीजा अनुभाग द्वारा किया जाता है । इस प्रबन्ध को सुधारने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) 45.

इसरायल के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रविरोधी तत्वों को प्रोत्साहन

1525. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा रब्बात सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में इसरायल के प्रतिनिधियों द्वारा यहां दूषित राजनैतिक वातावरण पैदा करने हेतु भारत में राष्ट्रविरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है ; तथा इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बाटा शू कम्पनी द्वारा निर्यात के लिए निर्मित जूतों के दाम

1526. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बाटा शू कम्पनी जिस जूते की जोड़ी को भारत में 45 रुपये में बेचती है निर्यात करने पर विदेशों में इस कम्पनी की दुकानों पर उसे दुगने दामों पर बेचा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशों में इस कम्पनी की दुकानों पर भेजी जाने वाली जूते की जोड़ी का निर्यात उस मूल्य के आधे दामों पर किया जाता है जिस पर वह भारत स्थित दुकानों पर बेची जाती है;

(ग) क्या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की इस नयी प्रक्रिया की जांच करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत से निर्यातित मदों के निर्यात मूल्य प्रायः देश में उनके बिक्री मूल्य से अपेक्षाकृत कम होते हैं ।

(ग) तथा (घ) . प्रश्न नहीं उठते ।

Steps to check Inflow of Chinese Arms to Nagas

1527. DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether China is still helping rebel Nagas with arms and ammunition ; and

(b) if so, the steps taken by Government to stop this inflow of arms ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) After the entry into India of the groups

led by Mowu Angami and Issac Swu in March last with Chinese arms and ammunition, there has been no further report of the underground Nagas having received any fresh consignment of arms and ammunition from China. The Chinese propaganda organs have, however, continued to incite the Underground Nagas, against the Government.

(b) The Security Forces and Intelligence agencies in the area are on the alert to foil any attempts to bring in weapons and ammunition from across the border.

Steps to check Pak help to Rebel Nagas

1528. DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Pakistan is still helping rebel Nagas to fight against India with arms ammunition ; and

(b) if so, the steps taken to check this activity ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) . Yes, Sir, Pakistan is still trying to do so. But Security Forces have been vigilant and have been able to foil repeated attempts since August, 1968 to send gangs Pakistan for arms and training.

भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तानी और चीनी सेनाओं का जमाव

1529. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री तुलसीदास जाधव :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान तथा भारत चीन सीमाओं पर पाकिस्तानी और चीनी सेनाओं का जमाव है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उनके सम्बन्ध में अन्य विवरण क्या है ; और

(घ) भविष्य में होने वाले किसी खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). चीन ने तिब्बत में लगभग 1,30,000 से 1,50,200 सैनिक तैनात कर रखे है । पाकिस्तान में भारत विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में 12 इन्फैन्टरी डिवीजन और 2 बख्तरबन्द डिवीजन के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अर्ध सैनिक और अन्य अनियमित सैनिक तैनात कर रखे हैं । सीमा के उस पार पाकिस्तानी और चीनी सैनिकों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर नही आया है । हमारी रक्षात्मक तैयारियां देश को होने वाले खतरों को ध्यान में रख कर की जाती हैं ।

Visit by Russian Warships to the Indian Ports

1530. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Russian Warships visited the Indian Ports and Naval bases in August, September and October, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that U. S. S. R. is trying to infiltrate into the Indian Ocean ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Government are aware of the fact that vessels of the U. S. S. R.

and other Powers are sailing in the Indian Ocean. While Government would like the Indian Ocean area to remain free of tensions, we can not ignore the international practice according to which the other Powers have freedom to use the high seas.

Analysis made by Planning Commission In Development of Backward State

1531. SHRI D. N. PATODIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an analysis made by the Planning Commission confirm that massive investment in public sector has not contributed to the general industrial development of the 'backward' States during the fifteen years from 1951 onwards ;

(b) whether it is also a fact that Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Kerala, Orissa, Assam, Rajasthan and Jammu & Kashmir continue to be backward and some of the States have in fact, lost their earlier position;

(c) if so, the cause far the fall in the progress in these States and what particular measures have been envisaged by Government to deal with the situation during the Fourth Plan period ;

(d) whether any State-wise analysis has been made to find out whether the public sector investments in the States referred to above were not done with proper forethought or for the causes of their failure; and

(e) if so, whether Government propose to lay copies thereof on the Table ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) No, Sir. In fact, the location of public sector projects in backward regions has contributed to the industrial development of these States.

(b) Over the Plan periods, more industries have been set up in all these States, but some States have progressed faster than others.

(c) In order to accelerate the development of industries in relatively backward areas, the Committee of Chief Ministers of the National Development Council have taken certain decisions in September 1969. They are:--

(i) the financial institutions should evolve a liberalised lending policy and formulate incentive schemes for promoting and attracting industries in the backward areas. The concessions and incentives for financing industries in selected backward areas should be made available in all States and Union Territories.

(ii) the Planning Commission may settle the criteria to be adopted for selection of industrially backward districts in the States and Union Territories, in consultation with the financial institutions and the State Governments ; and

(iii) the Centeral Government may give an outright grant or subsidy amounting to one tenth of the fixed capital investment of new units having a total fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each in two selected districts each of the 9 States indentified as industrially backward (viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh) and one district each of other States Union territories; schemes and projects for new units involving fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs may be considered on merit. The Planning Commission may also work out what should be the unit of a district.

(d) and (e). The implied suggestion that the public sector investments were made without proper forethought is not correct.

Indian Immigrants in Clash with Dacca Natives

1532. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI SAMAR GUHA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the according to news items appearing in the Statesman of the 2nd November, 1969, severe clashes had taken place in Dacca between the native Bengalis and the Indian immigrants;

(b) whether Government have obtained the details and the causes thereof; and

(c) the loss of human life involved particularly of the persons of the Indian origin and the reaction of Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c). According to reports, clashes took place in some areas of Dacca district between two groups of Pakistani nationals-Bengali Muslims and non-Bengali Muslims, in the first week of November, 1969. The cause of riots was the demands of non Bengali Muslims for voters' forms and electrol rolls to be printed in Urdu also, besides Bengali. Pakistani papers have reported that 10 persons died and 143 were injured, including 40 policemen, in these clashes. No Indian nationals were involved.

Increase in Armed strength of Pakistan

1533. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :
DR. SUSHILA NAYAR :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Pakistan have started making recruitment on a massive scale;

(b) whether with the increase in the armed strength of Pakistan, there has been any increase in the armed intrusions by the Pakistan army into our borders; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) A large number of advertisements have appeared in the newspapers of West Pakistan for recruiting Engineers, Doctors and Commissioned Officers in the Pakistan Armed Forces. The age limit for the recruitment has also been liberalised.

(b) and (c). There has been no significant change in the pattern of Pakistani activities. Our Security Forces continue to remain vigilant on the border.

Supply of Radar Epuipment by U. S. A.

1535. SHRI DEVEN SEN :
SHRI R. BARUA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether India have accepted the U S. offer for radar system for the country;

(b) if so, whether the Indian enterprises like the Indian Atomic Energy establishment and Bharat Electronics have been allowed to do the job; and

(c) the total cost involved in providing adequate radar cover for the entire country ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) A firm letter of offer for a limited radar cover is still awaited.

(b) Proposals from the Department of Atomic Energy and Bharat Electronics Limited have been received and are under examination by an Evaluation Committee. In all the three proposals, collaboration with foreign firms and some indigenous production would be involved.

(c) Over Rs. 200 crores.

Shortage of work in Clothing Factories

1536 SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is still shortage of work in clothing factories, namely, Shahjahanpur Parachute Factory, Kanpur, Government Harness and Saddlery Factory, Kanpur and Clothing Factory, Avadi;

(b) if so, whether this is due to giving work to various contractors at the cost of these factories; and

(c) the steps taken by Government to provide adequate work in these factories ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir. Particularly in the clothing factories.

(b) No, Sir. As the bulk of the deficiencies in clothing was met in, 1963 and 1964, the requirements of the Services for subsequent years have been considerably less and consequently there has been a reduction in the workload of the clothing factories.

(c) Action has been taken to diversify production in clothing factories by undertaking manufacture of items like tents, durries, ground-sheets etc. for the Services. To provide workload to the clothing factories efforts have been made and are still being made to obtain orders from other Central Government Departments for uniforms and garments. Effort is also being made to undertake the manufacture of civilian garments for sale in India and also for export.

Industrial workers not being given Earned Leave because of their participation in the 19th September, 1968 strike

1537. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the industrial workers who participated in the 19th September, 1968 strike are not getting their earned leave because of this participation;

(b) if so, whether orders have since been issued allowing them leave; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Yes, Sir; in respect of their service prior to 19th September, 1968.

(b) and (c). The matter is under the consideration of Government.

मन्त्रियों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

1538. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों में मन्त्रियों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कोई सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, आणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). प्रशासन सुधार आयोग ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के आकार के विषय पर अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं, जिसका शीर्षक है-'भारत सरकार की मशीनरी और उसके कार्य की विधियां'। सरकार इस रिपोर्ट पर अभी विचार कर रही है। राज्यों में मंत्रियों की संख्या का जहां तक सम्बन्ध है, आयोग ने 'राज्य प्रशासन' पर अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश की है, उस पर राज्य सरकारों को विचार करना है। आयोग ने यह रिपोर्ट इसी महीने में पेश की है।

भारतीयों द्वारा नेपाल में पटसन मिलों की स्थापना

1539. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैदेशिक** व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की तुलना में नेपाल में कम कर लगाये जाने के कारण नेपाल से भारत में आयात किये गये पटसन उत्पाद और पटसन मिश्रित उत्पाद नेपाल में बहुत सस्ते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में काम करने वाले व्यापारियों ने अपना व्यापार भारत के स्थान पर नेपाल में आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई पूर्वोपाय किये गये हैं ताकि भारतीय व्यापारियों को कोई कठिनाई नहीं हो ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Sale proceeds of Gandhi Medals in Japan

1540. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the proceeds from the sale of silver, gold and platimum Gandhi medals in Japan which have been donated to India by the Japan World Peace Society; and

(b) the names of relief projects in India to be benefited by the above donations ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) . The sale of medals is going on and will continue for a year. The Government of India understand that at the end of the sale the organisers plan to donate the proceeds to Indian relief works. Further detailed information is being obtained and will be laid on the Table of the House.

Joint Ventures in Latin American Countries

1541. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have explored the possibilities of further setting up joint ventures in Latin American countries;

(b) if so, with what results; and

(c) whether Government are considering modification of schemes governing investment abroad ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). An Indian Economic and Trade delegation toured Latin America in April-May, 1969 to explore the possibilities of expanding econonomic, commercial, industrial and technical collaboration between India and these countries. The recommendations made by the delegations are under examination in consultation with the various Ministries of the Government of India.

Canteen Stores Department (India)

1542. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some retired senior officials of the Canteen Stores Department (India), had taken up services immediately on retirement, with certain manufacturing firms supplying goods to the Canteen Stores Department (India);

(b) if so, whether Government have enquired into the *bona-fides* of the officers who have been in contact with them prior to their retirement, and the extent to which such dealings were detrimental to the interest of the Organisation; and

(c) whether Government have made any policy to intervene in such cases so that high officials do not join any suppliers'

organisation soon after their ratirement, at least for 5 years ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) Only one such case has come to the notice of the Government and this pertained to a civilian of the status of a Depot Manager who retired in 1966.

(b) Nothing has come to the notice of Government to suspect the *bona-fides* on the dealings of the officer in question.

(c) According the existing orders, service officers of the rank of Colonel and above are debarred from taking up commercial employment within 2 years of the date of retirement without prior Government permission, and these restrictions are considered adequate. Since there are at present no civilians in the Department equivalent to the rank of Colonel and above, and also since the civilian posts are non-pensionable, the question of extending similar restrictions to the civilian officers of the Department does not arise.

Reduction in Indian Army Strength

1543. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Army strength has been reduced;

(b) whether it has been considered after receiving the "Teeth-to-tail" ratio; and

(c) if so, the details regarding the last three years experience report ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

Indo Bulgarian Trade

1544. SHRI N. SHIVAPPA :
SHRI S. R. DAMANI :
SHRI N. R. LASKAR :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India and Bulgaria have signed a protocol to double the trade between the two countries;

(b) the main items of import from Bulgaria and the nature of items which India propose to export; and

(c) the estimate of volume and amount involved in the exports ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . A Bulgarian Trade Delegation recently visited India. On the conclusion of the trade talks, a Protocol was signed on 13. 10 1969, envisaging that the trade turnover between the two countries during 1970 would be of the order of Rs. 440 million. Major items of export from India to Bulgaria will be rolled steel products, wire ropes, finished and semi-finished leather, forgings and castings, knitting machines, tipper trucks and other engineering goods, drugs and pharmaceuticals, aluminium foils etc., in addition to traditional commodities. Principal items of import from Bulgaria into India will be urea, tractors, drugs and pharmaceuticals, special steels and rolled steel products, caprolactum and other industrial raw materials, non-ferrous metals and miscellaneous items of machinery. Copies of this Protocol have been made available to the Parliament Library.

Import of Industrial Raw Materials

1545. SHRI M. SUDARSANAM : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state ;

(a) the quantity and value of industrial raw materials imported into India during the period from the 1st April to 31st September, 1969;

(b) how much of it is already being canalised through the State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation; and

(c) what is the break-up ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The total value of imports of raw materials and intermediates during April-July 1969 was Rs. 17,258 lakhs. Figures for subsequent months are not yet available.

(b) and (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Emoluments of Jawans in Forward Areas

1546. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the basic pay and total of other emoluments to the form of various kinds of allowances paid to the jawans serving in the various sectors of India in the forward areas; and

(b) how they compare with the jawans of the Border Security Force (Police) serving in forward areas ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) The information is given in Appendix 'B' (pages 133 to 139) to the Annual Report of the Ministry of Defence for the year 1968-69.

(b) According to calculations made, ordinarily, the emoluments along with rations and other concessions in kind received by the Army Jawans exceed in value the corresponding emoluments, rations and concessions in kind received by personnel of the BSF.

Security of Service for Staff Working in General Reserve Engineering Force

1547. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff of the General Reserve Engineering Force is employed on an agreement basis for three years and thereafter renewed yearly;

(b) whether it is also a fact that this arrangement has created much dissatisfaction among them and they are not able to put their wholehearted attention due to the insecurity of their tenure of service; and

(c) if so, the steps which Government propose to take to make them permanent for the sake of efficiency in work ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH): (a)to(c). Initially the General Reserve Engineer Force was intended to be a purely temporary Organisation The period of service of its employees was limited to three years and renewed yearly thereafter. To provide greater sense of security amongst the General Reserve Engineer Force employees and increase their efficiency, a permanent nucleas has been created in the Force and their terms and conditions have been revised. Othet personnel in the General Reserve Engineer Force have now been made eligible for quasipermanency after rendering three years of service.

Export of Woollen Hosiery Goods from India

1548. SHRI MUHAMMAD SHERIEF : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Canada will be importing woollen hosiery from India for the first time this year;

(b) if so, the value of the orders placed; and

(c) the approximate foreign exchange to be earned by Government in this respect ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir. There were some exports of woollen hosiery goods to Canada in 1968-69.

(b) and (c) . Do not arise.

Revival of N.C.C. in Tamil Nadu

1549. SHRI MUHAMMAD SHERIEF :
SHRI HEM RAJ :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Tamil Nadu Government have planed to revive N C C. in the State; and

(b) if so, the details of the proposals which have been accepted by Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) NCC Training in Tamil Nadu was received in September 1969.

(b) The following formula has been accepted for revival of N. C C. in Tamil Nadu :-

(a) (i) Cadets will be trained by means of English Words of command;

(ii) Hindi Equivalent will be taught so that Cadets would be able to participate efficiency in parades in either language; and

(iii) Participation in the NCC will be on a voluntary basis.

इसराइलियों पर अरब देशों में जासूसी करने के बारे में लगाये गये आरोप लगाने के सम्बन्ध में समद सदस्यों द्वारा ज्ञापन

1550. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदसदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वे मानवता के नाम पर प्रयत्न करें ताकि उन इसराइलियों के जीवन बच सकें जिनको अरब देशों में जासूसी करने के आरोप में फांसी दी जानी है; और

(ख) प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। लेकिन इसमें ईराक् के यहूदियों का उल्लेख है इसराइलियों का नहीं।

(ख) चूंकि यह ईराक् का आंतरिक मामला है, इसलिए भारत सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करना वांछनीय नहीं समझती।

तिब्बती क्रांतिकारी युवकों के साथ सहयोग

1551. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फारमूसा समाचार एजेंसी के अनुसार स्वतन्त्रता प्रेमी तिब्बती युवकों ने तिब्बत की स्वतन्त्रता के लिए चीन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह आरम्भ कर दिया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सहयोग देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं, किन्तु सरकार को कोई प्रत्यक्ष या प्रामाणिक सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Theft of Explosives from Military Wagons of 6 UP Punjab Mail

1552. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the incident of theft of bombs and explosives from the military wagons of 6 UP Punjab Mail running between Harda and Bhusaval on the night of 22nd August, 1969;

(b) the details of the incident; and

(c) the steps taken by Government to detect the culprits and to punish them ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b).

There was no theft of bombs and explosives from the military wagons of 6 UP Punjab Mail running between Harda and Bhusaval on the night of 22nd August, 1969. However, one of the wagons in a special train proceeding from Pulgaon to Pathankot on 20th August, 1969 was found with one of its doors open at Khirkiya Station near Bhusaval on the morning of 21st August, 1969. On checking, one package containing live ammunition was found missing. This was subsequently recovered by the police.

(c) Some persons who have admitted the theft have been arrested and the police have registered a case against the persons concerned.

Issue of Pakhtoonistan in U.N.O.

1553. SHRI J. K. CHOWDHARY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Afghanistan raised the issue of Pakhtoonistan in the U.N. General Assembly and called on Pakistan to solve the problem on the basis of the right of Pakhtoons for self-determination; and

(b) the names of the countries who supported the issue ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir; this matter was referred to by Afghanistan in its statement in the General Debate.

(b) The Indian representative also referred to this matter in the General Assembly. No other country supported it.

Turning down of request from an Indian Student to stay in Guyana

1554. SHRI J. K. CHOWDHARY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Guyana Government turned down the request of Dr. R. Shrivastava, a Delhi Graduate to stay there for two years to work as a teacher at the Gandhi Educational Institute;

(b) if so, the reasons therefor and whether any enquiry was made into the affairs; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). Details of the case are being collected.

(c) The case will be considered when the facts of the case are received.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि

1555. **श्री विभूति मिश्र :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अगस्त 1947 से अब तक देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, वह आशानुकूल नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों मे भी प्रगति आशा के अनुसार नही हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान (1) अगस्त, 1966 में संसद को प्रस्तुत चौथी पचवर्षीय योजना–प्रारम्भिक रूपरेखा के अध्याय –1 और (2) ससद को मार्च, 1969 में प्रस्तुत चौथी पचवर्षीय योजना–1969–74-प्रारूप के अध्याय–1 में 1950 के बाद के विकास प्रयत्नों की प्रगति की समीक्षा की ओर दिलाया जाता है । यह सही है कि जो प्राप्ति हुई है वह आवश्यकताओं और संभावनाओं से कम है । परन्तु इस बात से इस तथ्य की उपेक्षा

नहीं की जा सकती कि जो अर्थ-व्यवस्था योजना पद्धति को अपनाने से पूर्व कई दशकों से एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकसित हो रही थी, वह 1950–51 से इस दर की अपेक्षा तिगुनी दर से विकसित हो रही है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–70 से 19 3–74 तक) को तैयार करने में अब तक जो सफलता और असफलतायें आई, अर्थ व्यवस्था में निरन्तर चलने वाली जो प्रवृत्तियां दृष्टिगत हुई और हाल के वर्षों में जो विशिष्ट अनुभव प्राप्त हुए उन्हें ध्यान में रखा जा रहा है।

Markets for Indian Handicrafts

1556. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is proposed to implement a five-point programme to capture more markets for Indian handicrafts;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when is it likely to be introduced ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c). A number of schemes and programmes are being implemented. The more important amongst these are :

(1) Provision has been made for grant of import replenishment licences to Registered Exporters.

(2) Design centres have been set up under All India Handicrafts Board at a number of places in the country to develop new export-oriented designs in handicrafts and impart training to young craftsmen.

(3) A scheme for supply of tools and equipment to craftsmen is in force.

(4) Credit facilities to artisans are given for raw materials through emporia.

(5) Exhibitions for publicity and promotion of handicrafts are held in India and abroad.

(6) Participation in trade fairs and exhibitions held abroad is organised.

(7) Showrooms and shops in foreign countries have been opened.

(8) Trade enquiries from Indian exporters and foreign importers are attended to and necessary information is provided to them.

(9) Indian exporters are given assistance in obtaining export credit.

(10) Credit facilities have been extended by banks to craftsmen.

In addition to the schemes mentioned above, the following steps are also proposed to be taken during the current and next years in order to capture more markets for Indian handicrafts :

(1) Conducting of market surveys for handicrafts in East European countries;

(2) Production and display of colour documentary films on handicrafts for foreign publicity;

(3) Sending abroad of study-*cum*-sales teams;

(4) Sending craftsmen for training in costume jewellery; and

(5) Bringing out of a directory of handicrafts exporters and importers by the All India Handicrafts Board in the near future to help establish trade contracts.

'रेडियो पोस एण्ड प्रांग्रेस" और रेडियो पॉकिंग का प्रसारण

1557. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री क० सुन्दर लाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो मास्को, रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस और रेडियो पीकिंग ने अगस्त 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों तथा नेताओं की आलोचना की थी;

(ख) क्या सरकार इसे भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप समझती है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है।

Inundation of 10,000 Acres of Paddy Land in West Bengal by Pakistan Bund Cut

1558. SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI R. BARUA :
SHRI N. R. LASKAR :
DR. SUSHILA NAYAR :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 4,000 villages were affected and 10,000 acres of paddy land was inundated as a result of the floods caused by a bund cut by Pakistan across the Indian border in 24 Parganas District in West Bengal;

(b) whether it is also a fact that the Government of West Bengal have asked Government to take up the matter with the Pakistan Government;

(c) if so, the estimated loss suffered as a result thereof;

(d) whether Government have taken up the matter with Government of Pakistan and had asked for compensation; and

(e) if so, the result thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Sixteen villages were affected as a result of the floods caused by a bund cut by Pakistan across the Indian border in 24-Parganas District in West Bengal.

(b) Yes, Sir.

(c) The loss is estimated as follows :

Paddy valued at Rs. 22,49,600

414 houses valued at Rs. 82,000.

(d) The Government have informed Pakistan that they reserve the right to claim compensation for the damage resulting from the action of the East Pakistan authorities.

(e) No reply has yet been received from the Government of Pakistan.

Report of Trade Delegation to Latin American Countries

1559. SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI MAYAVAN :
SHRI R. BARUA :
SHRI ONKAR LAL BERWA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Economic and Trade delegation which visited Latin American countries in April-May this year has submitted its report to Government;

(b) if so, the salient features of the assessment made by the team in regard to the prospects of expansion of India's trade and setting up of joint ventures; and

(c) the decision taken by Government, if any, in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) A summary of the conclusions and recommendations made by the delegation is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2114/69]

(c) The recommendations of the delegation are under examination in consultation with the various Ministries of the Government of India. Copies of the Report have been placed in the Parliament Library.

Production of Jute, Cotton, Woollen Worsted Yarn and Silk Mills

1560. SHRI ABDUL GHANI DAR : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the production of Jute mills, cotton mills, woollen worsted yarn mills, shoddy yarn mills, and silk mills in the years 1961, 1966, 1968 and 1969, and

(b) whether the targets were achieved and if so, the percentage effected in these years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scheme to save Foreign exchange by Promoting Tobacco Industry

1561. SHRI ABDUL GHANI DAR : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to save foreign exchange by promoting tobacco industry in the country;

(b) if so, how much foreign exchange is likely to be saved annually; and

(c) the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) India is one of the biggest producers and exporters of tobacco in the world. However, small quantity of tobacco is being imported as per details given below for the purpose of maintaining the required blend for producing high class cigarettes. Tobacco Export Promotion Council has advised the importers that import of tobacco in future will be allowed against export of cigarettes produced in India.

	Qty. (in tonnes)	(Value in Rs.)
1966–67	110	23,67,366
1967–68	630	1,32,82,229
1968–69	334	44,14,590

Talks with Israel

1562. SHRI ABDUL GHANI DAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Israel Government is discussing the recent differences between Israel and Arab countries with his Ministry; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Naval Base at Cochin

1563. SHRI N. SREEKANTAN NAIR : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the stage at which the expansion of the Naval Base at Cochin stands; and

(b) whether any suggestions have come from the Kerala Government in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) The development of the Cochin Naval Base is proceeding according to plan.

(b) No, Sir.

Facilities offered to Private Sector in Defence Production

1564. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the steps taken by Government after Chinese aggression in 1962 and Indo-Pak conflict in 1965 to offer facilities and incentives to the private sector to participate in the defence production to achieve sufficiency; and

(b) the results achieved so far ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) The following steps have been taken by Government to offer facilities and incentives to the private sector to participate in meeting the Defence requirements to achieve sufficiency :-

(i) A separate Department of Defence Supplies has been constituted to undertake the work of import substitution.

(ii) Sample rooms have been set up at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras where samples of various imported items have been displayed Intending manufacturers visit these sample rooms where guidance is provided by technical personnel.

(iii) Help is afforded to the firms, on which orders are placed, for the procurement of controlled or scarce raw materials.

(iv) Import licences are granted for getting necessary balancing equipment, if necessary.

(v) On account payment facility is given for the purchase of raw materials and components.

(vi) Where development costs are heavy or where the purchaser has to undertake several experiments and trials to meet specifications, such expenses are reimbursed by the Government.

(vii) Manufacturers who develop an item are given order for 100% of the first year's requirement, 80% of the requirement of the second year and substantial portion of the requirements in subsequent years

(b) Orders have been placed so far for items totalling to a value of about Rs. 34 crores and production has been established in the private sector of some very critical and sophisticated Defence items.

सैनिक प्रशिक्षण शिविर से गोली चलने के कारण महरौली खड के ग्रामवासियों को कठिनाइयां

1565 **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के महरौली खड में फतेहपुर, बेरी और यंग गांवों के निवासियों को सैनिक प्रशिक्षण शिविर से बारम्बार होने वाली गोली बारी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गोली-बारी के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति मारे गये हैं और घायल हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस कारण होने वाली मौतों के भय से इस क्षेत्र के निवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) फतेहपुर बेरी गांव के निवासियों को गोली बारी से कोई कठिनाई नहीं है लेकिन मांगर तथा कुछ अन्य गांवों के निवासियों को, जो कि चांदमारी क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हैं, कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गोलीबारी के समय सुरक्षा की दृष्टि से गांवों को खाली करना पड़ता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में खतरे के क्षेत्र से बाहर गोलियों के चले जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और एक व्यक्ति घायल हुआ । इसी समय के दौरान खतरे के क्षेत्र का उल्लंघन करने

और निसिद्ध क्षेत्र में आकर धातु के टुकड़े एकत्रित करने के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु ई और पांच व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार गोली बारी के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिये और मनुष्यों अथवा पशुओं को उस क्षेत्र से दूर रखने के लिए निम्नलिखित सुरक्षात्मक प्रबन्ध किए गए हैं :–

(1) खतरे के क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों को खाली करने के लिए सिविल अधिकारियों द्वारा पहले नोटिस जारी कर दिया जाता है ।

(2) गोली बारी केवल तभी शुरू की जाती है जबकि सिविल अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि गोलीबारी वाला क्षेत्र खाली हो चुका है ।

(3) गोलीबारी के दौरान लोगों को गोलीबारी के क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए स्थायी नोटिस-बोर्ड लगाए जाते हैं ।

(4) लोगों और जानवरों को रोकने के लिए लाल-झंडियों के साथ सन्तरी खड़े किये जाते हैं ।

(5) बिना फटे हुए गोलों का रिकार्ड रखा जाता है और प्रतिदिन गोली बारी के बाद उनकी खोज करके उनको नष्ट कर दिया जाता है ।

राजपूत रेजिमेंट में मुसलमान

1566. श्री शशि भूषण : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजपूत रेजिमैंट में कितने प्रतिशत मुसलमान भर्ती किये जाते हैं और उक्त रेजिमैंट में इस समय कितनी मुसलमान कम्पनियां हैं तथा इन कम्पनियों के कितने मुसलमान जवानों ने भारत पर चीनी आक्रमण के समय अपना जीवन बलिदान किया,

(ख) राजपूत रेजिमैंट की अल्पसंख्यकों वाली कम्पनियों के कितने जवानों को भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान वीरता और साहस के प्रदर्शन करने के लिए पदक दिये गये;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के जवान अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती किये जायें, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इनके आधार हर प्रत्येक भारतीय रेजिमेंट (तोपखाना) में मुसलमान, बौद्ध तथा ईसाई जवानों को भर्ती करने के लिये कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). राजपूत रेजिमैंट में मुसलमानों की एक कम्पनी की सख्या एक बटालियन की संख्या का 25 प्रतिशत है । मृतकों अथवा अर्जित पदकों के आकड़े समुदाय-वार अलग अलग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग), (घ) और (ङ). मुसलमानों, बौद्धों और ईसाइयों सहित सभी भारतीय नागरिक भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं बशर्ते कि वे निर्धारित शारीरिक और शैक्षिक स्तर के हो । इस दिशा में कोई विशेष व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

सेना में बौद्ध और ईसाई रेजिमेंट बनाना

1567. श्री शशि भूषण : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की जाति, सम्प्रदाय और धर्म के आधार पर जैसे सिक्ख, राजपूत और

जाट रेजमेंटों के समान सेना की रेजमेंट बनाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) जाट रेजमेंट में हरिजन युवकों का क्या स्थान है;

(ग) क्या सरकार का विचार धर्म के आधार पर सेना में बनी अन्य रेजमेंटों समान लद्दाख में बौद्ध रेजमेंट तथा अन्य स्थानों पर ईसाई रेजमेंट बनाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त बातों के आधार पर रेजमेंट बनाने की नीति को त्यागने तथा राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर इनकी स्थापना करने का है ताकि सरकार की धर्मनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण यहां पर भी हो ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). यद्यपि अभी तक कुछ रेजीमेंटों का नाम वर्ग के आधार पर है,तब भी सरकार की नीति सेना को दुबारा इस प्रकार संगठित करने की है, जिससे कि वर्ग-भेद को समाप्त किया जा सके। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार वर्ग-भेद से नई रेजीमेंटों की स्थापना करने के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है। जाट रेजीमेंट को छोड़ कर अन्य कई रेजीमेंटों और कोरों से हरिजन युवकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

Growth Rate Figures

1568. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the growth rate figures published in the World Bank atlas for the years 1961-67;

(b) the position of India as compared to the other developing countries;

(c) what is the annual increase growth rate; and

(d) whether it is a fact that it has very poor percentage of per capital income and if so, where the responsibility can be laid ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMITI INDIRA GANDHI) : (a) to (d). Government have seen the figure published in the World Bank Atlas for the period 1961-1967.

Full information about our achievements as well as our shortfalls, is contained in various documents which have been made available to the house from time to time, concerning our Plans, and the periodical Economic Surveys.

The House is aware of the severe economic set-back which we had to suffer during the period 1965 to 1967 as a result of unprecedented drought and industrial recession. The House is also familiar with the considerable recovery which we have made since especially in such fields as agricultural production.

Reduction in losses on account of Deterioration of Defence Stores

1571. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that by applying scientific technique of stores preservation, Government have been to reduce considerable the losses on account of deterioration of defence stores;

(b) if so, the amount saved during the last three years; and

(c) the further steps proposed to be taken to avoid any losses on this account ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) to (c). During the financial year 1951-52 loss due to deterioration of Service stores/equipment in storage was Rs. 75.13 lakhs. Due to the application of scientific techniques of stores preservation

over the years this loss has been considerably reduced. Losses due to deterioration of stores in the past 10 financial years are :-

Year	*Total* (in lakhs of Rs.)
1959-60	20.69
1960-61	7.87
1961-62	4.88
1962-63	7.32
1963-64	4.27
1964-65	3.62
1965-66	2.31
1966-67	4.00
1967-68	0.93
1968-69	2.28

2. Steps taken/proposed to be taken to avoid losses are :-

(i) Defence Stores personnel are being taught the techniques of preservation/pest control at the courses conducted by the Inter-Services Stores Preservation Organisation. One advanced and eight elementary training courses are being conducted annually. To meet the increasing demands for trained staff, a Defence Institute of Stores Preservation & Packaging is being set up at Kanpur.

(ii) To prevent damage/deterioration of stores in transit better packings are being devised.

(iii) Stores Preservation Pamphlets/Bulletins are being distributed to the defence storage installations from time to time.

(iv) Research work has been undertaken for further improvement in preservatives and insecticides.

Permission to persons to visit Russia and European Countries

1572. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names and addresses of non-Government servants who went to U.S.S.R. and other European countries during the last two years;

(b) the reasons for giving permission to go out and the amount of exchange sanctioned to each of them; and

(c) whether Government was satisfied before permitting some of these persons who went to these countries that their disease could not be treated in this country; if not, why not ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c) The information is being collected.

Defence Pact with U. S. A.

1574. SHRI P. VISWAMBHARAN :
SHRI SURENDRANATH DWIVEDY :
SHRI NATH PAI :
SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have signed with the United States of America a Defence Pact in early 1962;

(b) if so, whether the then Foreign Secretry had given a draft defence plan to the then U. S. Ambassador, Prof. J. K. Galbraith;

(c) if so, the details of this plan; and

(d) whether this plan ever materialised during the Chinese conflict in 1962 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) . No Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Different rules in respect of officers of the same rank in I. A. F.

1575. SHRI P. VISWAMBHARAN :
SHRI S. M. KRISHNA :
SHRI NATH PAI :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are different rules regarding basic salaries, allowances and promotions of officers of the same rank in the Indian Air Force;

(b) if so, details thereof; and

(c) the reasons for the provision of these different rules ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b). The pay scales of officers of the same rank of the Indian Air Force (other than medical officers) are the same for all Branches except officers of the General Duties Branch who do the flying. The allowances admissible to officers of different branches are also the same, except that officers of the General Duties Branch are given an additional allowance in the shape of Flying Bounty. The details of the pay and allowances admissible to officers of the IAF are given in appendix 'B' (pages 155-160) to the Annual Report of the Ministry of Defence for the year 1968-69.

As in the case of pay, substantive promotion rules of IAF officers of the different branches are the same except in the case of officers of the General Duties Branch. A statement showing the service limits for promotion in the IAF is laid on the table of the House [*Placed in Library. See* NO. LT-2115/69]

(c) Different pay scales and different promotion rules for officers of the General Duties Branch and Ground Duty Branches have been prescribed because of the greater risks involved and the need for younger officers for different levels of responsibility in the General Duties Branch.

Extension given to Army Personnel on their Retirement

1577. SHRI P. VISHWAMBHARAN :
SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI LAKHAN LAL KAPOOR :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a general practice/rule in the service conditions of the army men that at the age of 48 years, on their retirement they are generally given extension of two years;

(b) if so, what are the specific requirements for an army Infantry Officer to get such an extension after 48 years of service; and

(c) whether these are being followed in all such cases ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) and (b). Under existing orders which are effective upto the 31st December, 1971, individual officers of the ranks of Lt. Col. and Major in the Arms (i. e. Armoured Corps, Regiment of Artillery, Corps of Engineers, Corps of Signals and Infantry) whose age of compulsory retirement is 48 years, may on the recommendation of the Chief of the Army Staff be granted extension upto the age of 50 years, except for Lt Cols. of the Corps of Engineers for whom the extension may be upto 52 years, subject to the conditions specified below :–

(i) the officer should not be below medical category B-1 when he attains the age of 48 years;

(ii) the officer should be found suitable for retention in the service on the basis of his records; and

(iii) the officer should be one whose services are actually required by the Army in public interest.

(c) Yes.

Over-Staffing of Indian Embassy in Washington

1578. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the press reports regarding the over-staffing of Indian Embassy at Washington has been brought to his notices;

(b) if so whether the matter has been examined in the light of criticism made and whether in the opinion of Government the present strength is justified;

(c) the comparative strength of the staff in various wings of the Embassy three years ago as compared to the present strength; and

(d) what has necessiated the increase in staff since then ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir. There was a recent report in the 'Hindustan Times', on this.

(b) The Foreign Service Inspectors have inspected the Mission recently and they will no doubt take into consideration all aspects including some mentioned in the press report, while submitting their report.

(c) and (d) The requisite information is furnished in the statement Laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT- /69] The present strength of the Mission is less than what it was three years ago.

Effect of Rupee Trade on India's Tea Exports

1579 SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in a local English daily of the 30th September, 1969 in which references have been made to certain adverse aspects of the rupee trade on India's tea exports;

(b) if so, whether Government have made any survey in the matter in the light of the report;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps being taken by Government to prevent the diversion of India tea by the rupee-trade countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) . This has been a matter under continuous study. During the trade negotiations care is taken to see that export of tea to rupee trade countries is in accordance with the requirements of their domestic consumption. Sporadic cases of diversion at the enterprise level have come to the notice of Government from time to time. However, the quantum has been negligible.

Export of Bananas

1580. SHRI R. K BIRLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the world trade in bananas during the year 1968 rose by 3 percent and earned roughly $ 500 million from the exporting countries;

(b) if so, India's share in trade in bananas in 1968; and

(c) the names of countries where India's bananas are exported ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOUDHARY RAM SEWAK) : (a) The information is not available.

(b) and (c) . Country-wise export of bananas during 1968 was as under :-

Countries	*Quantity* (Tonnes)	*Value* ('000' of Rs.)
Bahrein Is.	2072	1014
Japan	971	55
Kuwait	4811	2393
Or. Tr. Oman	850	436
Others	121	109
Total	8825	4007

Permission to Exporters to Export non-traditional Goods to Afghanistan

1581. SHRI R K BIRLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to permit exporters who

undertake to export non-traditional goods to Afghanistan to import fresh and dry fruits from that country;

(b) the conditions on which permission given; and

(c) the period for which permission given ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The required information is contained in the then Ministry of Foreign Trade and Supply's Public Notice No. 145-ITC (PN) /69 published in Part I-Section 1 of the Gazette of India Extraordinary dated the 30th August, 1969, copy of which is available in the Parliament Library.

Establishment of Jute Factories in Purnea and Saharsa Districts, Bihar

1582. SHRI LAKHAN LAL KAPOOR : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jute is a major crop in Purnea and Saharsa Districts of Bihar State and all the jute is sent to Calcutta;

(b) whether Government propose to open jute factories in these districts in the public sector; and

(c) if so, when ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Jute is grown in Purnea and Saharsa Districts of Bihar State. The Jute mills located in Bihar obtain their requirements of fibre from the jute produced in these districts and only the balance is sent out.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Manipur Handloom Sale Emporium in New Delhi

1583. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Handloom Sale Emporium is being opened at New Delhi by the Government of Manipur for the sale of their handloom products;

(b) whether Government have given some plot to the Government of Manipur for the aforesaid purpose; and

(c) the steps so far taken to meet the crisis in Manipur handloom industry ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and and (b) . Yes, Sir.

(c) Government are not aware of any crisis in handloom industry in Manipur. The marketing of the Manipur handlooms is being done through Handloom Houses of the All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society and through private dealers.

Jute Mill in Tripura

1584. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10020 on the 7th May, 1968 and state :

(a) whether application of M/s. Industrial Development Syndicate, Agartala (Tripura) had since been turned down owingtoinability of the party to finalise a foreign exchange loan requires for importing essential machinery, any more proposals for setting up Jute-mills in Tripura, have been received;

(b) if so, the details of the proposals indicating the cost, foreign exchange content and capacity of the mills to be set up;

(c) Government's reaction thereto; and

(d) the extent of additional Jute mill capacity to be raised in Tripura under

the Fourth Year Plan and the details of of the programme, if any, for increasing jute cultivation in Tripura under the plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

(c) There is no proposal at present to set up a jute mill in Tripura in the Fourth Five Year Plan. As regards jute cultivation in Tripura a production target of 1.83 lakh bales of jute and mesta has been set for the Fourth Five Year Plan. This production is sought to be achieved by.

(i) Special package programme on jute and mesta involving supply of certified seeds, free supply of urea and supply of low volume power sprayers, construction of retting tanks, etc.; and

(ii) State intensive programme.

Disposal of Land Covered by surplus Airport at Imphal-Palel Road, Manipur

1585. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government have finally decided to dispose of the land covered by the surplus airport at 28 milestone at Imphal Palel Road of Manipur; and

(b) if so, the procedure being followed for disposing of the land and the progress made in this direction ?

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : (a) No, Sir.

(b) The matter is still under consiedration.

कपड़ा मिलों द्वारा भंडार रखने के नियम

1586. श्री य० चं० दीक्षित : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विभिन्न कपड़ा मिलों द्वारा रुई की खरीद और भंडार रखने के बारे में कुछ नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त नियम सहकारी कपड़ा मिलों और सहकारी कताई मिलों पर भी लागू होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन नियमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). कपास नियंत्रण आदेश, 1955 में ऐसे उपबंध विद्यमान हैं जो वस्त्र आयुक्त को कपास की खरीद तथा भंडारण का विनियमन करने की शक्ति प्रदान करते हैं । यद्यपि वस्त्र-आयुक्त द्वारा कपास की खरीद के लिये कोई सीमाएं अथवा शर्तें विहित नहीं की गई हैं तथापि उन्होंने इस वस्तु की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है जो कुछ हद तक छूट के साथ सहकारी मिलों पर भी लागू होती है ।

(ग) कपास नियंत्रण आदेश, 1955 की संगत धाराएं सभा पटल पर रखी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या LT-2117/69] 25.5.68 तथा 18.6.69 की अधिसूचनाएं भी संलग्न हैं जिनमें कपास की भंडार सीमाओं का उल्लेख किया गया है । कपास के उत्पादन स्तर में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव होने से कपास की प्राप्यता तथा मूल्यों में विविधता रही है । कपास के भंडारण तथा खरीद के विनियमन हेतु कानूनी उपबन्धों से कपास के उपबन्ध परिणाम के उपयुक्त मूल्यों पर व्यवस्थित विपणन तथा न्यायोचित वितरण में सहायता मिलती है ।

मध्य प्रदेश में कुछ कारखानों द्वारा स्टेनलैस स्टील कोटे की काले बाजार में बिक्री

1587. **श्री म० च० दीक्षित** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष मध्य प्रदेश में कितने नये कारखानों को स्टेनलैस स्टील के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनमें से कुछ कारखाने माल का निर्यात नहीं करते और अपना कोटा चोर बाजार में बेच देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के हज यात्री

1588. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों को सरकार ने इस वर्ष हज यात्रा करने की अनुमति दी है;

(ख) इसके लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिया था; और

(ग) इस वर्ष हज यात्रा के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) मुसलमान आबादी के आधार पर मध्य प्रदेश को समुद्री मार्ग से 404 और हवाई मार्ग से 27 सीटें नियत की गई हैं। इस तरह 1969-70 में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 431 व्यक्तियों को हज यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी।

(ख) मध्य प्रदेश से 1040 व्यक्तियों ने समुद्री मार्ग से अपना स्थान सुरक्षित कराने के लिए आवेदन किया है। अब तक सिर्फ दो व्यक्तियों ने विमान द्वारा अपना स्थान नियत कराने के लिए आवेदन किया है। (आवेदन की अन्तिम तारीख 16-12-1969 है)

(ग) 2,36,25,000/- रु० (विदेशी मुद्रा में)

मध्य प्रदेश में वास्तविक प्रयोक्ताओं को लाइसेंस देना

1589. **श्री म० च० दीक्षित** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन व्यक्तियों के नाम, पद तथा पते क्या हैं, जिनको 1 अप्रैल 1966 के अक्तूबर, 1969 तक, वर्ष वार, वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस दिये गये और उन प्रत्येक को कितने गेज तथा कितनी मात्रा में चादरों के आयात के लाइसेंस दिये गये; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वस्तुतः अपने कोटे के माल का प्रयोग किया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) लोहा तथा इस्पात नियंत्रण लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा 1.1.1967 से 31.3.1967 तथा 1.10.1967 से 30.9.1968 तक की अवधियों में दिए गये लाइसेंसों को छोड़कर सभी लाइसेंसों के ब्यौरे आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा "औद्योगिक लाइसेंसों' आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन"में प्रकाशित किये जाते हैं। बुलेटिन में, लाइसेंसों की संख्या, तारीख तथा मूल्य, माल का संक्षिप्त विवरण, लाइसेंसधारी का नाम तथा पता और देश/क्षेत्र जहां से आयात किया जाना है, दिये जाते हैं। बुलेटिन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। उन अवधियों की जानकारी एकत्र करने जिनके लिए वह प्रकाशित बुलेटिनों में प्राप्य नहीं है तथा विशिष्ट चादरों के गेज के सम्बन्ध

में, जिसके लिये प्रत्येक लाइसेंस जारी किया गया है, जानकारी एकत्र करने के लिये कई हजार फाइलों की संवीक्षा करनी पड़ेगी और जानकारी एकत्र करने में लगने वाला समय तथा श्रम उससे होने वाले लाभ के अनुरूप न होगा।

(ख) लाइसेंसों के उपयोग के आंकड़े नहीं रखे जाते।

मध्य प्रदेश को कच्चे रेशम की सप्लाई

1590. श्री ग० च० दीक्षित : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को कितना कच्चा रेशम सप्लाई किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य ने रेशम के उत्पादन की योजनाओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्यों को रेशम सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जी, नहीं। जनवरी-जून, 1969 में मध्य प्रदेश में टसर कच्ची रेशम का उत्पादन 95,000 किलोग्राम था; जबकि वर्ष 1968 में इसका उत्पादन 1.35 लाख किलो ग्राम हुआ था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड

1591. श्री मोलहू प्रसाद : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड, नई दिल्ली की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई थी;

(ख) इस बोर्ड की स्थापना के समय से लेकर अब तक इसमें प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय सैनिक बोर्ड का गठन 1919 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया गया था। 1944 में इसका दुबारा गठन भारतीय नौसैनिक सैनिक और वायु सैनिक बोर्ड के रूप में किया गया जिससे इसके अन्तर्गत नौसेना और वायु सेना के भूतपूर्व सैनिकों को भी लिया जा सके। मार्च 1951 में इसका दुबारा भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड नामकरण किया गया था। इस संगठन का मुख्य ध्येय भूतपूर्व सैनिकों, और सुरक्षा सेनाओं के सेवा कर रहे और दिवंगत सैनिकों के परिवारों के कल्याण से संबंधित बातों पर विचार करना था।

(ख) बोर्ड के स्टाफ में समय समय पर परिवर्तन होता रहा।

1961 में मंजूर शुदा स्थायी अमला और इस समय कार्य कर रहा अमला निम्नलिखित है :–

पदनाम	पद
1	2
सचिव	1 कर्नल (अंश कालिक)
लेखा अधिकारी	1
अधीक्षक (राजपत्रित श्रेणी)	1
लेखाकार	1

1	2
क्लर्क	1, 2, 3 सहायक, 4 यू डी सी, 5 एल डी सी
स्टेनोग्राफर	1
दफतरी	1
चपरासी	2

(ग) (1) भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति को कार्य रूप देना।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा पुनःस्थापन फंड का नियंत्रण।

(3) राज्य सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों बोर्डों के कार्यों में समन्वय।

(4) जिला सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्डों पर बजट सम्बन्धी नियन्त्रण और समग्ररूप से देखभाल।

Amendment in Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963

1592. SHRI C. K. CHAKRAPANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to amend the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963; and

(b) if not, whether it is not essential to ensure that this Act may be made more effective to inspect quality of our goods meant for exports to increase our exports to foreign countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) The existing provisions of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 are found adequate for effective inspection of quality of export goods notified under the Act. Notwithstanding this, in case of difficulty in the effective ensurance of the quality of export goods, amendment to the Act will be taken up

Colour Bar in United Kingdom

1594. SHRI J. K. CHOUDHURY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than three lakh Indians in Britain were experiencing difficulties due to colour bar as has been stated by the Chairman of the Indian Association of the United Kingdom in Calcutta on the 7th September, 1969; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Government have seen reports from time to time regarding difficulties experienced by Indians in United Kingdom.

(b) As and when necessary the Indian High Commissioner in U K. take up the matter with U. K. Government.

Proposal to make Cabinet Secretariat an effective link between the Prime Minister and Union Ministries

1595. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to make the Cabinet Secretariat an effective link between her and the various Ministries; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b) . Apart from providing secretarial assistance to the Cabinet and its committees, the Cabinet Secretariat is already performing useful functions in co-ordinating the

activities of Central Ministries, whenever required. No change in the present arrangement is considered necessary.

Disturbances in Ahmedabad

1596 SHRI PREM CHAND VERMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether as indicated in the Press reports, the Prime Minister received serious complaints from the State Chief Ministers and other organisations against a Central Minister who went to Ahmedabad during disturbances there;

(b) whether those complaints have been looked into and whether the Intelligence reports have confirmed the complaints;

(c) if the complaints are justified, the action which has been taken or is intended to be taken against the Minister concerned; and

(d) if no action is intended to be taken the reasons therefor and what are the actual facts which disprove the allegation ?

THE PRIME MINISTER MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) to (d). The Prime Minister received two letters from the Chief Minister of Gujarat, regarding the visit of Shri Mohd Yunus Saleem, the Union Deputy Law Minister. Letters were also received from some Members of Parliament on the subject. Shri Saleem also sent a report to the Prime Minister, regarding his visit and assessment of the situation. No action has been considered necessary.

Industries in Bikaner Division

1597. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Bikaner has the biggest of the woollen mandis in the country and the problem of unemployment assumes alarming dimensions, in the frequently occurring famines in the region;

(b) whether Government propose to start Hosiery, Carpet and Tweeds Industries in the Division for which there is great potential for earning foreign currency;

(c) whether Government have received any representation from the Rajasthan Wool Industries Development Company, Bikaner in this regard; and

(d) if so, the action which Government propose to take in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FORFIGN TRADE (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. However, woollen hosiery units and handlooms for the manufacture of carpets and tweeds, etc., utilising indigenous raw wool can be set up without any permission from the Central Government, provided the capital assets of hosiery units are below Rs. 25 lakhs. Permission is also granted freely for setting up of woollen spinning units, provided only indigenous raw wool and machinery are used. There will not, therefore, be any difficulty in setting up such units, in case private Entrepreneurs or the State Government desire to do so.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारत स्थित पाकिस्तान सूचना तथा प्रचार केन्द्र द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का वितरण

1598. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रहा पाकिस्तानी सूचना तथा प्रचार केन्द्र इस समय भारतीय भाषाओं में कितने समाचार पत्र तथा पत्रिकायें वितरित करता है; और

(ख) उनके भाषा-वार आंकड़े क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख).

भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन निम्नलिखित प्रचार सामग्री वितरित करता है–

1. पाकिस्तान प्रेस विज्ञप्ति
2. रेडियो पाकिस्तान न्यूज
3. पाकिस्तान न्यूज

ये प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में जारी किए जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

1599. श्री गंगा नारायणसिंह :
श्री रामसिंह अग्रवाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शारदा नन्द :
श्री भ्रा० सुन्दरलाल

क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जिन सैनिक कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों के रूप में कृषि भूमि दी जाती है उनके रैंक क्या है और प्रत्यक व्यक्ति को कितनी भूमि दी जा रही है;

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिन भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी गई थी उनके रैंक क्या थे और उनका सेवा काल कितना कितना था और प्रत्येक व्यक्ति को कृषि प्रयोजन हेतु कितनी भूमि दी गई;

(ग) जिन व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों के रूप में भूमि दी गई है उन के पास व्यक्तिगत रूप से अथवा अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में पहले से कृषि योग्य कितनी भूमि थी;

(घ) भूमि के आवंटन के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये है जो कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त हैं; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (ङ). सूचना उपलब्ध नहीं है और उसके एकत्र करने में लगने वाला समय और प्रयास उससे निकलने वाले परिणामों के अनुकूल न होगा।

विद्रोही नागा

1600. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत जुलाई और अगस्त में आत्म-समर्पण करने वाले विद्रोही नागाओं की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) जिन नागाओं ने आत्म-समर्पण किया है, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या आत्म-समर्पण के समय सौंपे गये शस्त्रास्त्र केन्द्रीय सरकार के पास रखे हैं अथवा सीमा सुरक्षा दल उनको अपने ढंग से रखता है ?

प्रति रक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 373।

(ख) आत्म समर्पण करने वाले नागाओं को या तो उनके गांवों में वापस जाने दिया जाता है जहां कि उनके गांवों में अथवा गांवों के निकट स्थित सुरक्षा चौकियां उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें, या फिर उन्हें उन चुने हुये क्षेत्रों में जाने दिया जाता है जहां कि सैनिक तैनात किए गये होते हैं।

(ग) सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले शस्त्रास्त्र सेना को सौंप दिए जाते हैं और

अन्य शस्त्रास्त्र राज्य सरकार को सौंप दिये जाते है ।

---

12 hrs.

REPORTED RAIDS ON CERTAIN VILLAGES IN WEST BENGAL

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : Sir, there has been very disconcerting news from West Bengal in today's papers that 2,000 men raided a village and hacked two people to pieces. These are said to be CPI (M) people. Not only had they gheraoed the thana but it was only after those who were arrested were let off that the gherao was lifted..... (*Interruption*)

MR. SPEAKER : We are having a debate at 4 Oclock on this.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : The Government should make a statement on this, if necessary, after verifying it from the West Bengal Government.

12.01 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported violation of air corridor between West and East Pakistan by Pakistani aircraft

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:--

> Reported continuous and wilful violation of the air corridor between West and East Pakistan by Pakistani aircraft over the territory of India.

THE MINISTER OF DEFENCE AND STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI SWARAN SINGH) : Mr. Speaker, Sir, I have to inform the House that on 30th October 1969, a Pakistan Air Force C 130 aircraft over flying Indian territory between Dacca and Karachi flew up to 5 nautical miles outside the Pre Determined Route for a distance of 160 nautical miles. This was, by any standard, a serious violation of Indian air-space and continued in spite of the fact that the Flight Control at Calcutta repeatedly asked the aircraft to return to the Pre-Determined Route. The Pakistan Air Force C-130 returned to the Pre-Determined Route only after our aircraft were sent to intercept it.

We have lodged a strong protest against the continued and frequent violation of Pre-Determined Route by Pakistan Aircraft over flying Indian territory. We have urged to Government of Pakistan to give firm instructions to the crew of all aircraft over flying Indian territory to remain strictly within the Pre-Determined Routes.

SHRI RANJEET SINGH (Khalilabad) : Our Defence Minister has one weapon, the weapon of protest.

SHRI D. N. PATODIA : It is a very serious matter and the hon. Minister by making a statement has concealed much more than what he has revealed.

SHRI RANJEET SINGH : We seriously protest to him.

SHRI D. N. PATODIA : This corridor facility given to Pakistan came out of an agreement signed between India and Pakistan more than two years ago by which Pakistan allowed only one Indian military courier plane to fly over their territory. Indian plane was to be fully searched at Karachi; no photographic material was permitted to be taken and the crew was not permitted to move out of the airport. In return, India allowed Pakistan to fly all sorts of military and combat planes, to transport all sorts of military equipment, to halt at Lucknow and to permit the crew to move out of the airport, mix with the civilians and make all sorts of investigations.

This agreement about which violation has been reported now has done no good to India. In fact, it has done a lot of damage to India. In course of these more than two years, all our missile sides of India have been thoroughly photographed by them and they have been able to locate the gap points of our radar system by which, in future, these Pakistani aircraft

[Shri D N. Patodia]

with be able to overfly our territory with out being detected by our radar system In respect of this violation, the manner in which the protest note has been made by the hon Minister is extraordinary. The violation took place on 30 October and the protest note was sent after 23 days on 23rd November only after some other protest note a similpr incident was sariler received from Pakistan

In view of these developments, I wish to ask certain pertinent questions from the hon. Minister. Where was the necessity for India to enter into such an agreement which is so much adverse to India's interests ? Was the agreement signed against the advice of the Air Chief at that time ? How many violations by Pakistan were detected from the beginning of the agreement ? Why was this protest note sent after 23 days after the date of the violation ? Why is it in this particular case India did not shoot down Pakistani aircraft because it dived in to our territory up to five miles, particularly, when sometime back an Indian plane was shot down by Pakistan on similar grounds ? Has the incidence of violations increased after resumption of arms supply to Pakistan by U. S. S. R. and U. S. A. ?

My last point is about the Tashkent Agreement. Regarding the Tashkent Agreement which is, in any case, a dead document about which neither U. S. S. R. nor Pakistan are any more concerned, is India now prepared, in view of these developments, to repudiate the Tashkent Agreement rather than permit herself to be humiliated on every occasion ?

SHRI RANJEET SINGH . Scrap it. (*interruption*)

SHRI SWARAN SINGH : The hon. Member has put too many questions. I will try to answer as many of them as possible briefly instead of trying to reply to his general agruments.

In the first place, I would like to say very categorically that is wrong to say that the agreement of over flights between India and Pakistan is weighted against us. It will be absolutely wrong for us to take that view. It is a reciprocal arrangement where over flights of the aircraft of the country are permitted over the air space of the other. C-130 is a transport plan with which we are concerned now ..... (*Interruption*)

SHRI RANJEET SINGH : What about their fighters and combat aircraft ? He is trying to mislead the House.

SHRI SWARAN SINGH : It is a very wild charge. If you make a charge in such a manner, it is very surprising. We have also got the right to overfly the fighter and combat aircraft of the Indian Air Force over the Pakistani territory and we have actually utilised this facility ..

AN HON. MEMBER : How many times ?

SHRI SWARAN SINGH : A very large number of times. That should set at rest any apprehension.

The other point made was that all our missiles sites and radar gaps have been detected. That is also incorrect. There was no justification from this question to make any such allegation ..

SHRI D. N. PATODIA : Why not ?

SHRI SWARAN SINGH : The first question was about the necessity of the agreement. That is a reciprocal arrangement where facilities are made available to either country and it is something which is in our mutual interest.

SHRI D. N. PATODIA : Not at all.

SHRI SWARAN SINGH : Then, this agreement was entered into after taking the advice of the Air Chief. It is wrong to suggest that this was entered into against the advice of the Air Chief. This is a suggestion which is totally unfounded. I would request the hon. Member not to make such an allegation unless he has verified it.

SHRI D. N. PATODIA : Are you sure about it ?

SHRI SWARAN SINGH : I am absolutely sure.

SHRI D. N. PATODIA : No.

SHRI SWARAN SINGH : It is amazing that you should go on persisting some thing without having any knowledge of facts. About this particular violation, as the House is no doubt aware, PDR is a Pre-Determined Route which is a line across which the aircraft of one country overfly another country's territory. If there is any deviation, according to well established international practices, the Air Control warns them that they are out of the PDR. and ask them to come back to the PDR If they do not come back, we scramble our aircraft.

In this particular case, out fighter air craft went up and drove it back to the PDR. It is no good...

SHRI RANJEET SINGH : It should have been forced to land.

SHRI SWARAN SINGH :...to shoot down transport aircraft of other countries. It will be bad and it is against international practice. Howsoever much you may have these feelings of suspicion against Pakistan, we should not depart in a light hearted manner and in a spirt of bravado, from international practices that obtain in such cases. Shooting is not undertaken in the case of transport aircraft about which they already notify that a particular plane is going. And I would request the hon. Member not to cite examples without carefully checking them up. In the case of shooting down of our Canberra, we protested at that time that it strayed into their territory.

SHRI RANJEET SINGH : We did not protest.

SHRI SWARAN SINGH : If a transport plane...(*Interruptions*).

I do not give way. That is not the way to deal with it. I refuse to take note of such interruptions.

The point is if in a particular case a transport plane is going and is permitted to go and it deviates from PDR, there are well recognised conventions and international practices about giving a warning to it and asking it to come back to the PDR. If it does not obey, we scramble our aircraft and compel it to come back to the PDR. But shooting down is an extreme step which we should not undertake and I am not also sorry that we did not undertake shooting.

SHRI D. N. PATODIA : What about the delay in protest ?

SHRI SWARAN SINGH : Sir, there is no connection between these deviations and the resumption of supplies of arms to Pakistan by some nations. Of course, hon. Members may not like many things, but lumping them all together and trying to build up a case without trying to undertand the real implications is unfair.

SHRI D. N. PATODIA : Why was there so much delay ?

SHRI SWARAN SINGH : In such cases, Mr. Speaker, the protests are lodged by the Ministry of External Affairs and in this particular case I think they lodged the protest on 15th November, 1969.

SHRI RANJEET SINGH : Why was it lodged after 3 weeks ?

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री जी से स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि एयर कौरीडोर एग्रीमेंट पाकिस्तान से होने के बाद कभी इस अवधि में कोई बोम्बर या मिलिटरी एयर क्राफ्ट ने हमारे आकाश का उल्लंघन किया था ? यदि हां तो क्या सरकार सदन को बतायेगी कि अगर भविष्य मे ऐसा किया गया तो हम उसको मार गिराने की कोशिश करेंगे ? क्या इस प्रकार बोम्बर या मिलिटरी हवाई जहाजों द्वारा हमारे आकाश का उल्लंघन किये जाने पर उनको मार गिराने के लिये सरकार के पास हिम्मत की कमी है, या तेज हवाई जहाज हमारे पास नहीं है, या इक्विपमेंट की कमी है ? क्या कारण है न मार गिराने के ? इस के बारे में मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

पहला यह कि क्या कौरीडार ऐग्रीमेंट होने के बाद पाकिस्तान के साथ, उन के मिलिटरी

[श्री रविराय]

या बौम्बर हवाई जहाजों ने हमारे आकाश का उल्लंघन किया है ? यदि किया है तो क्या दिक्कत थी जिस से उन को मार कर नहीं गिराया ? मार कर गिराने के लिये क्या सरकार के पास हिम्मत की कमी है, या तेज हवाई जहाजों की या इक्विपमेंट की कमी है ?

मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जैसे रूस सरकार ने अमरीका के "यू 2' जहाज को गिराया था उस का अनुकरण आपको करना चाहिए । इस तरह का कोई कदम उठाने का विचार सरकार का भविष्य में है : रूस ने दिखा दिया कि किस ढंग से अपने आकाश और मुल्क की रक्षा की जा सकती है । उनका अनुकरण हम को करना चाहिये । मैं चाहूंगा कि मेरे इन सवालों का उत्तर मन्त्री जी स्पष्ट रूप से दें ।

SHRI SWARAN SINGH : With regard to the first question, I would like to say that the House may kindly keep a distinction between the permitted flights even by military aircraft over the Indian territory and intruders.

श्री रवि राय : मैं वायलेशन के बारे में पूछ रहा हूं ।

SHRI SWARAN SINGH : So far as the mutual agreement is concerned, we can transport our military aircraft over Pakistani territory. That is permissable. On that, the precaution is that there has to be a landing. If it is our aircraft, then it has to land in Pakistani territory at one point which is mutually agreed. If it is Pakistani aircraft it has to land at an Indian airport before it is permitted to go ahead. If there is an intruding aircraft of Pakistan or of any other country, it is our job to shoot it down and it is wrong to suggest that we have not got the equipment. We have equipment and so far as courage is concerned, the hon Member may lack courage, but it will be a bad day if the Air Force lacks courage.

श्री रवि राय : एक लाख वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान और चान को दे कर आप करेज के बारे में उपदेश दे रहे हैं । इस तरह की बात मत कहा कीजिये । कोलम्बो प्लान की अभी भी अर्थी आप उतार रहे हैं ।

SHRI SWARAN SINGH : It is a well recognised international practice that intruding military aircraft can be shot down. We are in a position to undertake that. This is quite in accordance with international practice and we are well-equipped to do that.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Sir, we are told by his predecessor Shri Krishna Menon that shooting down would not be a civilised manner.

MR. SPEAKER : Shri Kanwar Lal Gupta.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मंत्री महोदय ने कहा कि यह जो एग्रीमेंट है यह म्यूचुअल इंटरेस्ट में है और रेसं प्रोकल है । मेरा कहना है कि यह ऐग्रीमेंट हमारे देश के हित में नहीं है और सरकार की अपीजमेंट पौलिसी का हिस्सा है शायद इस आशा में कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ नार्मल हो जायेंगे । लेकिन रिलेशन नार्मल होने के बजाय होस्टाइल हो रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, रबात में हमारी बेइज्जती कराई, खां अब्दुल गफ्फार खां को पाकिस्तान के ऊपर से नहीं आने दिया गया, उनको दूसरे रास्ते से आना पड़ा, तो इस तरह का होस्टाइल एटीट्यूड जो पाकिस्तान का है उस के बाद भी हम ने यह एग्रीमेंट किया हुआ है, और मन्त्री जी कहते हैं कि हमें भी फायदा हुआ है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दो साल से जब यह एग्रीमेंट हुआ है हमारे कितने जहाज उसकी सीमा पर से उड़े और उनके कितने हमारी सीमा पर से उड़े । हमें थोड़ी दिक्कत होगी इस ऐग्रीमेंट को खत्म करने से जब कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगी क्योंकि दोनों विंग्स मिलाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है । तो मेरा कहना है कि मंत्री महोदय क्या यह फिगर देंगे कि कितने

हमारे हवाई जहाज उधर गये और कितने उन के हमारे ऊपर से उड़े । जो स्पाइंग का काम कर रहे हैं, जैसे पटोदिया साहब ने कहा, उस का परिणाम कहीं यह न हो कि जैसे इजराइल ने अचानक यू० ए० आर० पर हमला कर दिया, ऐ ही कोई ताज्जुब की बात नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाय तब आप कहें कि हम क्या करें, पाकिस्तान ने हमारी बैक में छुरा मार दिया । इसलिये देश के इंटरेस्ट को देखते हुए क्या मंत्री महोदय अपनी पोलिसी को रिवाइज करेंगे और इस ऐग्रीमेंट को खत्म करेंगे ताकि पाकिस्तान का जो हौस्टाइल ऐटीट्यूड है, चाहे ताश्कन्द डिक्लेरेशन के बारे में हो, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में हो, चाहे रबात के बारे में हो गुरीला वार-फेयर के बारे में हो, यह बन्द ट्रैफिक बन्द हो । और क्या आप पाकिस्तान को बतायेंगे कि हम वही करेंगे जैसा आप हमारे साथ करेंगे । साथ ही क्या यह भी सही है कि आपने मिलिटरी अथोरिटीज को इन्सट्रक्शन्स दे रखे हैं कि किसी कीमत पर हवाई जहाज को शूट नहीं करना चाहिये ? क्या पोजीशन है यह जरा बता दें ।

SHRI SWARAN SINGH : Mr. Speaker, Sir, may I say very categorically that it is absolutely wrong to suggest that we are adopting a policy of appeasement ? There is no question of following a policy of appeasement. We have to follow a policy which is in the best national interest--and that is precisely our approach to this problem. As regards the specific question that has been asked, this has nothing to do with the general foreign policy overtones which are interwoven very cleverly by Shri Kanwar Lal Gupta into his question. This is a direct agreement in mutual interest ..

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What is the mutual interest ?

SHRI SWARAN SINGH :...and it will not be good to cast aside all agreement of mutual interest merely because we have got other problems which are irritating and which are straining the relations between the two countries.

A regards the number of aircraft, I have not got the information at present, and, therefore, I cannot give straightway the exact number of Indian aircraft which overflew their territory and of the Pakistani aircraft which overflew our territory. But I constantly keep an eye on this comparison, and I would like to say that the comparison is not unfavourable to India. It is more or less favourable; we are also equally interested, and it will be wrong for us to imagine that it is an one-way traffic. That would be a wrong assessment of the situation.

As regards the third question, after I have stated categorically in reply to an earlier question that if there is an intruding military aircraft, we would be perfectly justified in shooting it down, there was no justification to ask me whether there were any instructions issued by us that the IAF will not shoot down in any case; that is not correct; no Air Force can be given such an order, and no Government can give such an order. Each situation has to be judged on merits.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will he scrap this agreement ? That was my pertinent question.

SHRI SWARAN SINGH : We are not going to scrap the agreement. I should like to say that categorically.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why ?

SHRI SWARAN SINGH : Because it is not in our interest to do so.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : (Chittoor) : This is not the first time that Pakistani planes have intruded into our air space wilfully. There have been several such instances. In this case, it is not the case of any plane going on the basis of any agreement. Here, clearly they have violated our air space and have come about five miles into our territory. The hon Minister says that our fighter planes had gone and brought it back. May I know from the hon. Minister to which airport the plane was

]Shri Chengalraya Naidu]

brought ? It was not brought. He only says that our planes went and brought it. I would like to know whether we had asked them to come down and land in our airport. Then, we could have found out whether the plane was a military plane or a transport plan or even if it was a military plane, whether there were any military personnel in it or whether any photographic equipment had been fitted into it. We would have found out all those things. Wilfully, the hon. Minister is not instruct ng our Air Force to bring the plane down to our airport, so that our planes could go up and bring it down.

I know that the Air Force is fully equipped, andiour Air Force personnel has got courage; of course, the hon. Minister has no courage to ask them to shoot it down. In the face of this, I think it is better for him in the interest of the country to resign from Government here and now and come out. What steps did he take to instruct the Air Force to see that if there is an air space violation, the plane must be brought down to our airport and not to their airport in Pakistan ?

SHRI SWARAN SINGH : I am glad that my cousin.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is a step brother now...

SHRI SWARAN SINGH : who has walked over to the other side has been good enough to give all the credit to our Air Force which it deserves, both in regard to their capacity as well as in regard to their courage. I attach greater importance to that but I am not bothered about the hooes of the hon. Member, because they are absolutely irrelevant. This is a matter in which my courage or cowardice does not matter at all... There are well recognised. .

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I am not a coward. I have got courage; that is why I have come and sat down here. He is a coward, and that is why he is still sitting there

SHRI SWARAN SINGH : I would like to tell him again...

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : He is a brave because he is a kisan.

SHRI SWARAN SINGH : At least on facts, at any rate, let there be no disagreement. All military aircraft, whether they are fighters, bombers or transport aircraft, if they fly over Indian territory, have to land at an Indian airport of our choice, and no aircraft has been permitted to over fly our territory, that is, no Pakistani military aircraft has ever been permitted to overfly Indian territory without landing at an Indian airport, and this particular case is not an exception. Therefore, it is no use saying that if it had landed, we would have checked up and so on. Actually, every military aircraft lands, and this had also landed in our territory.

The present question is a simple one. It relates to deviation from PDR. Deviation from the PDR has to be corrected by warning by Air Control. If they do not need the warning, then we scramble our Fighter aircraft, that is, our aircraft go into the air and tell the pilot 'If you do not deviate, we shall shoot the plane down'. If he accepts it and comes back PDR, that is the end of the matter.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : The hon. Defence Minister is very adept in the art of evading issues. Here too, he is taking refuge under a very technical thing that it deviated only by five miles, and we did all that. But can he deny the fact that Paksitan is following a policy of enmity towards India, and that Pakistan is idoing everything possible to damage India's isnnterest, to work up the people within the country to work against the Government and it is fluting the Tashkent Agreement in every possible way ? In view of all these things, just to take shelter behind only five miles is not proper. My question is very simple. According to the hon. Minister, what is Pakistan's intention towards this country ? The Foreign Minister is also sitting here and he has said on 8th October, that he had met his Pakistani counterpart and that he saw that there was a definite change in the Pakistani atitude. On the very nevt day, the Pakistan Foreign Office declared that there was no change in Pakistan's attitude. He is living in a world of phantasy, in a wishful world. He thinks that something will happen according to him, but that is not happening.

Now, I would like to ask two or three very specific questions. Is it a fact that he lodged his protest only after the Pakistan Foreign Office, inkeeping with its policy of taking the offensive, had called our Military Attache and lodged a protest, and it is only after they lodged a protest that we thought of lodging a protest ?

Then, the hon. Minister has said that this agreement is not working against our interest. He says that he does not have any figures. But in reply to a question by Shri Ranjit Singh on the 11th December, 1968, he has said that between 1st January, 1966 and 11th September, 1966, 57 Pakistani planes were allowed to fly over our territory while only 23 Indian planes flew over Pakistani territory. If that was the ratio in 1966, what is the ratio in 1967, 1968 and 1969 ? How does the hon. Minister say that this agreement is not working against our interest and that we are more benefited by it than Pakistan ?

My third question is this. In reply to Q. No. 221 today, which relates to the Tashkent agreement, we have been told by Government that Pakistan has agreed only to those steps in the implementation of article 6 of the Tashkent agreement as are to its benefit, and then the other details have been given.

When Pakistan is doing all those things which are in Pakistan's interest, and Pakistan is making only piece-meal agreements with us, which go against our interest, may I know why we always oblige Pakistan by entering into agreements which are in favour of Pakistan and not in favour of India ? In view of this record of Pakistani behaviour for the last five years regarding the Tashkent agreement, may I know whether the hon. Minister is prepared to reject and scrap the Tashkent agreement altogether and say that we are no longer bound by it as Pakistan is not bound by it and that we shall adopt a posture of relationship towards Pakistan which is based on pure reciprocity and mutuality of interest and firmness and other things and that the cobwebs that we may have in our minds regarding our relations with Pakistan would be removed ?

SHRI SWARAN SINGH : I would suggest that so far as the foreign affairs aspect is concerned, the hon. Member should keep his powder dry for a debate on foreign affairs, and I would not like...

SHRI BAL RAJ MADHOK : Is defence separate from foreign affairs ? The Foreign Affairs Minister is sitting just close to him...

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : Is the hon. Minister hinting that he is going to take over the External Affairs Portfolio because he is asking my hon. friend to reserve his comments for the debate on foreign affairs ?

SHRI SWARAN SINGH : My insinuations are not as crude as the hon. Member's.

SHRI M. L. SONDHI : My insinuations may be crude, but are the hon. Minister's intelligent ones ?

SHRI SWARAN SINGH : This is a favourite pastime which the party to which the hon. member belongs always indulges in, raising this question and trying to show that they are very brave in the attitude India should adopt in relation to Pakistan.

SHRI BAL RAJ MADHOK : There is no question of any reflection. I have put specific questions to which I want specific answers.

SHRI RANJEET SINGH : You are not pinning him down to answer the question straightway.

SHRI SWARAN SINGH : He has not been pinned down either.

MR. SPEAKER : A number of times I have invited attention of hon. members to the rule. I feel myself completely helpless in spite of my repeated appeals. I will read it out. When the Minister replies, the member is entitled to ask with the permission of the Speaker ..

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : What is the rule, Sir ? 195 ?

MR. SPEAKER : This is about calling attention. He need not worry about it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Are you raising a point of order ?

SHRI S. M. BANERJEE : Tomorrow my name may be balloted.

MR. SPEAKER : Shri Madhok numbered his question 1, 2, 3, 4.

AN HON. MEMBER : No, (a), (b), (c).

MR. SPEAKER : He can ask only one question to save the time. Either we follow the rule or scrap it.

SHRI BAL RAJ MADHOK : It is true that it is not in consonance with the letter of the rule. But we have developed a convention during the last 10-15 years.

MR. SPEAKER : No, No

SHRI BAL RAJ MADHOK : We should be governed not only by the constitution but by conventions. You must honour the convention that has been established here. Here is a very very important subject involving the security of the country and therefore you should allow us some indulgence.

MR. SPEAKER : There is no question of 15 years. Only a few years back, the procedure of call attention was introduced. I know how it came into being. Should I follow the convention or where there are specific rules, I should follow the rule ? I have to follow specific rules, not according to what he says.

SHRI SWARAN SINGH : I do not know how many questions I should answer, but I will very briefly try to answer the various points made.

First, I would like to say very clearly that the policy that we follow in relation to Pakistan who is our neighbour is a policy in which we take note of their continued hostility to us. All our defence plans, and all our postures in the international field are based on that Unfortunately, the Government of Pakistan, as opposed to the people of Pakistan, is trying to adopt a policy of continued hostility to us in the diplomatic field, in the defence sphere and also in their collusion with China. All our thinking is based on that. I would like to assure the House that we do not take any light view of the situation but we fully take into account the postures of Pakistan.

On the specific questions asked, it is true that in this particular case the Pakistan Air Headquarters, not the Foreign Office, did call our Air Attache because they know that their aircraft had deviated and that we had used our fighters to bring it back to the PDR. Therefore, in order to forestal our action or protest, they did call our Air Attache to their Air Headquarters and asked why the extreme step of scrambling our fighters was resorted to in this particular case. But our Air Attache made the position quite clear to them that according to his information it was a clear deviation from the PDR and we were perfectly entitled to use our fighters to bring it back to the PDR. In this particular case, it was not a question of just protest; as soon as the deviation came to our notice, our fighters were actually up in the air and it was their presence that brought it back to PDR. There could not be a better protest than taking action then and there.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Then why did we lodge a protest ?

SHRI SWARAN SINGH : It is necessary, if there is a deviation from the PDR, that we should lodge a protest through diplomatic channels. About the second point about the agreement, he has quoted some figure that was given in 1968.

SHRI BAL RAJ MADHOK : 1966.

SHRI SWARAN SINGH : It is a three year old figure, and over the years when I say that the agreement is not unfavourable to us, I stand by that.

SHRI BAL RAJ MADHOK : You say you have no figures, but here are figures to disprove your contention.

SHRI SWARAN SINGH : This is not a very proper way of dealing with the situation. He is quoting same figure of 1966. Now we are in 1969.

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Then, give the figures.

SHRI SWARAN SINGH : If he tables a separate question, I can give the numbers also. I have said and I repeat that I have kept myself in touch with the movement of

aircraft over either country and the overall impression on my mind is that it is not unfavourable to us. If they ask for the exact figures, we can give the figures also.

About the Tashkent Declaration, I do not want to say anything. It is very much a foreign affairs matter, and at the appropriate time I would request the hon. member to address the question to the External Affairs Minister.

12.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification re : Management of Bengal Nagpur Cotton Mills etc.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK CHOWDHARY) : I beg to lay on the Table-

(1) A copy of Notification No. S. O. 4433 (English version) and S.O. 4434 (Hindi version) published in Gazette of India dated the 30th October, 1969, regarding management of the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgaon, under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-2098/69].

(2) A copy of the Export of Froglegs (Inspection) Second Amendment Rules, 1969 (Hindi and English versions) published in Notification No. S. O. 4537 in Gazette of India dated the 6th November, 1969, under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-2099/69].

(3) A copy of the Textile Committee (Third Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. G S R. 2172 in Gazette of India dated the 13th September, 1969, under sub-section (3) of section 22 of the Textiles Committee Act, 1963.

(4) A copy of Corrigendum to the Annual Report on the working of the Cardamom Board for the year 1967-68. [*Placed in Library. See* No. LT-2100/69].

REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Fifty-fifth Report

SHRI BHALJIBHAI PARMAR (Dohad) : I beg to present the Fifty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.37 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

Shri Nehru's decision on India's Participation in religious Conference.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : I am grateful to you for permitting me to bring to the notice of this House a point, a very significant point, on what the External Affairs Minister, Mr. Dinesh Singh, stated on 17 November in the proceedings in this House on the motion for adjournment.

I have had a look at the communication which was received by you from the Minister. What the Minister says in this is contradicted by the common knowledge of most of the elder members of this House who know Mr. Nehru, and all those who have read his views in the various debates on external affairs which took place in this House are rather dismayed and amazed that the Minister should claim, and claim in the manner that he did in this House, that if religious conferences are held, then it would be in our interest if people from India participate in these religious conferences; and he said it in a manner that suggests that Pandit Nehru said this or thought this. It almost conveys, it does in fact convey, the impression that he is quoting from a document.

Further on he says that he is dealing with the subject in a manner which correctly reflects policy and does not mislead the House and he claims that the files concerned

[Shri M. L. Sondhi]

are secret. With your permission, I would very briefly comment on this, because I think it is for this House to decide as it has inherited certain privileges from the House of Commons and has its own understanding of the issues.

I may reiterate that it is not à question of political arithmetic that I want to raise at this time. I am not interested in this question as to which faction of the Congress is interested or not. But the matter has a wider context in that it is the knowledge of this House. of senior members in the country, on the basis of records of Mr. Nehru, that he was categorically opposed to participation in religious conferences, because, in his view, such participation would undermine India's non-denominational constitutional system and, in fact, undermine India's capacity for a purposive diplomacy for a modern world order.

The Minister, in the manner in which he presented it to the House, has made a statement which is not merely inconsistent; it is not a mere irrigularity, it goes to the heart of the matter because it contradicts our understanding and experience of Indian foreign policy for the last twenty years, and it also inflicts on us such a grave and such a cruel denial of our own knowledge and understanding of our country and of its first Foreign Minister.

So, I would request you, and I would again request the Minister, who happens to be in the House, not to stand on prestige, not to make an issue of it which I think is a false one because there have been examples in the House of the Commons of Mr. Eden and other Ministers who, when they made a mistake, would either correct the statement or come to the House with full facts.

It would be disrespectful to the memory of Mr. Nehru and disrespectful to this House because from what appears from the debate and from his submission to you, *prima facica* lot of mischief has been done to our understanding and to our very appreciation of the tenor of foreign affairs.

The matter may or may not be sent to the Privileges Committee. I do not blame you because your hands are tied by the rules which we have in this House. But it will be remembered by history. It was a grave violation of the elementary responsibility of democratic duty, committed by the treasury benches. They were not prepared to lay before the House all the facts; what the facts are,what were Mr. Nehru's views; they are the property of this nation. There is a whole Institute which works on his thoughts. I do not want to quote from May's Parliamentary Practice but there are revelant quotations which Ican give.

This matter concerns not only Mr. Nehru but his close and trusted colleagues also, like Maulana Azad and others. If there are these written records why should we be unfair and say there is some struggle going on in the E. A. Ministry between the Minister and certain other officials. We do not know anything of this sort. We do not know anything of that sort. What we want is that the Minister should be prepared not to obstruct clear thinking by this House. He should be prepared to encourage Members to make up their mind. I therefore suggest that either you convene a conference of yourself, the Minister and the Opposition leaders. If you please, I am prepared to lend my assistance but I am not claiming for me any position in this. I am more interested in seeing that this matter is dealt with in a manner which does justice to the memory of Mr. Nehru and our academic understanding of the foreign policy.

MR. SPEAKER : Mr. Sondhi came to me with a request under direction No. 115. The only procedure was to send his request to the Minister and ascertain whether it was a quotation or not. If he had not used a quotation, he was quite privileged to do so, he can also put in the plea that it is a privileged document and would not be in the public interest to disclose it. He has come to me under rule 377. It is a borderline case under which a substantive matter cannot be raised. So far as the matter being referred to the Privileges Committee is concerned, I do not think I have any such rule under which I can send it to that committee. After all the Chair has to be guided by the rules and not always by what the hon. Members say, though sometimes it creates very difficult situations. If the hon. Minister wants to reply, he is welcome to reply.

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : Mr. Speaker, you had very kindly sent me a copy of the letter that the hon. Member has sent to you and had asked for my views; I had sent them to you. I got this intimation a short while ago that the hon. Member, Mr. Sondhi, would be raising this matter here. Mr. Sondhi has made a point about the secret document. I had said even on that day, it is in the record of the proceedings. I should like to say here that I am not in a position of privilege to give any quotation because it is a secret file; I have said that the papers were secret and I could not place them before the hon. Members. Mr. Sondhi has detached it out of context. He said as if it gave the impression that Mr. Nehru was anxious to send people to such conferences. That is not quite correct. If he goes through the records, he will see that I said that for a number of years we did not send any representatives; no one from India attended any of those conferences. If he was in doubt I shall be glad to read it out for his benefit.

SHRI M L SONDHI : I am not in doubt. It appears that Nehru said or Nehru thought like that. Those are in quotation; it is clear that you were quoting words; that there is no mistake about it.

SHRI DINESH SINGH : I had said that in 1955 it was felt that it would be in in our interest not to prevent people from going to those conferences, that if people went to those conferences they would be able to reflect correctly the position of Muslims in India. But the people who went were not Govern nental people. They were private people, and it is known that they have been going for a number of years, and the House has asked questions .....

SHRI M. L. SONDHI : That is not the point, Sir, (*Interruptions*)

SHRI DINESH SINGH : I can understand the point.

MR. SPEAKER : Mr. Sondhi, please be patient. I am anxious that you may not go out of control.

SHRI M. L. SONDHI : What the Minister said,–that question–does not arise. I would beseech him not to look upon it from Mr. Nehru's political standpoint. Here is the opinion of the chief policy-makers...

MR. SPEAKER : I am not going to allow any debate whatsoever.

SHRI DINESH SINGH : The hon. Member has already delivered his speech. I think he should now show the courtesy of listening to what I have to say. This is not a matter of debate, as you have pointed out. He has made a statement and I should make my statement, and then it is for you to decide. It is not a question of entering into any debate or argument on this matter. It is provided in the rules.

MR. SPEAKER : No debate at all.

SHRI DINESH SINGH : I have stated the position. I have also clarified the position about such conferences which were held in religious names but which dealt with political issues. I repeat that each conference should be consisdered on its merits and this is exactly what we have been doing.

SHRI RANGA (Srikakulam) : We made a departure this time by sending officials.

SHRI DINESH SINGH : The matter of sending our delegation to Rabat has been fully discussed in this House. I have nothing more to add on this subject.

SHRI M. L. SONDHI : Please permit me to quote only one sentence.

MR. SPEAKER : Please stand by your commitment; no debate.

SHRI M L. SONDHI : One second, Sir. He says there will be no departure in our policy, as laid down by Pandit Nehru. Now, he agrees with Mr. Ranga. What is this ? He should be consistent.

MR. SPEAKER : No argument.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : Please meet him in his room.

SHRI M. L. SONDHI : Sir, let this matter be not taken in such a frivolous manner. What is this frivolity ? I am trying to help him. Do not be frivolous.

SHRI RANDHIR SINGH : I love you.

SHRI M. L. SONDHI : Let there be a little seriousness. It is this sort of quality which brings about indiscipline in this House: it is this light-heartedness. He is a fine fellow to meet in the playground; but not here where he brings down the temper of this House. Let him tell the Minister to be forth right.

SHRI RANDHIR SINGH : I am so sorry.

MR. SPEAKER : Do not take the privilege of interrupting every Member when he is speaking. Please do not do that.

12.49 hrs.

COMMITTEE OF PRIVILEGES

Ninth Report

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Sir I beg to move :

> " That this House do agree with the Ninth Report of the Committee of Privileges laid on the Table of the House on the 19th November, 1969."

I do not think it needs any explanation; the report has been circulated.

MR. SPEAKER : Yes. The question is :

> " That this House do agree with the Ninth Report of the Committee of Privileges laid on the Table of the House on the 19th November, 1969."

The motion was adopted.

— —

12 50 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL–(*Contd.*)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि मोटर व्हीकल्ज एक्ट में सबसे बड़ी विशेष धारा परमिट के बारे में है और परमिट देने के सम्बन्ध में जितनी धांधली चल रही है, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है और उसके कारण जनता को जितना कष्ट पहुंच रहा है, उतना सरकार की किसी अन्य व्यवस्था से नहीं। जैसा कि मैंने कल कहा था, बाजार में एक एक लाख रुपये का परमिट बिक रहा है। इसके मानी यह है कि परमिट लेने वाले ज्यादा हैं और गाड़ियां कम हैं। इस स्थिति में यह समझ में नहीं आता है कि सरकार परमिट देने में हिचकिचाती क्यों है ? इसका एक ही कारण मालूम होता है कि सरकार के कर्मचारी भ्रष्टाचार चाहते हैं। उनके पाकेट गर्म होती रहें, इसी कारण से उन्होंने इस प्रणाली को दूषित बना रखा है।

मैं चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाये और जनता को राहत मिले। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार के पास परमिट के लिए जितने भी प्रार्थना पत्र आयें और सरकार जितने प्रार्थना पत्रों को प्रमाणित कर दे, उन सभी को परमिट मिल जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी रूट पर बस चला सकें। 1920 तक यही व्यवस्था थी, लेकिन बीच में षड्यन्त्र चला और जान बूझ कर भ्रष्टाचार उत्पन्न करने के लिए उसमें परिवर्तन कर दिया गया।

यह दलील दी जा सकती है कि अगर एक ही रूट पर ज्यादा बसें हो जायेंगी, तो लाभ नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूं कि लाभ और हानि के बारे में निर्णय करना परमिट लेने वालों का काम है। जहां लाभ नहीं होगा वहां कोई व्यक्ति परमिट नहीं लेगा। परमिट लेने वाले सोच लेंगे कि अमुक रूट पर लाभ होगा या नहीं। अगर किसी रूट पर बसों आदि की संख्या बढ़ जायेगी, तो यात्रियों को लाभ होगा, उन्हें किराया भी कम देना पड़ेगा और वे आराम से यात्रा करेंगे ओवरलोडिंग समाप्त हो जायेगा। इस तरह ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है।

अगर सरकार इस सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर उसने थोड़े ही परमिट देने हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसे यह प्रणाली अपनानी चाहिए कि जितने प्रार्थना पत्रों को वह सही मान ले, बैलट के द्वारा यह डिसाइड कर लिया जाये कि उनमें से किन को परमिट दिया जाये। बैलट प्रणाली लागू करने से भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। अगर सरकार ऐसा नही करती है और अपनी इच्छानुसार परमिट देने की व्यवस्था जारी रखती है, तो उसके कर्मचारियों के पाकेट गर्म होते रहेंगे और आम जनता को बहुत परेशानी होगी।

इस सरकार का कहना है कि देश में कुछ बिजिनेस हाउसिज और कैपिटलिस्टस ने उद्योग में अपनी मानोपली बनाई हुई है और उसको खत्म कर के वह आम जनता और गरीबों को लाभ पहुंचायेगी। यदि उसके इस कथन में कुछ सचाई है और यह केवल नारा नही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह की मानोपली बसिज और ट्रक्स के क्षेत्र में भी है। एक एक आदमी के पास बीस बीस और पचास पचास परमिट और बसें ट्रक आदि हैं। सरकार की नीति के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को काम मिलना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि इस बिल में यह व्यवस्था कि जाये कि एक आदमी को एक से ज्यादा परमिट नहीं दिया जायेगा। जिस व्यक्ति के पास पहले ही कोई परमिट है, जिसको कमाने का धन्धा मिला हुआ है, उसको दूसरा परमिट क्यों दिया जाये? जिस तरह बड़े बड़े बिजिनेस हाउसिज को न जाने कितने कितने लाइसेंस दे दिये गये हैं, वही नीति परिवहन के क्षेत्र में भी नहीं अपनाई जानी चाहिए। जिसके पास पहले ही एक परमिट है, उसको दोबारा न दिया जाये। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक आदमियों को काम मिले। परमिट देने में को-आपरेटिव सोसायटियों को प्रिफरेंस देनी चाहिए। इस बिल में यह व्यवस्था नहीं की गई है।

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : Preference for the cooperative societies is already there in the main Act.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : परमिट देने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था नहीं की गई है।

यह भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिसको परमिट दिया जाये, वह स्वयं बस चलाये। जो बस न चलाता हो और परमिट बेच देता हो, जो किसी दूसरे को परमिट देकर घर बैठे खाना चाहता हो, उसका न केवल परमिट कैंसल किया जाना चाहिए, बल्कि उसके लिए सजा की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

क्लाज 41 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी रूट का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई स्कीम घोषित की जाती है, तो पहले परमिट खत्म कर दिये जायेंगे और सम्बद्ध व्यक्तियों को टेम्पोरेरी परमिट लेने पड़ेंगे और जब माडिफाइड स्कीम घोषित की जायेगी, तो परमिट बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को तीन साल के लिए परमिट मिला है। छः महीने बाद सरकार ने उस रूट का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब ढ़ाई साल तक वह व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी स्थिति में उसको मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जहां तक इन्टरस्टेट परमिट का सम्बन्ध है, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जो नये प्रदेश बने हैं, उनमें एक प्रदेश की टांग किसी दूसरे प्रदेश में निकली हुई है। इसका परिणाम यह है कि एक प्रदेश की बस कहीं जाती है और बीच में किसी दूसरे प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है तो परमिट लेना पड़ता है। पहले यह व्यवस्था थी कि अगर किसी दूसरे राज्य

(श्री ओम प्रकाश त्यागी)

का 16 किलोमीटर भाग रास्ते में आ जाये, तो उसकी छूट होगी, लेकिन इस विधेयक में उसको घटाकर 8 किलोमीटर कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र को घटाना ठीक नहीं है। यदि दूसरे प्रदेश के हिस्से में कोई बस पैसेंजर नहीं उठाती है, तो उसको पास होने देना चाहिए और उसके लिए परमिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

परमिट देने के बारे में व्यवस्था की गई है कि स्कीम के सरकारी गजेट में प्रकाशित कर दिये जाने पर लोग परमिट के लिए सप्लाई करें। मै कहना चाहता हूं कि हर एक आदमी गजेट नहीं पढ़ता है। गजेट पढ़ने वाला एक खास वर्ग है। मेरा सुझाव है कि कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में, जो किसी क्षेत्र की अपनी भाषा में निकलता हो और एक स्थानीय समाचार पत्र में स्कीम को प्रकाशित किया जाये, ताकि साधारण जनता उसके बारे में जान सके।

श्री इकबाल सिंह : एक्ट में यह भी है। मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने एक्ट को पढ़ा नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने पढ़ा है। उसमें कहा गया है, "ऐनी न्यूज पेपर"। उसमें इंगलिश का समाचार पत्र भी आ जायेगा। मैं कहता हूं कि लोकल लैंग्वेज के एक दैनिक समाचार पत्र में स्कीम को प्रकाशित किया जाये।

सरकार की ओर से राष्ट्रीयकरण का नारा बहुत जोरों से लगाया जा रहा है। मै राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं, मैं उसका पक्षपाती हूं। परन्तु राष्ट्रीकरण वहीं तक सीमित रहना चाहिए, जहां तक जनता का हित हो, उसको हानि न पहुंचे। ऐसे राष्ट्रीयकरण का कोई अर्थ नहीं है, जिससे जनता को हानि और कष्ट होता है। जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं कि उनसे तमाम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सरकार को कम से कम दस बीस साल तक प्राइवेट बसों और ट्रकों का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो या कम्यूनिस्टिक सिस्टम, उसका मूल लक्ष्य होता है जनता की भलाई। इसलिए सरकार को देखना चाहिए कि किसी व्यवसाय आदि को राष्ट्रीयकरण करने से जनता की भलाई हुई है या नहीं।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह दिल्ली के अन्तरप्रान्तीय बस अड्डे पर आ कर देखें कि वहां क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसे वहां खड़ी हैं और वहीं गढ़ मुक्तेश्वर जाने के लिए प्राइवेट बसिज भी हैं। प्राइवेट बसों के बुकिंग आफिस पर यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं है। लोग आराम से टिकट लेते हैं और बसों में बैठते चले जाते हैं। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश रोडवेज के बुकिंग आफिस पर जून के महीने में स्त्री पुरुषों की एक लम्बी लाइन लगी रहती है। बुकिंग क्लर्क चाय आदि पीकर अपनी सुविधा के अनुसार आता है। वहां पर टिकट देने में भी बहुत गड़बड़ है। पुलिस के सिपाही अन्दर जा कर पांच सात टिकट ले आते हैं और बाकी लोग परेशान होते हैं। चाहें कोई बस खाली हो और केवल दो तीन सवारियां उसमें बैठी हों, लेकिन यह देखने की कोशिश नहीं की जाती है कि यदि कोई और लोग उस बस से जाना चाहते हैं, तो उनको भी ले लिया जाये। गढ़मुक्तेश्वर में मैंने एक ऐसी ही घटना देखी। एक उत्तरप्रदेश रोडवेज की बस में केवल तीन सवारियां थी। करीब दस बारह मुस्लिम व्यापारियों को मुरादाबाद जाना था। उन्होंने बस को रोका और कहा कि हमने भी मुरादाबाद जाना है। शाम का, सूर्य छिपने का समय था।

13 hrs.

लेकिन बस ड्राइवर ने रोका नहीं। कहा नहीं, नहीं और बस चल पड़ी। मैंने कहा कि रोक लो, बैठा लो, लेकिन उसने कहा नहीं,

बस नहीं रुक सकती। फिर मैंने कहा कन्डक्टर को कि बता तेरी बस होती तो रोकता या नहीं? उसने कहा, रोकता ही नहीं, चाचा और बाबा कह कर बुलाता और बैठाता। मैं ने कहा कि फिर आज क्यों नहीं रोका? तो उसने कहा कि मुझे क्या पड़ी है, मुझे तो अपनी तनख्वाह मिलती है और मैं कायदे के अनुसार काम करता हूं। यही वजह है आज तमाम बसें हानि पर चल रही हैं। मेरा सुझाव है कि आप सरकारी बसेज भी चलाइये लेकिन उसी रूट पर प्राइवेट-बसों को भी इजाजत दीजिए जिससे कि कम्पीटीशन में जनता का लाभ हो। आज हालत यह है कि आप न अपनी बसों को ठीक चला सकते हैं न उन्हें ठीक रख सकते है। यहीं दिल्ली में ही चल कर देख लीजिए। 100 के लगभग बसें खड़ी होंगी जिनका एक छोटा सा पुर्जा ठीक करना होगा जिसे एक आदमी दो मिनट में ठीक कर सकता है। लेकिन चूं कि वह सरकार की है, किसी को कोई चिन्ता नहीं इसलिए इस प्रकार की धांधली समाप्त होनी चाहिए जिसके कारण जनता को कष्ट उठाना पड़ता है। मेरा यह कहना है कि राष्ट्रीयकरण के बजाय इन बसों का आप समाजीकरण कीजिए। आप समाज की कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा इन बसों को चलाइये। गवर्नमेंट अपनी ओर से बसें न चलाए, समाज की ओर से जनता की ओर से चलाए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और ड्राइवर्स के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा ऐक्सीडेंटस होते हैं। आज ही आया है पेपर में कि दिल्ली में रोज पांच आदमी मर जाते हैं ऐक्सीडेन्टस के द्वारा। उसका मूल कारण यह है कि ड्राइवर्स की ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स बने हुए हैं जहां से सौ डेढ़ सौ रुपया देकर बड़ी आसानी से ड्राईविंग का लाइसेंस मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट के ट्रेनिंग स्कूल खोलिए, उनको पूरी ट्रेनिंग दीजिए और फिर चलाने का लाइसेंस दीजिए। इसके अलावा जब मोटर ड्राईविंग लाइसेंस के लिए ड्राइवर उसको रिन्यू कराने के लिए आता है तो आप ने उसमें शर्त लगा रखी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में दो और यह उस ड्राइवर के लिए है जो किराये पर या नौकरी पर मोटर गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है। आप का यही तो तात्पर्य है कि उसकी आंख खराब न हो जिससे कोई ऐक्सीडेन्ट वगैरह न हो जाय। लेकिन और जो कार-होल्डर्स हैं क्या उनकी आंखों को आप ने ईटर्नल समझ रखा है कि वह खराब होंगी ही नहीं? उनके लिए इस मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों नहीं है? बेचारे गरीब ड्राइवर के लिए ड्राईविंग लाइसेंस रिन्यू करते समय आप ने यह शर्त लगा रखी है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि 40 साल के पहले एक बार एक आदमी ने अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया है, अगर 40 साल से कम उसकी आयु हो तो इस के बीच में रिन्युअल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट उसे दोबारा पेश करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और यह मेडिकल सर्टिफिकेट हर एक के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। नम्बर प्लेट्स के मुताल्लिक एक बात और कह कर समाप्त करता हूँ। यह राष्ट्र एक है, सबका है, सबको समान सुविधा होनी चाहिए। आज बस किसी का एक्सीडेन्ट करके भागी जा रही है और न० प्लेट है तेलगू भाषा में। इसलिए आप यह शर्त लगाइए कि हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में प्लेट के नम्बर जरूर होने चाहिए। यहां दिल्ली में आप ने चालान कर दिया है केवल हिन्दी में प्लेट होने पर। यह माइल स्टोन जहां विदेशों के लोग भी आते हैं, हिन्दी और अंग्रेजी में जरूर होने चाहिए। उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी होने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

MR. SPEAKER : Shri Arumugham He will speak after lunch. We now adjourn for lunch to meet at 2 O'clock.

13 04 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI M. B. RANA *in the Chair*]

RE. RETRENCHMENT IN CERTAIN DEFENCE ESTABLISHMENTS

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I want to make a submission on a very important matter, Sir. The whole question is this. This morning, myself, Shri Jyotirmoy Basu and other's have tabled a call attention notice regarding the apprehended retrenchment in some of the Ordnance clothing factories. These defence installations are situated at Shahjehanpur, Kanpur and Avadi where nearly 3000 workers have been declared surplus only because the workload was transferred to the private sector against the assurance of the hon. Minister to the House. This Government claims to be a socialist Government. They talk of Bank nationalisation whereas the workload in the ordnance factories is transferred to the private sector. I would only request you to kindly convey our feelings to the hon. Defence Minister.

Sir, it is a matter for regret that the Minister of Parliamentary Affairs is not here. I do not know whether his assistant is here. Somebody should convey our feelings to the Defence Minister and let him make a statement on this because there is going to be a strike simultaneously in all the five ordnance factories. I can tell you as President of all India Defence Employees' Federation that there is going to be a retrenchment in ordnance clothing factories on account of the transfar of workload in favour of the private sector.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : सभापति महोदय, हम भी इस का समर्थन करते है। आप मंत्री महोदय से कहें, कि इस पर तत्काल यहां आ कर आश्वासन दें।

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : This is a very important issue, Sir. Government should take immediate action and carry out the assurance given to this House.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : I support it. I am also a Vice-President of the All India Defence Employees Federation.

MR. CHAIRMAN : There is no regular motion before the House. There should be proper notice of the motion and you may see the Speaker and if he allows, I have no objection.

SHRI S. M. BANERJEE : I wrote a letter to the Speaker. I can assure you, Sir, that I do not generally raise anything unless I write to the Speaker. The Defence Minister must be asked to make a statement on this matter.

MR. CHAIRMAN : Your call attention notice has been disallowed by the Speaker. However, inspite of that, if you want to bring it to the notice of the House, you first speak to the Speaker before you raise it here.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, on a point of personal explanation. I can assure you, Sir, that I do not raise irrelevant matters. Sir, this is my third term in this House. I do not believe in irrelevance and other things. I can assure you that I did write to the hon. Speaker. Sir, after 12 noon so many things come up and sometimes we do not want to embarrass the Speaker. When the House reassembles after lunch at 2 pm there is a comparatively peaceful atmosphere in the House. This is a very important issue. Sir, you usually hear things and the Minister must also take note of that. I have raised this issue and I do not want to give any embarrassment to you and I want the hon. Defence Minister to make a statement because 3000 men are likely to strike work in case the situation does not improve and all this work in these clothing factories which has been cancelled and off-loaded to the private sector should be brought back to the ordnace factories. If the Government is sincere, they should do something.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : वरना प्रधान मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन होगा। इन्दिरा गांधी की जय के बजाय मुर्दाबाद कहा जायगा।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : It is a clear case where the Defence Minister has not fulfilled an assurance that he had given and he had categorically said that they would not be retrenched.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या कोई सरकारी आदमी इसके बारे में नोट कर रहा है ?

MR. CHAIRMAN : If it is a breach of an assurance on the part of the Minister, you can bring it to the notice of the Committee on Assurances.

— —

14.10 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL---*Contd.*

**SHRI R. S. ARUMUGAM (Tenkasi) : Mr. Chairman, Sir, I feel that the Motor Vehicles (Amendment) Bill which is under discussion now, will do no good to anyone. Dr. Keskar Committee which was appointed by the Government some years ago recommended that there should be uniform taxation on Motor Vehicles throughout the country. This Report is with the Government for some years now. But I do not find any provision in this amending Bill incorporating this recomendation.

I would say that the workers in this field would also not get any benefit from this Bill. On the contrary, when this Bill becomes a law the workers will be put to a great hardship. I will give an example in this regard. There is a provision in this Bill according to which the driver has to submit a medical certificate at the time of renewal of his permit. I am sure that the driver will be unduly harassed by this provision and he will be put to financial inconveience also for getting a medical certificate every time he has to renew his permit. I request the hon. Minister to re-examine this question and see to it that there is no compulsion on the driver to submit a medical certificate at the time of renewal of his permit.

Clause 17 of this amending Bill enunciates that a transport vehicle should not be used on a route which is not covered by its permit. If any break-down occurs, then the vehicle has to be taken for repair immediately. The permitted route may be a long-winding one and may not be posssible to take the vehicle under repair all the way. Some exemptions have also been enumerated under this Clause giving permission for vehicles to be taken even on unauthorised route under certain conditions. I propose that an amendment should be incorporated in this Clause, permitting vehicles under repair also to move on unauthorised routes for the purpose of repair. I suggest that this amendment may be worded as follows :

> "To any transport vehicle while proceeding empty to any place for the purpose of repair."

I request the Government to include this exemption also in this amending Bill.

When the principal Act was last amended, some concessions in regard to issuance of stage carriage permits were extended to cooperative societies engaged in Motor Transport. I would like to stress here the need for extending such concessions to the members of scheduled castes and scheduled tribes interested in motor transport. As no amendment has been proposed to section 47 of the principal Act in this Bill, I am not able to suggest formally any amendment to that Section. In this connection, I wrote to the Prime Minister and also to the Minister of Transport stating that the Government should themselves bring forward an amendment to Section 47 of the principal Act extending this concession to the scheduled castes and scheduled tribes. I have received a reply to my letter in which it is said that the members of the scheduled castes and scheduled tribes will not be in a position to mobilise resources to the tune of Rs. 75,000/- which is the price of a bus and that is why they do not propose to bring forward any amendment in this regard. I was surprised to get such a reply. In fact I was greatly upset to hear such a plea from the Government. 95% of the operators do not buy vehicles with their own money. They are financed by other in buying these vehicles. On both the sides of Mint Street in Madras you will find rows of financiers ready to offer a loan of any amount of money when a stage carriage permit is obtained. In addition to these financiers, the scheduled banks also advance money to the private operators. The Indian Bank, the South Indian Bank, the Canara Bank and

**The original speech was delivered in Tamil.

(Shri R. S. Arumugam)

many such banks have been giving financial assistane to these people and I am sure that they will continue to do so in future. Now the major banks have been nationalised for the ostensible purpose of offering financial assistance to the weaker sections of the society. There is no justification in putting forth the plea that they will be finding it difficult to get an amount of Rs. 75,000/- for this purpose. Under Article 46 of the Constitution it is incumbent on the Government to promote the economic interest of the scheduled castes and scheduled tribes. Unless these people advance economically, there will be no economic development in the country. What facilities have so far been offered by this Government for the upliftment of the Harijans and other weaker sections of the society ? Everyone present in this House will agree with me that nothing tangible has so far been done for the economic development of this section of our society. We are talking of socialism and we profess the we shall remove disparity in the living standards of the different sections of our society. The Government of India of late has arrogated to itself a special role in the upliftment of the socially economically backward classes in our society. Socialism should not be a more shibboleth. I request thatthe Government should live upto its professions, atleast partially, and bring forward an amendment to Section 47 of the principal Act. I have roughly framed an amendment as follows :

> "If applications from members of the scheduled castes and scheduled tribes are received and found in order, priority shall be given to them over the other applicants."

Though Shri Raghuramaiah has written to me indicating his helplessness, even now it is not too late to bring forward an amendment of the kind I have suggested with a view to helping the socially and economically backward clases, especially the scheduled castes and scheduled tribes. With these few words, I conclude my speech.

श्री शशि भूषण (खारगोन) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है। वैसे वे अच्छा बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है।

AN HON. MEMBER : There is the translation being done.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli) : When you speak in Hindi we are also embarrassed. We do not follow anything.

MR. CHAIRMAN : He can speak in his mother tongue, Tamil.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah) : I rise to support this Bill that has been so ably moved by the Deputy Minister of Transport. This Bill was first introduced in 1965 by the then Transport Minister, namely Shri Raj Bahadur in the Rajya Sabha, and then in 1966, when Shri C. M. Poonacha was the Transport Minister, he asked for a Joint Committee. But unfortunately in 1967 the Lok Sabha was dissolved. So, it came again to the Rajya Sabha, and Dr V. K. R. V. Rao asked for a Joint Committee which was then appointed. The Joint Committee has since submitted its report to the Members. This Bill had been demanded for a long time by the people of the country, because the old 1939 Act could not serve the purpose of the present day needs, but then our hon. Minister has already admitted that this Bill which seeks to amend the 1939 Act is not sufficient to meet the needs of the time. So, he has promised to us that a comprehensive Bill will be brought forward before the House at a future date. And we very much hope that that Bill will come very early.

When the 1939 Act was formulated by the then Government run by the British imperialists here, the necessity was in a different direction from their point of view. So, the Act has many lacunae. There are also many handicaps which have really hampered the progress of road transport. Road transport system is the life-line of a developing country, and if we want to develop our rural areas, then road transport is the only thing that can do it. In that context, a comprehensive Bill to amend the whole Act should have been brought forward But, unfortunately, the present Bill is not sufficient enough for that purpose. If we are to connect the rural areas with the entire population of the country, the road transport system requires some kind of incentives. I find that not only have the incentives been absent, but certain hurdles

have been created, and the whole system had been overburdened with such heavy taxation that it was impossible for the road transport operators either to thrive or to continue their business.

It has been said that our vehicles are taxed the heaviest in the world. So something has to be done in that direction. We are glad that the Road Transport Taxation Enquiry Committee has pointed that out. This is the observation that the Keskar Committee have made in their final report :

> "Failure to realise the potential role of road transport in economic development and continuance of obstacles and barriers (like unduly heavy taxation burden, regulations, Octroi and other check posts, etc.), which keeps road transport from developing and making its full contribution, would only be at the expense of country's economic and social development and therefore suicidal "

This is the opinion expressed legitimately by the Enquiry Committee. The Committee has finally observed :

> "If this is not possible, the least that should be done is that no further changes should be made in the existing level of taxation except after mature consideration in the light of principles enunciated by the Committee and with reference to the advice of the proposed expert advisory bodies."

So, relief should come in motor vehicles taxation.

Having been connected with a transport organisation for about 20 years, namely, the premier organisation of the Taxi Operators, namely the Calcutta Taxi Association, I can tell you that the operational cost has gone up to such an extent that it is impossible to carry on the business of running these public service vehicles any more. We have got to get our tyres at blackmarket prices We have got to get our spare parts not in the open market but in the blackmarket by paying sometimes even 200 per cent increase in prices. The cost of petrol and lubricants has also gone up so high. In fact, the operational cost has gone up on the average by more than 50 per cent.

You will be glad to know that there are about 2.75 lakhs trucks and about 89,000 buses and about 35,000 taxis; 90 per cent of these motor operators are persons with just only one motor vehicle. Therefore, they cannot keep accounts properly, and they cannot manage those things. It is a difficult job for them to do those things.

I would like to urge that road transport is the only thing that can help us to solve our unemployment problem. Appalling unemployment is there all over the country, and if we can expand the possibilities of the road transport system, it is possible to absorb quite a number of unemployed people. We would require for one truck about 12 to 15 persons. Therefore, it is essential that the transport system should be allowed to work in such a way that we are not hampered by any obstacles.

My hon. friend Shri Tulsidas Jadhav has said that octroi is not a necessity. In fact, that is not his opinion only. The Road Transport Taxation Enquiry Committee themselves have said :

> "The Committee strongly feel that octroi is one of the greatest hindrances in the way of commerce and economic development of the country. Advanced countries realized it long ago and abolished octroi. While we whould leave to the State Governments to choose the alternative that suits them best, we would emphasise that octroi should be abolished as quickly as possible."

Then, we have also to think of developing inter-State transport. The Inter-State Transport Commissioner has not been able to function so well because of the limitations under which he is functioning.

If we have to increase the capacity of the road transport system as a whole, we have to see that the Inter-State Transport Commissioner is equipped with all necessary powers. There is a slight attempt in this Bill in that direction, but it is not sufficient.

We see that in many States, the transport system is virtually paralysed by overcrowding in buses. In Calcutta, Howrah

[Shri Krishna Kumar Chatterji]

proper, and other large cities people have to travel like beasts in the buses. The transport system is not adequate to cope with the traffic that is offering. People have to attend to their duties and have to take recourse to the transport system for the purpose. Therefore, on the question of penalising buses on account of overcrowding and other things, a lenient view has to be taken.

In conclusion, I would appeal to the hon. Deputy Minister to act up to his promise by bringing forward a comprehensive Bill soon so that we can deliberate on it and give a new dimension to the road transport system.

**SHRI KIRUTTINAN (Sivaganga) : Mr. Chairman, Sir, the Motor Vehicles (Amendment) Bill has been passed by the Rajya Sabha and it is now under discussion in this House. I am grateful to you for having given me an opportunity to speak in Tamil on this Bill. I would also take this opportunity to convey my gratefulness to this House and to the hon. Speaker for having extended this facility of speaking in our mother tongue on the Floor of this House. When I speak in Tamil on this Bill, I am paying my homage not only to the Tamil language, as such, but also to our great and inimitable leader, revered Anna, honoured by the people of Tamil Nadu as South Indian Gandhi.

This Motor Vehicles (Amendment) Bill should have been brought forward in 1965. Though belated, it is good that this Bill has been introduced now. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I extend my whole-hearted support to this Bill as it contains many salutory provisions.

I do not think we should be complacent to think that we will be able to fulfil all the needs of the people concerned by the introduction of this Bill. The Minister himself has assured this House that a more comprehensive Bill will be introduced in this House in course of time and I request him to do it at an early date.

When I began to speak on the provisions of this Bill, I am constrained to say that the road mileage in our country is very meagre. Unless you have enough roads, the road transport will never flourish In the total national income the road transport contributes 20%. Annually we get about four hundred crores of rupees from road transport, but we invest only an amount of Rs. 140 crores on the construction and maintenance of roads. The people of Tamil Nadu has this grievance that the Central Government has not been making adequate allocation of funds for road transport in Tamil Nadu. I request the Hon. Minister to look into this and do the needful.

Recently, our Deputy Minister of Transport toured Tamil Nadu and I requested him in person that the East Coast Road should be declared a national highway. He informed me that in the Fourth Five-Year Plan about three thousand miles of roads would be declared national highways and the East Coast Road would be one of them. As I fear that there is no possibility of this being done in the Fourth Plan, I request the Hon Minister to accede to the demand of Tamil Nadu people and declare the East Coast Road as a national highway.

I am sorry to say that there is no provision in this Bill as to what language should be used for inscribing matter on the milestones. A Jana Sangh Member perorated that it is enough if Hindi and English are used on the milestones. So far as I am concerned, I am certain that it will do if English and regional languages are used for this purpose. There is no need to write anything in Hindi. Delhi is not only the capital of India but also a cosmopolitan city. Not only the people from different States of the country but also from other countries of the World live here. In many places, I have seen that English has been removed from notice boards and sign boards and its place has been usurped by Hindi. I regret that this should have been allowed to happen here. I want to bring this to the notice of the Hon. Minister.

Many hon. Members referred to Clause 41 of this Bill. I wish so bring to the notice of this House that this clause has been incorporated in this Bill at the suggestion of the Tamil Nadu Government and I am sure that this House will express its appreciation of the Tamil Nadu Government for this.

**The original speech was delivered in Tamil.

There is opposition to nationalisation of bus routes; this opposition has emanated from many directions. Section 41 is not a new section providing for such nationalisation. In the principal Act, Section 68(f) empowers the Government to undertake nationalisation of road transport. As there were certain lacunae in the principal Act, the Tamil Nadu Government conveyed its desire that Clause 41 should be incorporated in the new Bill rectifying the lacunae in the existing Act. I am grateful to the Central Government that they have brought forward this Bill with Clause 41. I am sure the hon. Members belonging to different groups and parties would also welcome this.

Finally, I would like to say that of late we are talking too much about socialism. As compared to the Central Government and the Central Ministers I make bold to say that the State Government and the State Ministers have more contact with the masses for whom we want to establish a socialistic society. The Central Government enacts many laws, but the responsibility of implementing them is thrown on the State Government as if they were servants to carry out the orders of a master. The Congress Party, when it was a monolithic political organisation ruling the country, did not pay heed to the request of the State Governments for decentralisation of powers, but I think, in the changed circumstances when the ruling party is split into two, the Central Government will bring forward a constitutional amendment giving more powers to the States so that the popularly elected Government there will be able to fulfil the desires and ambitions of the people with full legal support behind them. I am sure that the Government of India will consider this proposition and do the needful at an early date. With these few words, I conclude my speech.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमेन महोदय मैं, मन्त्री साहब ने जो बिल पेश किया है, उसकी हिमायत करता हूं और चूंकि इस सिलसिले में आइंदा एक बिल आएगा, उसके लिए कुछ देहात की तरफ से सुझाव देना चाहता हूं।

पहली बात जो मैंने पिछली बार भी कही थी और उस वक्त जो बहस हुई तो उस समय डा० वी० के० आर० वी०, जो कि इस विभाग के मन्त्री थे, ने कहा था कि वे उधर ध्यान देंगे, उस बात को आज फिर मैं दोहराना चाहता हूं। आम तौर पर बड़े बड़े शहर जो हैं उनमें जगह जगह रिंग रोड्स बनी हुई लेकिन जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर जो बड़े बड़े गांव हैं उनके बीच से जो सड़कें जाती हैं, उन पर एक्सीडेन्टस हो जाते हैं। तो मैं यह नोटिस में लाना चाहता हूं कि उन रोड्स पर डेली हादसे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे और केटिल जो बीच में आ जाते हैं, मारे जाते हैं। तो जो बड़े बड़े गांव नेशनल हाइवेज पर हों, उन के लिए रिंग रोड्स या बाई-पास बनाने के लिए आप ध्यान दें।

दूसरी बात जो मैं खास तौर से कहना चाहता हूं वह यह है कि आप ने इनीशियेट करके स्टेट गवर्नमेंटस को कहा है कि जो गांव नेशनल हाईवेज के साथ लगते हैं, जो एक एक, दो दो मील के हैं, उनके लिए एप्रोच रोड्स का बंदोबस्त करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे जहां जनता को सहूलियत होगी, वहां आपको टैक्स और किराये वगैरह से फायदा होगा। पैसेन्जर टैक्स ज्यादा लगेगा और उससे गवर्नमेंट को फायदा होगा।

तीसरी चीज जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा वह यह है कि जगह जगह पर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवेज के जो बस के अड्डे हैं, वहां पर शेडस का बन्दोबस्त नहीं है। बारिश से और सूरज की गर्मी से मुसाफिरों को बचाने के लिए आप को शेडस का बन्दोबस्त करना चाहिए। ये ही तो आपके कमाऊ पूत हैं, उनसे आपको फायदा पहुंचता है और उनसे सारा काम चलता है और वहां पर इतनी ओवरक्राउडिंग होती है कि कई कई घन्टों तक हमारे बच्चों, औरतों और भाइयों को ठहरना पड़ता है। वहां पर वे हूंगर, ढोरों की तरह क्राउडेड रहते हैं और इससे उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो जब आप नेशनेलाइज करते हैं तो वहां पर बन्दोबस्त सरकार का

[श्री रणधीर सिंह]

होना चाहिये और साथ ही साथ यह भी हो कि आप के जो कंडक्टर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, वे लोग भी जाकर, जहां टर्मीनेशन प्वाइन्ट होता है, आराम करें और थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकें। इसके लिए जो आर० टी० एज० हैं उन को स्पेसीफिक इन्सट्रक्शन्स दें। उन लोगों की जो तकलीफें हैं उनके बारे में जो मेमोरन्डा आते हैं, उन पर आप ध्यान दें।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आर० टी० ए० का जो कान्सटीट्यूशन है, वह डेमोक्रेटिक नहीं है। उसमें नोमीनेशन किया जाता है और कमिश्नर, मिनिस्टर या गवर्नमेंट जिसको चाहें नोमीनेट कर देते हैं। मेरा कहना यह कि उसमें काट्रेक्टर्स और ट्रान्सपोर्टर्स का रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। दो साल की मियाद को अगर आप चार साल बढ़ा दें तो एतराज की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यह डेमोक्रेटिक हो और उस में उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा रेप्रेजेन्टेशन हो, जिससे उनकी तकलीफें हैं वे वहां आ सकें।

जहां तक परमिट का सवाल है, अव्वल तो मैं परमिट के हक में नहीं हूं और चाहता हूं कि परमिट नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें करप्शन को बढ़ावा मिलता है। आगे चल कर तो यह हो सकता है कि साइकिल का परमिट लेना होगा और छोटी छोटी रिक्शा का परमिट भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि परमिट सिस्टम रहे, तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि जो गरीब लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं, फौजी लोग हैं, एक्स-सर्विसमेन हैं, उनको परमिट देने में तरजीह दी जाए।

अगली बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि देहात में जो ट्रेक्स कच्चे हैं, उनके लिए आप ने टूटी फूटी बसें दे दी। आखिर देहात भी तो भारत का हिस्सा है। बढ़िया बसें आप नन्दा और कृष्ण को दे देते हैं जो कि बिक्टरी और कैपिटल सर्विस चलाते हैं। जो अच्छी अच्छी बसें हैं वे तो आप बड़े बड़े सरमायदारों को दे देते हैं, लेकिन देहातों में कोई अच्छा बन्दोबस्त नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जो रूटस पैसेवालों को आप देते हैं 50 परसेन्ट देहात की रूटस उनको दी जाए। होता क्या है कि टूटी फूटी बसें जो होती हैं वे तो गांव के लिए दी जाती हैं जो कि बहुत जल्दी टूट जाती हैं और अच्छी बसें बड़े सरमायदारों को दी जाती हैं। हल्वा हल्वा वे खा जाएं और गरीब लोगों को बेकार बसें मिलें। तो मैं आप से कहना चाहूंगा कि कच्ची रूटस उनको दी जाए और ज्यादा से ज्यादा दी जाए ताकि वे एफीशियेन्ट सर्विस दे सकें।

(व्यवधान)

एक बात मैं ट्रिब्यनल्स के बारे में कहना चाहता हूं। चेयरमेन महोदय, इस बिल में जो ट्रिब्यनल्स की बात कही गई है, वह बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो आर० टी० एज० और एस० टी० एज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन में जाते हैं, लेकिन जूडिशियल ट्रिब्यनल की जो बात की गई है, मैं उस की तारीफ करूंगा। यूनिफार्मली एक्ट इस तरह का लागू हो।

मैं खत्म कर रहा हूं। नेशनेलाइजेशन आफ ट्रान्सपोर्ट की जो बात है, मैं कहूंगा कि सारे देश में आप नेशनेलाइजेशन कीजिए। इस वक्त क्या हो रहा है कि छोटे छोटे लोग तकलीफ उठा रहे हैं। उनको आप सहूलियत दीजिए। हरियाना में नेशनेलाइजेशन बड़ी बड़ी रूटस का कर दिया गया और प्राइवेट आदमियों के हाथ में नहीं रहा। नेशनेलाइजेशन आप बड़ी बड़ी रूटस का कर दीजिए और उन को यह इन्सट्रक्शन्स जारी कर दीजिए।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि सफर तो आदमी करता है पांच मील का और उसको किराया देना पड़ता है दस मील का। मैं चाहता हूं कि दोबारा माइलेज को नपवाया

जाए । सोनीपत से रोहतक का असल फासला है 30 मील और कागजात में दिखाया गया है 35 मील जो पुराने जमाने से चला आ रहा है । यहां दिल्ली से वह 60 मील है और कागजात में 70 मील दिखाया गया है । अगर यात्री बीच में गांव के पास भी उतर जाता है तो उसको किराये आगे तक देना पड़ता है । वह छह मील पर ही उतर जाता है, पर उसको दस मील का किराया देना पड़ता है । जो बीच में अड्डे पर उतरे तो उसको जिस प्वाइंट से वह चढ़ा और जिस प्वाइंट पर उतरा वहां के फासले का किराया देना चाहिए जब कि उनसे लिया जाता है दूसरे अड्डे तक ।

लोकल बसेज की बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने शहरों में तो लोकल बसें चला दीं, यहां से नरेला ठीक है, गाजियाबाद ठीक है, मगर जहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं उनसे 15 मील के अन्दर जो रूट हैं, जो कि तहसील हैडक्वार्टर्स को मिलाते हैं ऐसे रूटों पर लोकल बसें चलानी चाहिए क्योंकि देहात का आदमी मुकद्दमों में जाता है, और दूसरे कामों के लिए जाता है तो उसको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । जब आप शहर में बसें चलाते हैं तो देहात वालों को भी सहूलियत दी जाए ।

स्कूटर के बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूं और वह यह कि स्कूटर्स में दुनिया भर का करप्शन है । अगर स्कूटर में कोई 10 मील जाता है तो उसमें बैठता है 25 मील । ये लोग पुलिस वालों से मिले रहते हैं और जनता से पैसा लूटते हैं । अक्सर ऐक्सीडेंट भी स्कूटरों के होते रहते हैं । अगर आप चैकिंग कराइये तो आपको पता लगेगा । अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, तो आप एम० पी० को भी चैकिंग के लिए लगा लीजिये । यह आप देखें ताकि पब्लिक को कोई तकलीफ न हो । उनमें खास तौर पर ओवर लोडिंग होता है, उसके लिए भी आप ध्यान दें ।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर्स के लिए आपने ऐसा कानून रखा है कि वह घर के 5 आदमी भी नहीं बैठा सकता । वह अपनी चौधराइन को बैठाकर भी कहीं ले जाये तो पुलिस वाले उसका चालान कर देते हैं । मोटर व्हीकल एक्ट में आपको ट्रैक्टर के लिए छूट देनी चाहिये । किसान का बेटा अगर अपने पड़ोसी को बैठाकर ले जाता है तो उनका चालान होता है, यह चीज बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए ।

मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया ।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Mr. Chairman, Sir, I think this amending Bill which is before the House is just a patchwork. There are some pinpricks here and there. I feel that after 22 years of freedom, this patchwork system of bringing Bills would not solve the problem, because, when the Motor Vehicles Act was enacted in 1939, the whole objective was that the British people wanted to keep the entire power with the officers. After 1939, the first Bill which was broughtforward for consideration here was in 1965, and then it is coming here for discussion in 1969.

There was a Committee for the reorganisation of road transport in 1959, and the Committee had also given certain recommendations. But even from 1959 to 1969, so many changes have taken place in India. National highway have come up, and the national highways have thrown up some new problems for the drivers, conductors and the travelling public as well : indeed it has thrown up all sorts of problems. Therefore, instead of bringing some sort of patchwork here and there, it would have been much better if a serious rethinking had been made over this matter and a comprehensive Bill was brought forward before this House, because I feel that the essence of success is the mobility of the people. Unless there is mobility provided for the people, progress will be retarded. For providing mobility, transport is a very important factor.

In the transport system, four sets of people are involved—(a) the travelling

[Shri S. Kundu]

public, (b) the crew consisting of drivers, conductors, etc., their needs, hopes and aspirations. (c)Government and(d) the people who own the transport system, whether they are cooperative societies or individuals. I am sorry to say this Bill has not met the requirements of these four sets of people.

The permit system has given so much vested power to the officers in the Government that it has become a source of corruption. The Road Transport Coordination Committee which submitted its report in 1959 pointed out that the permit system gives a lot of discretion to the officers, who try to cash it into financial rewards. I am sorry to find that section 55, which enunciates the main features of the permit system, is not being amended by this Bill at all.

In 1939, the British thought that the cooperative sector should be given preference in permits, but this remained only on the statute and was never implemented. There are a number of unemployed people—engineers, technicians, etc. Some provision should have been made in this Bill for helping them to form partnerships, and cooperative societies, etc During the last 10 years, the travelling public have increased considerably and they could have provided more buses on the crowded routes. But I find there is no such assessment made in this Act.

Lots of things are involved in giving a permit. In the Bill, there is mention of a judicial tribunal. I suggest that the entire system of giving permits should be handed over to the judicial tribunal. I have tabled a Bill in which I have said that the licensing system should go to a judicial body headed by a High Court or Supreme Court judge. Similarly, the entire system of giving permits should be handed over to a judicial tribunal who would decide each case on the basis of its merit, without showing any favours.

There are various types of corruption. Taking money and issuing permits is one way. Another way is to have *benami* transactions. Somebody has got some influence in the Government department and he gets two or there permits. Then, he gives it to some other people for some money. The Act says that a permit cannot be transferred. But they say, "We are not transferring it. We are holding it in our name. The other people are running the bus in my name." There is no provision in this Bill for checking such *benami* transactions.

The most important thing is about conductors and drivers. I take my hat off for the sturdy *sardars*. One *sardar* is piloting this Bill. The *sardars* are really the pioneers of national integration. They drive big trucks for thousands of miles. There is a definition of State Transport Undertaking given in section 68A. When there is so much talk of socialism, at least a breakthrough should be made in this section, providing for workers' representation, so that the hopes and aspirations of the workers could be fulfilled and they may get their due share. But I find no such provision in this Bill.

Most of the drivers and conductors are semi-literate and some are uneducated I have nothing against them, but sometimes some of them are very rude probably because their pay scales are very bad and they are neglected. In Calcutta, graduates and MAs come for posts of conductors. They need sympathy and training. Their service conditions—salary, leave, etc.—have to be improved. You should give them their proper status. Bus drivers and conductors must be given orientation courses and lessons of good behaviour, followed by better wages and better amenities. But there is no such provision in this Bill.

The Road Transport Coordination Committee in 1959 made a very valuable recommendation about the system of giving permits for operating in rural areas. People in the rural areas are gradually becoming mobile. We must make them more and more mobile. A certain sector of people have taken advantage of our national highways. The poor people also must be enabled to take advantage of the national highways and they should be assured of cheap mobility. Therefore, when you give a permit to somebody for a remunerative route, you must also give him an unremunerative route on the rural side. There is no such provision in this Bill to meet the need of the rural people.

Without going into more details, I would simply say, this sort of patch work will not solve the problem I would call upon the minister to do some serious thinking Let him bring forward a comprehnsive Bill in the near future incorporating all these suggestions I have made.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, मै सरदार इकबाल सिंह को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि वह बहुत ऊंचे आदमी हैं। हैंडसम इज ही वेंट हैंडसम डज। इसी लिये मैं उन को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन बिल में कमियां इतनी हैं कि अच्छा होता कि यह छः महीने बाद लाया जाता, लेकिन कम्प्रिहेन्सिव बिल होता और सम्पूर्ण इलाज करता। यह छोटी सी चीज हम देखते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती कि दरख्वास्तें आती है 30 हजार, 40 हजार और परमिट मंजूर होती हैं सिर्फ तीन या चार। जो ज्यादा से ज्यादा शराब पिला सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा रिश्वत दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा इल्लीगल ग्रैटिफिकेशन पेश कर सकता है उन की दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं। क्यों यह करप्शन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है ? सीधा कानून होना चाहिये कि कोई बस ले आये, जो आकर दर्ज कराये वह परमिट का मालिक होगा। परमिट सिस्टम खत्म होगा तो करप्शन दूर हो जायेगा। करप्शन परमिट से शुरू होता है, करप्शन कंट्रोल से शुरू होता है। यू पी में चौधरी चरण सिंह ने परमिट सिस्टम को हटा दिया था। ट्रकों पर कोई परमिट नहीं रक्खा था। वहां कोई परमिट नहीं था इसलिये करप्शन खत्म हो गया था। यह बसों का परमिट मेरी समझ में नहीं आता। जब हिन्दुस्तान आजाद है, हमारी मातृभूमि आजाद है, हमारा देश आजाद है, जनता आजाद है तब परमिट के क्या माने ? इसलिए परमिट सिस्टम को खत्म किया जाये।

दूसरी बात यह है कि स्पीड के मुताल्लिक कोई खास कानून होना चाहिये। इस युग में जब सारा संसार रेस कर रहा है, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि जो ऊपर जायेगा उसका चालान होगा और जो अन्डर जायेगा उसका चालान नहीं होगा। चाहिये तो यह था कि जो 80 मील से कम जायेगा उसका चालान होगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। चाहिये यह था कि जो चालीस मील से कम चले उसका चालान हो और कानून के जरिये उसको सजा दिलाई जाय। अगर कोई तेज जायेगा और 10, 20, 30, 100 इन्सान मर भी जायेंगे तो क्या होगा ? गवर्नमेंट वैसे ही पापुलेशन कम करने के लिये नये नये लूप सिस्टम कर रही है, परिवार नियोजन और भ्रष्टाचार नियोजन आ रहा है। इसलिए जो 80 मील से कम चले उसका चालान किया जाये। इस जमाने में जो कम स्पीड से चलता है वह सारे देश की गति को मन्थर करता है, राष्ट्र की स्पीड को पीछे डालता है। कनाडा में जो 135 मील से कम चलता है उसका चालान किया जाता है, हिन्दुस्तान में जो चालीस मील से ज्यादा जाता हैं उसका चालान होता है। कानून बनना चाहिये देश की गति को देखते हुए। 80 मील से कम चलने वाले का चालान होना चाहिये और जो 80 मील से ज्यादा चले उसका चालान नहीं होना चाहिये। सुधार कुछ करने से होगा, नारेबाजी से नहीं होगा।

आज बसों मे मैं देखता हूं कि लोग झुक कर बैठते हैं। क्या कभी मिनिस्टर साहब ने हिसाब लगाया है कि क्यों लोग झुक कर बैठते हैं ? इससे देश में कितनी तपेदिक पैदा होती है और कितने अरब रुपया तपेदिक के इलाज पर खर्च होता है ? बजाय इसके कि टी बी के इलाज पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च किया जाये, ऐसी चीज होनी चाहिये जिसमें तपेदिक हो ही न सके। जो शख्स कार, बस या ट्रक में झुक कर बैठता है वह कभी ऊर्ध्व गति को हासिल नहीं कर सकता। इससे सारे राष्ट्र की ग्रोथ स्टिंटेड हो जायेगी। अगर ग्रोथ स्टिंटेड हो जायेगी तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की रेस में हम सबसे पीछे रह जायेंगे।

[श्री यशपाल सिंह]

इसलिये जो छोटी चीजें हैं जैसे फियट हैं, स्टैन्डर्ड है यह दर्जा चार के लड़कों को स्कूल ले जाने और स्कूल से ले आने के लिए है, नौजवानों के बैठने के लिये नहीं है । यह बीमारी का घर है । इन छोटी छोटी स्टेन्डर्ड और फियट गाडियों को दर्जा 4 के लड़कोंको स्कूलों से लाने के लिए अलाऊ किया जाये, लेकिन नौजवानों के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिये नीची सीट, घुटी हुई सीट और छोटी सीट की हर्गिज इजाजत न दी जाय ।

इस बिल में आपने प्राविजन रक्खा है कि जो ट्रक ड्राइवर है वह आये साल एक या दो साल पर जाकर फिटनेस सर्टिफिकेट ले आये । सबसे पहले तो सवारी के लिए फिटनेस की जरूरत है । अगर सवारी के लिए फिटनेस और लाइसेंस हो तो ड्राइवर के लिए भी हो वर्ना जब हमने अपने कांस्टिट्यूशन में यह वादा किया है कि फेअर फील्ड ऐंड नो फेवर, सबके लिये ईक्वल अपार्चुनिटीज हैं तब कोई कारण नहीं है कि ड्राइवर के लिये फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े । आपको सवारी की फिटनेस देखनी चाहिये । पैसेंजर्स की छाती न नापी जाय और गरीब ड्राइवर की छाती नापी जाय, जिसके बच्चे हैं, ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता । यह हमारे कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है ।

इसके बाद जो मेरा अमेंडमेंट है उसके मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि इस जमाने में अंग्रेजी मे रजिस्टर्ड नम्बर जो हैं वह देश के लिए कलक है । इस को चेन्ज करना चाहिये । नियम यह होना चाहिये कि अंग्रेजी का नम्बर देश के ऊपर कलक है और अगर कोई अंग्रेजी नम्बर लिखता भी है तो उसके नीचे हिन्दी और इलाकाई जबानों में नम्बर जरूर होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों पर गौर करेंगे, इनको यों ही नहीं उड़ा देंगे । जो सुझाव मैंने अर्पित किये हैं उन पर वह गौर करें ।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : सभापति महोदय, जो बिल सदन में आया है वह अजीब गड़बड़ घोटाले का कानून है । इस देश के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार ने देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है । हम देखते हैं कि यह स्वागत का काम हमारे मित्र ने किया । लेकिन जो कानून इस सदन में आते हैं उनमें ऐसी मर्यादायें जोड़ दी जाती हैं जिनसे समाजवाद की ओर जो देश बढ़ सकता था वह नहीं हो पाता । मिसाल के लिये मैं बतलाऊं कि हमारे देश में लगभग 89 हजार बसें हैं और 2 लाख 75 हजार ट्रक हैं करोड़ों आदमी उन पर काम करते हैं । मगर इसके लिए जो कानून बनाया गया है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि रोड परमिट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी ओर सारे सदन के सदस्यों ने ध्यान दिलाया है उसको कैसे रोका जाय । हजारों दरख्वास्तें पड़ती है और लाखों रुपयों का सौदा होता है और जो लोग ज्यादा रुपया देते हैं वह रोड परमिट पाते हैं । यहां एक एक आदमी के पास पचास पचास बसें हैं । कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रोड परमिट लिया है उनमें बहुत से पोलिटिकल सफरर हैं, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी हैं जिन्होंने रोड परमिट लेकर उसका बेच दिया है । आपके कानून में उसकी बन्दीश का कोई व्यवस्था नहीं है ।

15 hrs.

हमारे देश में बड़े बड़े फाइनेंशर हैं, पूंजीपति लोग है जोकि लोगों को रुपया दे देते हैं और वे उस रुपये से बसें, ट्रकें, टैक्सियां आदि खरीद लेते हैं । अगर कोई आदमी मोटर खरीदना चाहता है तो उसके लिये वे रुपया फाइनेंस कर देते हैं और दस साल का जो सूद है वह पहले ही उससे वसूल कर लेते हैं । अगर वह पैसा देने के साथ किस्त देने में डिफाल्ट करता है तो उसकी मोटर को जब्त कर लिया जाता है । इस तरह के लोगों से गरीब आदमी पैसा ले कर बसें और टैक्सियां चला रहे हैं ।

वे इन करोड़पतियों के गुलाम हो चुके हैं। आपने बकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका सारे देश ने स्वागत किया देश में आपका आदर इसके लिये किया गया। मै चाहता हूं कि आप इसकी व्यवस्था करें कि बैंकों से रुपया ले कर लोग टैक्सियां और बसें आदि खरीद सकें, अपना कारोबार चला सकें। बैंकों को खुले आदेश दिये जायें कि वे लोगों को टैक्सियां, बसें आदि खरीदने के लिए सस्ते सूद पर रुपया उधार दें। इस बिल में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। यह होनी चाहिये।

बसों के मालिक लोग सवारियों की बुरी तरह लूट मचाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण बस उद्योग का नहीं होना चाहिये। हमारी तरफ एक कहावत है कि पारस मणि जो पत्थर होता है वह किसी चीज के साथ अगर छू जाता है तो वह चीज सोना हो जाती है। उस में यह खासियत होती है। लेकिन हमारी सरकार में यह खासियत है कि जिस वस्तु को वह छू देती है, वही पत्थर हो जाती है।

श्री रणधीर सिंह: तुम हाथ लगा दो, भाई।

श्री सरजू पाण्डेय: हम तैयार हैं। लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं कम्युनिस्ट न हो जायें। अगर हो भी जाओगे तो क्या बुराई है। अब हो जाओ तो अच्छा है वर्ना मजबूर हो कर आपको इस रास्ते पर आना पड़ेगा। बसों के परमिट देने मे कोओप्रेटिव्ज को तरजीह दी जानी चाहिये। ऐसी व्यवस्था तो रहती है लेकिन अब कोओप्रेटिव सोसाइटीज को कोई परमिट नहीं मिलता है। वीकर सैक्शंज को परमिट देने के बजाय जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ही परमिट दे दिये जाते है। आपको कोशिश करनी चाहिये कि कोओप्रेटिव सोसाइटीज को, वीकर सैकशंज आफ दी पब्लिक को अधिक से अधिक परमिट दिये जायें ताकि वे लोग अधिक से अधिक संख्या में इस उद्योग में लग सकें।

राष्ट्रीयकरण की ओर भी आपको कदम बढ़ाना चाहिये। जितना भी और जहां तक भी हो सके इस उद्योग का आपको राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

बहुत से भाइयों ने कहा है कि बस स्टैंडों पर टिकटें नहीं मिलती हैं, बसें खाली जाती हैं, कंडक्टर, ड्राइवर उनको बिठाते नहीं हैं। ये जो खराबियां हैं ये तो राष्ट्रीयकरण से ही दूर नहीं हो सकती हैं। अगर हमने राष्ट्रीयकरण किया तो देश को पैसा मिल सकता है और उस पैसे से हम बस सर्विस को और सड़कों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इधर आपको कदम बढ़ाने चाहियें।

अब मैं नम्बर प्लेट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस पर सिलैक्ट कमेटी में भी बहुत बहस हुई थी। यह चीज वहां उठाई गई थी। कुछ सदस्यों ने कहा था कि सिर्फ अंग्रेजी में ये नम्बर प्लेटस होनी चाहियें, किसी ने कहा एक भाषा में नहीं जितनी हिन्दुस्तान की भाषायें हैं, चौदह, उन सब में लगाया जाना चाहिये। यह जो चीज है यह चलने वाली नहीं है। रोमन के जो न्यूमरल्ज हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। अगर यही रहें तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि एक ही सिस्टम आप सारे हिन्दुस्तान के लिए रखिये ताकि पुलिस कांस्टेबल आसानी से पढ़ सके इन नम्बर प्लेटस को। अगर आपने पूरी तालिका खड़ी कर दी तो उस बेचारे की समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते हैं कि ये प्लेट्स हिन्दी और अंग्रेजी में हों। वैसे एक ही भाषा में, अंग्रेजी में हों तो ज्यादा बेहतर है।

यह कहा गया है कि बसों में ओवर क्राउडिंग होता है। ओवर क्राउडिंग अगर होता है तो चालान भी किया जाता है और परमिट भी

[श्री सरजू पान्डे]

कैंसल कर दिया जाता है। अब जहां तक परमिट कैंसल करने की बात का ताल्लुक है, उस में मालिक का कोई कसूर नहीं होता है। ओवर क्राउडिंग ड्राइवर और कंडक्टर करते हैं लेकिन अगर परमिट कैंसल होता है तो इसकी सजा मालिक को भुगतनी पड़ती है। ओवर क्राउडिंग इसलिए होता है कि लोगों को बसों में जगह नहीं मिलती है। अगर बस वाले बिठायेंगे नहीं तो पब्लिक उनको मार कर उनकी कमर तोड़ देगी, बस में आग लगा देगी। इसका इलाज यह है कि आप परमिट ज्यादा से ज्यादा दें, जितने लोग परमिट चाहें, उनको आप परमिट दे दें। बजाय इसके कि आप परमिट देने पर रेस्ट्रिक्शन लगायें, आपको लिबरली परमिट देने चाहियें। आप रोक क्यों लगाते हैं? मैं समझता हूं कि यात्रियों की तादाद जो बढ़ रही है इस का कारण यही नहीं है कि आबादी बढ़ रही है। लेकिन मूवमेंट बढ़ रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इस वास्ते ज्यादा से ज्यादा परमिट दिये जायेंगे तो अच्छा होगा। और माननीय सदस्यों ने भी कहा है और मैं भी उसी राय का हूं कि जिस को एक बस के लिए परमिट दिया गया हो उसको दूसरी बस का परमिट न दिया जाए। इसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिये। साथ ही साथ इस उद्योग का विस्तार भी अधिक से अधिक हो।

मैं यह भी चाहता हूं कि मालिक को सजा देने की जो बात कही गई है, उसको आप निकालिये।

आप तीन बस के परमिट देते हैं। अगर कोई आदमी उसको रिन्यू कराने जाता है तो उसको उसी तारीख से रिन्यू हुआ समझा जाता है जिस तारीख से उसको जारी किया जाता है। मान लो दफ्तर में किसी की एक साल से दरख्वास्त पड़ी रही तो इस में उसका क्या कसूर। आपको मालूम ही है कि आपके अधिकारी कैसे हैं। उनके यहां दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं। उनका कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। दरख्वास्तें अगर इस तरह से रुकी रहेंगी और बाकी पीरियड के लिये अगर उनको रिन्यू कर दिया जाएगा तो इसमें नुकसान होगा। इससे घूस खोरी बढ़ेगी।

ड्राइवरों से सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं फ़िटनैस के। आप जानते ही हैं कि किस तरह से सर्टिफिकेट प्राप्त किये जाते हैं डाक्टरों से। अंधा भी अगर लेना चाहे सर्टिफिकेट तो उसको भी मिल जाएगा कि उसकी आंखें है। ऐसे ईमानदार डाक्टर लोग तथा दूसरे लोग हमारे देश में हैं। इस बार डाक्टरी कराना गरीब आदमी के लिये मुश्किल होगी। एक बार करा दें, बार बार न करायें। यह मुनासिब नहीं है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक अच्छा बिल आप सदन में लायें और ठीक ढंग से आप समाजवाद की ओर बढ़ें, यही मेरी आप से अपील है।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : जो बिल मन्त्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जिस बिल में एमेंडमेंट्स मन्त्री महोदय ने पेश की है वह बिल 1939 का बना हुआ है। इस बिल को बने तीस साल हो गए हैं। बजाय इसके कि इस बिल में संशोधन करने वाला विधेयक वह लाते उनको चाहिये था कि बिल्कुल नया बिल वह लाते। 1939 की जो पीढ़ी थी वह पुरानी पीढ़ी हो चुकी है। तब से कई नई बातें हो चुकी है। जिस की पैमाइश 1939 में हुई थी उसके छः बच्चे हो गए होंगे। आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको एक नया विधेयक लाना चाहिये।

हम देखें कि हर जगह मोटरों की भरमार है। बसों में बहुत ओवर-क्राउडिंग होता है। इसका कारण यह नहीं है कि आदमी ज्यादा चलने वाले हैं। बल्कि इसका कारण यह है कि हर स्टेट में मोटर परमिट्स पर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंज, प्रतिबन्ध लगाए गये हैं। परमिट हासिल

करने की लोगों में होड़ लग जाती है। पचास मील लम्बे रूट के लिए अगर परमिट लेना होता है तो पैसे वाले हो ले सकते है क्यों कि दो दो सौ और पांच पांच सौ रुपया फी मील के हिसाब से बिड लग जाता है। जो ज्यादा पैसा देगा, उसको परमिट मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को राय दे कि जितने भी लोग जिस रुट के लिए परमिट लेना चाहें उनको परमिट लेने की खुली छूट दे दी जाए। हर एक आदमी को तो परमिट लेना चाहे, मिलना चाहिये ताकि बसें चलाने वालों के मध्य कम्पीटिशन हो और अगर कम्पीटिशन होगा तो वे ज्यादा सवारियां ले जायेंगे, लोगों को सुविधायें प्रदान करेंगे। जो पैसे वाले होते है आज की व्यवस्था मे वे अनेकों परमिट ले लेते हैं और उनकी उस रूट पर मोनोपोली हो जाती है।

बसों में कितनी सवारियां बैठे और कितनी सवारियां न बैठे, इसके बारे में अगर वे लोग दारोगा से मिल जाते हैं तो फिर उनकी चांदी ही चांदी है। फिर आनन्द से वे जितनी सवारियां चाहें ले जा सकते है। दारोगा जी घर में नहा रहे हों या नाश्ता कर रहे हों, तो उनके घर के आगे से बस तब तक नहीं जा सकती है जब तक वह नहा कर या नाश्ता करके नहीं आ जाते हैं। तब तक बस वहीं खड़ी रहती है। सवारियां परेशान होती हैं, जो बीमार सवारियां होती हैं, वे भी परेशान होती हैं। इस तरह की जो चीज है यह नहीं होनी चाहिये। समय पर बसों को चलना चाहिये।

जो रोड्ज हैं वे भी ठीक हालत में रहनी चाहिये। न केवल प्रांतीय सड़कें है, बल्कि जो नैशनल हाइवेज हैं, वे भी आजकल बहुत खराब हालत में हैं। सागर से ग्वालियर, झांसी, ललितपुर हो कर नैशनल हाइवे नम्बर 26 आगे नागपुर की तरफ चली जाती है। इस सड़क की हालत बहुत खराब है। इस सड़क की हालत को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो जिलें की सड़कें हैं, उससे भी कहीं बदतर हालत इस सड़क की है। बैलगाड़ी के रास्ते से भी खराब उसकी हालत है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इन सड़कों के वास्ते वह सीधे राज्य सरकार को पैसा दे दिया करे और वह इन सड़कों की मरम्मत करा दिया करें। आपके पास न उतना स्टाफ है, न गैंग है और न आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। राज्य सरकारों को आप पूरा पैसा दे दें तो वे उनको ठीक ठाक हालत मे रख सकती हैं।

नैशनल हाइवेज पर बहुत सी नदियां भी पड़ जाती हैं जिन पर पुल बनाने की जरुरत पड़ती है। इनको लेकर दो राज्यों के बीच में झगड़े भी पैदा होते हैं। झगड़े इस लिये होते हैं कि कितना आप देंगे और कितना दूसरी सरकार देगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। झांसी और टीकमगढ़ के बीच जामन नदी पर घूंटाघाट है। वह डाकू ग्रस्त क्षेत्र है। डाकू डकैती डाल कर उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। वहां पुल के लिए हम सरकार से बार बार मांग करते रहे हैं। अब जा कर सरकार ने शायद उसकी मंजूरी दी है और उसके लिए सौलह लाख रुपये का प्राविजन किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी उस पुल का निर्माण किया जाए इस तरह से जहां जहां पुलों की आवश्यकता है, वहां वहां पुल जल्दी बना दिये जाने चाहियें।

हम रेल गाड़ी की मांग करते है तो आप कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सड़कों की मांग करते हैं तो सड़कें भी आप नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर नार्थ एवेन्यू में एम पीज के जहां बगले है, वहां डामर की सड़कें भी हैं और वहां बजरी भी बिछाई गई है। यहां पर तो इतनी सुविधायें लेकिन वहां सड़क तक नहीं। हमारा देश गरीब देश है। 80 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। वहां पर आप ज्यादा सड़कें बनायें न कि दिल्ली और कलकत्ते में। पहली योजना में कहा गया था कि कोई गांवऐसा नहीं रहेगा जो सड़क से पांच मील दूर हो, हर गांव

[श्री नाथूराम अहिरवार]

में स्कूल हो, पांच दस हजार की आबादी पर अस्पताल होगा। हम गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें देना चाहते हैं, हम उन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, आदि। लेकिन इस तरफ ध्यान न दे कर सरकार ने एक दूसरा ही रास्ता अपना लिया है। गांवों की जनता की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान न दे कर वह बड़े बड़े शहरों में सड़कें बनाने में लगी है, ताकि उन पर मोटरें आदि सुविधा से चल सकें। केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को इतने ज्यादा फंड्ज़ दे कि वे देहात की सड़कों की मरम्मत करवा सकें।

हम देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा परिवहन का यांत्रिक राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिस से एक ही रूट पर सरकारी बसें भी चलती हैं और प्राईवेट बसें भी चलती हैं। होता यह है कि प्राइवेट बसों वाले सरकारी बसों के कन्डक्टर और ड्राइवर को दस रुपये देते है और वे अपनी गाड़ी को खाली ले जा कर सीधे अपने अड्डे पर ले जाते हैं और प्राइवेट बसों वाले सब सवारियों को उठा लेते हैं। इस प्रकार दस रुपये ले कर सरकारी बसों के कर्मचारी सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। इस लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्य सरकारें किसी भी रूट को पूरी तरह से नैशनलाइज़ करें और उस पर प्राईवेट बसों को चलने की अनुमति न हो।

मैं तहसील हैडक्वार्टर निवाड़ी में रहता हूं। यू० पी० की बसें वहां से होकर गुज़रती हैं, लेकिन वहां पर उनका कोई स्टैन्ड नहीं बनाया गया है। बस स्टैन्ड वहां से पांच मील दूर बनाया गया है और जो कोई हमारे यहां आना चाहता है, उस को पांच मील दूर बने स्टैंड तक का टिकट दिया जाता है। मैंने इस बारे में कई दफा उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, लेकिन उस ने अभी तक वहां कोई बस स्टैन्ड बनाने की व्यवस्था नहीं की है।

मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को आम जनता को अधिक से अधिक सुविधायें देने की व्यवस्था करनी चाहिए। बसों के परमिट के लिए जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं, उन सब को परमिट दिये जायें, ताकि कम्पीटीशन में वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जायें। थोड़ी बसें होने से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार इस विषय में एक नया पूर्ण बिल लाये।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस विधेयक को पेश करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा कि वह इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने वाले हैं। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि जब वह इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने वाले हैं, तो फिर उन्हें यह बिल लाने की ऐसी कौन सी सख्त ज़रुरत पड़ गई। तमाम सदस्यों ने कहा है कि इस बिल में बड़ी गड़बड़ है। मै भी उन की राय से सहमत हूं।

इस विधेयक को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति कहां तक ठीक या ग़लत है और वह इस बारे में कहां तक ईमानदार है, यह बात इस विधेयक की दो क्लाज़िज़ से साफ़ हो जाती है। क्लाज़ 1(2) में कहा गया है :

> "It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. and different dates may be appointed for different provisions of this Act."

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक का कौन सा मुद्दा सबसे पहले लागू करेगी और कौन सा मुद्दा आखिर में लागू करेगी। विधेयक में कहा गया है कि आफ़िशल गजेट में

एलान किये जाने के बाद यह विधेयक लागू किया जायेगा और उस के विभिन्न प्राविज़न्ज़ समय समय पर भिन्न भिन्न तारीखों को लागू किये जायेंगे। सभापति महोदय, आप यकीन रखिये कि इस विधेयक का कोई मुद्दा कार्यान्वित नहीं होगा और इस का जो कोई प्राविज़न लागू होगा भी, उस से घांधली और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इस विधेयक का कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान अभी बाइसिकल एज में है। ये लोग साबित करना चाहते हैं कि अब हम मोटर एज में आ गये हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में मोटर व्हीकल्ज़, स्कूटर्ज़, टैक्सीज़ और प्राइवेट कारों आदि की सख्या मोटे तौर पर दस लाख है; या ग्यारह लाख समझ लीजिए। इस देश की आबादी पचास करोड़ है। इस प्रकार हमारे देश में पांच हज़ार व्यक्तियों पर एक मोटरगाड़ी है। अमरीका में दुनियां में सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ियां हैं—तीन आदमियों पर एक मोटरगाड़ी है। मुझे वहां का निजी तजुर्बा है। मैं बर्कले में विद्यार्थी था। मैं अमरीका में सात बरस तक रहा। मैं ने सान फ्रांसिस्को, न्यूयार्क और शिकागो आदि में देखा कि वहां इतना रश है, इतना ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन पथिक, पैदल चलने वाले, के लिए जितनी सुविधायें वहां हैं, उन को ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे इन लोगों ने समाजवाद का साइनबोर्ड अपने माथे पर लगाया हो।

उदाहरण के लिए अमरीका में स्कूल ज़ोंज में सड़कों पर लिखा रहता है: "स्कूल गो-स्लो"। उस पर लिखा रहता है कि अमुक स्पीड से ज़्यादा तेज़ न चलाया जाये। इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि स्कूल ज़ोन में प्राईवेट और सरकारी गाड़ियां कितनी स्पीड पर चलनी चाहिएं।

कुछ दिन पहले मैं तीन मूर्ति के पास खड़ा था। एक गाड़ी तेज़ी से आ रही थी। बहुत से बच्चे वहां खेल रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई एक्सीडेन्ट हो जायेगा। वह कार रुकी नहीं, बल्कि एक आइस क्रीम वाले से लड़ गई। उस कार वाले ने आईस क्रीम वाले को कहा तुम ने क्यों रास्ता ब्लाक किया हुआ है। इस देश में पेडेस्ट्रियन्ज़ का कोई खयाल नहीं है। हमारे समाज में इन्सान इम्पार्टेन्ट नहीं है, गाड़ी इम्पार्टेन्ट है।

श्री इकबाल सिंह : "गो स्लो" वाली बात मेन एक्ट में है।

श्री शिव चन्द्र झा : इस में यह व्यवस्था नहीं है कि हास्पिटल्ज़ में चूंकि मरीज़ होते हैं, इसलिए वहां हार्न नहीं बजाना चाहिये।

इस विधेयक में कहा गया है कि जो लाइसेंस का परमिट नहीं लेगा, उस को सज़ा दी जायेगी। जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनाए जायेंगे इस व्यवस्था से उन की घांधली के लिए फाटक खुल जायेगा। कुछ समय पहले की बात है कि एक भद्र पुरुष ने कनाट प्लेस में हरी लाइट न होने पर सड़क को पार किया और मोबाइल कोर्ट ने उस व्यक्ति के पास पैसा न होने की वजह से उस के कपड़े तक उतरवा लिये। उस की फोटो नैशनल हैरल्ड और अन्य अख़बारों में छपी थी। इस प्रकार की कोर्टस से घांधली बढ़ जाती है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राइवेट सैक्टर की बसों को खत्म कर देना चाहिए और लार्ज स्केल पर मुसाफ़िरों तथा माल के ट्रांसपोर्टेशन का काम पब्लिक सैक्टर में आना चाहिए। लेकिन जहां सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं की जा सकती है, वहां प्राईवेट सैक्टर को काम करने दिया जाये और उन को परमिट तथा कर्ज़े के रूप में प्रोत्साहन दिया जाये। बड़ी सड़कों पर तो बसों और ट्रकों आदि का थोड़ा बहुत इन्तज़ाम है, लेकिन सुदूर देहात में जाने के लिए इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, जिस की कल्पना नहीं की जा

[श्री शिव चन्द्र झा]

सकती है। सरकार का ध्यान केवल दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों की ओर है। देहात की सड़कों की तरफ़ उनका ध्यान नहीं है। वहां पर को-आपरेटिव सोसायटीज़ को गाड़िया चलाने की सुविधा दी जानी चाहिए। इस प्रकार उन क्षेत्रों में प्राईवेट सेक्टर को को-आपरेटिव्ज़ में बदल देने से समाजवाद का रास्ता साफ़ होगा।

इस विधेयक में पेज 34 पर कोर्ट आदि के अफ़सरों को विदआउट वारन्ट खर्च करने का हक़ दिया गया है। यह संविधान के खिलाफ काम है। जो कोई भी मन्त्री कोई विधेयक यहां पर लाता है और इस बात को उठाता है कि किसी नागरिक की तलाशी होगी वगैर वारन्ट के वह जनतन्त्र के खिलाफ काम करता है। इस में वारंट की गुंजाइश है पेज 34 पर, लेकिन उस के लिए ग्राप और फाटक खोले देते हैं।

इस के अलावा मेरा कहना यह है कि यह जो कंडक्टर लोग हैं उन में एक सेंस आफ ड्यूटी होनी चाहिए। उन की सुविधाएं और भी बढ़ाई जानी चाहिएं लेकिन उस के साथ साथ सेंस आफ ड्यूटी भी उन में पैदा करनी चाहिए। दिल्ली में ही आज देख लीजिए, इतनी भीड़ लगी रहती है और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि कंडक्टर बस भगा लिए चला जाता है। आप ने एक ला बनाया है कि इस से ज्यादा आदमी नहीं बैठेंगे। ठीक है, उस का पालन कराइए। उस से ज्यादा जो लोग बैठते हैं वह क्यों बैठते हैं? इस के ऊपर भी आप सोचिए और इस का भी कोई उपाय निकालिए। यह जो वर्कर्स हैं, कंडक्टर, ड्राइवर वगैरह इन के लिए आप क्लब बनाइए जहां वह ठहर सकें और रिक्रियेशन कर सकें। कितने वर्कर्स ऐसे है जिन के लिए रहने की कोई सुविधा नहीं होती। तो उन के लिए डिपोज़ में और दूसरी जगह आप एक कामन हाल के रूप में कोई क्लब या रिक्रियेशन सेंटर बनाइए जिस से उन को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ जनता की सेवा और उन को सुविधा पहुंचाने की भावना आप उन में पैदा करें। यह सब बातें आप लाएंगे तब यह विधेयक मोटे तौर पर काम्प्रीहेंसिव हो सकता है और अभी जिस रूप में आप ने इसे रखा है मैं समझता हूं कि यह एक लिप सर्विस आप दे रहे हैं, चूंकि 65 से यह विधेयक पड़ा हुआ है इसलिए इस को पास कराकर आपको एक डिग्री लेनी है लेकिन इस से न आप का ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होगा और न सुविधाएं बढ़ेंगी। उलटे धांधली और बढ़ जायेगी। इसलिए बेहतर है कि अभी कोई देरी नहीं हुई है, इस को आप वापस ले लें और इस सत्र के आखीर तक दूसरा एक काम्प्रीहेंसिव विधेयक लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की मुखालिफत करता हूं।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : This Bill tries to meet the needs of the nation in regard to road transport requirements, but with due respect, I submit that it has sufficiently failed to achieve its object.

The primary object of a Motor VehiclesBill should be to provide a convenient conveyance to the public in general and it should also provide cheap transport of goods from one place to another so that there is fact development of the industrial sector of the country, because the better and cheaper the movement, the easier it is to-develop industry. The third object should be that it should normally provide some form of income by way of tax to the Government. Last but not least is the consideration that in case of accidents, the passengers should get their claims for damages settled quickly and those who send their goods on the public carriers should be able to get quick compensation in case of loss or other contingencies. The question before us is whether this Bill achieves these objectives.

Taking first the question of the convenience of passengers, what we find on roads is that where there is more traffic the number of buses is not enough. Why is it not so ? The answer is very simple. Those who run buses on those particular routes

see to it that a lesser number of buses run on those routes so that they can overload their buses and earn more money. This also leads to deterioration in the economy of the country because it leads to the growth of monopolies On the one hand, we are crying hoarse for ushering in a socialistic pattern so that the rights of the common man are realised the inequalities between rich and poor are removed; on the other, we adopt a system which necessarily leads to the growth of monopolies. The easiest way of raising or increasing monopolies is to develop the system of licences and route permits, and that is exactly what we are doing. We are developing it and we are so much accustomed to the system of permits and licences that we cannot think otherwise. The best way to finish monopolies is to do away with the system of licences and permits. The best way of developing the transport system and doing away with monopoly in transport is to do away with the route permits. The result will be that more people will go into this particular line of business. There will be competition *inter se* and they would reduce the fares and try to improve their service and the public would, in general, gain.

There is another way of doing it, and that is to completely monopolise a particular route and see that we introduce more buses in that route. If we do not have sufficient money to buy enough number of buses to completely cover the particular route, an alternative is to allow private enterprise to enter till we are able to completely take over that particular route. Therefore, I submit that the time has come to reconsider this system of granting permits.

Who gains by this system of permits ? One gainer, of course, is the transporter because he gets monopoly in a particular area, and the second gainer is the bureaucracy because the transporter has to go the bureaucracy to see that no body else gets the routes and to see that they decide that this is the number of routes that they have to give in a particular region. What is the qualification of the people in the Transport Department who decide that a particular needs only so many routes and not more ? Already, in the railways we are in a mess and equally we are trying to create a mess in this particular line also.

Another argument was advanced that we need this syetem of route permits because otherwise the railways will suffer, freights and passenger fares will go down, and nobody would travel by the railways. To keep up an inefficient system we need not make another system equally, if not more, inefficient. Therefore, I submit that there should be rethinking as to whether we at all need the system of route permits especially in those regions and routes where Government is not running its own buses.

The second question is, those who run the buses, do they also suffer any inconvenience ? The answer is very simple, that they also suffer. If you have to run buses in Punjab, Haryana, Delhi and Bombay, you have to go to four different corners in four different States to get route permits. So, I submit that it is high time you had a central authority covering the whole of India which can finally decide to whom the route permits should be given in a particular region.

Thirdly, you have developed two types of courts for granting damages to the people who suffer by travelling in buses. So far as personal damage is concerned, that is if person breaks his legs or arms or dies, a Claims Tribunal has been set up, but if he loses luggage of Rs. 2,000 or above, he has to go to different courts. The object of the statute should be that the passengers or the people should be made to spend the least and should be given the maximum advantage What is the difficulty in the same Tribunal deciding the claims regarding the property also above the value of Rs. 2,000 ? The procedures in the courts are very lengthy and very costly and I submit that the Government should reconsider this aspect and all types of claims, personal or property, should be decided by the same Claims Tribunal.

Then there are various fees prescribed under the statute for transporters. There should be a consolidated fee so that the transporter knows what he has to pay once for all instead of each Government or authority trying to take a fee from him.

Last of all, the question of taxation is there and I submit that if there

[Shri Vikram Chand Mahajan]

are more buses, there will be more tax realisation. If there are more buses, more persons will get employment; freight and passenger rates would go down. From all these points of view the system of route permits should by done away with.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Road transport is an important amenity of civilised life and Government should give thought to the system The system of regional authorities, granting permits for only one State and the system of endorsement validating that permit in another State--all these look like passports and visas and it makes one feel as if in India all the States are independent States, foreign States. The whole thing must go Even in international life we are trying to reduce barriers and hurdles in commerce and trade; I do not see why in the same country there should be such a system of passport and visa. If a passenger bus or lorry or a car is licenced in one State, it must have free access without any necessity for endorsement from any other State. The whole thing is based on central legislation; it is not as if one State is passing its own law as against another.

Taxation is heavy; everybody knows it. But what is the *quid pro quo* for this heavy taxation ? Are our roads good ? In some parts of our country, the tarred surface is not even 12 feet wide; in many cases it is just 12 feet in our national high ways. Often the sides are so low that the buses topple down because of the difference in the levels of the black top and the other surface.

Is there no duty on the Government to provide shelters at convenient distances ? Can you not adopt the system of the private operators. Burmah Shell is constructing motels everywhere. On national high ways you must have your own places where the passengers can sit and take refreshments; your drivers and crew can go and take rest. unless you provided adequate facilities, mere rules that the driver cannot work for more than five hours will not help Even where some shelters are provided, they do not conform to decent civilised standards; there is no privacy for men, and worse, for women.

There is talk of nationalisation. It is good if it is done well. We want all things to be nationalised. We started it in Madras when Mr. Prakasam was the Chief Minister. He nationalised the city bus service and that was one of the reasons that caused his exit. It does not matter; his successors are reaping the benfit. You cannot have nationalisation in some districts and private operators in other districts. It is like killing half a hen for cooking and retaining the other half for laying eggs. What are these 'eggs' ? At the time of elections you will find them in all the districts where there is no nationalisation from the election funds collected. It is a well known scandal throughout India; one need not dilate upon it. Therefore, I suggest that if you nationalise bus transport it should be done on a rational basis. You have got the national highway. Why don't you nationalise the entire routes throughout India, having one system, one method and then give shuttle services to the private-owners ? Because, when there are shuttle services, short services, the private buses, restricted to run three or four buses would not have chance to exploit the people very much and they will be under control. Please consider that aspect also.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : The private bus owners have not increased their fares since 1947.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Because they want somehow or other to run the buses. Now, about efficiency of the nationalised services, you have got to take care about it. You are retaining nationalisation, and I am also suggesting nationalisation, but you must efficient. We have got the public services here, the DTU and there is the public transport service in Hyderabad or else where. We have coal smoke in Calcutta to cover the city and here we have got the bus smoke. Then, you see here in the DTU or in Hyderabad, only the worst and the oldest buses are dumped upon the nationalised services. I do not know why no action for improvement is taken at all in this matter Not only that : the buses rattle. The seats are not good. Then you have got the system of tourist buses and the de luxe buses with the result that the ordinary buses are completely neglected. Therefore, unless the Minister takes some special inte-

rest in this, nationalisation will be brought into contempt. In fact, half the number of officers who are in these nationalised services do not believe in this nationalised transport service They want to do everything which will lead to bring these services into contempt.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Only five minutes, Sir ? The national highways run into 2,500 miles, and only five minutes to speak on this ?

MR. CHAIRMAN : Five minutes for everyone, and I hope you will also agree.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Then, the number of accidents that are happening in this country on the roads is appalling. I understand from the most conservative estimates that there are at least 350 persons who die everyday under the wheels of the motor vehicles in India. I think you must take some special care about this. There is no road which you travel on and where you will not fail to see a car upturned and all the four wheels looking up into the sky every day; it is a common sight not only in Delhi but in all cross-country roads. Why don't the Government do something about this ?

I understand you have got the mobile magistracy here who are there to punish the people who overspeed and to prevent overcrowding But I also understand that they require some protection. Recently, I read in the newspapers that these mobile magistrates are being belaboured and therefore, unless you give them some protection, there is no purpose, and your mobile justice will become mobile injustice; therefore, it is very important that you should attend to it.

Then there is the problem of overcrowding. Overcrowding is very great. There is overcrowding in the trains and the buses have come in order to relieve the congestion in the trains. But here also, they are unable to avoid overcrowding. Once it happened that a tall gentleman was travelling in one of the buses; he was too tall for the size and height of the bus; there were several turns and jerks. When once there was a jerk, he landed himself down on a seat on which a lady was sitting. "Excuse me," he said, and he rose. By the time he got himself excused by the lady, there was another jerk, and then he again landed himself on the seat. "Excuse me," he said, but then the query came : "But who are you ?" Then he replied, All the while I was thinking I was a Scotlander, but now I do seem to be a Laplander !"

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : चेयरमैन साहब, मैं अपने अजीज़ को मुबारकबाद देता हूं कि कुछ न कुछ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की हैं । ये खुद भी बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर रहे हैं, इसलिये इन्हें इस काम का पूरा तजुर्बा है । इनकी जिन्दगी का खासा हिस्सा ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता रहा है और अब तक वावस्ता है । अपनी मेहनत से कमाते हैं, इसलिये सूरज को चिराग़ क्या दिखायेगा रोशनी ।

इसलिये जैसा विश्वनाथ जी ने कहा कि एक कार की जहां रजिस्ट्री होती है, जहां उसकी फीस दी जाती है, उसके बाद सारे हिन्दुस्तान में उस के लिये कहीं रुकावट नहीं है, तो कोई वजह नहीं है कि वे लोग जिन्होंने उस वक्त खिदमत की, जब मुल्क डिवाइड हुआ, उस वक्त खिदमत की जब पाकिस्तान ने हमला किया, उस वक्त खिदमत की जब चीन ने हमला किया, अपने ट्रक्स और बसों को गवर्नमेन्ट की डिस्पोज़ल पर छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जानें भी खतरे में डालीं, कई मारे गये, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करें, जिससे गवर्नमेन्ट को भी नुकसान न हो, आप का रेवेन्यू आपको पूरा मिल जाय, और एक ही जगह दे कर उन का छुटकारा हो जाय, जगह जगह उनको रिश्वत न देनी पड़े, परेशान न होना पड़े । जहां से माल उठायें और जहां तक जाना हो चले जांय । परमिट सिस्टम को शायद आप इसलिये जरूरी समझते हैं कि इस के न होने से शायद एक जगह ज्यादा चलेंगी और उससे शायद इन का नुकसान होगा । मेरी बदनसीबी यह है कि मैं एक ऐसे सूबे से ताल्लुक रखता हूं जिसका

[श्री अब्दुल गनी डार]

ट्रांसपोर्ट में सब से ज्यादा हिस्सा है, जिस सूबे से सरदार इकबाल सिंह भी आये हैं। मेरी पैदायश गुरु की नगरी में हुई है। उस वक्त हरयाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ थे और हम चाहते थे कि पंजाब और भी बड़ा हो। लेकिन बदनसीबी से पंजाब के तीन हिस्से हुए। तीन हिस्से होने से आप यकीन मानिए, जगह जगह परेशानी है और जगह जगह पर टैक्स देने में ही सारा वक्त निकल जाता है। किसी भाई ने कहा कि टायर नहीं मिलते। सरकार का इण्डियन आयल कार्पोरेशन है। लेकिन जो ल्यूब्रिकेन्ट हैं वह एस्सो और बी ओ सी 11 पैसे ज्यादा फी लीटर सोलह साल से बेचते रहे। चूंकि सारा काम सरकार के हाथ में आ रहा है, इस लिए मैं मुबारिकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारा नेशनलाइज हो जाये लेकिन यह कहां का न्याय है कि लेबर को पूरी वेजेज न दें। खुद वह 80 रुपए देते हैं, शकूर बस्ती से फरीदाबाद के लिये लेकिन जो लेबरर होते हैं उनको 63 रुपये देते हैं और उसके बाद उसमें दलाली भी खाते हैं। जैसे जैसे मंहगाई बढ़ती है उसका एक बहाना लगा-कर कहते हैं कि हम टेन्डर काल करेंगे। किसी की ताकत होती है लेकिन मेरी तरह का छोटा आदमी क्या लेगा। जिसकी तीन ट्रक्स हैं उसके नाम एक मिलेगा जबकि वहां जरूरत है सौ ट्रक्स की। तो उसको मलाई खाने के लिए मिलेगी और चौधरी रणधीर सिंह जैसे किसानों के हिस्से में आयेगी। किसानों के ही ज्यादा ट्रक हैं। तो पब्लिक सेक्टर को इस तरह का फ्राड नहीं करना चाहिए। आप उनको खुली छूट दीजिए और साथ ही अपना पैसा पूरा ले लीजिए क्योंकि बिना पैसे के सरकार कैसे चल सकती है—चाहे वह स्टेट की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो। लेकिन वह जगह जगह रुकें, जगह जगह इजाजत लें और एक एक हफ्ते के परमिट बनवायें और उसके बाद ही कहीं जा सकें, मेरे खयाल में यह बहुत ही परेशानी की बात होती है। आप खुद एक शानदार ट्रांसपोर्टर हैं, और सरदार गुरचरण सिंह जोकि नये एम पी बन कर आये हैं। इनके साथ उन्होंने भी ट्रान्सपोर्ट का काम खूब किया और इस तरह सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सारे देश की खिदमत की। आज भी हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां कि आपको पंजाब का ट्रान्सपोर्टर न मिल जाये—चाहे वह ट्रक की सूरत में हो या बसेज की सूरत में हो या फिर टैक्सी वाला होगा तो उसे भी आप सिख ही पायेंगे या हरियाणे का जाट पायेंगे। मेरा मतलब यह है कि वह पंजाबी ही होगा। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह रेवोल्यूशन लाये और ऐसी आसानियां पैदा करे जिससे कि देश का हित हो ताकि फिर गवर्नमेंट की भी इज्जत बढ़े।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसकी क्लाज 41, 54 और 62 को फिर से देखने की कोशिश करें। उसमें अगर कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं तो वह करें। अभी जैसा कि कहा गया बिना वारन्ट के जिस को चाहें पकड़ लें, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं इसके लिए इनको मुबा-रिकबाद देता हूं और चाहता हूं कि ये कदम को बढ़ायें और यह जो बिल है इसको काम्प्रि-हेंसिव बनाकर लायें ताकि उससे इस देश की भी भलाई हो और ट्रान्सपोर्टर की भी भलाई हो।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں)

چیرمین صاحب میں اپنے عزیز کو مبارک باد دیتا ھوں کہ کچھ نہ کچھ انھوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ھے-یہ خود بھی بھت بڑے ٹرانسپورٹر رھے ھیں اس لئے انھیں اس کام کا پورا تجربہ ھے-ان کی زندگی کا خاصا حصہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ وابستہ رھا ھے اور اب تک وابستہ ھے-اپنی محنت سے کمائے ھیں-اس لئے سورج کو چراغ کیا دکھائیگا روشنی-

اس لئے جیسا وشوا ناتھن جی نے کہا
کہ ایک کار کی جہاں رجسٹری ہوتی
ہے جہاں اس کی فیس دیجاتی ہے اس
کے بعد سارے ہندوستان میں اس کے
لئے کہیں روکاوٹ نہیں ہے تو کوئی وجہ
نہیں ہے کہ وہ لوگ جنھوں نے اس
وقت خدمت کی جب ملک ڈوائڈ
ہوا-اس وقت خدمت کی جب پاکستان
نے حملہ کیا-اس وقت خدمت کی جب
چین نے حملہ کیا- اپنے ٹرکس اور بسوں
کو گورنمینٹ کے ڈسپوزل پر چھوڑ دیا-
انھوں نے اپنی جانیں بھی خطرے
میں ڈالیں-کئی مارے گئے-ان کے
ساتھ کوئی ایسا ویوھار کریں جس میں
گورنمینٹ کو بھی نقصان نہ ہو آپ کا
ریوینیو آپ کو پورا مل جائے اور ایک
ہی جگہ دیکر ان کا چھٹکارا ہو جائے
جگہ جگہ ان کو رشوت نہ دینی پڑے
پریشان نہ ہوا پڑے-جہاں سے مال
اٹھائیں اور جہاں تک جانا ہو چلے
جائیں- پرمٹ سسٹم کو شاید آپ اس
لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے
نہ ہونے سے شاید ایک جگہ زیادہ
چلینگی اور اس سے شاید ان کا
نقصان ہوگا-میری بدنصیبی یہ ہے کہ
میں ایک ایسے صوبے سے تعلق
رکھتا ہوں جس کا ٹرانسپورٹ میں سب
سے زیادہ حصہ ہے جس صوبے سے
سردار اقبال سنگھ بھی آئے ہیں-
میری پیدایش کرو کی نگری میں ہوئی
ہے- اس وقت ہریانا اور ہماچل پردیش
پنجاب کے ساتھ تھے اور ہم چاہتے
تھے کہ پنجاب اور بھی بڑا ہو-لیکن
بدنصیبی سے پنجاب کے تین حصے ہوئے
تین حصے ہونے سے آپ یقین مانئے جگہ

جگہ پریشانی سے اور جگہ جگہ
پر ٹیکس دینے میں ہی سارا وقت
نکل جاتا ہے- کسی بھائی نے کہا کہ
ٹائر نہیں ملتے- سرکار کا انڈین آئیل
کارپوریشن ہے-لیکن جو لیوبریکینٹ ہے
وہ ایسو اور بی او سی ۱۱ پیسے زیادہ
فی لیٹر سال ہا سال سے بیچتے رہے-
چونکہ سارا کام سرکار کے ہاتھ میں آ
رہا ہے اس کے لئے میں مبارک باد دیتا
ہوں-میں چاہتا ہوں کہ سارا نیشنلائز
ہوجائے لیکن یہ کہاں کا نیائے ہے کہ
لیبر کو پوری ویجیز نہ دیں-خود وہ ۸۰
روپے دیتے ہیں-شکور بستی سے
فریدآباد کے لئے لیکن جو لیبور ہوتے
ہیں ان کو ۶۳ روپئے دیتے ہیں اور
اس کے بعد اس میں دلالی بھی کھاتے
ہیں-جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے
اس کا ایک بہانا لگاکر کہتے ہیں کہ
ہم ٹینڈر کال کرینگے- کس کے طاقت
ہوتی ہے لیکن میری طرح کا چھوٹا آدمی
کیا لیگا-جسکے تین ٹرکس ہیں اس
کے نام ایک نہیگا جب کہ وہاں ضرورت
ہے سو ٹرکس کی- تو اس کو ملائی کھانے
کے لئے ملیگی اور چھاچھ رلدھیر سنگھ
جیسے کسانوں کے حصے میں آئیگی-
کسانوں کے ہی زیادہ ٹرکس ہیں- تو
پبلک سیکٹر کو اس طرح کا فراڈ نہیں
کرنا چاہیئے-آپ انکو کھلی چھوٹ
دیجئے اور ساتھ ہی اپنا پیسا پورا لے
لیجئے-کیونکہ بنا پیسے کے سرکار کیسے
چل سکتی ہے-چاہے وہ اسٹیٹ کی
سرکار ہو یا کیندر کی سرکار ہو-لیکن
وہ جگہ جگہ رکیں-جگہ جگہ اجازت
لیں اور ایک ایک ہفتہ کے پرمٹ
بنوائیں اور اس کے بعد ہی کہیں جا

[شری عبدالغنی ڈار]

سکیں-میرے خیال میں یہ بہت ھی پریشانی کی بات ھوتی ھے-آپ خود ایک شاندار ٹرانسپورٹر ھیں اور سردار گرچرن سنگھ چونکہ نئے ایم پی بنکر آئے ھیں ان کے ساتھ انھوں نے بھی ٹرانسپورٹ کا خوب کام کیا اور اس طرح صرف پنجاب ھی نہیں بلکہ سارے دیش کی خدمت کی-آج بھی ھندوستان کا کوئی حصہ نہیں ھے جہاں کہ آپ کو پنجاب کا ٹرانسپورٹر نہ مل جائے--چاھے وہ ٹرک کی صورت میں ھو یا بسیز کی صورت میں ھو یا پھر ٹیکسی والا ھوگا تو اسے بھی آپ سکھی پائینگے یا ھریانے کا جاٹ پائینگے-میرا مطلب یہ ھے کہ وہ پنجابی ھی ھوگا- تو میں سرکار سے یہ کہنا چاھتا ھوں کہ وہ ریولیوشن لائے اور ایسی آسانیاں پیدا کرے جس سے کہ دیش کا ھت ھو تاکہ پھر گورنمینٹ کی بھی عزت بڑھے-

میں منتری مھودے سے کہوں گا کہ اس کی کلاز ۴۱-۵۴ اور ۶۲ کو پھر سے دیکھنے کی کوشش کریں-اس میں اگر کچھ آسانی پیدا کر سکتے ھیں تو وہ کریں-ابھی جیسا کہ کہا گیا کہ بنا وارنٹ کے جس کو چاھیں پکڑ لیں میں سمجھتا ھوں ایسا نہیں ھونا چاھئیے-بہرحال میں اس کے لئے ان کو مبارک باد دیتا ھوں اور چاھتا ھوں کہ یہ قدم کو بڑھائیں اور یہ جو بل ھے اس کو کامپریھینسو بنا کر لائیں تاکہ اس سے اس دیش کی بھی بھلائی ھو اور ٹرانسپورٹر کی بھی بھلائی ھو-]

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, जो भी कानून हम यहां बना रहे हैं उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए और वह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। किन्तु जब इस बिल को हम इस कसौटी पर कसते हैं तो मुझे बड़ी निराशा होती है। मुझे इस बिल की सेलेक्ट कमेटी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां मैंने कहा था कि यह आप जो पैबन्द लगाकर 1939 माडल की गाड़ी चला रहे हैं वह कितने दिन चलेगी ? 1939 में जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट बना था तब परिस्थितियां दूसरे प्रकार की थीं। तब मोटर कारें बहुत कम थीं, ट्रकें बहुत कम थीं और बसेज़ भी बहुत नहीं थीं लेकिन आज सड़कों पर ट्रकों और बसों का तांता लगा हुआ है। किसी भी नेशनल हाईवे पर आप चले जाइये, हर दो मिनट के बाद आपको ट्रकें और बसें जाती हुई मिलेंगी। ऐसी स्थिति में यह बिल जो लाया गया है मेरी समझ में वह बहुत नाकाफी है। इस सदन में सभी पार्टियों की ओर से कहा गया है जब तक एक काम्प्रिहेंसिव बिल नहीं लाया जाता तब तक परिवहन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। मैं भी उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। सभापति जी, हम बैलगाड़ी के युग से साईकिल युग नहीं बल्कि बसों के युग में आ गए हैं। आज गांवों गांवों में बसें जाती हैं। जितने गांवों में लोग हैं और उनकी संख्या 90 प्रतिशत है वे इसी बस परिवहन के आश्रित हैं। लेकिन आज गांवों में जाने वाली जो बसें हैं उनकी क्या अवस्था है ? मैं बड़े बड़े शहरों की बात नहीं करता-उसके सम्बन्ध में जो भी कहना है वह पीछे कहूंगा। लेकिन गांवों में जो बसेज़ चलती हैं वे अमूमन टूटी फूटी होती हैं। फिर उन बसों में जितने आदमी नीचे बैठते हैं, शायद उससे दूने उसके ऊपर बैठते हैं और उससे तीन गुने उसके चारों ओर लटके रहते हैं। सड़कों की अवस्था यह है कि जगह जगह पर एक एक, दो दो फिट के गड्ढे होते हैं। किस प्रकार से सफर करते हुए लोग बचते हैं यह परमात्मा की ही दया है। ऐसी अवस्था के बावजूद परमिट सिस्टम

के द्वारा बसों की संख्या को सीमित किया जाता है। मैंने अपने नोट आफ डिसेन्ट में भी इस बात का उल्लेख किया है कि इस बिल में इस प्रकार का प्राविधान किया जाना चाहिए जिससे पर्मिट सिस्टम कतई न रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि इस हाउस में सभी ओर से, सिंडीकेट, इंडीकेट कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सभी की तरफ से इसका समर्थन किया गया है और इस बात की मांग की गई है कि पर्मिट सिस्टम को उठा देना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लाइसेंस और पर्मिट क्यों है। जहां जितनी आवश्यकता होगी, डिमान्ड सप्लाई के आधार पर वहां उतनी ही बसें चल सकेंगी। आप आर्टिफिशल ढंग पर वहां के लिए क्यों कोई संख्या निर्धारित करते हैं। व्यापारियों के पास पैसा है, वे बसें खरीदते है। वे वहां पर बसेज चलायें। जिनकी बसें अच्छी होंगी, जो अच्छी सर्विस देंगे वे ही यहां अपनी बसें चला सकेंगे। आपको तो आम लोगों की चिन्ता होनी चाहिए जो रात दिन की सफर करते हैं लेकिन आप उन आम लोगों की चिन्ता न कर केवल व्यापारियों की चिन्ता करते हैं कि अगर बसों की संख्या अधिक हो जायेंगी तो उनकी पूंजी नष्ट हो जायेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप अपने को सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहते है तो फिर जो पूंजी लगाने वाले अनसोशलिस्ट लोग हैं उनके फायदे के बारे में आप क्यों सोचते है।

श्री यशपाल सिंह जी ने स्पीड की बात कही, मैं उनकी ताईद करता हूं। लेकिन इस देश में जैसी सड़कों की अवस्था है उसमें यदि हम कनाड़ा, अमरीका और जर्मनी जैसे देशों की स्पीड की नकल करना चाहेंगे तो फिर शायद हमारे यहां एक भी बस और गाड़ी नहीं चल सकेगी। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी कुछ मित्रों ने चर्चा की है, मैं भी उसकी ताईद करता हूं लेकिन राष्ट्रीयकरण से ही सारी समस्या हल नहीं हो जायेगी। कलकत्ते में जो ट्रान्सपोर्ट चलती है उसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार लोग सफर करते हैं। हमारे बहुत से मित्र वहां गए होंगे और उन्होंने लोगों को सफर करते हुए देखा होगा कि उनको फुट बोर्ड पर एक इंच भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसलिए यदि राष्ट्रीयकरण किया जाये तो साथ ही पर्याप्त मात्रा में बसेज भी दी जायं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर प्राइवेट लोगों को ही बसें चलाने दीजिये। कलकत्ते में श्री ज्योति बसु को भी प्राइवेट बसेज मंगानी पड़ी हैं लेकिन फिर भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। तो चाहे राष्ट्रीयकरण के द्वारा या प्राइवेट ओनर्स के द्वारा, किसी भी प्रकार से पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आम लोगों को यातायात में सुविधा हो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज यहां माइल स्टोन और नम्बर प्लेट के बारे में भी चर्चा की गयी है। हमारे डी० एम० के० के मित्र का जो मेरे पहले बोल चुके हैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसके लिए हम को अंग्रेजी की शरण नहीं लेनी चाहिये बल्कि रीजनल और हिन्दी भाषा में, जो सब जगह समझी जाती है, नम्बर प्लेट होने चाहिये।

एक बात मैं थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस के संबंध में कहना चाहता हूं। थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस के जो प्रोवीजन्स दिये गये हैं उसमें कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस वाली बात मेरी समझ में उचित नहीं है। अगर कोई आदमी रास्ता पार कर रहा है और ऐक्सीडेंट हो गया तो यह सवाल उठाना कि वह सड़क क्यों पार कर रहा था, सही नहीं है। अगर वह किसी ऐक्सीडेंट का शिकार होता है तो उसको उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिये।

आज हमारे यहां रेल गाड़ियों में बहुत से लोगों को समय पर रिजर्वेशन नहीं मिलती है इसलिये बहुत से लोग मोटरों से भी लम्बे सफर करते हैं। उनसे जगह जगह ओक्ट्राय ड्यूटी वसूल की जाती है जिससे बड़ा सर दर्द होता है। मैंने यू० पी० में हरद्वार में देखा है कि

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

जगह जगह 8 आना, 1 रु०, 2 रु० ड्यूटी ली जाती है। यह सिस्टम हटाना चाहिये जिससे मोटर से सफर करने वाले लोगों को सहूलियत हो।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : सभापति जी, मैं आखिरी स्पीकर हूं, इस सिलसिले में बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तमाम स्पीचें मेम्बरों की सुनीं। मैंने इसमें सोशलिज्म की भी बात सुनी। जो सोशलिज्म के परम शत्रु हैं उनसे भी सोशलिज्म की बात सुनी और उन लोगों से भी सुनी जो कुछ दिनों तक सरकार चला रहे थे लेकिन अब अलग हो गये हैं। जो कुछ भी हो, इस बिल की सलेक्ट कमेटी का भी मेम्बर रहा हूं, मैंने अपनी बात वहां भी रखी थी और वहां मुझे यह बताया गया था कि जल्दी ही एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाया जायगा। मैंने जो बातें वहां पर रखी थीं उनको आज फिर यहां सदन में रखना चाहता हूं। जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट इस समय देश में चल रहा है यह ऐसा ऐक्ट हमारे देश में है जिससे तमाम किस्म के करप्शन इसके अन्दर भरे हुए हैं। इस बिल के माने यह हैं कि हर स्टेट जो स्टेट जहां पर चाहे, जो ड्राइवर जहां चाहे, जो मालिक जहां चाहे, इससे जितना फायदा उठाना चाहे वह उठाये। ऐसे ऐसे परमिट दिये जाते हैं स्टेट सरकार की तरफ से, और हाई कोर्टस में जाकर ऐसे ऐसे सवाल उठाय जाते हैं कि इस एक्ट को बिल्कुल थोथा बना दिया गया है। अभी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट नहीं चल रहा है बल्कि मनमानी चल रही है। जिसके पास ज्यादा बसें है, पैसा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर जिस के हाथ में है वही वहां का मालिक है। और जो 1, 2 बसों के मालिक है उनकी हालत खराब है। इसलिए मैं चाहूंगा कि काम्प्रीहेन्सिव बिल में इन बातों का खयाल रखा जाय जिससे छोटे लोगों को परेशानी न हो। जिनके पास एक ट्रक या लारी है, वही सबसे ज्यादा सफरर इस समय हैं हमारे देश में। काम्प्रीहेन्सिव बिल लाते वक्त इसका मंत्रीजी ध्यान रखें कि उनके ऊपर ज टैक्स का बोझा है वह कम हो।

इसके साथ छोटे लोगों को, मालिकों को टायर लेने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस बिल के अन्दर कम से कम इसका भी खयाल रखा जाय कि उनको टायर वैगरह के लिये ज्यादा पैसे न देने पड़ें और सामान आसानी से मिल जाय। उसके बाद स्पेयर पार्टस में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बड़े बड़े लोग तो किसी तरह ज्यादा पैसे देकर चीज इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन जो गरीब मालिक हैं उनको पार्टस नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो उनको दामों में लूटा जाता है। इन बातों का भी खयाल काम्प्रीहेन्सिव बिल में रखा जाय।

जहां तक मजदूरों का सवाल है, कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर या कुली, उनके बारे में इसमें कोई गारन्टी नहीं है। जितने लोग इस उद्योग में काम कर रहे हैं सब टेम्पोरेरी हैं, 20,20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक टेम्पोरेरी हैं उनको कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है। इस इंडस्ट्री के मजदूर, इंडस्ट्री की तरह ही डिस आर्गेनाइज्ड हैं। उनके वीकली वेज का सवाल नहीं, बीमारी में किसी मेडिकल फेसिलिटी का सवाल नहीं, सालाना तरक्की का सवाल नहीं, अगर तनख्वाह न मिले तो उसके प्रोटेक्शन का कोई सवाल नहीं है। हालांकि इस ऐक्ट के मातहत उनको भी सजायें भोगनी पड़ती हैं लेकिन जहां तक उनके आराम और फायदे की बातों का सवाल है उस बारे में इस बिल में कोई प्रोवीजन नहीं है। मैं चाहूंगा कि काम्प्रीहेन्सिव बिल में इन तमाम बातों का खयाल रखा जायगा।

आखिर ऐक्सीडेंट्स होते क्यों हैं; इसलिये कि ड्राइवर मजबूरी में रहते हैं। उनको मजबूर किया जाता है डिफेक्टिव गाड़ी चलाने के लिये, ओवर लोडिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर ड्राइवर रिफ्यूज करता है तो उसको

फौरन काम से हटा दिया जाता है। जो भी ड्राइवर, कंडक्टर ओवर क्राउडिंग करके मालिक को ज्यादा पैसे लाकर देता है उसी को रखा जाता है और जो ईमानदारी से काम करेगा, ओवर लोड नहीं करेगा, उसकी नौकरी चली जायगी। इन तमाम चीजों की गारन्टी होनी चाहिये। 9 टन की गाड़ी में 12, 14 टन माल लादा जाता है, ब्रेक डिफेक्टिव हैं, मगर फिर भी मालिक कहता है कि तुमको गाड़ी ले जानी है और फलां समय फलां जगह पहुंचना है। अब अगर वह हुक्म न माने तो नौकरी गयी। और अगर हुक्म मानता है तो जरूर रास्ते में ऐक्सीडेंट हो जायगा। यही वजह है ऐक्सीडेंट होने की।

मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट बना है मजदूरों की गारन्टी के लिये मगर वह भी इनइफेक्टिव है, उसको अमल में नहीं लाया जाता है। मन्त्री जी इन तमाम बातों का ध्यान काम्प्रीहेन्सिव बिल में रखेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। काम का कोई समय नहीं है, दिन रात मजदूरों को काम करना पड़ता है। सारी सारी रात गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, बीमार हैं लेकिन फिर भी मालिक का हुक्म मानना पड़ता है जिसकी वजह से ऐक्सीडेंट होता है। आप सोचें कि रात भर कैसे कोई आदमी जगकर गाड़ी चलायेगा। मगर करना पड़ता है नहीं तो नौकरी से अलग कर दिया जाता है। इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए मंत्री जी जरूर बिल में कोई न कोई इंतजाम करेंगे।

यह अमेंडमेंट बिल जो आया है इसकी बहुत सी चीजों का मैं समर्थन करता हूं। और यह ठीक बात है कि अभी काम चलाने भर के लिए जो इसको सरकार लायी है, उसको रखें। मगर इसके साथ साथ जो ड्राइवर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की बात की जा रही है वह मेरी समझ में मालिकों के हाथ में आप एक हथियार देने जा रहे हैं। जो ड्राइवर कमजोर होगा, मेडिकली अपने को फिट नहीं पायेगा वह खुद ही गाड़ी नहीं चलायेगा, और कोई दूसरा काम कर लेता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के माने यह हैं कि मालिकों के हाथ में एक हथियार है और जब भी मालिक किसी ड्राइवर से नाराज हो जायगा वह फौरन कह देगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ। वैसे तो लाइसेंस के वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे में मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना, यह बात मेरी समझ में मुनासिब नहीं लगती। उस वक्त तो गाड़ी खुद हो नहीं चला सकता है। फिर इस प्रोवीजन की क्या जरूरत है?

नेशनेलाइजेशन का जहां तक सवाल है साइड बाई साइड प्राइवेट बसें भी चलनी चाहियें। क्योंकि बंगाल में हम जानते हैं कि विधान बाबू ने यही कहा कि नेशनेलाइज कर के यह काम नहीं चलेगा। 10 वर्ष बाद उनको मानना पड़ा। आज यहां साइड बाई साइड प्राइवेट बसें चल रही हैं। इसलिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये रूट नेशनेलाइज हो गया वहां स्टेट अपनी बसें चला रही है और एक एक, दो दो बसों के मालिकों को भगा दिया गया। यह ना-इन्साफी है। रेल के लिये तो सेन्ट्रल कंट्रोल है, मगर ट्रांसपोर्ट जो रेल के साथ काम कर रहा है **

सभापति महोदय : आप बैठिये, बहुत देर हो गयी, आपका नाम था ही नहीं। ऐसा करेंगे तो आप को कभी नहीं बोलने दिया जायगा। और आप जो कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायगा।

16 hrs.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : Mr. Chairman, Sir, I am very thankful to the hon. Members who have participated in this debate. As I said in the beginning, they have given some

** Not recorded.

[Shri Iqbal Singh]

suggestions. Some members have made suggestions for improvement of this Bill. We will consider them when the clauses are taken up. Others have given some general suggestions. Some have touched topics which are beyond the scope of this Bill like improvement of National Highways. Though I will not reply to them at this time, I will deal with them at the appropriate time. We will see to it that whatever improvement can be done, is done.

I will deal with one suggestion that was generally made Some have appreciated this Bill. Others have said 'Why have you brought this Bill when you are thinking of bringing a comprehensive Bill ?'. I want to place a proposition before this House. This Bill was introduced in 1965 when Shri Raj Bahadur was the Transport Minister and again Shri Poonacha piloted this Bill and after the Third Lok Sabha, this Bill was brought back and then both Houses appointed a Joint Select Committee which has made certain recommendations and this Bill is based on these recommendations. Why we are bringing this Bill when we are thinking of bringing a comprehensive ligislation, is that there are so many good points and we do not want to delay the matter any further. When we bring the comprehensive legislation, first we will draft a model Bill which will be considered by the Transport Development Council. Because the application of this Act is to be done mostly by the State Government and many of the powers we have given in this Bill are to be exercised by the State Governments we have to carry the State Governments also with us. Even in this Bill we have taken provisions from 35 State Bills that have been passed by the State Governments in order to make the legislation universal and they can be applied throughout the country. For any new Bill, for any new ideas or for anything which we wanted to put in the comprehensive Bill, we have to carry the State Govenments also with us. For that we need time. We have to draft the Bill. Then we will have to consider it in the Transport Development Council. But all these procedures will take some time. But we do not want to delay these matters.

श्री शिवचन्द्र झा : कितना समय लगेगा ?

SHRI IQBAL SINGH : I cannot give any assurance of hand, but I can give one assurance that we will start right earnest on the comprehensive Bill. Here hon. Members have given some important suggestions. We have to examine them. Their suggestions are far-reaching in character. We would like to know whether they will be acceptable to the State Governments. Some of the Members have even suggested in this Bill that there should be no permit system I do not know whether we will be able to carry the State Governments with us on this point. I can tell the hon Member one thing that as far as goods transport is concerned, the permits are available freely. In all States there is no restriction. But regarding other suggestions how far they will be acceptable to the States, I cannot give the time. But I can give one assurance that we will in right earnest examine the suggestions given by the hon Members and we will see to it that the suggestions given, so that the transportation system may improve and other facilities may be given to the people and that we may provide more facilities of transportation especially when we are constructing so many rural roads and people living in villages must get better facilities, are implemented. There also we will ask the State Governments to provide facilities at great speed so that the roads which are constructed at the cost of the exchequer are utilised by the villagers. Every one of the suggestions which has been made will be taken note of by us.

There is one suggestion which has been made about the Inter-State Transport Commission. That Commission was constituted long ago but the State Governments have been asking about various things. We are taking steps. That Commission will be given more powers We should really develop Inter-State Transport which would meet the needs of long-distance passengers and in respect of goods traffic also, and what ever difficulties come in the way will be removed. And, for that, we are giving more powers and we are asking them to function effectively. I hope, with that, some more improvement will be made in this regard.

Regarding the tourist traffic and tourism in the Bill we are providing that tourist transport should be developed. They cater to export and that is earning foreign

exchange for the country and it is necessary to develop it not only for export, but also for the country's needs, for integration and for various other purposes, for religious purposes, for various other purposes, people go from one State to another and we should see that all these facilities are available to them so that there may be free movement and more movement of the people from one area to another area by the use of these facilities.

Regarding the Octroi, this was considered last year by the Transport Development Council. After that we have taken this up in right earnest with the State Governments and the position is not as and as is being depicted. There are so many States where there are no octroi duties. We are asking the other State Governments to abolish octroi. We are taking some other steps. We have written to the States. My previous senior colleague Dr. Rao has written to all the Chief Ministers in this regard. This is one of the biggest bottlenecks in the movement of traffic. Not only bottleneck, but there are some other problems which are being created, like delays and even some complaints of corruption. We are writting to the State Governments but again the State Governments are faced with this problem of resources and even on that we are taking some steps. Some States have agreed; some States are still not agreed. We are asking the State Governments to remove the octroi so that free movement of goods and free movement of traffic may be improved further.

Regarding one other point raised by Shri Mahajan I wish to say something. He mentioned about rail-road coordination and rail-road competition. That is an old story. I don't think so now. It is not so in the present context of the situation when the total rail mileage is only about 36,000 miles in our country and the total road mileage is about more than 3 lakhs metalled road and in respect of unmetalled road it is more than 3 lakhs and the total comes to about 6 lakhs. Very any areas will be covered and remote areas have to be interlinked, which have to be opened up for traffic. So, what he says is an old story. Traffic is originating from these areas very much more and we want to cater for that traffic. We want to provide more facilities so that the roads are properly utilised. We are taking necessary steps so that the whole system may be improved.

Regarding some of the criticisms made, some severe criticisms have been made about the issue of permits. I may tell the hon. Member that all these permits are issued by State Governments. Still we are providing in this Act that there may be some system whereby the semi-judicial or quasi-judicial proceedings may be introduced. That is what we are providing so that we may have a tribunal where members whose qualifications are equal to the district judges may be appointed. Regarding certain other points made out, we have taken steps and the State Governments are also cooperating. When we will be able to reach that farther end when there will be no complaints and all that, I don't know. We have made statutory provisions. In respect of applications when there is inter-State agreement between two States it must be published in the gazette and published in the newspapers, so that people may know that permits are to be issued and they can apply and they can claim.

It this context, Ch. Randhir Singh and one other hon. member spoke about the Scheduled Castes and ex-servicemen. There is no provision here, but we do encourage co-operatives societies of Scheduled Castes and ex-servicemen. They could apply and that is why there is provision specially made in the principal Act.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga) : What about Scheduled Tribes ?

SHRI IQBAL SINGH : They can also apply. For that purpose, we give preference to co-operative societies. In some States like Punjab and Haryana, permits are issued to co-operative societies which have been formed. They will get preference. Still if anything further can be done, we will examie it. We will write to the State Governments in regard to this matter.

So also with regard to ex-servicemen. Ten or twenty years ago, there was a lot of assistance given, but now not much. We can again ask State Governments to look after their interests and see that their interests are not neglected.

[Shri Iqbal Singh]

As for the issue of permits, it is entirely with the State Governments. We can ask them and bring these points to their notice.

SHRI R. S. ARUMUGAM : There is no provision in sec. 47 to give preference to Schduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI IQBAL SINGH: There is a provision for giving preference to co-operative societies which can be formed, as they have been in Punjab and Haryana. Thus they get preference. But this lies entirely with State Governments. As to whether we can do anything further we will examine in the next Bill. I cannot say it can be done in this Bill because we are not amending that clause now.

Shri Naidu asked why we should extend the period for filing claims from 60 to 180 days. The man who is injured may be in hospital. The place where he was injured may be far away from the place in district or tehsil headquarters where he should file the claim. Some persons represented to us that their claims were time-barred because they were in hospital and could not file the claims in time. So we have extended the timelimit. Also, along with the claim, they have to file the police report. Some police proceedings are not completed within the existing timelimit. Hence this extenstion.

Then a point was generally made asking why when a permit is issued for three years and there is delay on the part of the State Government in issuing the permit, the period of delay is also included in the permit. Previously when an application was made for permit, the time used to be 60 days. Now we have extended it to 120 days Also when an application for renewal was made, the formalities were not completed in some States in six months or four months or three months. In some cases, the permits were renewed from the date of expiry of the original permit while in others it was effective from the actual date of sanction. We wanted that there should be fixed time within which this should be done and there should be uniformity in this regard. So whatever time is taken in the process should be included in the period of three years. There were also complaints received that purposely the whole matter was delayed so that they could get more benefit. We do not want to give any benefit this way or that way. When a permit is issued again for three years, that time will be included and the fees will be refunded. The rules were different in different States, but now we have made it uniform.

Clause 29 states that when the buses of one State pass through the corridor of another State, they will not require any counter-signature up to 8 km There is a suggestion that it should be increased to 16 km, as it was in the original Act. We are not increasing because if we increase to 16 km practically any bus can pass through some part of Union Territories like Delhi, Chandigarh, etc. without taking permit. That will create more complications and that is why the Select Committee has made it 8 km. Even if it is more than 8 km., it does not debar a person from going, only he has to take the counter signature of that State through which he is passing.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : 16 किलोमीटर तो पहले था । उसको 8 किलोमीटर कर दिया है । सिगनेचर लेने की बात आप करते है । आप जानते हैं कि करप्शन कितना है । इसलिये अभी तक तो दिल्ली की बात है, मैं हरियाना और चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं क्योंकि इनके चंडीगढ़ और हरियाणा को बने बहुत अर्सा हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई तो उसको 8 किलोमीटर क्यों कर रहे है, 16 किलोमीटर क्यों नहीं कर रहे है ?

SHRI IQBAL SINGH : We are bringing this for the first time. So far there was no other counter-signature.

SHRI K. N. TIWARY : Because you are a Minister, you cannot be ignorant of it I do not know whether you run any bus.

SHRI IQBAL SINGH : I do not.

SHRI K. N. TIWARY : Had you been running, you might have come to know by this time that every officer takes somethin before putting his signature So, do yo

mean to say that you want to put every bus owner to truck owner to disadvantage ?

SHRI IQBAL SINGH : I appreciate what my respectable friend says. If we allow more distance, the States through which the buses pass will lose revenue, and the States objected to that. So, for that purpose also for the first time we have given this facility. Let us watch this and in future if further extension is required, we will exmine it in the next Bill.

So far, one had to pass through three regional authorities. Now we are giving powers to the State Governments and the counter-signature can be taken at one place, either at the State level or the regional level. These two facilities we are giving and we think that with these facilities there will be some improvement If still they feel that the smaller State will lose larger revenue, we will take note of that.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अगर एक बस यहां दिल्ली से चलती है तो बीच में हरियाणा आया, फिर पंजाब आया, फिर उत्तर प्रदेश आया तो इस तरह वह बेचारा हस्ताक्षर ही लेता रहेगा।

श्री इकबाल सिंह : सबसे बड़ा ऐतराज तो दिल्ली का ही है। उनका ऐतराज सबसे बड़ा है।

We shall consider all the other points raised by the hon Members and benefit by them when a Bill is drafted in the future. Because this Bill has been pending for the last four yeas; this will benefit the workers Previously, they were to work for nine hours at the steering wheel; we are reducing it to eight hours. Clause 41 is in favour of nationalisation There were so many objections and counter objections and nationalisation was kept pending and it could not be finalised. This Bill enables that and we do not want to delay things. We have given such a type of formula in clause 41 which was agreed in the Rajya Sabha and both sides will not feel any difficulty.

Some points were made about writing number plates in English and the other languages. We ... examining it; we have asked the State Governments. We propose to bring in legislation after ascertaining the views of all the State Governments. It will help enforcement of law; a constable who will be more or less a matriculate should be able to read all the regional languages if we allow all the regional languages to be used. Why not then go to the new formula where only the number are there ? We are considering the most effective way of enforcement.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सबसे जरूरी चीज यह है कि जो गाड़ियां ऐक्सिडेंड करके भाग रही हैं उनका चालान करना होगा पुलिस को। अभी आप एग्जामिन ही कर रहे हैं कि अंग्रेजी नम्बर हों या न हों या रीजनल लैंग्वेज में हों।

श्री इकबाल सिंह : इस बिल में इस वक्त जो दिया गया है वह है, लेकिन बाद में हम उस को बदलेंगे। यह कैसे हो इस की बाबत राय बना कर और सबको साथ ले कर ही हम उसको बदल सकते हैं।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : ज्वायेंट कमेटी में सुझाव दिया गया था कि अंग्रेजी में नम्बर जरूर हो और रीजनल लेंग्वेजमें भी हो। इस पर मिनिस्टर साहब ने गौर करने का वादा किया था।

[شری اسحاق سمبھلی (امروھہ)
جوائنٹ کمیٹی میں سجھاو دیا گیا تھا کہ
انگریزی میں نمبر ضرور ھو اور ریجنل
لینگویج میں بھی ھو۔اس پر منسٹر
صاحب نے غور کرنے کا واعدہ کیا تھا۔]

श्री इकबाल सिंह : मैंने कहा कि हम गौर कर रहे हैं कि अंग्रेजी में हो उसके साथ हिन्दी में हो और रीजनल लेंग्वेज में हो या वहां पर सिर्फ नम्बर ही हो। स्टेट को भी नम्बर दे दिये जायें जैसे कि यू पी को मान लीजिये 15 नम्बर दे दिया गया, किसी को कुछ और दे दिया गया और उस के बाद

[श्री इकबाल सिंह]

डिस्ट्रिक्ट का नम्बर दे दिया गया। नीचे भी नम्बर, ऊपर भी नम्बर। वहां कोई अल्फाज़ है ही नहीं। इन सब चीजों पर हम गौर कर रहे हैं। इस के बाद स्टेट्स के साथ राय करके फैसला करेंगे। जिस पर वह रजामन्द होंगे वही हम रक्खेंगे। जब तक हम उसको बदलेंगे नहीं तब तक मौजूदा चीज को चालू रक्खेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस बिल को कंसीडरेशन में लिया जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

" That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2.–*(Amendment of section 2.)*

MR. CHAIRMAN : We take up clause 2. There are two amendments-40 and 41 by Shri Lobo Prabhu. Shri Abdul Ghani Dar is not here.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I move :

Page 2 -

omit lines 23 to 26. (40)

Page 3, line 5,-

for "State" *substitute* "Central" (41)

I may begin by saying that I have some experience of motor transport administration. I have been a district officer and to that extent I have been a regional transport authority for a number of years. I have also been Home Secretary. In those circumstances I am in a position to lay my knowledge before this House and I hope they will bear with me if I point out that there are three or four main defects in the administration of motor transport. These will come again and again in the various amendments which I have tabled.

The first defect was mentioned by my good friend Tenneti Viswanatham-the excessive liability to accidents of our motor transport. He mentioned that the daily mortality rate was 350. Even accepting that very conservative figure; it means that in three days motor transport does what the railway does in a year. Their fatal accidents add up to 800. This is not a matter about which the Minister could be complacent, when we are killing off our population at this very high rate of 350 persons a day. That is important, because it is so serious, and that is the basis of the first amendment which I am moving about the weight of the buses and the speed which you allow for the medium and the heavy vehicles.

The second grave and big defect is corruption. This has also been mentioned, and I shall make this matter very clear with the figures. Not a single permit is given, not a single licence is renewed by the Regional Transport Officer unless Rs. 25 are paid. There is no denying this. I have written to the Vigilance Commissioner, both at the State level and at the Central level, but they have not been able to do anything. The permit, if it is on a good service route-can fetch Rs. 30,000 on transfer. It, therefore, means that the opportunities for corruption by the vendability of a permit are enormous, and at the stage of giving the permits, the opportunities for corruption cannot be at all assessed. I am going to say a little more on the subject later on, because I myself had something to do with a system known as the marking system; this was aimed to reduce the amount of discretion of the issuing authority. In adddition to that, we have corruption through the police. There is not a single bus checked by any police station on the route without paying a certain *mamul* which may be Rs. 2 to Rs. 8 according to the needs of the police station, but on an average—I have calculated this—Rs. 3,000 is the monthly earning of a police station from buses and lorries.

The third point which I want to stress is that our road transport is most costly in the country. It was said sometime ago in this House that only the taxes paid on mileage per tonne on road transport exceeded the total charges made by the railways for the same disance: only the taxes. This is a very, very high rate. It is unfair to road

transport. When you come to passengers, you have the railways carrying the passengers, at four paise, and you have the bus which takes them at nine to 10 paise. These are the three main defects; in the frame-work of these defects, I am proposing my various amendments.

My first amendment is in respect of the weight of the buses. For heavy buses, it has been raised from 8,200 to 11,000 and for the medium buses, from 3,000 to 4,000. What we have to consider in raising the limits is that though buses may have improved in respect of their mechanical aids, their difficulties in regard to the road or other traffic have not been remedied, in keeping with the size of the buses. Therefore, when you think in terms of liberalising the weight of the buses, you are without doubt adding to the incidence of accidents.

I would mention one thing which was reported in the papers recently. A heavy bus travelling one direction near Bangalore and a car travelling in the other direction met because the heavy bus had a deflated tyre. The result was that when the remains of the car were examined, not one of the seven bodies in the car could be identified. This is an aspect which arises both from the size and the speed of the bus. So, I would say that before you liberalise these rules in respect of weight and consequently in respect of speed, you must have better roads and you must have accident proof transport/vehicles.

I will speak tomorrow on the other amendments.

MR. CHAIRMAN : I shall put the amendment to the vote.

SHRI LOBO PRABHU : I have spoken on only one amendment.

MR. CHAIRMAN : I am putting amendment No. 40 now.

SHRI LOBO PRABHU : The time was up, and therefore, I stopped.

MR. CHAIRMAN : We will put the first amendment.

SHRI LOBO PRABHU : Tomorrow, I will speak on the second amendment.

MR. CHAIRMAN : I am putting amendment No. 40.

Amendment No. 40 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the other discussion. It is now 4.30.

16.30 hrs.

MOTION RE : SUBVERSIVE AND VIOLENT ACTIVITIES IN THE COUNTRY--*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now resume further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on 16th May, 1969, namely :-

> "That the situtation arising out of the encouragement being given to the subversive and violent activities in the country by certain political parties and by some foreign powers, be taken into consideration."

We have one hour.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Yesterday during the discussion on drought in Rajasthan, representatives of three groups could not get any time to speak at all because the Chair said the time was over. That should not be repeated today. Whatever time is fixed, I would request you to see that all groups' representatives have their say, because the subject is important.

MR. CHAIRMAN : It is not possible to call all the parties on all the subjects.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : That would be doing violence to non-violence !

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : There is a half hour discussion at 5.30. Therefore, I take it that this discussion will be for one hour from 4.30 to 5.30 and this is going to spill over to some other day. The debate would not be concluded today.

MR. CHAIRMAN : Shri Prakash Vir Shastri may continue his speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, कुछ राजनैतिक दलों द्वारा विदेशों से सहयोग लेकर देश में जो अराजकता, तोड़-फोड़ और हिंसा की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो कि हमारे जनतन्त्र और स्वतन्त्रता के लिए चुनौती बन गई हैं, आज मैं उस प्रश्न को इस सदन में उपस्थित करना चाहता हूं ।

जिस समय मैं इस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूं, आज से ठीक पांच दिन के बाद एक प्रमुख राज्य के मुख्य मन्त्री और उनके साथी अपनी विवशता की सीमी लांघने पर उस राज्य में साठ जगह सत्याग्रह करने जा रहे हैं । यह स्वाभाविक ही है कि जब थानों और पुलिस पर हमला करके हथियार लूटे जा रहे हों, रक्षा सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों को जंगल में खड़ा करके लूटा जा रहा हो, विदेशों से भी धन, हथियार और साहित्य भारी मात्रा में आ रहा हो, राजनैतिक हत्याओं का सैकड़ों की तादाद में तांता लग गया हो, पुलिस और दूसरी सरकारी सेवाओं में अपने ढंग की भरती आरम्भ हो गई हो, न्यायालयों में राष्ट्र-द्रोह और फौजदारी के अभियोग सरकारी स्तर पर वापिस हो रहे हों, संविधान के स्थान पर सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया जा रहा हो, तो किसी राज्य का मुख्य मन्त्री विवशता की स्थिति में सत्याग्रह का सहारा ले, यह एक बड़ी गम्भीर और सोचने योग्य बात है ।

16.33 hrs.

[SHRI VASUDEWAN NAIR *in the Chair*]

कुछ राज्यों में ऐसी भी स्थिति है कि कुछ राजनैतिक दलों ने अपनी स्वतन्त्र अदालतें बना कर सजा और जुर्माने करने भी प्रारम्भ कर दिये हैं । मेरे हाथ में एक ऐसे ही आदेश की फोटो-कापी है, जिसमें पश्चिमी बंगाल के दीनाजपुर जिले के काकी गांव में इस तरह की एक अदालत ने किसी व्यक्ति पर जुर्माना किया गया है ।

ये घटनायें देश के सीमावर्ती राज्यों में प्रमुख रूप से हो रही हैं । इनके केन्द्र आन्ध्र, केरल, उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब और असम जैसे सीमावर्ती राज्य तो हैं ही लेकिन मैं इन सब राज्यों के सम्बन्ध में विस्तार में न जाकर पहले अकेले पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

पश्चिमी बंगाल में अक्तूबर से पहले पिछले सात महीनों में 378 कत्ल और 201 राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो चुकी हैं । अगस्त और सितम्बर के दो महीनों में राजनैतिक दलों में 65 आपसी संघर्ष हुए, जिनमें 673 व्यक्ति घायल हुए । रवीन्द्र सरोवर कांड के अलावा अन्य मामलों में आठ महिलाओं की इज्जत लूटी गई । 36 हाई स्कूलों के मुख्याध्यापकों को डरा धमका कर त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया । 37 मामलों में कानून और व्यवस्था का खुले आम उल्लंघन करके अस्पतालों के कर्मचारियों पर आक्रमण किये गये । पुलिस ने 292 मामलों में उदासीनता बरती । जिनमें 202 मामले अकेले 24 परगना जिले के है । इन सात दुर्भाग्यपूर्ण महीनों में औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर 551 हड़तालें हुई । अगस्त तक 367 घेराव और 73 कारखनों में तालाबन्दी हुई । 5 लाख 74 हजार कर्मचारी हड़ताल और तालाबन्दी से प्रभावित हुए । 61 लाख श्रम के घन्टे बरबाद हुए और 1010 इस प्रकार के अभियोग थे जो कचहरियों में चल रहे थे लेकिन राज्य सरकार ने उनको वापस लिया । इसी तरह से 218 ऐसे गरीब और मध्यम श्रेणी के किसान थे जिनकी धरती पर बलात् कब्जा किया गया । यह घटनाएं जिनको मैं सुना रहा हूं पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नदिया 24 परगना, हुगली, बर्दवान, पुरुलिया, मिदनापुर और विशेषकर कलकत्ता में हुई । इसी प्रकार की घटनाएं आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में विशेष रूप से वनवासी क्षेत्र के अन्दर बढ़ रही हैं । उसके

अतिरिक्त आन्ध्र के दूसरे जिलों मे भी बराबर यह गतिविधियां बढ़ रही हैं।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : Sir, I rise on a point of order. I think it is recognised parliamentary practice that if the affairs of a particular State in our Union of States is going to be discussed in the detailed manner which Shri Prakash Vir Shastri has already displayed, then that is not permissible under the rules unless there is some special reason where you can invoke the provisions of the Constitution or parliamentary procedure. I can understand Shri Shastri talking about what he says his motion purports to be, the situation which has arisen out of what he considers to be "undesirable activities" of certain people. But to give, on his own computation, particularly in relation to a particular State, namely, West Bengal, a whole host of figures which are open to doubt and controversy, and to base his motion on that, is certainly against the spirit of the rules and entirely unwarranted by the Rules of Procedure. If we are going to have a discussion on West Bengal law and order problem, if this Parliament has the right to be in possession of facts, all right let us go ahead; but why do it by the back door ? Why not we put the matter on a higher pedestal of principled discussion of what is happening in some parts of our country ? Why should we try to put the West Bengal Government in the dock, as Shri Shastri has tried to do ? He has mentioned the Rabindra Sarovar incident and even Shri Chavan must be rather ashamed in regard to the kind of exaggeration which he has made of this particular incident. I say this is absolutely unwarranted procedure and this is not a proper discussion... (*Interruptions*)

SHRI RANGA (Srikakulam) : I would like to say something on this point of order.

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : मेरा भी एक व्यवस्था का सवाल है। जो बात मेरे पुराने मित्र ने कही....

MR. CHAIRMAN : I have not allowed him to raise that point of order.

SHRI JAIPAL SINGH : How can you shut out members from raising points of orders ?

MR. CHAIRMAN : Because I have to give my ruling on a point of order which has already been raised.

SHRI JAIPAL SINGH : Then I will raise mine after the ruling is given.

MR. CHAIRMAN : It is very clear to every hon. Member that the motion is worded in very general terms. It refers to the general situation of violence and subversive activities in the country. I hope hon. Members would refrain from going into the details of the law and order situation in a particular State because then the State Legislature and the State Government come into the picture. Of course, when such a discussion is taking place I cannot entirely shut out members from making some references to some of those incidents. All the same, I would request the mover as well as other members not to make an accusation or a chargesheet against any particular State government, because that will not help us. As Professor Mukerjee has rightly pointed out it should not appear that this discussion is directed against any particular State or State Government. Of course, it is obvious that we cannot be completely shut out from making any reference to any particular incident. I hope, within that limit Members will make only responsible statements in the House and we can proceed with the discussion.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur) : I rise on a point of order.

MR. CHAIRMAN : Why should we waste time on orther points of order ?

SHRI S. M. BANERJEE : I can assure you, I am not going to waste the time of the House. My point of order is based on past rulings.

MR. CHAIRMAN : I am sure, both Shri Banerjee and Shri Jaipal Singh will cooperate with the Chair as well as with the House in not raising points of order at this stage.

SHRI S. M. BANERJEE : I can assure you, I will co operate with you in the Chair and even here.

MR. CHAIRMAN : Let us now proceed with the discusston. Let us wait and see. Shri Prakash Vir Shastri may continue his speech.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : लेकिन इसको एक्सपन्ज कराइये, अब तक उन्होंने एक ही स्टेट के बारे में कहा है ।.... (**व्यवधान**) ...

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : एक के बारे मैंने नहीं कहा है, दूसरी स्टेटों के बारे में भी कहा है । ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद इस्माइल : आपकी रूलिंग के मुताबिक काम होना चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सभापति महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल के बाद आन्ध्र प्रदेश की चर्चा कर रहा था...

श्री जयपाल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं बहुत कम हिन्दी में बोलता हूं । देखिए ये हमारे पुराने मित्र हैं ...

MR. CHAIRMAN : Are you speaking on that point of order ?

SHRI JAIPAL SINGH : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN : I have already given my ruling on that.

SHRI JAIPAL SINGH : I know.

MR. CHAIRMAN : Perhaps, it is not a point of order; you want to enlighten the House.

SHRI JAIPAL SINGH : It is a point of order.

My hon. friend, Professor Hirendra Nath Mukhopadhyaya, raised a point of order and you have already stated that a general discussion can take place but references to details or to States cannot be made.

MR. CHAIRMAN : Accusation of State Governments or of particular States should be avoided.

SHRI JAIPAL SINGH : It should be avoided if it can be avoided.

MR. CHAIRMAN : That should be avoided.

SHRI JAIPAL SINGH : My hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri cannot make out his case unless he gives you instances.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : That he has allowed.

SHRI JAIPAL SINGH : Then how do you avoid instances ? I want to know that. My hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri has been to my State. He has been to Ranchi, my constituency.

MR. CHAIRMAN : I cannot allow this speech to go on like this. I cannot be indulgent to one hon. Member like that.

SHRI JAIPAL SINGH : Professor Hirendra Nath Mukherjee has raised a point that details cannot be mentioned and you say that little things can be mentioned. I want to know...(*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Will you please read the motion yourself ? The motion is about the activities of certain political parties and some foreign powers. The motion itself is an obvious motion. It is not a charge-sheet against any State Government. You cannot accuse the State Governments

SHRI JAIPAL SINGH : I submit..... (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Order, Order. This cannot continue.

SHRI JAIPAL SINGH : I submit to you. I sit down.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सभापति जी, मैंने प्रारम्भ में यह कहा था कि देश के सीमावर्ती राज्यों में विशेषकर इस प्रकार की घटनायें हो रही है । बंगाल के पश्चात् मैंने

आन्ध्र की घटनाओं का कुछ उल्लेख किया था। उसके पश्चात् तीसरा उल्लेख में उड़ीसा के सम्बन्ध में कर रहा था। उड़ीसा के उप-मुख्य मन्त्री, श्री पवित्र मोहन प्रधान से अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि आन्ध्र और उड़ीसा की सीमा पर इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं भी होती हैं कि जीवित आदमियों को पेड़ पर लटका कर उसके शरीर के एक एक अंग को पृथक पृथक काटा जाता है–और सबके सामने इस प्रकार का प्रदर्शन होता है और कहते हैं देखो हमारे विरोध करने का क्या परिणाम सामने आता है ?

अभी कुछ दिन पहले असम के वित्त मन्त्री श्री त्रिपाठी ने 21 मार्च को राज्य विधानसभा में एक वक्तव्य दिया कि शिव सागर जिले में नागा विद्रोहियों के साथ मिल करके जो इस प्रकार के तत्व हैं वे किस तरह से असम सरकार का तखता पलटने का यत्न कर रहे हैं। उन तत्वों ने अपने कार्यक्रम में अनेक बातें रखी हैं जैसे रेल के पुलों को उड़ाना, पाइप लाइन, पेट्रोल डिपो और हवाई अड्डो को नष्ट करना इत्यादि। इसी प्रकार की कुछ घटनाओं की आवृति उत्तर प्रदेश में हुई हैं। बिहार की जो सीमा नेपाल से लगती है वहां पर भी इस तरह की घटनायें हुई है। पंजाब में रोपड के पास भी इसी प्रकार की घटनायें हुई है। केरल में भी ऐसी ही घटनायें हुई हैं।

मैं इन सब बातों के विस्तार में अधिक न जाकर प्रमुख रूप से इस बात पर आता हूं कि आखिर इन सब का सूत्र संचालन कहां से हो रहा है।.....(व्यवधान)...अबसे कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में....(व्यवधान)

श्री इसहाक सामली (अमरोहा): यू०पी० का जिक्र नहीं किया कि जिला मुजफ्फर नगर में श्री जैन को बी० के० डी० वालों ने मार डाला।...(व्यवधान)...

[شری اسحاق سمبھلی (امروھہ) یو پی کا ذکر نہیں کیا کہ ضلع مظفرنگر میں شری جین کو بی-کے-ڈی-والوں نے مار ڈالا...(ویودھان)-]

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : चोर की दाढ़ी में तिनका ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि इन सबका सूत्र संचालन कहां से होता है मैं उसकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। सदन के सदस्यों को ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में चीन में साम्यवादी पार्टी का 9वां सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध में अपने दस्तावेज पेश किए कि किस किस देश में हमारा कार्यक्रम किस ढंग से चल रहा है। भारत के सम्बन्ध में भी, पार्टी के जो उपाध्यक्ष श्री लिन पियाओ हैं, उन्होंने अपने कुछ कार्यक्रम दिए। सारी बातें बताते हुए उन्होंने भारत सरकार पर एक आरोप लगाया कि भारत में इस समय जो सरकार चल रही है वह रूस, अमरीका और ब्रिटेन की दास हो चुकी है। हम इस प्रकार का वातावरण वहां पर उत्पन्न कर रहें कि समय आने पर एक धक्के में उस सरकार को वहां से हटाया जायेगा ये सारी योजनायें वहां पर बैठ कर बन रही हैं। उसी आधार पर भारत वर्ष में जो कुछ कार्यक्रम तैयार किए गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है;

1. सत्ता बन्दूक की नोक से बदली जा सकती है संविधान से नहीं। सत्ता वोट से नहीं, बुलेट से बदली जा सकती है।

2. किसानों, मजदूरों और छात्रों को सशस्त्र संघर्ष के लिए उभारा जाये।

3. कारखानों के अन्दर घुसकर तोड़-फोड़ की जाये और उत्पादन में बाधा उत्पन्न की जाये।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

4. कानून और व्यवस्था को हाथ में लिया जाये। थानों और पुलिस पर हमले किये जायें, इत्यादि।

अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी संघ के महामन्त्री, श्री कुलकर्णी ने भी बम्बई में अभी इस तरह के तथ्य का उद्घाटन किया। उन्होंने लिखा था कि पेकिंग से इस प्रकार के निर्देश, उनके निर्देश पर काम करने वाली पार्टियों को आये हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं में, रक्षा प्रतिष्ठानों में और पुलिस के अन्दर भी हमारी पार्टी के लोग प्रवेश करें। उसका प्रकार यह होना चाहिए की उनका रहस्य न खुले इसके लिए हमेशा अपने पास गीता की पुस्तक, कुरान या बाइबिल रखें जिससे उनका रूप धार्मिक रहें। अगर कहीं उनको अपनी मीटिंग करनी हो तो मन्दिर, मश्जिद जैसे स्थानों में करें। यानी इस प्रकार से अन्दर प्रवेश करके तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां की जाय और बाहर सशस्त्र विद्रोह किया जाये। यह गोदी कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी ने कहा था। इसी सन्दर्भ में शायद गृह मन्त्री श्री चव्हाण को याद होगा कि वे इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि चीनी दूतावास से केरल में कुछ स्थानों पर मनीआर्डर भेजे गये। केवल गृह मन्त्री श्री चव्हाण ने ही स्वीकार किया हो, ऐसी बात नहीं है, केरल के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री नम्बूद्रीपाद ने स्वयं 26 मार्च को केरल विधान सभा में इस तरह का एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे यहां के वामपंथी साम्यवादी सदस्य श्री कुन्नीकल नारायणन हैं जिनको चीनी दूतावास से दूकान खोलने के लिए धन मिला। इस प्रकार से उन्होने स्वीकार किया कि चीनी दूतावास से यहां पर आर्थिक सहायता आई। रायपुर में गृह राज्य मन्त्री, श्री विद्याचरण शुक्ल ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राजनीतिक पार्टियां विदेशों से धन लेकर काम चलाती हैं। जब इस तरह के वक्तव्य गृह मन्त्री श्री चव्हाण ने भी दिए हैं तब मैं चाहूंगा कि जब वे उत्तर दें तो इस बात को बतायें कि आपके गुप्तचर विभाग ने इस प्रकार के जो आकड़े दिए हैं उनमें क्या कुछ इस प्रकार का धन है जो चीन से आता हैं और यहां पर उसका प्रयोग राजनीतिक तोड़-फोड़ के कार्यों में किया जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के माध्यम से धन और हथियार दोनों आ रहे हैं। उधर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल के अन्दर एक पार्टी है जिसका नाम है माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जिसका भारतवर्ष की कुछ पार्टियों के साथ सम्बन्ध है। वहां पर ट्रेनिंग देने का काम, हिन्दी में लिट्रेचर छाप छाप करके बांटने का काम, धन बांटने का काम, इस प्रकार के कार्यक्रम वहां चल रहें है। ये सारी घटनायें उस समय और भी अधिक प्रकाश में आयी जिस समय पहली मई, 1969 को कलकत्ता में कनु सानयाल ने अपनी एक नयी पार्टी का उद्घाटन किया और उन्होंने मार्क्स-लेनिनवादी पार्टी को कार्यक्रम दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि माओ की नीतियों का अनुसरण करना हमारा प्रमुख रूप से ध्येय रहेगा। अन्डर ग्राउन्ड (भूमिगत) रह कर हम कार्य करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी करेंगे, और हमारी पार्टी की आस्था चीन की पार्टी के साथ में रहेगी। सशस्त्र संघर्ष में आस्था रखने वाले ही इसके सदस्य होंगे, क्रान्ति की परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया जायगा। इसी प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने दिये कि कृषक वर्ग में किस तरह से क्रांति की जा सकती है। कैसे उनको सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार किया जाता है? लेकिन मैं इन सारी बातों को कहने के बाद इस सरकार को दोषी ठहराना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि या तो अभी तक वह इन सारी विषमताओं की जो गम्भीरता है, या जो सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी देश में चल रही हैं, उसकी गम्भीरता को अनुभव नहीं कर रही है। या फिर मेरा यह दोषारोपण है कि अगर सरकार गम्भीरता अनुभव कर रही है तो सरकार के अन्दर कुछ व्यक्ति इस प्रकार के है जिनके मन में इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए सॉफ्ट कार्नर है।

जो इस प्रकार की प्रवृतियों को देश में चालू रहने देना चाहते हैं ।

आखिरकार यह बात क्या है ? जब सरकार समझती है कि जनतंत्र के लिए चुनौती दी जा रही है, संविधान के लिए चुनौती दी जा रही है, जेलों को खुलवाकर कैदियों को वहां से निकाला जा रहा है, अन्दर घुसकर करोड़ों रु० की सम्पति हमारे कारखानों की नष्ट की जा रही है, खेतों खलिहानों पर बलात कब्जे किये जा रहें हैं, राजनीतिक हत्यायें हो रही है, फिर सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठी है । क्यों नहीं इस दिशा में कोई सक्रिय कदम उठाती है ?

कलकत्ते से "देशवृर्ती" नाम का एक पत्र निकलता है, उसमें स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी कि हमारा राष्ट्रपति माओसे-तुंग है, वी० वी० गिरी नहीं हो सकता है । तो इतनी सारी बातें होने के बाद अगर सरकार चुप्पी साधती है तो यह शुतुर्मुर्गी नीति है, जैसे वह विपत्ति को देख कर रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है । यह नीति इस देश में नहीं चलेगी ।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश में एक वह भी समय था, गृह मन्त्री, श्री चव्हाण को याद होगा, जब नन्दा जी ने एक बार इसी प्रकार की प्रवृतियों पर प्रतिबन्ध लगाया था । उस समय उन्होंने बताया कि कुछ लोग गुप्त रूप से इस प्रकार का षड़यन्त्र बना रहे थे, इसलिए विवश हो कर यह कदम उठाना पड़ा । लेकिन जब स्पष्ट रूप से षड़यन्त्र सामने आ गया और खुल्लमखुल्ला नारे लगने लगे और खुलकर कनु सान्याल, चारू मजूमदार, जंगल संथाल और नागी रेड्डी, ये सब दहाड़ रहे हैं, उस समय गृह मंत्रालय यह सोचे कि सामाजिक स्तर पर हम उनका समाधान करेंगे, सरकारी स्तर पर समाधान नहीं करेंगे तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

आज सात पार्टियां हैं विशेष रूप से जो काम कर रहीं हैं । पहले साम्यवादी पार्टी एक थी । 1962 में बट कर उसके दो टुकड़े हो गये—एक वाम पन्थी और दूसरा दक्षिण पंथी । फिर 1967 में नक्सलाइट ग्रुप निकला । लेकिन अब जो अनेक नये गुट बन गये हैं—नागी रेड्डी ग्रुप, दक्षिण देश, लाल झंडा, कहीं खेत मजदूर, कहीं दक्षिण कम्युनिस्ट, कहीं मार्क्सवादी लेनिनवादी, मिथी गुट,--जो इस प्रकार के गुट हैं जो देश के अन्दर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं उनको रोकना अत्यन्त आवश्यक है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को कुछ सुझाव दूं । और मैं इन शब्दों में देना चाहता हूं :

1. पहला मेरा सुझाव तो यह है कि देश द्रोह की बीमारी के ये कीड़े कहां कहां और किन कारणों से पनप रहें हैं, उन कारणों को दूर किया जाय । केवल यही नहीं कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाय । जिन कारणों से यह बुराई पैदा हो रही है उन कारणों का भी समाधान सरकार और देश को मिलकर सोचना चाहिए ।

2. दूसरा सुझाव यह है कि संविधान और जनतन्त्र के विरुद्ध जिन संगठनों ने योजनाबद्ध अभियान छेड रखे हैं उन्हें सख्ती के साथ दबाया जाय ।

3. तीसरा सुझाव यह है कि हिंसा, तोड़-फोड़, अराजकता और हत्या जिनके कार्यक्रम का अंग हो और जिनका संचालन सूत्र भारत से बाहर बैठकर हिलता हो उन राजनीतिक दलों को भारत में कार्य करने की अनुमती न दी जाय ।

4. चौथा सुझाव यह है कि जो राज्य सरकारें इन प्रवृतियों को सरकारी प्रश्रय

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

दे रही हैं वहां केन्द्र सरकार केवल मूक दर्शक बनी न देखती रहे। वहां की स्थिति भयंकर होने के पूर्व अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता हो, तो सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए लेकिन देश को अराजकता के मार्ग पर जाने से बचाना चाहिए।

पांचवा सुझाव यह है कि चीन और पाकिस्तान जो सीमाओं पर हमले की तैयारी के अतिरिक्त अन्दर भी गड़बड़ पैदा करने में लगे हैं, उनसे राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये जायें। आस्तीन के सांप पालना दिमागी दिवालियेपन का प्रमाण है।

छटा सुझाव यह है कि जनतन्त्र विरोधी साहित्य विशेपकर माओ और लिन पियाओ आदि के साहित्य को भारत में बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

सातवां सुझाव यह है कि साम्यवाद और सम्प्रदायवाद (कम्युनिजम और कम्युनलिजम) का चीन और पाकिस्तान के समझोते के बाद भारत में जो नया गठबन्धन हुआ, उसके परिणामों से सावधान रहा जाय और उससे देश को बचाया जाए।

और अन्त में मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है, जिसको मै विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अपनी कुर्सी अथवा सत्ता में बने रहने के लिए कोई ऐसा कदम न उठाया जाय जो देश में इस प्रकार के साम्यवादी तत्वों को प्रोत्साहन दे।

सभापति महोदय। श्री प्रेमचन्द वर्मा....

श्री स० मो० बनर्जी : चरण सिंह साहब को मुख्य मन्त्री बना रहे हैं ?

श्री शिव नारायण (बस्ती) : बनर्जी साहब को यहां का इन्फार्मेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। (व्यवधान)

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति जी, जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उसमें श्री शास्त्री जी ने बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। बेशक वे बातें कुछ लोगों को कड़वी लगें लेकिन उन में सच्चाई बहुत हद तक है और जो लोग हकीकत को नज़रान्दाज करते हैं और सच्चाई को सामने देखते हुए आंखों को बन्द करते हैं, वे लोग वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी को नहीं निभाते।

एक माननीय सदस्य : चव्हाण साहब को कहिए।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मुझे बोल लेने दीजिए। ऐसी बातें मुझे भी करनी आती है।

श्री इसाहाक सम्भाली (अमरोहा) : कभी सिंडीकेट में बैठते हैं, कभी यहां बैठते हैं। ....(व्यवधान)....

[شری اسحاق سمبھلی (امروہا): کبھی سنڈیکیٹ میں بیٹھتے ھیں کبھی یہاں بیٹھتے ھیں-]

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं यह समझता हूं कि यही वे लोग हैं जो इस तरह की कार्यवाही करते है, वे इस सदन में भी शान्ति नहीं रखना चाहते और जमूहरियत के गले को काटना चाहते हैं, किस ढंग से काटना चाहते हैं ...(व्यवधान)... बेशक वे आज हमारा साथ दे रहे हों लेकिन सच्चाई यह है कि देश में जो हालात इस वक्त है कानून के और जिस तरह के उन्होने उदाहरण दिये बंगाल के, वही हालत सारे देश में होने वाली है। मैं पत्रकार होने के नाते यह कह सकता हूं, विश्वास से कह सकता हूं कि ये लोग जो इस प्रकार का देश में एक वातावरण पैदा कर रहे हैं कि वे ताकत के जोर से, गुंडागर्दी के जोर से अपनी बातें मनवाने के लिए हर हर्बा, हर तरीका इस्तेमाल करते रहें, वे तरीके हिन्दुस्तान में कबूल नहीं होगें बेशक थोड़ समय के

लिए वे उन से लाभ उठा सकते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि राजनितिक तौर पर जो घटनाएं बंगाल में हो रही हैं, कौन व्यक्ति है जो उनसे सहमत नहीं हो सकता। एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं और जनता का वहां पर दिवाला निकल रहा है। वहां के कारोबार का सत्यानाश हो रहा है। इकानाम्कि कंडीशन जो वहां पर है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। बंगाल की जो हालत हो रही है यहां पर भी ये लोग करना चाहते हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं, इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें सच्चाई नहीं है। अगर इनमें सच्चाई हो तो ये सुनें, दूसरे की बात को सुनें। और जम्हूरियत का ढिंढोरा पीटने वाले लोग दूसरे की बात को टोकते नहीं हैं। जो प्रतिनिधि जम्हूरियत पर विश्वास करते हैं, वह अपने विरोधी की बात सुनते हैं, ये कहते है कि ये बोलते नहीं हैं। ....(व्यवधान)।

17 hrs.

श्री इसहाक सम्भली : आप न्यूज़प्रिंट का कोटा लेते हैं और उसको ब्लेक मार्किट में बेचते है।

[شری اسحاق سمبھلی-آپ نیوز پرنٹ کا کوٹا لیتے ھیں اور اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچتے ھیں-]

श्री प्रेम चन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं नहीं बोलूंगा अगर इस तरह से ये टोकाटाकी करेंगे।

श्री इसाहक सम्भली : कितना कोटा मिलता है न्यूज़प्रिंट का ?

[شری اسحاق سمبھلی-کتنا کوٹا ملتا ھے نیوز پرنٹ کا ؟]

श्री प्रेम चन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं ....(व्यवधान)। मैं सदन के सामने इस बात को लाना चाहता हूं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, इसकी जड़ ये हैं। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय, जम्मू-काश्मीर में, आंध्र प्रदेश में और बहुत से प्रदेशों में ऐसी बातें हो रही हैं जहां पर देश के दुश्मन जो इस देश में रहते हैं, वह विदेशों से मिलकर वहां पर कार्यवाहियां कर रहे हैं। वह इस मज़हब का भी हो सकता है और दूसरे मज़हब का भी हो सकता है। वह एक दल का भी हो सकता है और दूसरे दल का भी हो सकता है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सारे देश के अन्दर एक तरह का इंकलाब लाने की कोशिश की जा रही है और जिस इंकलाब को खूनी इंकलाब कहा करते हैं।

मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहूंगा जो बड़े महत्त्व की है और सदन के कुछ व्यक्तियों को शायद वह अच्छी न लगे। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बीमारी का स्त्रोत जो शास्त्री जी ने बताया वह मैं नहीं बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वह स्त्रोत यह है कि विदेशों के राजदूतों के साथ जिन मैम्बरों का ऐकाउन्ट है और रात को जो बार बार वहां जाते हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए।

पार्लियामेंट के अन्दर हर रोज विदेशियों के साथ मीटिंगें होती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह कहें तो मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि कौन कौन से मैम्बरों की कितनी बार विदेशों के जो यहां राजदूत हैं उनके घर में रात में आना जाना रहता है। वह लम्बी लिस्ट मेरे पास है। मैं चाहूंगा कि गृह-मंत्री महोदय उस को सी बी आई को देकर जांच करवायें। यही हालत कई प्रदेशों के वजीरों की है, यही हालत कुछ पार्टियों के पोलिटिकल लीडर्स की है। विदेशों के दूतों से यहां पैसा लोग वसूल करते हैं और मुफ्त के पैसे के जोरसे सारे का सारा राजनैतिक काम किया जाता है। यह

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो आदमी इस वक्त यह काम करते हैं उन को चाहिये कि देश के हित को देखते हुए वह विदेशों से रोशनी लेना छोड़ दें और विदेशों के पैसों से देश में गड़बड़ करना बन्द करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें उन को देशद्रोही कहेंगी। इस तरह से हमारा प्रजातन्त्र भी ठीक से चलने वाला नहीं है। मैं ने यहां पर वह हालात बयान किये जो यहां पर चलाई जा रही हैं। प्रजातन्त्र के नाम पर जो बातें यहां चलती हैं और गरीबों के नाम पर जो लोग इस तरह से अपनी बातें कहते हैं, वह देश के लिये वफादार नहीं हैं। वह चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहां की शासन सत्ता को तथा कांग्रेस पार्टी को हटा दें। भले ही आज वह लोग हमारी मदद करें लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं सकता कि वह लोग आज क्या कर रहे हैं। जो कुछ वह लोग कर रहे हैं वह देश के हित में नहीं है।

इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि यह मसला बड़ा अहम है। यह छोटी सी बात नहीं है। अगर यही हाल चलता रहा तो न जाने इस देश का क्या होगा। हमारे गृह-मंत्री मजबूत हाथ वाले हैं। वह अपने मजबूत हाथों से देश की बागडोर को सम्भालें और मजबूत हाथों से, सख्ती के साथ इस देश में जो ताकतें विघटन लाना चाहती हैं और देश का सत्यानाश करना चाहती हैं उन को रोकें। अगर इस के लिये कांस्टिट्यूशन में भी तब्दीली लानी पड़े तो हम को इस में पीछे नहीं हटना चाहिये।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): If the debate goes on in this manner, it is no debate. It is better to postpone it. No speaker is being allowed to speak. It is up to you to control the House.

MR. CHAIRMAN: Every Member knows that this is a problem for all of us to consider seriously. Not only on this occasion but on many occasions this problem has arisen.

श्री मनुभाई पटेल (डभोई): सभापति महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने देश की वास्तविक स्थिति पर इस सदन में जो विचार पेश किये उनसे देश की बड़ी सेवा हुई है क्योंकि हम कितना भी कहें कि देश में जो परिस्थिति है वह ठीक है, चाहे वह साम्प्रदायिक दंगों के बारे में हो, चाहे विदेशी इन्टरफिअरेंस के बारे में हो चाहे हमारी पोलिटिकल पार्टीज जो काम कर रही हैं उनके बारे में हो चाहे समस्या चीनी और पाकिस्तानी इन्टरफिअरेंस की हो या हमारे अन्दरूनी झगड़ों के बारे में हो, इन चीजों के कारण देश के ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है। यह चीज सबको स्वीकार करना पड़ेगा।

हमारे दोस्त श्री प्रेमचन्द वर्मा ने कहा कि राजदूतावासों के साथ सम्बन्ध रखने वालों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। उन्होंने सही बात कही। परसों ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो तीन नये सदस्य लिये गये हैं अर्थात् श्री चन्द्रजीत यादव, श्रीमती नन्दिनी सत्पथी और श्री गणेश, उनके बारे में श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री बेदव्रत बरुआ आदि ने जाकर प्राइम मिनिस्टर से यही शिकायत की है कि वह कम्यूनिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि वह कम्यूनिस्ट है मैं इसलिये विरोध नहीं करता हूं, मैं विरोध इसलिये करता हूं कि **वे आर एम्बेसी पीपल**। इसका जवाब क्या है? (**व्यवधान**) एम्बेसी पीपल होने की वजह से उसी दल के साथियों ने उनकी शिकायत की है। इसलिये परसों तक जो होम मिनिस्टर बहुत मजबूत माने जाते थे, कल से वही होम मिनिस्टर कमजोर बन गये हैं। वह बचाव नहीं कर सकते हैं। यह बात मैं इसलिए नहीं कहता कि हम लोग इधर हैं। हमने होम मिनिस्टर साहब को इसके पहले भी चर्चा में कहा था कि देश में जितनी भी कम्युनल आर्गेनाइजेशंज हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाओ। क्यों नहीं लगाये उन्होंने। हमने कहा था कि आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगाओ....

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI (Berhampore): On a point of order.

The hon. Member named certain Members and said that they were embassy people. I think it is not permissible.

SHRI RANGA (Srikakulam) : He says that somebody else has said so.

SHRI MANUBHAI PATEL : I am quoting what has been said.

MR. CHAIRMAN : He is not making that charge himself.

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने कहा है कि तीन संसद सदस्य एम्बैसी के लोग हैं । मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच के लिए आप एक पार्लिमेंटरी कमेटी बनाइये और माननीय सदस्य वहां जाकर इसको साबित करें.....

MR. CHAIRMAN : The same point was raised and he clarified that he did not make that allegation but that he only referred to some statement made by somebody else.

श्री मनुभाई पटेल : मैंने गत सैशन में होम मिनिस्टर से विनती की थी कि आप देश में जितनी भी कम्युनल आर्गेनाइजेशंज़ हैं उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगायें । और एस एस पर आप क्यों नहीं लगाते हैं ? क्यों मुस्लिम लीग पर नहीं लगाते हैं ? जितनी कम्युनल आर्गेनाइजेशंज़ हैं उन पर क्यों नहीं लगाते हैं ? मुझे शक होता है कि होम मिनिस्टर ऐसा कर सकेंगे । उन्हें इसमें थोड़ी तकलीफ है । क्योंकि यदि इन पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो उनको शिव सेना पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा । शिव सेना पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते हैं ? प्रधान मंत्री लास्ट टाइम बम्बई गई थीं । उस समय शिव सेना के नेता बाल ठाकरे के साथ उन्होंने खानगी गुफ्तगू क्यों की थी ? क्यों एनकरेज करते हैं आप ऐसी आर्गेनाइजेशंज़ को ?

यहां ए आई सी सी की मीटिंग हुई । उसमें एक सेवा दल का गठन किया गया था । सेवा दल में स्वयं सेवक होते हैं । लेकिन सभापति महोदय, आप देखें कि उस सेवा दल का नाम इन्होंने नेहरु ब्रिगेड रखा था । क्या ब्रिगेड शब्द कुछ कनोट करता है या नहीं करता है ? कौन से नाम का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ? शशि भूषण जी ने कांग्रेस प्रेजीडेंट को मिसहैंडल किया था । तारकेश्वरी सिन्हा को जिस तरह से तमाचा लगाया गया था, उसकी बुराई सबने की है, उसको सबने कैंडम किया था । खुद प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा था कि यह जो किया गया है ठीक नहीं किया गया है । फिर भी उन सब लोगों को इन्होंने वापिस ले लिया । जिन्होंने वायोलेंस किया था, वायोलेंट एक्टिविटीज़ में भाग लिया था, उन सबको इन्होंने वापिस ले लिया । क्या ऐसे एकशंज़ से देश में वायोलेंस को बढ़ावा नहीं मिलता है ? क्यां देश में इस तरह से कम्युनल परिस्थिति बिगड़ती नहीं है ?

यहां बंगाल की बात कही गई है । वहां एक दिन ऐसा नहीं गया जब टैररिज्म न हुआ हो । मैं एक एक कर गिना सकता हूँ । ट्रेन सर्विसिस के बारे में सुनिये :

> "Train services on six out of seven divisions of the South Eastern Railway were dislocated on 52 occasions during the nine month period ended September 30 as the result of which mail, express and passenger trains are stated to have lost 577 hours, out of which trains running in the West Bengal sector alone suffered 541 hours detention-*Statesman* 21.10.1969".

इन्डस्ट्री के बारे में वहां के इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर कहते हैं :

> "The West Bengal Labour Minister is apparently concerned about the continued closure of a large number of industrial and other establishments. A non-official estimate of such units is over 50," etc. (*Statesman* dated 5.10.69)

5 अक्तूबर, 1969 के युगान्तर में लिखा है :

> "Mr. Ashoke Ghose, Secretary, West Bengal Forward Bloc, told a press

conference here today that the CPI(M) alone was responsible for adverse law and order situation in West Bengal..." (*Jugantar* dated 5.10.69)

श्री राज नारायण ने कहा है :

"Mr. Raj Narain, SSP leader, in a press statement on Tuesday, said the kind of gangsterism which the CPI(M) was perpetrating under governmental aegis in West Bengal was unknown to any part of the world."

श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है :

"Shri Jaya Prakash Narayan, in a letter to Mr. Jyoti Basu, mentioned the "reign of terror" prevailing there. Mr. Narayan also blamed the district Magistrate as unwilling to do anything without ascertaining the view of Mr. Jyoti Basu."

इस परिस्थिति से तंग आकर पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री अजय मुकर्जी, को मजबूरन सत्याग्रह और फास्ट करने का निर्णय लेना पड़ा। इस बारे में कहा गया है :

"Concerned about the continuing lawlessness and violence in West Bengal, the Bangla Congress Secretariat which met here today gave the green signal to the party's programme for a satyagraha largely in the form of fasting by party volunteers at public places from December."

42,000 volunteers will participate.

जहां के चीफ मिनिस्टर खुद कैदी बन गये हों, वहां के शासन की क्या हालत होगी ! (व्यवधान)

सरकार द्वारा हरिजनों को कोई सेफ्टी नहीं दी जा सकी है। धर्म-परिवर्तन के नाम पर आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। फादर फेरर को पहले देश से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उनको फिर यहां आने की अनुमति दे दी गई और वह आज भी धर्म-परिवर्तन का काम कर रहे हैं।

जहां तक अहमदाबाद की घटनाओं का सम्बन्ध है, वहां पर जो कुछ हुआ, वह किसी को पसन्द नहीं है। उन घटनाओं से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि सारे देश में अल अक्सा के प्रश्न पर जलूस आर्गनाइज करने वाली कमेटी में केन्द्रीय सरकार के मंत्री, श्री फखरुद्दीन अली अहमद भी थे। जब उनको यह बात कही गई, तो उनको बुरा लगा। अहमदाबाद में अल अक्सा के बारे में जो जलूस निकाला गया, उसमें अल अक्सा के बारे में जो नारे लगाये गये, उन पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। इस मामले में हम उन लोगों के साथ हैं और उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हमारा मत है कि किसी भी धार्मिक स्थल को जलाना, हानि पहुंचाना या अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उस जलूस में "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे भी लगाये गये। (व्यवधान)

श्री इसहाक सम्भली : गलत है। श्री चव्हाण ने इस बात से इन्कार किया है। (व्यवधान)

[شری اسحاق سمبھلی-غلط ھے- شری چوان نے اس بات سے انکار کیا ھے (ویودھاں) ...]

श्री मनुभाई पटेल : इसमें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी इसलिए आती है कि उस जलूस में जो पाकिस्तानी नागरिक थे, उनके वीसा खत्म हो गये थे, लेकिन फिर भी उनको इस देश में रहने दिया गया। (व्यवधान) उस जलूस में, और जितने कम्युनल दंगे हुए, उनमें काम करने वाले पाकिस्तानी एजेन्ट थे। खुद बादशाह खां ने कहा है कि उसमें परदेशी एजेन्टों का हाथ है। मैं केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन पाकिस्तानी सिटीजन्ज के वीसाज् की लिमिट खत्म हो गई है, वे आज भी भारत में क्यों हैं।

जगन्नाथ जी के मन्दिर पर जो हमला हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस मुहम्मद सईक के घर में बम फटा, उसकी कार में श्री भूपेश गुप्त थे। (व्यवधान) कम्युनलिस्ट्स और कम्युनिस्ट दोनों का दंगे कराने में इन्ट्रेस्ट है, क्योंकि देश में ला एण्ड आर्डर खत्म होने, अराजकता फैलने और देश की आम परिस्थिति खराब होने से उनका काम आगे बढ़ता है।

प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसमें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं। आज देश में जो स्टेबल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। (व्यवधान) क्या इसमें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जहां मैजारिटी है, गुजरात जैसे राज्य में जहां स्थिर शासन है वहां आप सरकार को खत्म करने के लिए अपनी हुकूमत का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस के अन्दर जो मैथड और मीन्स इन्होंने अभी अभी अख्तियार किये हैं वह कांग्रेस के सिद्धान्तों और आदर्शों के खिलाफ हैं। आपस में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन हमारा मत यह है कि जिस दिन उन्होंने प्रेसीडेंशियल एलेक्शन में जातिवाद और कौमवाद का आश्रय लेकर गलत मेथड और मीन्स अख्तियार किए और इन्डिसिप्लिन का नेतृत्व किया उसका प्रभाव भी ला एण्ड आर्डर पर पड़ता है....(व्यवधान) इसकी जिम्मेदारी सीधे इनके ऊपर आती है। देश में क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है....

MR. CHAIRMAN : This is a motion on subversive and violent activities being encouraged by political parties and foreign powers. Are you citing this instance as one of encouraging subversive and violent activities by the Prime Minister ? (*Interruptions*)

श्री मनुभाई पटेल : देश में जहां जहां स्टेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए जितनी भी फोर्सेज काम करती हैं चाहे अन्दर की हों, चाहे बाहर की हों, वह सब इसमें कांट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं।

This is one of the contributory factors and that is why I am putting emphasis on this also.

मैं आखीर में यही बात पूछना चाहूंगा कि क्या जो लोग एक्सट्रा कांस्टीट्यूशनल ऐक्टिविटीज करते हैं और जो अन्दर आकर कांस्टीट्यूशन को तोड़ने की बात करते हैं जैसे ज्योति बसु, उनके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जो स्ट्रीट्स में पालिटिक्स ला रही हैं उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन जो होता है उसके बारे में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जो चाइनीज लिटरेचर्स यहां पर बांटे जाते हैं और नक्सलाइट्स के साथ उनकी लिंक बन जाती है उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? जो रशियन एम्बैसी और दूसरी एम्बैसी वाले वहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका गवर्नमेंट उपयोग करती है अपनी पालिसी बनाने में उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? जो रशियन मनी यहां फ्लो कर रहा है उसको आप कैसे रोकने जा रहे हैं....(व्यवधान)...अमेरिकन हो तो और भी गलत बात है। हम उसके भी खिलाफ हैं। आखरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आर० एस० एस०, मुस्लिम लीग, गोपाल सेना, नेहरू ब्रिगेड, शिव सेना क्या इन पर आप बैन लगाएंगे या नहीं? यदि यह सब करने को तैयार नहीं हैं तो देश में कानून व्यवस्था नहीं बन पायेगी और यदि देश में कानून व्यवस्था तोड़ने की किसी पर भी जिम्मेदारी होगी तो यह इस सरकार की जिम्मेदारी होगी।

MR. CHAIRMAN ; Shrimati Ila Palchoudhuri. (*Interruptions*). Will you please listen to the hon. Lady Member ? She cannot raise her voice as many of you. (*Interruptions*).

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : Mr. Chairman, I have been listening to the debate carefully. I am very grateful to Mr. Prakash Vir Shastri for having brought this matter to the notice of the House. There is one thing we must really take into consideration : What are the things that are working in this country

[Shrimati Ila Palchoudhuri]

to bring about this state of chaos and disruption that is there in many States, particularly in West Bengal ? What is the mind that is working behind it ? The Central Government had sent a circular to all State Governments to observe the Solidarity Day, which is always observed all over India on 18th October ever since the Chinese aggression on India. What was the answer that the West Bengal Government gave ? According to Shri Jyoti Bhattacharyya, the Minister of Information, the Cabinet...

MR. CHAIRMAN : I would like to remind the House that we are not discussing the conduct of any particular State Government at this stage. So, I would request hon. Members not to bring in State Governments as such.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Please listen to the objection. He says that they took objection to certain words in the solidarity pledge which forbids violence in seeking redressal of grievances political, religious or linguistic So, they want violence to be perpetuated and that is why they objected to observing the solidarity day. Therefore, no function was held in a certain State; if you want to know the name, it was the State of West Bengal.

Then, in the Gandhi Centenary year what happened in Bangalore ? Mao Tse-tung posters appeared in Bangalore, condemning Gandhi thinking and Gandhian policies. It is these things which are responsible for eruption of violence.

Shri Prakash Vir Shastri quoted some figures. I do not want to take the time of the House. So, I will quote only a few figures. Even according to the figures quoted in the Assembly, upto July 1969 there were 75 political murders, 166 violent and illegal gheraos...(*interruptions*) If you want the latest figures you have to add at least 100 to each.

Then I would like to say with shame what happened in Kankey, when an expectant mother was speared to death. That case has been withdrawn and nobody has been arrested on that account. Surely, it is a dark day for India if an expectant mother is put to death and no action is taken against the culprits.

I would like to invite the attention of the House to another peculiar thing. CPI(M) has a funy logic. Whenever their workers go to a coalfield or a tea garden they tell the workers that they are fighting for full implementations of the wage board awards in regard to dearness allowance. At the same time, they make an offer to the employers that if they recognise the trade unions of CPI(M) they will not press for full implementation of those awards...(*interruptions*) and that the dearness allowance given in instalments.

SHRI UMANATH : The hon. Member has read from some paper. We are entitled to know from where she has got this information.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : *Hindustan Standard.*

SHRI UMANATH : Birla paper.. (*interruptions*) It belongs to the syndicate. Do not quote your adversaries, the syndicate...(*interruptions*)

SHRI PILOO MODY (Godhra) : The same item appeared in the Peking Times.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURY : This morning it has appeared in all papers.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Which paper ?

SHRI PILOO MODY : Peking Times... (*interruptions*)

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Not Peking papers...(*interruptions*) It has come out in all the papers.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I seek your protection, Sir. I want to know from which paper she is reading.

SHRI UMANATH : Do not take inspiration from Shrimati Sucheta Kripalani.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : I do not take inspiration from him.

It has come out in all the papers. 2,000 people raided a village in 24-Parganas and hacked two men to pieces. The police has done nothing about it. In fact, the thana

was gheraoed and till the people, who had been arrested, were released, the gherao was not lifted.

SHRI UMANATH : How many people were killed by the Jotedars in West Bengal ? You were silent about it.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : The Jotedars do not go about killing people. They cultivate fields in co-operation with the cultivators (*Interruptions*)

Then, in Memari Thana 3,000 to 4,000 people went with lethal weapons and looted the poor cultivators' paddy and police has done nothing...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Order, order. We cannot carry on a discussion like this. It is impossible to make out what the hon. Member is speaking and what hon. Members want to say when they intervene. Of course, interruptions are quite common in a debate but let us understand what hon. Members want to say when they intervene. Let that also be conducted in an orderly manner, one by one. If all Members get up and interrupt, what they say cannot be understood. If somebody wants to know the name of the newspaper, she will naturally let him know.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : This is the newspaper. It is there in the *Statesman*. It has come out in all the papers.

The Memari Thana incident has been sent to us by telegrams and trunk calls. Then, I wrote to the Prime Minister regarding the Ghosh Commission where my own counsel, Shri Mihir Sen, had to give up arguing because his life had been threatened and his junior had to give up because he was assaulted. Lady advocates and lawyers were insulted. Their idea in insulting them is to see that the Commission should be wound up and no evidence should be taken or recorded because the evidence was heavy against them and they did not want the public to know that evidence. So, they intimidated the witnesses and assaulted the lawyers. A commission is put up by Government when they want to get at the bottom of some very heinous occurrances that have happened. To obstruct that commission is surely one way by which chaos can be created. I wrote to the Prime Minister and told her that what they are propagating is that when the banks have been taken over why we should not take over fisheries and lands. That is the kind of propagation that is going on. I would only beg of the Government that they take note of this because here the law and order situation is greatly jeopardised...(*Interruption*)

SHRI UMANATH : Move a resolution in your parliamentary party meeting.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : All right; I will. It is not for you to advise me.

The Constitution is for the people. The Constitution speaks in one voice in times of peace and in times of war; at all times. So, I would ask the Government to take note and not to take the attitude that they can do nothing because they are bound by the Constitution and are helpless. Much can be done and this chaos can be put a stop to if the Government takes strong action.

MR. CHAIRMAN : Obviously, this discussion will continue on another day and I hope the hon. Speaker will fix up the date.

SHRI PILOO MODY : Meanwhile, let us put the Home Minister on notice that he either rectifies the situation or else...

17·35 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION
INCOME-TAX ARREARS

श्री ओमप्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न का जवाब देते हुए बहुत बड़े रहस्य की बात कही है। मैंने पूछा था कि जो आय कर इस देश में बकाया है वह कितना है ? उन्होंने कहा था कि 554.08 करोड़ रु० आय कर का बकाया है। मैंने यह भी पूछा था कि बकाया की वसूली किस प्रकार हो रही है ? जिसका उन्होंने एक बड़ा लम्बा उत्तर दिया। जिस देश में पांच, छै अरब रु० टैक्स का बकाया हो उसकी क्या आर्थिक स्थिति होगी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बकाया वसूल न होने का दोष किसका है ? मेरी राय

[श्री ओमप्रकाश त्यागी]

में यह दोष सरकार का है जो आय कर का इतना रु० बकाया है। और केवल यही नहीं एक बहुत बड़ा राज इस आय कर के धन के पीछे है और वह है काला धन जो इस देश के आर्थिक ढांचे को हिलाने वाला है। इस देश में दो धन हैं—एक पी० एल० 480 का बाईस अरब रु० अमरीका का जो रिजर्व बैंक में जमा है और दूसरा वह काला धन जो अनएकाउन्टेड फ़ार लोगों के पास पड़ा है। वह बाजार में इधर उधर से निकल कर आता है और वस्तुओं की कीमतों को स्थिर नहीं होने देता। जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई भत्ता, ऐजीटेशन और सत्याग्रह होते हैं। इस सब का दोष सरकार के इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। और मैं कहूं कि उन्होंने एक प्रकार से क्रिमिनल ऐक्ट किया है जो तमाम देश के आर्थिक ढांचे को लड़खड़ा देता है। दोष यह है कि इन्कम टैक्स अफ़सर सरकार ने बनाये हैं। चाहिये तो यह कि निर्धारित नियम के अनुसार आप कर ले लीजिये। लेकिन उन्होंने निर्धारित नियम के अलावा भी इन्कम टैक्स अफ़सरों को बेलगाम बना दिया है। वे इन्कम टैक्स वसूल करते हुए मनमाने ढंग से इन्कम टैक्स लगा सकते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि एक व्यापारी अगर 25,000 रु० की अपनी आय दिखा रहा है तो उसको कहा जाता है कि इन्कम टैक्स एक लाख पर लेंगे। तुम बेईमान हो। परिणाम यह हुआ है कि तमाम देश के व्यापारी वर्ग को इनके इस विभाग ने बेईमान बना कर खड़ा कर दिया है। भारतवर्ष में कोई एक भी व्यापारी नहीं होगा जिसके दो रजिस्टर नहीं होंगे। एक रजिस्टर वह सरकार के लिये झूंठा रखता है और एक सच्चा अपने घर के लिये बनाये हुए है जिसमें सच्ची आमदनी है। अगर एक लाख की आमदनी है तो 25,000 रु० अपनी आमदनी दिखाता है। कारण यही है कि इन्कम टैक्स अफ़सर मनमानी टैक्स लगायेगा और इस प्रकार की स्थिति पैदा करेगा। परिणाम यह हुआ है कि उस कारण से लोगों ने अपनी आय को छुपाना शुरू कर दिया है। जितनी आय होती है उसका तीन चौथाई हिस्सा इस देश की आय का काले धन के रूप में जा रहा है। अगर वह काला धन इस देश के निर्माण में लगे तो मैं कह सकता हूं कि हमको विदेशों से सहायता की आवश्यकता नहीं है। उस काले धन के द्वारा हमारा बहुत कुछ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, अगर सरकार अक्ल से काम ले। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण से काला धन बढ़ता चला जा रहा है, और वह विदेशों में काले धन के रूप में पौंड में जमा हो रहा है। वहां जो हमारे भारतीय लोग कमा रहे हैं वह रु० अपनी सरकार को नहीं आ रहा है और उसको वहीं पौंड के रूप में जमा किया जा रहा है, और काले धन से यहां चुकता होता है।

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पर मैं ही दोषारोपण नहीं कर रहा हूं बल्कि हमारी प्रधान मंत्री ने भी दोष लगाया है, मैं मंत्री महोदय चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि मेरा इशारा माननीय जगजीवन राम की तरफ़ है। वह बात आप सबके सामने आयी है जब से श्री मोरारजी देसाई ने इस प्रकार की बात कह दी कि 10 साल से उन्होंने कर नहीं दिया और उन्होंने रिटर्न नहीं भरे। तो उसके जवाब में प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि दोष उनका नहीं है, बल्कि आय कर विभाग का है कि उसने उनको टोका क्यों नहीं कि तुम इन्कम टैक्स दो। इतना ही नहीं अभी कल परसों राज्य सभा में पूछा गया।

यह नियम इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का है कि अगर कोई ठीक रिटर्न न भरे या रिटर्न बिल्कुल भी न दें और धोका करे, तो उस पर पेनेल्टी लगती है। अध्यक्ष महोदय, सेठी साहब ने राज्य सभा में जवाब देते हुए कहा था कि पेनेल्टी श्री जगजीवन राम पर नहीं लगी यह कौन सा कानून और नियम है—और कहा कि ऐसे तो सैकड़ों केसेज होंगे जिन पर पेनेल्टी नहीं लगती हैं। इस के माइने यह हैं कि धांधली

चल रही है और जिन लोगों पर पेनेल्टी लगनी चाहिए उन पर पेनेल्टी नहीं लगती है। इस प्रकार इस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

एक बात मैं खास तौर से सेठी साहब से पूछना चाहूंगा कि 554 करोड़ का जो बकिया धन दिखाया है, अध्यक्ष महोदय, यह 554 करोड़ का बकिया एक बोगस आंकड़ा है। मैं पूछना चाहूंगा कि इस में कितना रुपया पेनेल्टी का है और कितना रुपया ऐसा है जोकि इन्कम टैक्स लगने के बाद उस की अपील हुई है। अगर उस की अपील हुई है तो वह तो हमारा इन्कम टैक्स नहीं हुआ, वह तो आयकर नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कितना रुपया ऐसा है जिस में अपील हुई है, कितना रुपया पेनेल्टी है कितनी पेनेल्टी ऐसी है जो कि वसूल नहीं होगी। सन् 1947 बाद बहुत से लोग पाकिस्तान भाग गये, बहुत से लोगों का दिवाला निकल गया या धर्म तेजा भाग गया। जो लोग भाग गये उन से तो आय कर वसूल होने की आशा नहीं है। ऐसे कितने धर्म तेजा हैं, जिनसे रुपया वसूल नहीं होगा। इसमें से बहुत सा रुपया ऐसा है जो आप को राइट आफ करना पड़ेगा। उस को आप राइट आफ क्यों नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें अपील की बात, अध्यक्ष महोदय, जब कि इन्कम टैक्स किसी के ऊपर लगा देते हैं तो नियम इस का यह है कि जो बिजनेसमैन या इन्डस्ट्रियलिस्ट आया, अपने खाते के अनुसार उस पर एसेस कर दिया जाता है और अब एक नियम यह हो गया है जिस से कि एरियर नहीं हो सकता, कि आगे का भी कर उस के हिसाब से हो वह इन्कम टैक्स जमा हो। इस प्रकार का नियम है। अगर वह न जमा करे देरी से करे तो पेनेल्टी लग जाती है। इसलिए उस आमदनी के हिसाब से पहले से ही इन्कम टैक्स जमा करा लेते हैं लेकिन बीमारी कहां आ कर लगती है। बीमारी यह है कि इन्कम टैक्स आफिसर रजिस्टर देखता है फाइनल एसेसमेंट करते हुए और कहता है कि तुमने यह नहीं दिखाया, वह नहीं दिखाया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के व्यापारी लोग हैं जो सरकार से आय कर को छिपाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन के साथ मेरा कोई समझौता नहीं है। गवर्नमेंट को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जो आयकर छिपाने की कोशिश करता है और जिसने गलत हिसाब पेश किया है, उस को शख्त सजा दी जाये, उस को जेल-खाने भिजवा दिया जाए, उस का परमिट केंसिल कीजिए, लाइसेन्स केंसिल कीजिए उस की इंडस्ट्री का। इस प्रकार का कड़ाई का आप नियम बनाइए। लेकिन वह सब कुछ न करके होता यह है बेईमानी कराई जाए कि उस डाके में से तुम गवर्नमेंट को कुछ दे दो, तो व्यापारी भी डाकू और गवर्नमेंट भी डाकू, दोनों डाकू मिल गये। इस प्रकार से इस देश में चल रहा है। मैं मानता हूं कि इस पर फिर अपील होती है, लेकिन अपील करने वाले को एपेलेट ट्रिब्यूनल में 42 महीने लगते हैं। तब ट्रिब्यूनल सुनवाई करती है। इसके बाद एरियर्स की वापसी होगी। ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए 4 साल तक लग जाते हैं और तब कहीं जा कर सुनवाई होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे कि अपील की सुनवाई शीघ्र हो सके।

एक बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस एरियर में जो अपील हो चुकी है और गवर्नमेंट के खिलाफ अपील हुई है, क्या आप ने यह जो एरियर दिखाया है, इसमें से वह धन जितना कि अपील के बाद कोर्ट ने निश्चित किया है, वह धन इसमें है और जो बाकी फालतू है, इसमें से निकाल दिया है या इस में शामिल है। यदि शामिल है तो उस को निकाला क्यों नहीं और इस की व्यवस्था कितने दिन में करने वाले हैं आप।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और पूछना चाहूंगा। अपील जितनी सफल होती है, श्री

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

बेनी शंकर शर्मा को जवाब देते हुए यहां मिनिस्टर साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट के खिलाफ कितनी अपील कामयाब होती हैं, 1965-66 में 31 प्रतिशत और 39 प्रतिशत क्रमशः, 1966-67 में 31 प्रतिशत, 41 प्रतिशत। और यह कहा "Percentage of success before the Appellate Assistant Commissioner of Income Tax was in the vicinity of 65%."

इससे साफ जाहिर है कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट बोगस है और इस प्रकार गलत टैक्स लगाता हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप से कि जो इन्कम-टैक्स आफिसर इस प्रकार गलत असेस करके गवर्नमेंट और व्यापारियों दोनों को तंग करते है और इस प्रकार से पैसा बरबाद कराते हैं, उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लेने का आपने विचार है ? क्या ऐसे आफिससं के खिलाफ आपने ऐक्शन लिया है और अगर लिया है तो कितनों के खिलाफ लिया है, यह मैं जानना चाहता हूं।

एक बात काले धन के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने 1962 में ऐलान किया था कि काला धन जो लोग अपने आप प्रकट कर देंगे उनको 65 प्रतिशत पर टैक्स लगाया जाएगा और 35 प्रतिशत की माफी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने जाहिर किया तो ये लोग भेड़ियों की तरह चिपट गये और जो वायदा किया था उससे मुकर गये। उनसे कहने लगे कि तुमने पूरा काला धन नहीं दिखलाया हम तो पूरे का अन्दाजा लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चल रहे है जिन्होंने ईमानदारी से काला धन जाहिर किया और आपके डिपार्टमेंट ने मनमाने ढंग से उन पर टैक्स लगाया ?

सभापति महोदय, अन्त में एक चीज मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह जो इन्कम टैक्स की घांधली है, इस देश में जो काला धन है, क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा मार्ग सोच रही है जिससे कि इन्कम टैक्स सही ढंग से लगाया जा सके जिससे व्यापारियों को कोई झंझट न हो नियमों के अनुसार और काला धन भी रुक जाए। जो काला धन है उसको निकालने की गवर्नमेंट ने कोई चेष्टा की है, अगर हां तो क्या की हैं, यह मैं जानना चाहूँगा।

MR. CHAIRMAN : You can put questions and the Minister will answer together.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : Mr. Chairman, Sir, a little background before I put my question. About arrears, in this Parliament, I have got half a dozen or more questions to my credit. The figures of arrears given by the Ministry are alwyas incorrect. In reply to an Unstarred Question of mine, No 7100, dated the 15th April 1968 wherein I had asked about the amount of income tax arrears as on 1st April, 1967, the then Minister had said that the amount was Rs. 551.71 crores and this was reduced to 381.61 crores as at the end of January, 1968 as a result of adjustments due to appeal effects, revisions, rectifications, etc. When I put another question being No. 5608 dated 26th August, 1968 to get a clarification as to how this amount Rs. 381.61 crores was made up, I was told that Rs. 55 crores were due on account of assessment made prior to 1956-57 and another sum of Rs. 91 crores was due for assessments made between 1957-58 to 1963-64. Thus the effective arrears were only Rs. 235 crores.

As regards this Rs. 235 crores even a good portion was due to amounts disputed in appeals, amounts disputed in respect of assets and so on and stayed under section 220(6) of the I. T. Act. I had also raised this question in the consultative committee and wanted the Minister to make his calculations in such a way that we could get correct figures of arrears. I don't understand why by giving incorrect and false figures the Minister invites abuse for himself and for his subordinate officers. We do not get the correct figure. The correct figure will not be beyond Rs. 250 crores.

In this background, Sir, I want to put my question.

I understand that very reeently an adjustment fortnight was observed throughout India in which all the ITOs were asked to adjust the amount of reliefs given in appeals etc. leaving all other normal work. What is the figure of this adjustment and how far has this gone to reduce the current effective arrears ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने बतलाया है कि 5 अरब 54 करोड़ रुपया आय कर का बकाया पड़ा हुआ है। यह बात सब लोगों को बुरी लगी। यह बड़ी गलत और बुरी बात है कि इतना आय कर बाकी है। यह तो सरकार की नीति है जिसके कारण यह बकाया पड़ा हुआ है।

पहली बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि जो कुल बकाया है उसमें से श्री मोरारजी देसाई के मन्त्रित्व काल का, जब से और जब तक वह वित्त मन्त्री रहे, बकाया का फिगर क्या है, उनके पहले के मन्त्री के मंत्रित्व काल में कितना था ? अगर यह सर्वश्री मोरारजी देसाई के मन्त्रित्व काल का है तो दूसरे मन्त्रियों के काल का कितना बकाया है ?

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Ask Shri T. T. Krishnamachari. I was a member of the Public Accounts Committee and I know it better than the hon. member.

श्री रामावतार शास्त्री : आपने सुना नहीं, मैं वह भी कह रहा हूं। मैंने यही कहा था कि पहिले जो मन्त्री थे, बीच में श्री मोरार जी देसाई जितने दिन तक मन्त्री रहें और अब जो फाइनेन्स मिनिस्टर हैं वह बतलाये कि उन के अलग अलग फिगर क्या हैं।

दूसरी बात यह कि इस बकाया में से हमारे देश के जो बड़े बड़े सरमायेदार हैं टाटा, बिड़ला, डालमिया वगैरह, उनके ऊपर कितना बकाया पड़ा है। आखिरी सवाल यह है कि मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वह वसूली के लिये यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह वह गरीबों की प्रापर्टी को अटैच करवा लेते हैं उसी तरह से क्या उन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई है कि कुछ खास समय देकर, अगर वह उतने दिन के अन्दर अपना बकाया न दे दें तो उनकी प्रापर्टी को अटैच कर ली जाये ? अगर कोई ऐसी योजना उन्होंने बनाई है तो बतलायें और अगर नहीं तो क्यों ?

कुछ मिनिस्टरों के पास भी बकाया पड़ा हुआ है जैसे श्री जगजीवन राम और दूसरे लोग भी हैं....

एक माननीय सदस्य : गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : उन लोगों पर जो बकाया पड़ा हुआ है उसके लिये या तो मन्त्री कहें कि पूरा हो गया है या फिर बतलायें कि कैसे वसूल किया जायेगा और जो भंडाफोड़ श्री मोरारजी देसाई ने अब आ कर किया वह पहले क्यों नहीं किया ? इसके पीछे क्या राज है ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : पहली बात तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि साढ़े पांच अरब रुपया जो असेसीज के खिलाफ आता है क्या उसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स आफिसर्स के पास, नीचे से लेकर ऊपर तक, पेन्डिंग केसेज बहुत ज्यादा हैं, और अगर है तो कितने हैं और क्यों सालहा साल से लटक रहे हैं ? कलेक्शन न होने की क्या वजह है ? अगर उनके पास काम ज्यादा है तो क्या फाइनेन्स मिनिस्ट्री कलेक्शन के लिए कोई स्पेशल सेल क्रिएट करना चाहती है ताकि यह साढ़े पांच अरब रुपया वसूल हो ? अगर स्पेशल स्टेप्स लेने के बाद एक आधा अरब रुपया बकाया रह जाता है तो बात दूसरी है नहीं तो क्या मन्त्री महोदय कोई स्ट्रिंजेंट मेथड्स अख्तियार करेंगे, एन्फोर्समेंट स्टाफ रक्खेंगे और लोगों को जेल में डालेंगे या उनकी कुर्की भी करायेंगे ?

[श्री रणधीर सिंह]

यह रुपया आप इकट्ठा नहीं करेंगे तो आपके महकमें की रैपुटेशन भी खराब होगी। इनकम टैक्स आफिसर्स इनकम टैक्स एक्ट के मातहत कोर्टस भी हैं। उनकी जो फाइंडिंग्ज होती हैं वे ज्यूडिशल फाइंडिंग्ज होती हैं। एक दफा वे फैसला दे दें और पार्टी पेमेंट भी कर दे और पैनलटी जो लगा दें; वह भी अदा कर दी जाए उसके बाद भी अगर कोई इनकमटैक्स कोर्ट पर किसी तरह का आरोप लगाता है तो क्या वह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं है, क्या अदालत पर रिफलैक्शन नहीं है? इनकम टैक्स की पेमेंट, पैनेलटी की पेमेंट सब हो गई, बोना फाइड पेमेंट हो गई अब उसके बावजूद भी उसके ऊपर कमेंट करना क्या यह फेयर कमेंट है? क्या यह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं है? इस तरह के रिफलैक्शन पास किये जायें, सार्वजनिक रूप से क्या यह सही है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : This question has been raised from time to time for the last several years and we have been hearing that the arrears has always been Rs. 550 crores, sometimes Rs. 560 crores and so on. That raises a suspicion in our minds that probably either the Government are not taking adequate steps to collect proper statistics or are not taking adequate steps to collect the arrears. It was very painful to hear from the Finance Minister of India about the condonation of arrearism on the ground of forgetfulness. Therefore, my first specific question is this. After the exit of Shri Morarji Desai from the Finance Ministry, what steps have been taken by the Government to see that this huge accumulation arrears to the tune of about Rs. 550 crores are reduced, and has it already been reduced to any appreciable extent ?

Some questions have been raised during the last one week about the arrears of Ministers. I want to know whether in their returns of Income-Tax they have shown any item of income on account of agriculture which is not subject to agricultural income-tax.

Thirdly, I want to know what concrete steps have been taken during the last two or three months to see that the arrears are realised properly and that penalties in cases where people do not submit returns and do not pay income-tax are properly assessed.

18 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : On the basis of a reply given to a question on 17 November, the hon. Member has raised this discussion I had given the figure of Rs. 554 crores as the arrears and this reflects what we would call the net arrear. This excludes amounts pending disposal of appeal where a stay had been granted (Rs. 60,78,38,000) and the amounts for which extension of time for payment has been granted by the ITO and/or other competent authority (Rs. 25,01,77,000) and demand covered by advance tax which is awaiting adjustments (Rs. 107,85 34,000). If you also include the amount not fallen due, the total comes to about Rs. 211 crores and the gross arrears would be of the order of Rs. 765 crores.

Now it is difficult to segregate the arrears in respect of periods when a person was a Minister or was not a minister. The arrears for 1959-60 and earlier years, that is to say, arrears which are ten years old amount to Rs. 64.28 crores and arrears for 1960-61 to 1967-68 (between two and nine years old) amount to Rs. 265 55 crores and arrears for 1968-69 amount to 211.77 crores while arrears for 1969-70 (current year) come to Rs. 12·48 crores.

Hon. Members would recall that the number of assessees had increased from 9,82,277 in 1958-59 to about 27 lakhs during the year 1968-69. The staff has not increased proportionally or correspondingly.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Why not ?

SHRI P. C. SETHI : On account of various factors I do not say that the staff did not increase at all ; I am only saying that the increase was not in proportion.

The collection of income-tax revenue in 1964-65 was Rs. 580 crores and in 1968-69 the amount is Rs. 673 crores. Both the quantum collected and the number of assessees have increased. With this increase in the number of assessees, there has been an increase in the number of assessments pending with various commissioners. The emphasis during the last two years was that we should try to complete the assessments as mucn as possible. We had a special drive in that direction and during 1968-69 over eight lakhs more income-tax assessments were completed as compared to the preceding year. The total assessments pending before the various commissioners comes to about 16 lakhs. We have issued directives that the pending assessment work should be completed within the next two years.

श्री रामावतार शास्त्री : बहुत लम्बा समय दिया ।

श्री प्र० च० सेठी : नहीं, देखिये, वह ऐसा है कि जितना असेसमेंट कम्पलीट कर सकते हैं उस से 8 लाख ज्यादा आया है तो उस हिसाब से हमने यह अन्दाजा लगाया कि 16 लाख केसेज का तो असेसमेंट पुराना बकलाग उनको क्लीअर करना होगा और साथ साथ जो नये असेसमेंट के केसेज आते हैं उनको पूरा करना होगा ।

This means that they will have to complete as it comes, and at the same time, have to clear the backlog. Therefore, we hope that period would come after a year and a half to two years where there would be no backlog of assessments and therefore, the work would be done on a year to year basis. As the assessments come, they would be completed and so to that extent it would facilitate the work.

These arrears which I have enumerated have accrued on account of very many reasons. Since the time at my disposal is very limited, I would like to draw the attention of hon. Members to some of the reasons which I would like to enumerate. They are, demands wherein the assessees have gone in appeals; demands when recovery proceedings have been stayed by the high courts and other courts; demands due from persons who have left India and or not traceable; demands due from persons who have nil or inadequate assets at present; demands due from companises which have gone into liquidation ; demands locked up on account of the same income having been taxed in the hands of more than one assessee as a protecive measure; demands pending realisation on account of the verification of assessee's claims for double income-tax relief, etc.

I am not going into more details, but I would like to say that we had also called meetting of the Commissioners; last year, it was also decided that we should take courage and wherever it is effectively proved that it is absolutely impossible to realise the arrears, then we have started the machinery to write off. Of course, it is a difficult process in the sense that the officer–

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जो लोग पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने दिवाला निकाल दिया, ऐसे लोगों को राइट आफ क्यों नहीं करते हैं ?

श्री प्र० च० सेठी : वही तो मैं कह रहा हूं ।

It is a complicated process because the moment the amount is written off, a sort of suspicion and many other things start rolling and therefore the cocerned officer has to take effective steps only when there is a very, very conclusive proof.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : If it is written off, more people will run away to Pakistan.

SHRI P. C. SETHI : I would also like to say that this is not as if the arrears are not being collected. As far as the collection is concerned, out of the arrears, this year we have been able to recover Rs. 65 crores up to 31-8-1969. Apart from this fact, I would also like to bring to the notice of the hon. House that this year's collection, as yet up to the end of October, 1969, was about Rs. 65 crores more, as compared to the last year's collection, as far as the regular collection is concerned.

[Shri P. C. Sethi]

Therefore, all possible measures both with regard to the collection of arrears and the write off are taken. With regard to the collection of current dues also, all possible steps are being taken.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक सवाल पूछना चाहता था राइट आफ के बारे में। जो लोग पाकिस्तान चले गए, इंगलिस्तान चले गये या कब्रिस्तान चले गए उनका तो राइट आफ हो जायेगा लेकिन 31 लाख रुपया राम रतन गुप्ता का राइट आफ किया गया था, दोबारा मुकदमा शुरु किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह वसूल किया जायेगा या नहीं ?

MR. CHAIRMAN : You are pursuing that subject for the past so many years.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : On 8th July last, in his speech, previous Finance Minister, Shri Morarji Desai, mentioned that the arrears up to the end December, 1967 were Rs. 587 crores. Now, you are saying that the arrears are Rs. 554 crores. The collection during these two years has been only Rs. 34 crores. At the same time, you are mentioning that it is Rs. 64 crores. How is it ?

SHRI P. C. SETHI : I have already explained it ; perhaps the hon. Member hos not taken note of the fact that arrears for 1968-69 were added to it, and the amount is Rs. 211.77 cores. Besides that. the current year has added an arrear of Rs. 12.48 crores. Therefore, the set of figures given at a particular time would never tally because sometimes the arrears are collected and sometimes they are added and therefore it would be very difficult to tally the set of figures given, unless they are given for a particular period.

SHRI E. K. NAYANAR : With in two years, how much of arrears have been collected ?

SHRI P. C. SETHI : As far as this year is concerned–

SHRI E. K. NAYANAR : Up to December, 31, 1967, it was Rs. 587 crores. Now you say it is Rs. 554 crores. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : This is a very vast subject and it cannot be finished in half an hour. The minister should be allowed to complete his speech.

SHRI P. C. SETHI : As far as tax relief is concerned, various bodies have gone into it like the Administrative Reforms Commission. On account of the recommendations of the various committees, the Taxation Laws (Amending) Bill is before a Select Committee. In that Bill we have provided specifically that as far as smaller assessees are concerned, it would not be incumbent upon them to go to the income-tax office with their records. We would normally believe them unless by check and cross check, we find there is something. Some stray cases where we are suspicious might be examined. Otherwise, we would accept whatever figures are given by the smaller assessees. Smaller assessees will be given that relief.

I have already pointed out the various legal and administrative measures we have taken. We have taken the recovery work of taxes from the States. We have had the functional division but sometimes we are experiencing some difficulties in the functional system; There is a possibllity that what one arm does may not be known to the next arm. That has to be coordinated properly. One might have filed his return but the recovery officer might have issued the notice if there is no proper coordination. So, we have to be careful about that.

This is a vast subject and I cannot enter into all its aspects. As far as ministers are concerned, every day some wrong information comes. In today's or yesterday's papers, names of various ministers have appeared. I was asked through an unstarred question who are the ministers who had filed their income-tax returns late. In reply to it, I said that I have already given the reply to this question on 24-3 69. Unfortunately, instead giving this reply, my reply of 24-3-69 has been reproduced in the papers and the names of persons who have already filed their returns have appeared again ?

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : आपको अप टू डेट जवाब देना चाहिये था। आपने

पहले जवाब के लिए कहा, लोगों ने उसे छाप दिया।

श्री प्र० चं० सेठी : मुझ से पूछा गया था कि जिन मिनिस्टरों ने रिटर्न लेट फाइल किये हैं, उनके नाम क्या हैं। मैंने कहा था कि उनके नाम मैं फलां उत्तर में दे चुका हूं।

As far as the ministers' income-tax returns are concerned, I would request you that I would make a comprehensive statement giving the factual position as it stands today. I would not go into the particular case of Shri Jagjivan Ram, referred to by my hon. friend, because I am told a question has been allowed on it. I am also told that a discussion has been allowed and it is coming before the House. I do not know what time will be allotted to it. So, I would not go into the details because it is going to come up in the form of either a question or a discussion.

Then a question was asked about the disposal of appeals. While the disposal of appeals has been increasing, at the same time, the institution of appeals is also increasing with the result that even in appeals we are quite in arrears. We are looking into the problem as to how the procedure with regard to appeals and disposal of appeals could be hastened so that so many appeals may not remain pending.

Shri Shastri referred to total disposal under black money. Under the various schemes of disclosure about Rs. 197 crores were disclosed and to that extent people got relief. But wherever it was apprehended that the disclosures are not complete or comprehensive the cases were reopened. But is not as if all the cases were re-opened. I will not be able to give the number of cases which were re-opened.

Shri Banerjee has asked a particular question about Shri Ram Rattan Gupta. I could not envisage that in a comprehensive debate of this nature a particular question about Shri Ram Rattan Gupta would be asked. For that reason, I have not come prepared about this case. I know that the name of Shri Ram Rattan Gupta is uppermost in the mind of Shri Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE : I am interested in all Guptas, whether it be Kanwar Lal Gupta, C. B. Gupta or Ram Rattan Gupta.

SHRI P. C. SETHI : If the hon. Member asks a specific question I will certainly come before the House with full information.

SHRI RANDHIR SINGH : What about my question ? Are the proceedings before the income-tax officer judicial or not ?

SHRI P. C. SETHI : Shri Randhir Singh asked a very pertient question whether the proceedings before the income-tax officer are final. In the proceedings before the income-tax officer when he takes a decision there is always provision for appeal. If the remedy of the appellate authority is exhausted, one can go in appeal to the tribunal. After the tribunal he can go to the High Court. Therefore, thhre are various procedures.

As far as the proceedings before the income-tax officers are concerned, they are judicial proceedings and, to that extent, they are covered as judicial proceedings. Under section 271 (4A) the proceedings before the Income-tax Commissioner are not only judicial under section 271 (4B), whatever decision it gives in its capacity as Income-tax Commissioner cannot be challenged in a court of law. To that extent, the hon. Member is right that the proceedings before the Income-tax Commissioner under section 271 (4A) is a final verdict and it cannot be questioned or opened anywhere.

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Minister to conclude his speech.

SHRI UMANATH : He has not replied to a relevant question. All the measures that he has enumeaated to clear off the arrears are the measures which the Government have been resorting to far the past 22 years. A relevant question was asked now that Shri Morarji Desai is no more in the government and their hands are free whether any special or new measures are contemplated to clear off the arrears and to recover all the black money.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, let him reply to my question first. If a judicial verdict is challenged, is it a contempt of court not ?

SHRI P. C. SETHI : I have stated that legal position. He is a big lawyer himself.

SHRI RABI RAY (Puri) : Big lawyer ? He is an illustrious lawyer.

SHRI P. C. SETHI : I would not go in to that. I have stated the legal and factual position.

We are ourselves aware of the fact that there is scope for improvement. It is not as if the last word has been written and there is no scope for improvement, not only in the law but also in the administratative machinery. Therefore, we are thinking whether we should appoint an expert committee to go into this aspect of the problem and see how this thing could be streamlined and what measures could be taken so that not only the old arrears of assessment are disposed of but effective measures of collection are adopted. We are seriously thinking of that aspect of the problem. He shall take a clue from the suggestions made by the hon. Members both here and in the other House. On that basis we will go into that aspect also.

18.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 27, 1969/Agrahayana 6, 1891 (Saka).

Diamond Printing Press, Jaipur-3